FEBRUARY 2021

IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE (HINDI)

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट

बैंकों का निजीकरण

बजट 2021-22

वाहन मालिकों पर ग्रीन टैक्स

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामसयकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तयैार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट **www.iasbaba.com** दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – 'इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए ?

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 66 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो NOVEMBER-2020 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें **https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/**से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।**
- **इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्निsnippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारितPrelims MCQs) प्रस्तुत किया हैं जो आपको बेहतर revisionके लिए मार्गदर्शन करेंगे।**
- '**Must Read' section,**आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

'**Must Read' section**: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनसुरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

"Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them."

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- समाचार में समुदाय: मटुआ
- समाचार में कला: पट्टाचित्र
- 'चौरी चौरा' घटना का शताब्दी समारोह
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 नए सर्किल बनाए गए
- भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उपाय
- खबर में जगह: ढेकियाजुली
- राष्ट्रीय मानसून मिशन
- थोलपावकुथु
- श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष
- श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित

राजनीति / शासन

- राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (NEVA) परियोजना
- फेक न्यूज़ पर अमेरिकी मुकदमा: प्रेस स्वतंत्रता बनाम फेक न्यूज़
- संसदीय समिति और 5 जी
- आंध्र-ओडिशा सीमा विवाद
- भारत के राज्यपालों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान
- किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन
- जम्मू और कश्मीर के संघटक के संबंध में परिसीमन की प्रक्रिया
- स्मार्टकोड प्लेटफार्म का शुभारंभ किया
- संघवाद और भारत की मानव पूंजी
- केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संरचनात्मक समस्याएं
- दलबदल विरोधी कानून

सामाजिक मुद्दे / वेलफ़ेयर

- ओबीसी का उप-वर्गीकरण: जी रोहिणी आयोग
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम: जनसंख्या नियंत्रण के उपाय
- समाचार में समुदाय: कोच राजबंगशी
- प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
- SAKSHAM (श्रम शक्ति मंच) का शुभारंभ

- SANKALP (कौशल संवर्धन और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता)
- कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ
- भारत में आंतरिक प्रवास
- समाचार में समुदाय: देवेंद्र कुला वेल्लार
- वैक्सीन हेसिटेंसी/ हिचकिचाहट
- प्रवासी श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति मसौदा
- जनसंख्या बनाम ग्रह सम्मेलन
- भारत की बेरोजगारी की समस्या
- नेतृत्व पहल के लिए डच भारतीय जल गठबंधन (DIWALI)
- समलैंगिक विवाह

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

- नई रोशनी: अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक योजना
- "लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) पर कौशल प्रशिक्षण" का शुभारंभ
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: प्रिया रमणी केस

स्वास्थ समस्या

- 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)
- औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं पर शोध
- इंडिया पोस्ट और टाटा मेमोरियल सेंटर ने विश्व कैंसर दिवस पर एक विशेष कवर जारी किया
- एफएसएसएआई ट्रांस-फैटी एसिड (टीएफए) कैप करने के अपने नियमों में संशोधन
- राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM)
- विश्व यूनानी दिवस
- मलेरिया वेक्टर के विस्तृत जीनोम मानचित्र का अनावरण किया गया
- टीबी नियंत्रण के लिए सीओवीआईडी -19 से सबक
- गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग (NAFLD)

सरकारी योजनाएँ

- ONORC योजना का कार्यान्वयन
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त
- प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) को 16000 करोड़ रुपये आवंटित
- प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन
- बाल भिक्षावृत्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (MGNF) शुरू
- पायलट पे जल सर्वेक्षण का शुभारंभ
- टेक्नोग्राही के लिए नामांकन मॉड्यूल लॉन्च किया गया

अंतरराष्ट्रीय

- हांगकांग के निवासियों के लिए यूके स्पेशल वीज़ा योजना
- न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी
- व्यापार और निवेश पर प्रथम भारत-यूरोपीय संघ के उच्च-स्तरीय संवाद
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की पुन: भागीदारी की योजना
- नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन
- लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र पर आईसीसी का फैसला
- व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA)
- भारत और मॉरीशस के बीच CECPA
- ऑस्ट्रेलिया बनाम फेसबुक: समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता

भारत और विश्व

- भारत और श्रीलंका: भारत कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट
- म्यांमार में सैन्य तख्तापलट
- एक 'स्वस्थ' भारत-अफ्रीका साझेदारी की ओर
- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली भारत-बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक
- वैक्सीन कूटनीति
- भारत-ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था (I-ACE) हैकथॉन, 2021
- भारत और मालदीव के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

अर्थव्यवस्था

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: रोजगार
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: आत्मानिभर भारत योजना (ABRY)
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: बैंकिंग क्षेत्र
- भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8 वें संस्करण का उद्घाटन किया
- बजट 2021-22: विनिवेश
- बजट 2021-22: न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन
- बजट 2021: 10 सबसे बड़े कदम

- कपिला अभियान बौद्धिक संपदा के लिए शुरू किया गया
- एमएफआई: डिजिटल और फिजिकल माइक्रो-लेंडिंग
- RBI छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक सीधी पहुँच प्रदान करे
- सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका (CBSL) ने RBI से 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप सुविधा का निपटान किया
- पंद्रहवां वित्त आयोग (15 वां एफसी)
- कर्नाटक में लिथियम रिज़र्व
- बैंकों का निजीकरण
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक 2021
- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना
- जेबी एक्का समिति का गठन किया जाए
- RBI लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है
- उबर ड्राइवरों को श्रमिक माना जाता है और फ्रीलांस ठेकेदारों को नहीं: यूके सुप्रीम कोर्ट
- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल
- कारीगर आधारित SFURTI क्लस्टर का उद्घाटन किया गया
- द इंडिया टॉय फेयर 2021
- एकीकृत बांस उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया

कृषि

- कृतग्य: एग्री इंडिया हैकथॉन
- 'प्रति बूंद अधिक फसल'
- सोयाबीन के लिए कालाहांडी में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
- संसद ने कृषि यंत्रीकरण के बारे में जानकारी दी
- मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र
- उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव
- समुद्री शैवाल मिशन वाणिज्यिक समुद्री शैवाल की खेती के लिए शुरू किया
- कृषि-बाजार की स्वतंत्रता: चीन और इज़राइल से सबक
- कृषि ने रिमोटली एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी

पर्यावरण/ प्रदूषण

- डेनमार्क की कृत्रिम ऊर्जा द्वीप परियोजना
- विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021
- मेडागास्कर में दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप खोजा गया
- वाहन मालिकों पर ग्रीन टैक्स

- भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया
- समाचार में प्रजाति: लेदरबैक सी कछुआ
- डब्ल्यूसीसीबी ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 जीता
- हैदराबाद संसार के ट्री सिटी के रूप में उभरा है
- ग्रीनपीस का विश्लेषण वायु प्रदूषण के कारण अर्थव्यवस्था में लागत का विश्लेषण
- 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू किया गया
- कार्बन वॉच ऐप: कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए
- स्वाच आईसीीनिक प्लेसेज़

समाचारों में जंतु / राष्ट्रीय उद्यान

- मंदारिन बतख
- ब्लैक-ब्राउनेड बब्बलर 170 साल बाद फिर से खोजा गया
- Caracal (स्याहगोश) संकटग्रस्त लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- मेट्रोनो: बड़े पैमाने पर परिवहन की नवीन प्रणाली
- दक्षिण अफ्रीकी कोविड वेरिएंट
- शहरी गतिशीलता के साथ मुद्दे
- बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया
- रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान
- फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए दिशानिर्देश जारी
- अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए न्यायिक निर्णयों की जांच के लिए अध्ययन
- डोभी - दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अनुभाग का उद्घाटन किया
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020
- सागरिका: पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल
- सभी प्रकार के इस्पात को राजमार्ग निर्माण में अनुमति दी गई
- तेल और गैस परियोजनाएं तमिलनाडु में
- महाबाहु-ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ
- केरल में ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा
- केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
- फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

- अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से परिवहन के लिए एल.पी.जी.

विज्ञान और तकनीक

- एथिलीन ग्लाइकॉल: एक रसायन जो एंटीफ्रीज़र में पाया गया
- बजट 2021-22: विज्ञान और तकनीक
- स्टारडस्ट 1.0: बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम
- स्क्वायर किलोमीटर ऐरे वेधशाला (SKAO) परियोजना
- सोशल मीडिया विनियमन: ट्विटर को केंद्र की सूचना
- समाचार में कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- JATP - उत्कृष्टता केंद्र (JATP - CoE)
- आवर्त सारणी में 99 वें तत्व के गुण बताए गए हैं
- यूएई का होप मिशन
- क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन पर
- टेक कानून को कैसे लागू कर सकता है
- सुपरमैसिव ब्लैक होल, बीएल लैकर्टे से सबसे मजबूत फ्लेयर्स में से एक
- सोशल मीडिया विनियमन: केंद्र की नोटिस ट्विटर पर - भाग 2
- सैंड्स: एक त्वरित संदेश मंच
- भू-स्थानिक क्षेत्र - डीरेग्युलेटेड
- मंगल पर उतरने के लिए नासा की दृढ़ता और चीन का तियानवेन -1 सेट
- ग्रीन हाइड्रोजन
- यूके COVID-19 के लिए पहला मानव चुनौती परीक्षण करने के लिए
- नई लेड (Pb) मुक्त सामग्री की खोज की गई
- भारत शहरी डाटा एक्सचेंज (IUDX) का शुभारंभ
- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) का शुभारंभ
- न्यू सोशल मीडिया कोड
- ग्लोबल बायो-इंडिया 2021

आपदाप्रबंधन

- उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा
- हिमनद झील का प्रकोप बाढ़ (GLOFs)

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- समग्र कच्चे माल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन
- 'मेड इन इंडिया' MK-III एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH)
- लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (LUH) को प्रारंभिक परिचालन मंजूरी प्राप्त होती है
- केए -226 टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर
- समाचार में मैलवेयर: नेटवायर
- अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (Mk-1A)
- ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया
- हेलिना और ध्रुवस्त्र के लिए परीक्षण किया गया
- वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM)
- ग्रेटर टिपरलैंड

विविध

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

फरवरी 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

IASbaba's
Baba's 8 fold path to success!!
Baba's Foundation Course
(Baba's FC)
UPSC 2022
Learn more

IAS baba
60 DAY PLAN
60 Small Steps For Success In Prelims
Detailed GS & CSAT Schedule To Keep You On Track
Highest Hit Ratio For The Last 6 Years
60 DAY PLAN
Recommended By Toppers
Micro Analysis Matrix To Help You Understand Your Weak Areas & Improve.
The Most Awaited 7th Edition Of Successful 60 DAY PLAN For Prelims 2021 Is Here,
STARTING FROM MARCH 22ND
LET'S CLEAR PRELIMS WITH ONE SMALL STEP AT TIME

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

समाचार में समुदाय: मटुआ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

- हाल ही में पश्चिम बंगाल का मटुआ समुदाय खबरों में रहा

महत्वपूर्ण तथ्य

- मटुआ समुदाय में बंगाल सीमा के दोनों तरफ के सदस्य हैं।
- 1870 के दशक में यह समुदाय एक नामसुद्र (एससी) परिवार के सदस्य हरिचंद ठाकुर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन से जुड़ा है, जो पूर्वी बंगाल के सफालडांगा से आया था।
- 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में, उनके बेटे गुरुचंद ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस आंदोलन का आयोजन किया।
- 1915 में मटुआ समुदाय महासंघ की स्थापना हुई थी।
- आज, मटू पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी एससी आबादी है।
- वर्षों से, माटूस नागरिकता अधिनियम 2003 में संशोधन की मांग कर रहे थे, जिसके प्रावधानों ने इन शरणार्थियों को नागरिकता प्राप्त करना मुश्किल कर दिया था।

समाचार में कला: पट्टाचित्र

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

- पट्टचित्रा की पेंटिंग हाल ही में खबरों में थी, जब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान,' पट्टाचित्र 'पेंटिंग में गहरी रुचि के लिए ओडिशा के राउरकेला के एक युवा छात्र भाग्यश्री साहू का उदाहरण दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पट्ट का अर्थ है कपड़ा, और चित्रा का अर्थ है चित्र।
- पट्टचित्रा एक प्रकार का चित्र है जिसे कपड़े के टुकड़े पर चित्रित किया जाता है।
- यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में स्थित है।
- **बंगाल परंपरा:** यह कालीघाट (कोलकाता में) के आसपास केंद्रित है।
- **ओडिशा परंपरा:** यह पुरी के आसपास केंद्रित है। पुरी जिले के एक छोटे से गाँव रघुराजपुर में चित्रकार समुदाय के लगभग सभी लोग रहते हैं।
- ओडिशा पेंटिंग्स हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं जो विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित हैं।
- पेंटिंग में उपयोग किए जाने वाले सभी रंग प्राकृतिक हैं।

अंजीर: 'पट्टाचित्र' पेंटिंग

'चौरी चौरा' घटना का शताब्दी समारोह

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - आधुनिक इतिहास

समाचार में-

- 4 फरवरी 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।
- जिसके 100 साल हुए है। 'चौरी चौरा' की घटना का दिन, भारत की आजादी की लड़ाई की एक ऐतिहासिक घटना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी।
- इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। और गोलियां चला दी।
- जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसने इस थाने में कार्यरत सभी पुलिसकर्मी मारे गए
- इस घटना में 3 \नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।
- महात्मा गांधी, जो इस हिंसा के सख्त खिलाफ थे इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के बाद में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 6 नए सर्किल बनाए गए

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। भारत सरकार ने अपने मौजूदा सर्किलों के विभाजित करके 6 नए सर्किल स्थापित किए हैं: -

1. राजकोट सर्किल, गुजरात - वडोदरा सर्कल के द्विभाजन द्वारा।
2. जबलपुर मण्डल, मध्य प्रदेश - भोपाल मण्डल के विभाजन द्वारा।
3. तिरुचिरापल्ली (त्रिची) सर्कल, तमिलनाडु - चेन्नई और त्रिशूर सर्कल के द्विभाजन द्वारा।
4. मेरठ सर्कल, उत्तर प्रदेश - आगरा सर्कल के द्विभाजन द्वारा
5. झाँसी सर्किल, उत्तर प्रदेश - लखनऊ सर्किल के विभाजन द्वारा।

6. रायगंज सर्किल, पश्चिम बंगाल - कोलकाता सर्किल के विभाजन के द्वारा।
इसके अलावा, हम्पी मिनी-सर्कल को पूर्ण सर्कल के रूप में अपग्रेड किया गया है वहीं दिल्ली के छोटे मिनी-सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ विलय कर दिया गया है।

भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उपाय

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

- संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में संसद को सूचित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संस्कृति मंत्रालय ने "भारत की अमूर्त विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए योजना" नामक एक योजना बनाई है।
- इस योजना का उद्देश्य: भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।
- ज्ञातव्य है कि भारत ने 2003 के सम्मेलन के तहत मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत के 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) तत्वों को सफलतापूर्वक दर्ज किया।
- सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची ICH बनाने की दिशा में, संस्कृति मंत्रालय (MoC) ने अपनी वेबसाइट पर एक सूची डाली है जिसे "सांस्कृतिक विरासत के लिए राष्ट्रीय सूची" कहा जाता है।
- सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची भारत की अमूर्त विरासत में समाहित इस विविधता को पहचानने का एक प्रयास है।

महत्वपूर्ण तथ्य

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के बाद, इस सूची को पाँच व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दिखाई देती है:
1. मौखिक परंपरा और अभिव्यक्ति इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में शामिल किया गया है।
2. कला प्रदर्शन
3. सामाजिक प्रथाओं, अनुष्ठान, और त्यौहारों का आयोजन
4. प्रकृति और ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान और अभ्यास
5. पारंपरिक शिल्प कौशल

संबंधित लेख:

- संस्कृति संबंधी शब्द: यहां क्लिक करें
- सिंगापुर में हॉकर संस्कृति: यहां क्लिक करें

खबरों में: ढेकियाजुली

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - आधुनिक इतिहास

समाचार में-

- हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने असम के ऐतिहासिक शहीद शहर ढेकियाजुली में दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी तथा एक सड़क और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ढेकियाजुली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद संभवतः असम के ढेकियाजुली टाउन से ही थे।

- 20 सितंबर, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में, स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूसों ने असम के कई शहरों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों तक प्रदर्शन किया।
- 'मृत्यु बाहिनी' के नाम से प्रसिद्ध इन समूहों में महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की व्यापक भागीदारी रही और ये लोग औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले पुलिस स्टेशनों पर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे।
- इन प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बर्बरता पूर्ण कारवाही किया ।
- ढेकियाजुली टाउन में, कम से कम 15 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनमें से तीन महिलाएँ और जिनमें 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ भी शामिल थीं।

क्या तुम जानते हो?

- ढेकियाजुली टाउन में 20 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- हाल ही में, ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन को विरासत का दर्जा दिया गया और असम सरकार द्वारा पुनः बहाल किया गया।

राष्ट्रीय मानसून मिशन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - भूगोल और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राज्यसभा को राष्ट्रीय मानसून मिशन के बारे में सूचित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मानसून मिशन के तहत, मंत्रालय ने अत्याधुनिक मौसम और जलवायु भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया है, जो अब परिचालन में हैं।
- इन मॉडलों में लघु-श्रेणी से मध्यम श्रेणी (1-10 दिन), विस्तारित-श्रेणी (10 दिन से 30 दिन) और मौसमी मॉडल शामिल हैं।

मानसून मिशन के लक्ष्य

- इसका उद्देश्य लघु, मध्यम और लंबी दूरी के पूर्वानुमानों के लिए एक अति आधुनिक गतिशील मानसून भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है।
- सामाजिक प्रभावों (जैसे कृषि, बाढ़ पूर्वानुमान, चरम घटनाओं का पूर्वानुमान, पवन ऊर्जा, आदि) वाले जलवायु अनुप्रयोगों के लिए एक प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन करना।
- आदर्श भविष्यवाणियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को तैयार करने के लिए उन्नत डेटा आत्मसात करना।

पिछले तीन वर्षों के दौरान NMM की प्रमुख उपलब्धियां

- मौसमी भविष्यवाणी; विस्तारित रेंज भविष्यवाणी और बहुत उच्च-रिज़ॉल्यूशन शॉर्ट-रेंज भविष्यवाणी के लिए एक उन्नत भविष्यवाणी प्रणाली की स्थापना।
- 12 किमी पर लघु और मध्यम श्रेणी की भविष्यवाणी के लिए एक ग्लोबल एनसेंबल फोरकास्ट सिस्टम (GEFS) का गठन।

थोलपावकुथु

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

- पहली बार, थोलपावकुथु, प्रसिद्ध छाया चमड़े की कठपुतलियां रोबोट की मदद से महाकाव्य रामायण की कहानियां बतायेंगी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- थोलपावकुथु छाया कठपुतली का एक रूप है।

- भारत के केरल में अभ्यास किया जाता है।
- भद्रकाली को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग करके इसे प्रदर्शित किया जाता है।
- इनका प्रदर्शन देवी मंदिरों में तथा विशेष रूप से निर्मित सिनेमाघरों में किया जाता है जिसे आम बोल-चाल में कुथुमादम कहा जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति नवीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी।
- यह कम्बा रामायण को अपने मूल पाठ के रूप में उपयोग करता है।

श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री राम चंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- श्री रामचंद्र मिशन (एसआरसीएम) एक गैर-लाभकारी संगठन है और भारत में उत्पन्न होने वाला एक आध्यात्मिक आंदोलन है।
- यह "सहज मार्ग" या हृदय की साधना का अभ्यास सिखाता है।
- यह 1945 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के राम चंद्र द्वारा पंजीकृत किया गया था।
- **वर्तमान मुख्यालय:** हैदराबाद (तेलंगाना) है।
- सहज मार्ग (प्राकृतिक मार्ग) राज योग का एक रूप है।
- यह योग की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ध्यान, सफाई और प्रार्थना शामिल है।

श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

• भारतीय राष्ट्रपति ने हाल ही में नई दिल्ली में 'श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन' को संबोधित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वे एक दलित-कवि संत थे।
- वे भक्ति आंदोलन युग से सम्बंधित थे।
- उनका समय शायद 14 वीं से 16 वीं शताब्दी था।

- वह चमड़े के काम करने वाले चमार समुदाय से थे।
- गुरु रविदास के 41 भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है।
- प्रसिद्ध संत कवयित्री मीराबाई गुरु रविदास की शिष्या थीं।

उनकी शिक्षाएँ

- हर कोई हर तरह से समान है, चाहे वह किसी जाति का हो, रंग या ईश्वर के किसी भी रूप में विश्वास; सार्वभौमिक भाईचारे और सहिष्णुता पर जोर दिया।
- ईश्वर ने मनुष्य को बनाया न कि मनुष्य ने ईश्वर को;
- उन्होंने ईश्वर के सगुण (गुण, छवि के साथ) रूपों को त्याग दिया तथा ईश्वर के निर्गुण (गुण, अमूर्त) रूप पर ध्यान केंद्रित किया।

राजनीति / शासन

राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (NEVA) परियोजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - राजनीति और शासन

समाचार में-

- हाल ही में मेघालय में राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (NEVA) परियोजना खबरों में थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ई-विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है।
- इसके कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA)
- नेवा की फंडिंग केंद्रीय प्रायोजित योजना के पैटर्न पर है, अर्थात 60:40; और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100%।
- ई-विधान के लिए धनराशि MoPA द्वारा प्रदान की जाती है।
- **तकनीकी सहायता:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीत)।

क्या आप जानते हो?

- पेपरलेस असेंबली या ई-असेंबली एक अवधारणा है जिसमें विधानसभा के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल हैं।
- यह संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया, निर्णय और दस्तावेजों पर नज़र रखने, सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है।
- **नेवा का उद्देश्य:** देश के सभी विधानसभाओं को एक साथ लाने के लिए, एक मंच पर जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण करना है।
- इसके अलावा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की लाइव प्रसारण भी इस एप्लिकेशन पर उपलब्ध है।
- राज्य विधानमंडलों के संबंध में इसी तरह की सुविधाओं को शामिल करने के प्रावधान के साथ दूरदर्शन पहले से ही सक्षम है।

फेक न्यूज़ पर अमेरिकी मुकदमा: प्रेस स्वतंत्रता बनाम फेक न्यूज़

संदर्भ: वोटिंग मशीन बनाने वाले स्मार्टमैटिक ने अमेरिकी मीडिया पावरहाउस फॉक्स न्यूज के खिलाफ झूठे चुनावी दावों के लिए 2.7 बिलियन डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

मामला क्या है?

- 258 पृष्ठ के मुकदमे में, कंपनी ने दावा किया कि फॉक्स समाचार मीडिया ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और स्मार्टमैटिक के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया साथ ही यह आरोप भी लगाया कि डेमोक्रेट्स चुनाव को जब्त करने की अनुमति देने के लिए इसकी मशीनों और सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों को हैक कर लिया।
- एक शो में, स्मार्टमैटिक को फॉक्स न्यूज द्वारा "वेनेजुएला की कंपनी के रूप में समाजवादी देशों के भ्रष्ट तानाशाहों के नियंत्रण के रूप में दर्शाया गया था।
- हालांकि इन दावों ने चुनाव के परिणाम को नहीं बदला, स्मार्टमैटिक ने दावा किया कि समाचार मीडिया संगठन और इसके मेजबान ने रेटिंग और विज्ञापनों में इस कथा को फैलाने से लाभ उठाया
- दूसरी ओर, कंपनी को प्रतिष्ठा का नुकसान उठाना पड़ा और इन दावों पर विश्वास करने वालों से नफरत भरे मेल और मौत की धमकी मिली
- फॉक्स न्यूज ने अदालत को यह कहते हुए मुकदमा खारिज करने की मांग की कि यह संविधान के तहत फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स को रद्द करने का प्रयास है (प्रेस की स्वतंत्रता की मान्यता)

मामले का महत्व

- **नकली समाचार के खिलाफ लड़ाई:** इस तरह के भारी नुकसान का दावा करने वाले मुकदमे को विघटन से लड़ने के लिए एक परीक्षण मामले के रूप में देखा जा रहा है।
- **फेक न्यूज़ की सुधारात्मक कार्रवाइयाँ संदेह का कारण हैं:** मुकदमे की सुनवाई होने से पहले ही, फॉक्स न्यूज़ के शो को रद्द करना जिसमें होस्ट प्रतिवादी है, को एक सुधार उपाय के रूप में देखा जा रहा है।
- पिछले उपायों से बहुत कम परिणाम मिले: विज्ञापन बहिष्कार, और नकली समाचारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियानों का हाल के वर्षों में बहुत कम प्रभाव पड़ा है।
- **प्रेस बनाम मानहानि कानून की स्वतंत्रता:** इस कानून में पहला संशोधन सुरक्षा के साथ, मानहानि कानून वादी (व्यक्ति दाखिल मामला), विशेष रूप से सार्वजनिक आंकड़े और सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकारियों के लिए असंगत है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि मुकदमा एक निजी पार्टी द्वारा लाया गया है, जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वजनिक आंकड़ों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा रखता है।
- **मानहानि कानून में न्यायिक वरीयता:** अमेरिका में, 1964 का महत्वपूर्ण मामला जो न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम मीडिया के पक्ष में सुलिवन परिवाद (मानहानि) कानून को फिर से परिभाषित करता है। मामले ने मानक निर्धारित किया कि

सार्वजनिक चिंताओं से जुड़े मामलों में एक परिवाद मुकदमा जीतने के लिए, केवल यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तथ्य का एक गलत बयान दिया गया था, लेकिन उन्हें वादी को नुकसान पहुंचाने के लिए या तो दुर्भावनापूर्ण विचार-विमर्श के प्रयास की आवश्यकता होगी या तथ्यों के साथ छेड़छाड़। इसलिए स्मार्टमैटिक कंपनी के पास लड़ने के लिए कड़ी लड़ाई है

- **निर्णय का वैश्विक स्तर पर महत्व:** हालांकि अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन में प्रेस की स्वतंत्रता की स्पष्ट मान्यता अमेरिकी मीडिया को एक अनोखे स्थान पर रखती है, इस मामले में प्रेस फ्रीडम को संतुलित करने और विश्वभर में सूचनाओं का गलत इस्तेमाल करने वांको को भी दण्डित करने की आश्वकता है।

क्या आपको पता है?

- भारत का संविधान, अमेरिका के विपरीत, भारत में प्रेस की स्वंत्रता बोलने की आजादी में ही समाहित है।
- अनुच्छेद 19 (1) (A), जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, प्रत्येक नागरिक के लिए है। प्रेस अधिकारों के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में योग्य नहीं है, लेकिन स्वतंत्र भाषण के सामूहिक अधिकार में प्रत्येक व्यक्तिगत पत्रकार शामिल है।
- अमेरिकी कानून की तुलना में, भारत का नागरिक मानहानि कानून वादी के पक्ष में है। वादी को केवल यह साबित करने की आवश्यकता होगी कि उसके खिलाफ दिए गए बयान से उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और किसी को बदनाम करने लिए के सबूत की आवश्यकता नहीं है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- डिजिटल मीडिया (सुदर्शन टीवी केस) के नियमन पर: यहाँ क्लिक करें

संसदीय समिति और 5 जी

संदर्भ: सूचना प्रौद्योगिकी पर लोकसभा की एक स्थायी समिति ने 5 जी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कहा है कि भारत 5 जी बस सेवा अभी लागू नहीं होगी।

आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के निष्कर्ष क्या हैं?

- **जमीनी स्तर पर प्राप्ति बहुत कम:** दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत को अगस्त 2018 की शुरुआत में 5G के रूप में तैयार करने के लिए सुझाओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसके बावजूद जमीन स्तरपर बहुत कम प्रगति हुई।
- **उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य:** 5 जी की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य दुनिया में सबसे अधिक था। इसे देश की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए और अन्य देशों के लिए अनिवार्य आरक्षित मूल्य के साथ तुलना करके इसे तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता थी।
- **परीक्षण मामलों की अपर्याप्त और खराब विकास:** वैश्विक रूप से, 59 देशों में 118 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 5 मिलियन नेटवर्क की तैनाती शुरू कर दी है। जनवरी 2020 तक सभी तीन प्रमुख निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने आवेदन जमा नहीं किये, वहीं भारत को 5G परीक्षण के लिए औपचारिक अनुमोदन देना बाकी है।
- **5 जी की विलंबित रोलआउट:** इसकी तुलना अन्य पुरानी तकनीकों जैसे 2 जी की तैनाती से की जाती है, जिस पर चार साल की देरी हुई; 3 जी जिस पर भारत को एक दशक से अधिक का समय लगा था, और 4 जी जिस पर भारत 7 साल से चूक गया था, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि "भारत में 5 जी सेवाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी।"
- पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर की कम पहुंच, बुनयादी क्षमता की कमी एक अन्य कारक है जो भारत में 5 जी की तैनाती में देरी कर रहे हैं।

निष्कर्ष

- जहां तक भारत में 5 जी को बंद करने की बात है, सभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं

- संसदीय समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक किए जाने से पहले ही, DoT ने नई सेवाओं के लिए तेजी से काम किया है और से टेलोकोस कंपनियों के लिए नोटिस की अवधि को एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया था।
- कम समय का मतलब यह होगा कि इस साल सितंबर तक टेलिस्कोप तीनों बैंडों में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 5 जी नेटवर्क का परीक्षण शुरू कर देगा ये हैं अर्थात निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम
- इसके अलावा, संसदीय समिति को यह भी उम्मीद थी कि स्पेक्ट्रम के आवंटन को जल्द से जल्द करने के लिए DoT अंतरिक्ष विभाग और रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझ बनाएगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- यूके ने हुआवेई पर दरवाजा बंद कर दिया

आंध्र-ओडिशा सीमा विवाद

संदर्भ: आंध्र प्रदेश ने हाल ही में कोटिया क्लस्टर में तीन गांवों में पंचायत चुनाव आयोजित किए, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवाद के केंद्र में है।

- आंध्र के पंचायत चुनावों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 18 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- ओडिशा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव के संचालन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

गाँव

- **आदिवासी प्रभुत्व:** लगभग 5,000 की आबादी वाले ये गाँव, अंतर्राज्यीय सीमा पर एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं और कोंध आदिवासियों द्वारा बसाए गए हैं।
- **वामपंथी उग्रवाद:** क्षेत्र, एक बार माओवादी घटना घटित हुई इससे इस क्षेत्र में अभी भी हिंसा की छिटपुट घटनाओं की रिपोर्ट रहती है।
- **समृद्ध संसाधन:** ये गांव सोने, प्लैटिनम, मैंगनीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट और चूना पत्थर जैसे खनिज संसाधनों से भी समृद्ध हैं।

विवाद का संक्षिप्त इतिहास

- 1 अप्रैल, 1936 से पहले, कोटिया पंचायत के तहत आने वाले गाँव जेयपोर एस्टेट का हिस्सा थे।
- ओरिसा ऑर्डर, 1936 के संविधान में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, भारत सरकार ने तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी से ओडिशा का सीमांकन किया (जिसमें वर्तमान आंध्र प्रदेश भी शामिल है) ।
- 1942 में, मद्रास सरकार ने सीमा लड़ी और दोनों राज्यों के पुन: सीमांकन का आदेश दिया।
- ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश के संयुक्त सर्वेक्षण में, कोटिया ग्राम पंचायत के सात गांवों को राजस्व गांवों के रूप में दर्ज किया गया था और ओडिशा सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता था, लेकिन विवाद के कारण राजस्व एकत्र का कार्य अब 21 गांवों में छोड़ दिया गया।
- जब 1955 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गांवों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

इन विवादित गांवों में रहने वाले लोगों की राजनीतिक स्थिति क्या है?

- यह पहली बार है जब आंध्र ने इनमें से किसी भी गाँव में पंचायत चुनाव कराए हैं।
- लेकिन गांव दोनों राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाग लेते हैं। वे आंध्र के सालुर विधानसभा और अराकू लोकसभा सीटों और ओडिशा की पोटका विधानसभा और कोरापुट लोकसभा सीटों के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
- ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के तहत दोनों राज्यों से लाभ मिलता है।

- ओडिशा ने एक ग्राम पंचायत कार्यालय, एक गाँव कृषि केंद्र, एक बोर्डिंग स्कूल, छात्रावास का निर्माण, MGNREGA को लागू किया और 800 परिवारों को BPL कार्ड और 1800 परिवारों को जॉब कार्ड वितरित किए हैं।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों को सड़कें, बिजली की आपूर्ति और राशन उपलब्ध कराया है

वर्तमान स्थिति

- 1980 के दशक की शुरुआत में, ओडिशा ने 21 गांवों पर अधिकार और अधिकार क्षेत्र की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया।
- हालांकि 2006 में, अदालत ने फैसला दिया कि चूंकि राज्य की सीमाओं से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए यह मामला केवल संसद द्वारा हल किया जा सकता है और विवादित क्षेत्र पर एक स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर सकता है।

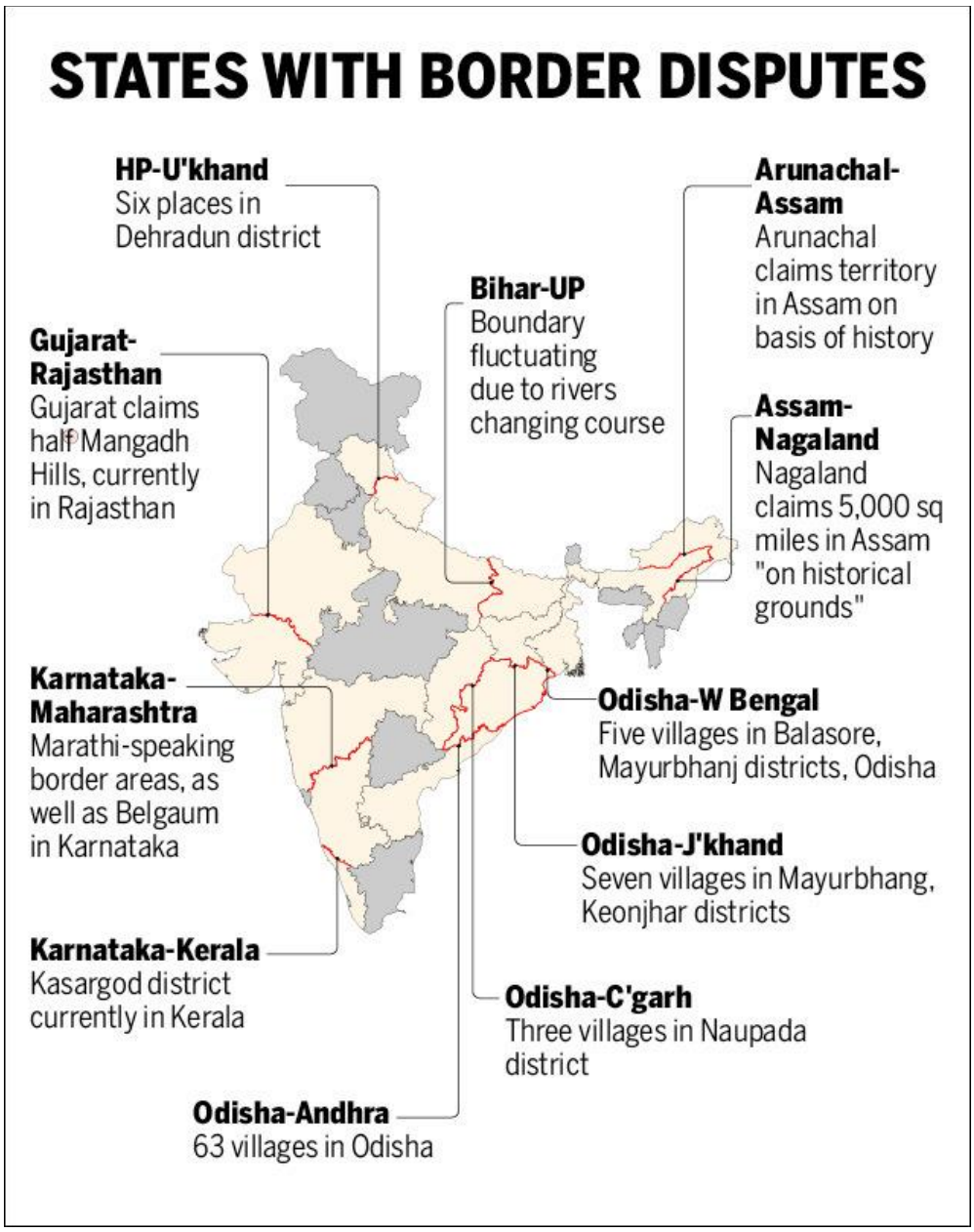

Pic Source: Times of India

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा विवाद (बेलागवी मुद्दा)

भारत के राज्यपालों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - संविधान

समाचार में-

- डॉ. किरण बेदी को हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया।
- तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई साउंडराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में 'दोहरी क्षमता' में कार्य करता है।
- वह संघ और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है।
- अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158: राज्यपाल के लिए अहर्ताएं
  - भारत का नागरिक हो
  - कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो
  - संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य न हो
  - लाभ के पद पर न हो
- पद की अवधि: 5 साल
- इसे पहले राज्यपाल को हटाया जा सकता है
  - मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्तगी।
  - राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकेगा जब इसका कार्य न्यायालयों द्वारा असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण घोषित किया जाता है।
  - राज्यपाल द्वारा इस्तीफा

किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पष्टता लाने के लिए जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 में कुछ बड़े संशोधनों की शुरुआत की और कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए नौकरशाहों पर अधिक जिम्मेदारियां सौंपी।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम) 2015 क्या है?

- **अद्यतन विधान:** किशोर कानून और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम) 2000 को बदलने के लिए इसे 2015 में संसद में पेश और पारित किया गया था।
- **नामकरण में परिवर्तन:** अधिनियम जुवेनाइल से बच्चे या कानून के साथ संघर्ष में बच्चे नाम दिया गया है। इसके अलावा, यह शब्द "किशोर" से जुड़े नकारात्मक अर्थ को घटाता है।
- **16-18 साल के लिए विशेष प्रावधान:** नए अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में से एक यह है कि जिन किशोरों पर जघन्य अपराधों के आरोप लगाए गए है और जो 16-18 साल की उम्र के बीच के हैं, उन्हें वयस्कों की तरह जाएगा और वयस्क न्याय प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद इस प्रावधान को गति मिली, जिसमें से एक आरोपी की उम्र महज 18 साल थी और इसलिए उसे किशोर के रूप में पेश किया गया।

- **जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड:** अपराध की प्रकृति, और किशोर को नाबालिग या बच्चे के रूप में रखने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसको किशोर न्याय बोर्ड (हर जिले में स्थापित) द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही हर जिले में बाल कल्याण समितियों का गठन किया जाना चाहिए। दोनों में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।
- **दत्तक ग्रहण से संबंधित धाराएँ:** एक अन्य प्रमुख प्रावधान यह था कि अधिनियम ने अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों के लिए गोद लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और मौजूदा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया ताकि वह अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर सके।
- **नए अपराधों को शामिल करना:** इस अधिनियम में बच्चों के खिलाफ किए गए कई नए अपराध शामिल हैं (जैसे, अवैध गोद लेना, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चे का उपयोग, विकलांग बच्चों के खिलाफ अपराध, आदि) जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से कवर नहीं किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या संशोधन पारित किए गए हैं?

1. जघन्य अपराधों के अलावा गंभीर अपराधों का समावेश

- इसमें पहली बार "गंभीर अपराधों" की श्रेणी को शामिल किया गया है, किसी भी अस्पष्टता को दूर करते हुए, पहली बार जघन्य और गंभीर अपराधों को भी स्पष्ट किया गया है।
- इसका मतलब यह है कि किशोर द्वारा किया गया जघन्य अपराध वयस्कों द्वारा किया गया अपराध समझा, अपराध की सजा में न केवल अधिकतम सात साल या उससे अधिक की सजा होनी चाहिए, बल्कि न्यूनतम सात साल की सजा भी होनी चाहिए।
- यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि बच्चों को, जितना संभव हो, संरक्षित किया जाए और वयस्क न्याय प्रणाली से बाहर रखा जाए।
- सात साल के न्यूनतम कारावास के साथ जघन्य अपराध ज्यादातर यौन अपराधों और हिंसक यौन अपराधों से संबंधित हैं। अवैध पदार्थों जैसे ड्रग्स या अल्कोहल की तस्करी और बिक्री जैसे अपराध अब "गंभीर अपराध" के दायरे में आएंगे।

2. जिला और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों के दायरे का विस्तार करना

- एनसीपीसीआर की रिपोर्ट 2019 में पाया गया था कि देश में एक भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया।
- डीएम और एडीएम हर जिले में जेजे एक्ट के तहत विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे। इसमें बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ और विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयाँ शामिल हैं।
- संशोधन कहता है कि डीएम की मंजूरी के बिना कोई भी नया घर नहीं खोला जा सकता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि उनके जिले में पड़ने वाला सीसीआई सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।
- गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और घरों और पालक घरों में बच्चों के तेजी से पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए, संशोधन यह प्रावधान करता है कि डीएम अब लंबी अदालती प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए हुए गोद लेने के प्रभारी होंगे।

निष्कर्ष

हालांकि संशोधनों का स्वागत किया गया है, लेकिन देखभाल की जरूरत में बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के अपने प्रयास में, डीएम को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर के संबंध में परिसीमन की प्रक्रिया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - शासन; चुनाव; संविधान

समाचार में-

- परिसीमन आयोग ने हाल ही में J & K के UT के संबंधित सदस्यों के साथ एक बैठक की।

- उद्देश्य: यूटी के संबंध में परिसीमन की प्रक्रिया पर उनके सुझाव लेना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- परिसीमन लोक सभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को कम करने का कार्य है।
- **परिसीमन का उद्देश्य:** किसी आबादी के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना यह एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन है ताकि एक राजनीतिक दल को चुनाव में दूसरों पर फायदा न हो।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 82 के तहत, संसद हर जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है।
- परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
- परिसीमन आयोग चार बार स्थापित किए गए हैं - 1952, 1963, 1973 और 2002
- 1981 और 1991 के जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ।

स्मार्टकोड प्लेटफार्म का शुभारंभ किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीति और शासन

समाचार में-

- स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया था।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- स्मार्टकोड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सभी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को शहरी शासन के लिए विभिन्न समाधानों और अनुप्रयोगों के लिए ओपन-सोर्स कोड के भंडार में योगदान कर उन्हें सक्षम बनाता है।
- यह उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है जो शहरी स्थानीय निकायों (ULB) डिजिटल अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती में सामना करते हैं।
- यह शहरों को मौजूदा कोड का लाभ उठाने में सक्षम करेगा और उन्हें नए समाधान विकसित करने के बजाय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए अनुकूलित करेगा।
- स्रोत कोड बिना किसी लाइसेंस या सदस्यता शुल्क के उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा

संघवाद और भारतीय मानव संसाधन

संदर्भ: पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा में हस्तक्षेप के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की मानव राजधानी

- विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में, भारत 116 वें स्थान पर है।
- 2019-20 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 दर्शाता है कि अधिकांश राज्यों में कुपोषण के संकेतक स्थिर या इसमें कमी आई हैं।
- नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 में सीखने के नतीजे खराब बताए गए हैं। राज्यों में इसका बहुत अभिसरण कम है।
- भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4% मानव पूंजी पर खर्च करता है (क्रमशः 1% और स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगभग 3%) - विकासशील देशों में सबसे कम।
- इस संबंध में सरकार की विभिन्न पहलें जैसे पोशन अभियान 2.0 और समग्र शिक्षा अभियान - बेहतर परिणामों की ओर अग्रसर नहीं हैं।

- विश्व स्तर पर, उप-राष्ट्रीय सरकारों के प्रति व्यय और राजस्व के वितरण में एक मौलिक बदलाव आया है।
- इन प्रवृत्तियों का अध्ययन विकेंद्रीकरण और मानव पूंजी के बीच एक सकारात्मक संबंध का प्रदर्शन करते हुए किया जाता है।
- हाल के वर्षों में, भारत ने विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने कर विचलन में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, जिसे प्रभावी रूप से पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा बनाए रखा गया था।

मुद्दे

- **शक्तियों के विचलन का अभाव:** कई राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए स्पष्ट रूप से सीमांकन या कार्य नहीं करते हैं
- **स्थानीय निकायों की भूमिका में असमानताएँ:** 73 वें और 74 वें संशोधन ने संवैधानिक रूप से पंचायतों को मान्यता देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। हालाँकि, संविधान राज्यों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि वे कैसे पंचायतो को सशक्त करें, जिसके परिणामस्वरूप तृतीय-स्तरीय सरकारों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में भारी असमानताएं हैं।
- **अनुच्छेद 282 के साथ मुद्दा:** संविधान के अनुच्छेद 282 को विविध वित्तीय प्रावधान 'के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अनुच्छेद 270 और 275 के विपरीत, जो संघ और राज्य के बीच राजस्व के वितरण के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 282 का सम्बन्ध आम तौर पर विशेष, अस्थायी या तदर्थ योजनाओं के लिए है।
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के साथ मुद्दा:** इनमें आमतौर पर एक लागत-साझाकरण मॉडल होता है, जिससे राज्यों के राजकोषीय स्थान को खाली कर दिया जाता है।
- तृतीय-स्तरीय सरकारें राजकोषीय रूप से सशक्तीकृत नहीं हैं। संपत्ति कर का संग्रह, तृतीय-स्तरीय सरकारों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत, भारत में बहुत कम है (जीडीपी का 0.2% से कुछ अन्य देशों में जीडीपी के 3% की तुलना में)।
- **संस्थागत विफलता:** कई राज्यों ने समय पर राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का गठन पूरा नहीं किया है।

आगे की राह

- केंद्र को राज्यों के बीच ज्ञान-साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक सक्षम भूमिका निभानी चाहिए।
- राज्यों के लिए मानव पूंजी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए, उन्हें पर्याप्त राजकोषीय संसाधनों की आवश्यकता है।
- राज्यों को मानव पूंजी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को तर्कसंगत बनाना चाहिए।
- केंद्र को सीएसएस की लागत-साझा अनुपात में बदलाव करके और उपकर बढ़ाने जैसे कर विचलन से बचना चाहिए।
- सीएसएस पर भारी निर्भरता कम की जानी चाहिए, और कर विचलन और अनुदान सहायता ऊर्ध्वाधर राजकोषीय हस्तांतरण के प्राथमिक स्रोत होने चाहिए।
- ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध कार्यों के साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं को निहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- हमारी बहु-स्तरीय संघीय प्रणाली की सच्ची क्षमता का उत्थान मानव पूंजी के विकास की दिशा में सबसे अच्छा तरीका है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद

केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संरचनात्मक समस्याएं

संदर्भ: हाल ही में, पुडुचेरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सदन में पार्टी का बहुमत अचानक कम हो गया और सरकार गिर गई।

क्या आपको पता है?

- सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है।

- लेकिन संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार, इस्तीफा स्वैच्छिक या वास्तविक होना चाहिए। यदि अध्यक्ष को इसके विपरीत जानकारी है, तो वह इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

संघवाद के साथ हालिया मुद्दा क्या है?

- अब विधायकों के इस्तीफे के लिए एक परिचित पैटर्न है। इस तरह के इस्तीफे राज्यों में सत्तारूढ़ दलों से बड़े पैमाने पर होते हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ होते हैं और इस तरह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की सरकार गिर जाती है।
- सरकार को गिराने के इस तरीके का एक फायदा यह है कि किसी भी विधायक को दोष नहीं देना पड़ता है और न ही अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।
- हालांकि, यह एकमात्र तरीका नहीं है जहां केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सरकारें कमतर हैं। कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं जो संघ शासित प्रदेशों की संरचनात्मक नाजुकता को दर्शाते हैं

केंद्र शासित प्रदेशों की संरचनात्मक नाजुकता

1. विधानमंडल की संरचना

- अनुच्छेद 239 ए मूल रूप से 1962 में लाया गया था ताकि संसद को संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने में सक्षम बनाया जा सके (उद्देश्य यूटी में लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रदान करके पूरा करना था)
- हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 में एक साधारण संशोधन 50% से अधिक नामांकित सदस्यों के साथ विधायिका बना सकता है। यह सवाल बना हुआ है कि मुख्य रूप से नामांकित हाउस प्रतिनिधि लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा देता है।

2. नामांकन का मुद्दा

- पुडुचेरी के लिए 33 सदस्यीय सदन में, तीन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। हालांकि, अनुच्छेद 239 ए या केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, जो इसे राजनीतिक दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बनाता है।
- इसलिए, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना तीन भाजपा सदस्यों को विधानसभा में नामांकित किया, तो इसे अदालत में चुनौती दी गई।
- अंत में, सर्वोच्च न्यायालय (के। लक्ष्मीनारायणन बनाम भारत संघ, 2019) ने माना कि केंद्र सरकार को विधानसभा में सदस्यों को नामित करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है और नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्य के रूप में वोट देने का अधिकार है।

3. प्रशासक की शक्ति

- केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम की धारा 44 और संविधान के अनुच्छेद 239 एए (4) के अनुसार, प्रशासक को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से असहमत होने और फिर उन्हें अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है संघ सरकार की सहायता और सलाह पर।
- इस संवैधानिक प्रावधान का शस्त्रीकरण पूर्ण रूप में किया जाता है जब केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा शासित होता है।
- हालांकि दिल्ली बनाम भारत संघ (2019) के एनसीटी में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि प्रशासक को इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ताकि क्षेत्र में निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न न हो हालांकि वास्तव में इसका दुरुपयोग ही होता है

निष्कर्ष

- अनुभव से पता चलता है कि केंद्रीय प्रशासक में निहित अंतिम नियंत्रण वाले विधायिका केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने योग्य नहीं हैं।
- इसका समाधान कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों को हटाने में निहित है जो संघ शासित प्रदेशों की संरचनात्मक नाजुकता को कमजोर करते हैं और इसके बजाय उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए हैं ताकि लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षा को पूरा किया जा सके।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- जम्मू-कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में परिसीमन की प्रक्रिया
- दिल्ली के चलने में न्यायिक संघर्ष

दल-बदल रोधी कानून

बारे में

- दलबदल विरोधी कानून 1985 में दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में "राजनीतिक दल-बदल " का मुकाबला करने के लिए शामिल किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य सरकारों की स्थिरता को बनाए रखना।
- किसी भी संसद सदस्य (सांसद) या राज्य विधानमंडल (विधायक) सदस्य को उनके पद से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रस्ताव पर मतदान किया है।
- यह प्रावधान विश्वास प्रस्ताव की मंशा या मनी बिल (जो अर्ध-आत्मविश्वास की गति है) तक सीमित नहीं था।
- यह सदन के सभी मतों पर, प्रत्येक विधेयक और प्रत्येक अन्य मुद्दे पर लागू होता है। यह राज्यसभा और विधान परिषदों पर भी लागू होता है, जिनका सरकार की स्थिरता में कोई मतलब नहीं है।

मुद्दे

- इसलिए, एक सांसद (या विधायक) को किसी भी मुद्दे पर अपने फैसले के लिए वोट करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। पार्टी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
- यह प्रावधान प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है।
- दलबदल-रोधी कानून सांसद को न तो निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाता है और न ही एक राष्ट्रीय विधायक, लेकिन उन्हें सिर्फ पार्टी का एजेंट बना देता है।
- विधायक मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है, और सरकार विधायकों के प्रति जवाबदेह है। (यह प्रतिनिधि लोकतंत्र का आदर्श होना चाहिए)।
- विधायकों को मुख्य रूप से पार्टी के प्रति जवाबदेह बनाकर जवाबदेही की श्रृंखला को तोड़ा गया है।
- इसलिए, सरकार बनाने वाली पार्टी - सरकार को जवाबदेह बनाये रखने में असमर्थ है।
- विधायक विभिन्न मुद्दों पर अपने पदों को उन लोगों को नहीं बता सकते हैं जिन्होंने उन्हें पद के लिए चुना है।
- कानून हमारी विधानसभाओं को खोखला कर देता है। यदि किसी सांसद को नीति और विधायी प्रस्तावों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो विभिन्न नीतिगत विकल्पों और उनके परिणामों को समझने के प्रयास में क्या प्रोत्साहन होगा।
- दलबदल विरोधी विधेयक जवाबदेही तंत्र को कमजोर करता है।
- यह स्थिरता प्रदान नहीं करता है। राजनीतिक व्यवस्था ने सरकारों को गिराने के तरीके ढूंढ लिए हैं।

निष्कर्ष

- दलबदल रोधी कानून हमारे विधायिकाओं के कामकाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह जानबूझकर बनाया गया एक निकाय हैं जो नागरिकों की ओर से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाये रखता है।
- इसने उन्हें विधेयकों और बजटों पर सरकार के निर्णय का समर्थन करने के मंचों में बदल दिया है।
- इसने सरकारों की स्थिरता को संरक्षित करने का काम भी नहीं किया है।

सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर

ओबीसी का उप-वर्गीकरण: जी रोहिणी आयोग

संदर्भ: 21 जनवरी को, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण से सम्बंधित आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। आयोग के पास अब अपनी रिपोर्ट देने के लिए 31 जुलाई तक का समय है।

- मंडल आंदोलन के तीन दशक: यहां क्लिक करें

ओबीसी का उप-वर्गीकरण क्या है?

- ओबीसी को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है।
- सितंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को फिर से खोल दिया।
- उप-श्रेणीकरण बहस इस धारणा से निकलती है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक संपन्न समुदायों में से केवल 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है।
- उप-वर्गीकरण के लिए तर्क - या आरक्षण के लिए ओबीसी के भीतर श्रेणियां बनाना - यह है कि यह सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व के "समान वितरण" को सुनिश्चित करेगा।

आयोग का गठन

- आरक्षण के लाभों के इस असमान लाभों का परीक्षण करने के लिए, रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था।
- उस समय, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन तब से कई बार समय बढ़ाया गया हैं, वर्तमान में 10 वीं बार समय बढ़ाया गया है।
- आयोग में अन्य सदस्य पूर्व पत्रकार जितेंद्र बजाज, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं।
- रोहिणी आयोग की स्थापना से पहले, केंद्र ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया था।
- रोहिणी आयोग विज्ञान भवन एनेक्सी में एक कार्यालय के बाहर संचालित होता है और इसका खर्च NCBC द्वारा वहन किया जाता है। दिसंबर 2020 तक वेतन, सलाहकार शुल्क और अन्य खर्चों सहित आयोग पर 1.92 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं।

आयोग के संदर्भ की शर्तें क्या हैं?

यह मूल रूप से संदर्भ की तीन शर्तों के साथ स्थापित किया गया था:

- केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में ओबीसी की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना;
- ऐसे ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, मानदंड और मापदंडों को पूरा करने के लिए
- ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थी लोगों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कवायद।

(जब मंत्रिमंडल ने इसे विस्तार दिया तब) 22 जनवरी, 2020 को एक चौथा संदर्भ जोड़ा गया

- ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों के सुधार की सलाह देने के लिए हैं।

- यह 30 जुलाई, 2019 को आयोग को सरकार के एक पत्र के बाद जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि आयोग ने सूची में कई अस्पष्टताएं नोट की हैं और केंद्रीय सूची को उप-वर्गीकृत करने से पहले इन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इसने अब तक क्या प्रगति की है?

- 30 जुलाई, 2019 को सरकार को लिखे अपने पत्र में, आयोग ने लिखा है कि यह मसौदा रिपोर्ट (उप-वर्गीकरण पर) के साथ तैयार है।
- यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि रिपोर्ट के बड़े राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और न्यायिक समीक्षा का सामना कर सकते हैं।
- आयोग को दिए गए संदर्भ के नवीनतम शब्द (22 जनवरी, 2020 को) के बाद, यह केंद्रीय सूची में समुदायों की सूची का अध्ययन कर रहा है।
- नौकरियों और प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के साथ तुलना करने के लिए विभिन्न समुदायों की आबादी के लिए आयोग की बाधा डेटा की अनुपस्थिति रही है।
- आयोग ने शुरुआत में ओबीसी की जाति-वार जनसंख्या के अनुमान के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में कहा कि इसने इस तरह के सर्वेक्षण का विचार छोड़ दिया है।
- 31 अगस्त, 2018 को, गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि जनगणना 2021 में, ओबीसी का डेटा भी एकत्र किया जाएगा, लेकिन तब से सरकार इस पर चुप है, जबकि ओबीसी के समूह जनगणना में ओबीसी की गणना की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी भर्ती की सीमा क्या है?

- 24 जुलाई, 2020 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा NCBC को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, OBC का नौकरियों में प्रतिनिधित्व है
  - ग्रुप-ए केंद्र सरकार की सेवाओं में 16.51%
  - ग्रुप-बी में 13.38%

ग्रुप-सी में 21.25% (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

  - ग्रुप-सी (सफाई कर्मचारियों) में 17.72%
- यह डेटा केंद्र सरकार के केवल 42 मंत्रालयों / विभागों के लिए था।
- यह बताया गया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित कई पदों को सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा भरा जा रहा था क्योंकि ओबीसी उम्मीदवारों को "एनएफएस" अर्थात कोई भी उपयुक्त नहीं मिला घोषित किया गया था। गृह मंत्री ने एनसीबीसी को इस पर देशव्यापी डेटा एकत्र करने के लिए कहा है लेकिन एनसीबीसी को "एनएफएस" के डेटा को इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए अभी तक कोई प्रगति नहीं की है।
- सरकार ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में संशोधन पर भी विचार कर रही है।

इसके निष्कर्ष अब तक क्या हैं?

2018 में, आयोग ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछले पांच वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत दिए गए 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। निष्कर्ष थे:

- सभी नौकरियों और शैक्षिक सीटों के 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के सिर्फ 25% ही प्राप्त हुए हैं;
- इन नौकरियों और सीटों के 24.95% सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों के लिए गए हैं;
- 983 ओबीसी समुदाय - कुल का 37% - नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व है;
- 994 ओबीसी उप-जातियों की भर्ती और प्रवेश में कुल 2.68% का प्रतिनिधित्व है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम: जनसंख्या नियंत्रण के उपाय

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य और जीएस- I - सोसायटी

समाचार में-

- सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू कर रही है जो देश में जनसंख्या वृद्धि की जाँच करने के लिए लक्ष्य-मुक्त दृष्टिकोण के माध्यम से लाभार्थियों को स्वैच्छिक और सूचित विकल्प प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी।
- **उद्देश्य:** 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना।
- **नई गर्भनिरोधक विकल्प:** वर्तमान गर्भनिरोधक में दो नए गर्भ निरोधकों- इंजेक्शन गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमन (छा) के समावेश के साथ विस्तारित किया गया है।
- पोस्ट-पार्टम अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (PPIUCD) प्रोत्साहन योजना जिसके तहत PPIUCD सेवाएं प्रसव के बाद प्रदान की जाती हैं।
- नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए मुआवजा योजना जो लाभार्थी को मिलने वाले मजदूरी के नुकसान की भरपाई और साथ ही सेवा प्रदाता और नसबंदी के संचालन के लिए टीम प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एनएफपीआईएस) जिसके तहत क्लाइंट को मौत की स्थिति, जटिलता और नसबंदी ऑपरेशन के बाद विफलता की भरपाई की जाती है।
- परिवार नियोजन लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सूचना प्रणाली (FP-LMIS): स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।
- मिशन परिवार विकास को सात उच्च फोकस राज्यों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए लाया गया है, (जिनमें कुल प्रजनन दर 3 से अधिक है।)
- लाभार्थियों के दरवाजे पर आशाओं द्वारा गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी की योजना शुरू की गई है।
- समुदायों में उपयोग के लिए आशा की दवा किट में गर्भावस्था परीक्षण किट के प्रावधान के लिए योजना।

समाचार में समुदाय: कोच राजबंगशी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - सोसायटी

समाचार में-

- हाल ही में कोच राजबोंगशी समुदाय खबरों में था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ये ऐसा समुदाय हैं जो अपनी जड़ें कामता साम्राज्य से जोड़ते हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और आसपास के प्रदेश शामिल हैं।
- मध्यकाल में, समुदाय प्रमुख था और कामतापुर क्षेत्र पर शासन करता था, तत्कालीन कामतापुर में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और भारत के उत्तर-पूर्व का एक बड़ा हिस्सा शामिल था।
- आजादी के बाद, कूच बिहार की रियासत पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गई।
- आज, कोच राजबंशी असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- उनकी अनुमानित जनसंख्या पश्चिम बंगाल में 33 लाख से अधिक है, ज्यादातर उत्तरी जिलों और असम में इनकी बड़ी संख्या उपस्थिति है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- NITI Aayog ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप-समूह का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **रचना:** विभिन्न मंत्रालयों, विषय विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के सदस्य।
- **उद्देश्य:** प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करना।

महत्वपूर्ण बिंदु

OSH कोड

- अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों, 2020 (OSH कोड) में शामिल किया गया था।
- कोड को सितंबर 2020 में अधिसूचित किया गया था
- **OSH कोड का प्रावधान:** निर्णय लेने की स्थिति, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, दुरुपयोग और शोषण से सुरक्षा, कौशल में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा।
- **लक्ष्य:** प्रवासी श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियां।
- **प्रयोज्यता:** प्रत्येक स्थापना जिसमें 10 या अधिक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे।

SAKSHAM (श्रमिक शक्ति मंच) का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II- कल्याण योजनाएं; नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस- III - रोजगार

समाचार में-

- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) ने SAKSHAM (श्रम शक्ति मंच) लॉन्च किया है।
- TIFAC भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह MSMEs की आवश्यकताओं के संबंध में श्रमिको के कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नौकरी पोर्टल है।
- **उद्देश्य:** MSMEs के साथ श्रमिक को सीधे जोड़ना और उनके काम की सुविधा प्रदान करना
- पोर्टल श्रम ठेकेदारों को खत्म करने में मदद करेगा।
- यह श्रमिक दक्षता स्तर की पहचान करने और श्रमिको के लिए कौशल कार्ड के विकास में मदद करेगा।
- पोर्टल श्रमिको की उपलब्धता के लिए एल्गोरिथ्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का उपयोग करता है।
- पोर्टल को शुरू में दो जिलों में लॉन्च किया गया था और अब इसे अखिल भारतीय पोर्टल के रूप में लॉन्च किया जा रहा है।

SANKALP (कौशल संवर्धन और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - कौशल विकास

समाचार में-

- AL SANKALP कार्यक्रम के तहत रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ट्रांसफ़िलिंग स्किलिंग हाल ही में आयोजित की गई थी।
- मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)

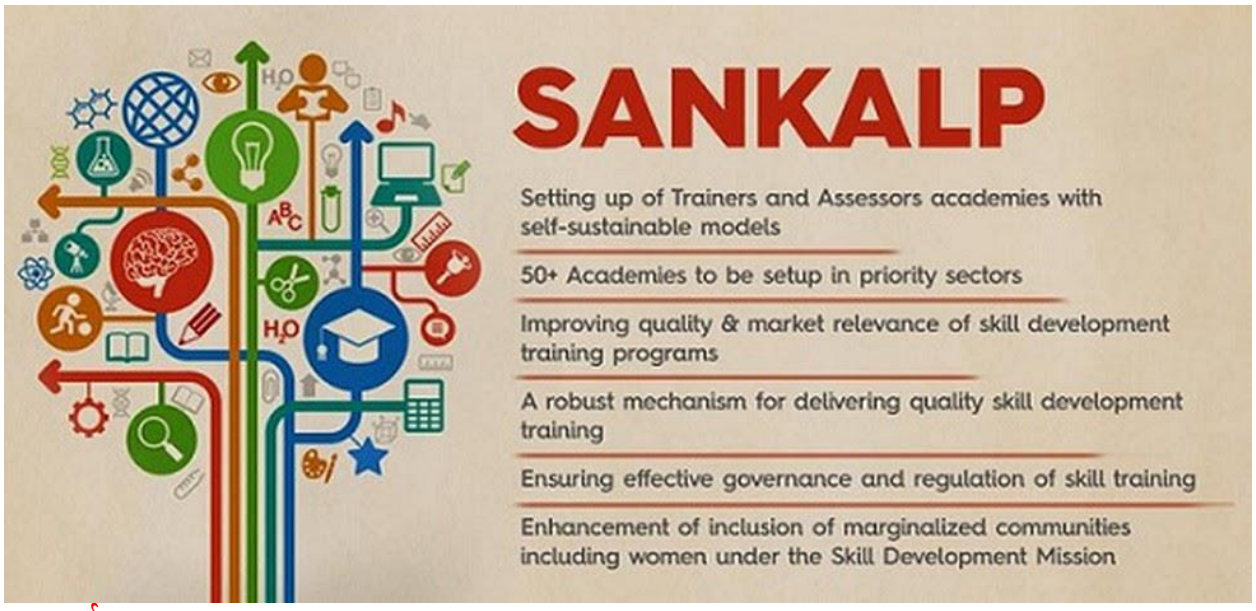

महत्वपूर्ण तथ्य

- SANKALP (कौशल संवर्धन और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता) एक विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम है
- **उद्देश्य:** जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों (डीएससी) को मजबूत करना।
- यह दो साल का शैक्षणिक कार्यक्रम है।
- यह जिला प्रशासन के साथ ऑन-ग्राउंड व्यावहारिक अनुभव के एक अंतर्निहित घटक के साथ आता है।
- यह पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर (टीओटी) प्रणाली का भी समर्थन करेगा।
- MSDE ने 2018 में SANKALP योजना के तहत "जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार" (DSDP पुरस्कार) की स्थापना की है।

कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - कौशल विकास

समाचार में-

- राज्य सभा में भारत में कुशल युवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी गयी।
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)

महत्वपूर्ण तथ्य

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के युवाओं को लघु अवधि के प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना:** गैर-साक्षरों, नव-साक्षरों और स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना और उन्हीं के क्षेत्र में बाजार उपलब्ध कराना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS):** प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और द अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं के जुड़ाव को बढ़ाना।

- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस):** भारत में 14,788 आईटीआई के माध्यम से 137 ट्रेडों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है।

भारत में आंतरिक प्रवास

संदर्भ: लॉकडाउन के समय में आंतरिक प्रवासियों का संकटपूर्ण प्रवास उस अवधि की सबसे स्थायी स्मृति थी, जिसने उनकी दुर्दशा का संज्ञान लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
मार्च 2020 के लॉकडाउन के ग्यारह महीने बाद, स्थिति काफी अलग है।

भारत का आंतरिक प्रवासन

- **विशाल संख्या:** भारत में अनुमानित 600 मिलियन प्रवासी हैं। दूसरे शब्दों में, भारत का लगभग आधा हिस्सा ऐसी जगह पर रह रहा है, जहाँ उसका जन्म नहीं हुआ था।
- **अन्तर्राज्यीय प्रवासन:** अनुमानित 400 मिलियन भारतीय "जिस जिले में रहते हैं, उसके भीतर" प्रवास "करते हैं। अगले 140 मिलियन एक जिले से दूसरे जिले में और उसी राज्य के भीतर प्रवास करते हैं।
- **इंटर-स्टेट माइग्रेशन:** और केवल लगभग 60 मिलियन - यानी, सभी आंतरिक प्रवासियों का सिर्फ 10% - एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं।
- **ग्रामीण प्रवासन:** प्रवास का सबसे प्रभावी रूप ग्रामीण क्षेत्रों में है। कुल प्रवास का लगभग 20% (600 मिलियन) ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में है।
- **शहरी प्रवासन:** कुल प्रवास का 20% एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र का है। उल्लेखनीय है की शहरी प्रवास (ग्रामीण से शहरी के साथ-साथ शहरी से शहरी) कुल प्रवास का 40% हिस्सा है।
- **भविष्य में वृद्धि संभावित:** जैसा कि भारत ने तेजी से शहरीकरण की रणनीति अपनाई है - उदाहरण के लिए, स्मार्ट शहरों के निर्माण और अनिवार्य रूप से आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में शहरों का उपयोग आंतरिक प्रवास के स्तर में और वृद्धि करेगा।
- **COVID-19 प्रेरित शॉक:** यह अनुमान है कि 60 मिलियन के करीब महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के मद्देनजर अपने मूल "स्रोत" ग्रामीण क्षेत्रों में वापस चले गए। यह संख्या आधिकारिक अनुमानों से लगभग छह गुना है। यह अनुमान उस श्रम आघात की भावना को भी मापता है जो भारत की अर्थव्यवस्था ने प्रवासियों के रूप में सामना किया।

"कमजोर परिपत्र प्रवासियों" की चिंता

- 200 मिलियन कोविद व्यवधान से व्यापक रूप से प्रभावित थे।
- सबसे ज्यादा प्रभावित "कमजोर परिपत्र प्रवासियों" थे। ये वे लोग हैं जो नौकरी के बाजार में अपनी कमजोर स्थिति और "परिपत्र" प्रवासियों के कारण "कमजोर" हैं क्योंकि भले ही वे शहरी परिवेश में काम करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पैर जमना जारी है।
- ऐसे प्रवासी निर्माण स्थलों या छोटे कारखानों में या शहर में रिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं, लेकिन जब इस तरह के रोजगार घटते हैं, तो वे अपनी ग्रामीण परिवेश में वापस चले जाते हैं।
- वे कृषि के बाहर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के 75% का योगदान करते हैं लेकिन उनकी आजीविका को करने के लिए अधिकांश समस्या में, विमुद्रीकरण, जीएसटी या कोबिड-19 व्यवधान हो सकता है।

निष्कर्ष

- भारत में आंतरिक प्रवासियों का अनुपात (समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में) रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे कुछ तुलनीय देशों की तुलना में बहुत कम है - सभी में बहुत अधिक शहरीकरण अनुपात है।

- COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान देखे गए संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए श्रमिक वर्ग की गहन समझ आवश्यक है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- श्रम कोड का नया संस्करण: यहां क्लिक करें

समाचार में समुदाय: देवेंद्र कुला वेल्लार

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - सोसायटी

समाचार में-

- देवेंद्र कुला वेल्लार समुदाय हाल ही में खबरों में था।
- मीडिया ने अनुसूचित जाति से इस समुदाय को बाहर करने से संबंधित सूचना दी है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार गलत सूचना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मंत्रालय के अनुसार कैबिनेट ने 7 एससी समुदायों में देवेंद्र कुला वेल्लार में वर्गीकृत करने के लिए मंजूरी दे दी है।
- एससी सूची के तहत इन समुदायों को वर्गीकृत करने का विधेयक पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है।

क्या आप जानते हो?

- पल्लर, जिसे मल्लर कहा जाता है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली तमिल किसान जाति है।
- समुदाय के सदस्य खुद को देवेंद्र कुला वेल्लार (डीकेवी) के रूप में संदर्भित करते हैं, यह दर्शाता है कि वे देवेंद्र भगवान द्वारा बनाए गए थे।

वैक्सीन हेसिटेंसी

- वैक्सीन संकोच को टीका सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीकाकरण के लिए अनिच्छा या अस्वीकार के रूप में परिभाषित किया गया है।

वैक्सीन हेसिटेंसी के क्या कारण हैं?

COVID-19 टीकों के लिए संकोच के आसपास बहस शामिल हैं

- टीकों की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग टाइमलाइन के कारण सुरक्षा, प्रभावकारिता, और दुष्प्रभावों पर चिंता
- कई कंपनियों, गलत सूचनाओं के बीच प्रतिस्पर्धा
- धार्मिक मान्यताये
- COVID-19 टीकों के आसपास गलत सूचना का तूफान
- मौजूदा पक्षपात, सूचना अधिभार और सीमित ध्यान फैलाव के कारण गलत सूचना देने वाले लोगों की आशंका।

आगे की राह

- लक्षित दर्शकों को स्विंग आबादी यानी लोगों पर संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों और उचित संचार के माध्यम से समझा जा सकता है।
- सेलिब्रिटी प्रभाव का उपयोग - टीके लेने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तित्व की क्षमता का उपयोग
- सेलेब्रिटीज सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, टीके को अपनाने से जुड़े संशय को मिटा सकते हैं और सूचना प्राप्त करने और रोकथाम के व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं
- COVID-19 टीकों से संबंधित किसी भी समाचार के फैक्ट को चेक करें।

- COVID-19 टीके से सम्बंधित भ्रम, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों से सक्रिय रूप से निपटा जा सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- अफवाहों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण: यहां क्लिक करें

विशिष्ट भूमि टाइटल

संदर्भ: 2020 में, भले ही खेतों से संबंधित सुधार और श्रम संहिता सुधार के कानून बनाए जा रहे है, सरकार के थिंक टैंक, NITI Aayog, ने समावेशी भूमि टाइटल पर मॉडल बिल का मसौदा तैयार करके भूमि सुधार शुरू करने के लिए कदम उठाए। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी सहमति के लिए भेजा गया था।

वर्तमान प्रणाली कैसे काम करती है?

- भारत वर्तमान में अनुमान लगाने योग्य भूमि की एक प्रणाली का अनुसरण करता है। इसका मतलब है कि कब्जे की जानकारी के साथ भूमि रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है, जो पिछले लेनदेन के विवरण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
- स्वामित्व, तब, वर्तमान कब्जे के आधार पर स्थापित किया जाता है।
- भूमि का पंजीकरण वास्तव में लेनदेन का पंजीकरण है, जैसे बिक्री कर्म, विरासत के रिकॉर्ड, बंधक और पट्टे।
- होल्डिंग पंजीकरण कागजात में वास्तव में सरकार या कानूनी ढांचे को शामिल नहीं किया जाता है जो भूमि के स्वामित्व के शीर्षक की गारंटी देता है।

कॉनक्लूज़न लैंड टाइटलिंग की नई प्रणाली में क्या बदलाव आएगा?

- दूसरी ओर, इस निर्णायक भूमि शीर्षक प्रणाली के तहत, भूमि रिकॉर्ड वास्तविक स्वामित्व को निर्दिष्ट करते हैं।
- शीर्षक सरकार द्वारा दिया जाता है, जो सटीकता के लिए जिम्मेदारी लेता है।
- एक बार एक शीर्षक दिए जाने के बाद, किसी अन्य दावेदार को सरकार के साथ विवादों को निपटाना होगा, न कि शीर्षक धारक को।
- आगे निर्णायक भूमि शीर्षक के तहत, सरकार विवादों के मामले में दावेदारों को मुआवजा प्रदान कर सकती है, लेकिन शीर्षक धारक स्वामित्व को अपनी जमीन खोने का कोई डर नहीं होगा।
- 2020 में नीति आयोग द्वारा परिचालित विधेयक, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले भूमि प्राधिकरणों के लिए बात कहता है, जो मौजूदा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर भूमि शीर्षक की एक मसौदा सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए एक शीर्षक पंजीकरण अधिकारी (TRO) नियुक्त करेगा।

निर्णायक भूमि की आवश्यकता क्यों है?

- **कम मुकदमेबाजी:** इससे जमीन से संबंधित काफी कम मुकदमेबाजी होगी। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, भारत में सभी लंबित अदालती मामलों में भूमि संबंधी विवादों का दो-तिहाई हिस्सा है।
- **भूमि विवादों का त्वरित समाधान:** इससे भूमि संबंधी मुकदमे को हल करने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। NITI Aayog के अध्ययन से पता चलता है कि भूमि या अचल संपत्ति के विवादों को सुलझाने के लिए अदालतों में औसतन 20 साल का समय लगता है।
- **मालिकों के लिए मामले का दस्तावेजीकरण और अस्पष्टता को कम करता है:** अभी, क्योंकि भूमि के शीर्षक लेनदेन पर आधारित हैं, लोगों को लेन-देन के रिकॉर्ड की पूरी श्रृंखला रखनी होती है, और उस श्रृंखला में किसी भी लिंक पर विवाद स्वामित्व में अस्पष्टता का कारण बनता है,
- **व्यापार करने में आसानी:** एक बार निर्णायक शीर्षक लगाने के बाद, जो निवेशक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, वे निरंतर जोखिम का सामना किए बिना ऐसा करने में सक्षम होंगे कि उनके स्वामित्व पर सवाल उठाया जा सके और उनका पूरा निवेश बेकार चला जाए।

- **तेजी से बुनियादी ढाँचा विकास:** भूमि विवाद और अस्पष्ट शीर्षक भी बुनियादी ढाँचे के विकास और आवास निर्माण के लिए बाधा पैदा करते हैं, जिससे लागत में देरी और अक्षमता होती है। समावेशी शीर्षक इन चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा।
- **निवेश आकर्षित करता है:** भूमि स्वामित्व में अस्पष्टता के कारण भूमि प्राप्त करने में देरी से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में निवेश कम हो जाती है। समावेशी भूमि शीर्षक से विदेशी निवेश आकर्षित करने और सक्रिय भूमि बाजार को बढ़ावा देने के लिए ऐसी अस्पष्टताएं दूर हो जाएंगी।
- **सरकारी राजस्व को बढ़ाता है:** शहरों में, शहरी स्थानीय निकाय संपत्ति करों पर निर्भर करते हैं जो केवल तभी स्वामित्व में हो सकते हैं जब कोई स्पष्ट स्वामित्व डेटा उपलब्ध हो। स्वामित्व में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप भूमि लेनदेन के लिए एक काला बाजार भी बनता है, जो सरकार को करों से वंचित करता है।
- **सस्ता संस्थागत ऋण तक पहुंच को बढ़ाता है:** कृषि ऋण तक पहुंच भूमि को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर है। अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने में सक्षम होने के बिना, ग्रामीण लोग अक्सर निजी ऋणदाताओं के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। उचित स्वामित्व लोगों को सस्ते संस्थागत ऋण का उपयोग करने में सक्षम करेगा।

आगे की चुनौतियां

- **अद्यतन की कमी:** भूमि रिकॉर्ड दशकों से अद्यतन नहीं किया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में
- **वंशानुक्रम का मुद्दा:** भूमि के रिकॉर्ड अक्सर वर्तमान मालिक के दादा दादी के नाम पर होते हैं, जिनमें विरासत का कोई प्रमाण नहीं होता है।
- **अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है:** जब तक कि वे अद्यतन रिकॉर्ड पर आधारित न हों, निर्णायक भूमि शीर्षक और भी अधिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
- **फेडरल सेट अप:** हमारी तरह एक बहु-पक्षीय सेट में फेडरलिज्म की चुनौती भी है। यहां, राज्यों को कानूनों को लागू करना होगा और इसे सफल बनाने के लिए पूरी भावना के साथ लागू करना होगा
- **कमजोर स्थानीय निकाय:** समुदाय की भागीदारी के साथ स्थानीय रूप से स्वामित्व साबित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, स्थानीय सरकारों को ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए संसाधन या श्रमशक्ति प्रदान नहीं की गई है।

आगे की राह

सामुदायिक भागीदारी के साथ व्यापक ग्राम-स्तरीय सर्वेक्षण भूमि शीर्षक प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान रिकॉर्ड्स या यहां तक कि उपग्रह इमेजरी पर भरोसा वास्तविक, स्थानीय सर्वेक्षणों के समान सटीकता प्रदान नहीं करेगा

प्रवासी श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति मसौदा

संदर्भ: कोविद -19 लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों से 10 मिलियन प्रवासियों के पलायन (सरकारी अनुमान के अनुसार) के कारण नीति आयोग, अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के एक कार्यसमूह के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा तैयार किया है। ।

मौसादा गठित की मुख्य विशेषताएं

- **अधिकार आधारित दृष्टिकोण:** नीति एक अधिकार-आधारित ढांचे के बजाय, एक हैंडआउट दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है। मसौदा नीति दो दृष्टिकोणों का वर्णन करता है: एक नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और आरक्षण पर ध्यान केंद्रित

और दूसरा जो एजेंसी और क्षमता को बढ़ाता है। समुदाय और इस प्रकार उन पहलुओं को हटाते हैं जो किसी व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक क्षमता को पनपने देते हैं

- **अभिस्वीकृति:** प्रवासन को विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और सरकार की नीतियों में बाधा नहीं होनी चाहिए, बल्कि आंतरिक प्रवास को सुविधाजनक बनाना चाहिए।
- **पॉलिसी में दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए:** ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार लक्ष्य अस्थायी या स्थायी आर्थिक या सामाजिक सहायता प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य अधिक स्थायी आधार पर होना चाहिए
- **विधान:** NITI Aayog के नीति मसौदे में उल्लेख किया गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को "प्रवासियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपयोग" के लिए अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 में संशोधन करना चाहिए।
- **प्रभावी समन्वय की आवश्यकता:** यह विभिन्न एजेंसियों / विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए साथ ही प्रवासियों से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में स्थापित करना चाहिए है।
- **विशेष इकाई के माध्यम से संस्थागत तंत्र:** मसौदा मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों की गतिविधियों में मदद करने के लिए श्रम मंत्रालय के तहत एक विशेष इकाई बनाने का सुझाव देता है। यह इकाई उच्च प्रवास क्षेत्रों में एक प्रवासन संसाधन केंद्रों का प्रबंधन करेगी, एक राष्ट्रीय श्रम हेल्पलाइन होना चाहिए तथा सरकार के लिए श्रमिक परिवारों के लिंक योजनाओं का क्रियान्वयनऔर अंतर-राज्य प्रवासन प्रबंधन निकायका गठन किया जाना चाहिए।
- **अंतर-राज्य समन्वय:** अंतर-राज्य प्रवासन प्रबंधन निकायों को चाहिए कि प्रमुख प्रवासन गलियारों के साथ स्रोत और गंतव्य राज्यों के श्रम विभाग, प्रवासी कार्यकर्ता के माध्यम से एक साथ काम करना चाहिए। स्रोत राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को गंतव्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है - जैसे, नई दिल्ली के बिहार भवन में श्रम आयुक्त की नियुक्ति महत्वपूर्ण है।l;
- **स्थानीय निकायों की बढ़ी हुई भूमिका:** नीतियों को "प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए" और प्रवास की स्थितियों में सुधार करने के लिए शहरी और ग्रामीण नीतियों को एकीकृत करना चाहिए। पंचायतों को प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस रखना चाहिए, पहचान पत्र जारी करना करने के साथ साथ पास बुक उपलब्ध करना, साथ ही कौशल विकास के माध्यम से प्रवास प्रबंधन और शासन उपलब्ध कराना जिससे लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- **प्रशासन रोकने के उपाय:** भले ही विकास में माइग्रेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, मसौदा प्रशासन रोकने की वकालत करता है। मसौदा राज्यों को "आदिवासी के स्थानीय आजीविका में प्रमुख बदलाव लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए कहता है जिसके परिणामस्वरूप रुक सकता है। कुछ हद तक प्रवास"।
- **डेटा का महत्व:** मसौदा एक केंद्रीय डेटाबेस के लिए नियोक्ताओं को "मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को भरने" और "सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ" सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए सिफारिश करता है। यह मंत्रालयों और जनगणना कार्यालय को प्रवासियों और उप-योगों की परिभाषाओं के अनुरूप होने, और मौजूदा सर्वेक्षणों में प्रवासी को शामिल करने के लिए कहता है।
- **प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा:** शिक्षा मंत्रालय को मुख्य धारा के प्रवासी बच्चों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उपाय करना चाहिए, जिससे प्रवासी बच्चों की पहचान की जा सके और प्रवासी स्थलों में स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें।
- **शिकायत निवारण:** राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और श्रम मंत्रालय को प्रवासी श्रमिकों के लिए तस्करी, न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं के शिकायत तथा उसके निवारण फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करनी चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

जनसंख्या बनाम प्लेनेट सम्मेलन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - सोसायटी

समाचार में-

- हाल ही में (जनसंख्या बनाम प्लेनेट सम्मेलन) आयोजित किया गया था।
- यह WION और ज़ी मीडिया के साल भर के अभियान का एक हिस्सा है जिसे 'मिशन सस्टेनेबिलिटी: पॉपुलेशन बनाम' ग्रह कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व जनसंख्या वर्ष 1800 में 1 बिलियन से बढ़कर आज 7.8 बिलियन हो गई है।
- भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ से बढ़कर 2011 में 121.02 करोड़ हो गई है।
- इसने प्रजनन और मृत्यु दर दोनों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी है।
- जन्म दर 1951 में 40.8 / 1000 से घटकर 2018 में 20.0 हो गई है।
- कुल प्रजनन दर (TFR) 1951 में 6.0 से घटकर 2015-16 में 2.2 हो गई है।
- भारत में मृत्यु दर 2012 में 7 से घटकर 2018 में 6.2 हो गई है।
- भारत और राज्यों के लिए 2011-2036 के जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार, टीएफआर में और गिरावट की उम्मीद है।
- 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की आबादी 2011 में 233 मिलियन से घटकर 2036 में 227 मिलियन हो जाने का अनुमान है।
- कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 2011 में 61% से बढ़कर 2036 में 65% हो जाने की उम्मीद है।

भारत की बेरोजगारी की समस्या

संदर्भ: ट्विटर पर एक ट्रेंड चला हुआ था जिसमें सरकार को देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए कहा गया। 2019-20 वित्तीय वर्ष के अंत में कोविद संकट से ठीक पहले, भारत में लगभग 403.5 मिलियन नियोजित लोग और लगभग 35 मिलियन (या 3.5 करोड़) खुले तौर पर बेरोजगार लोग थे (जो काम मांग रहे हैं और लेकिन इन्हे काम पा रहे हैं)।

मुद्दे

- **प्रत्येक वर्ष नौकरी चाहने वालों को जोड़ना:** भारत की जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, प्रत्येक वर्ष लगभग 20 मिलियन (या 2 करोड़) लोग हैं जो 15 से 59 वर्ष की कार्य-आयु की आबादी में प्रवेश करते हैं।
- **रिकवरी पोस्ट महामारी:** जनवरी 2021 तक, भारत में केवल लगभग 400 मिलियन कार्यरत थे (पूर्व COVID यह 403.5% था)। एक स्तर पर यह अच्छी खबर है क्योंकि अब तक नौकरियों की कमी थी और कई लोगों को लगता है कि रोजगार फिर से मिलने लगा है क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक होने लगी है।
- **नियोजित लोगों की संख्या में स्थिर गिरावट:** 2016 के बाद से CMIE के आंकड़ों के अनुसार, भारत में नियोजित लोगों की कुल संख्या में लगातार कमी आ रही है। 2016-17 में यह 407.3 मिलियन था और फिर 2017-18 में गिरकर 405.9 मिलियन और 2018-19 के अंत में 400.9 मिलियन हो गया।
- **बेरोजगारी का समाज पर बड़ा प्रभाव है:** प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति एक बड़े परिवार का हिस्सा है ऐसे में रोजगार के अवसरों की कमी (लाखों परिवारों को) प्रभावित करता है।

- **गिरती श्रम शक्ति भागीदारी दर:** भले ही लोग कुशल हों, फिर भी विभिन्न कारणों से श्रम बाजार में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कानून और व्यवस्था खराब है या सांस्कृतिक मंडली महिलाओं को काम मांगने से रोक सकती है। इसके अलावा, बार-बार असफल प्रयासों के बाद पुरुष काम की तलाश छोड़ देते हैं। परिणामस्वरूप, भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) गिर जाती है। भारत की LFPR लगभग 40% है (अधिकांश विकसित देशों में यह 60% है)
- **रोजगार विहीन विकास:** आमतौर पर, तेजी से आर्थिक विकास बेरोजगारी चिंताओं का ख्याल रखता है। हालाँकि, विकृत आर्थिक संरचना (सेवा में वृद्धि) के कारण भारत के विकास का नौकरियों में अनुवाद नहीं हुआ है। आवश्यक था श्रम गहन विनिर्माण नेतृत्व विकास की जो लाखों लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है।
- **तकनीकी प्रगति और बेरोजगारी:** जीडीपी जारी रह सकती है क्योंकि अधिक से अधिक कंपनियां पूंजी (मशीनरी) के साथ श्रम को प्रतिस्थापित करके अधिक उत्पादक बन जाती हैं, लेकिन यह केवल भारत की बेरोजगारी की समस्या को गहरा करेगी।
- **रोजगार सृजन में सरकार की भूमिका की आलोचना:** 2021-22 के केंद्रीय बजट में "न्यूनतम सरकार" का मंत्र नई नौकरियां पैदा करने में सरकार की भूमिका को अनिवार्य रूप से रेखांकित करता है। कागज पर यह समझ में आता है, समय संदिग्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है और निजी क्षेत्र ने पहले ही नौकरियों में कटौती और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

निष्कर्ष

आमतौर पर, तेज आर्थिक विकास बेरोजगारी की चिंताओं का ख्याल रखता है। हालाँकि, भारत के मामले में, कोई ऐसा नहीं मान सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ऐतिहासिक मंदी: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मंदी: यहाँ क्लिक करें
- बैंकिंग स्वास्थ्य: एनपीए और सीओवीआईडी -19: यहां क्लिक करें

नेतृत्व पहल के लिए डच भारतीय जल गठबंधन (DIWALI)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - जल प्रबंधन

समाचार में-

- भारत और नीदरलैंड के बीच हाल ही में डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव (DIWALI) की स्थापना की गई
- **उद्देश्य:** पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान खोजना

महत्वपूर्ण तथ्य

- दोनों काउंटियों के विशेषज्ञ भारत में विशिष्ट जल-चुनौतीपूर्ण साइटों से संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए डच सॉल्यूशंस की क्षमता और स्थिरता का उपयोग करेंगे।
- स्केलेबल, टिकाऊ और किफायती समाधानों को महत्व दिया जाएगा।
- **नेतृत्वकर्ता:** डच कंसोर्टिया शीर्षक "परिवर्तन के लिए पानी। एकीकृत और फिट-फॉर-पर्पस वाटर सेंसिटिव डिज़ाइन फ्रेमवर्क फॉर फास्ट-ग्रोइंग लिवेबल सिटीज " तथा IIT रुड़की प्रमुख और अन्य कंसोर्टिया सदस्यों के रूप में - MANIT, भोपाल; सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद; IIT गांधीनगर; CWRDM, कालीकट।

लुप्तप्राय भाषाएँ

- दुनिया में 7,000 जीवित भाषाएँ हैं उनमें से लगभग 3,000 को 'लुप्तप्राय' माना जाता है। इसका मतलब है कि विश्व की वर्तमान भाषाई विविधता का लगभग आधा हिस्सा खतरे में है।
- भारत में स्थिति चिंताजनक है। कुछ लगभग 197 भाषाएँ देश में खतरे के विभिन्न चरणों में हैं, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है।
- भारत में 1961 से अब तक लगभग 220 भाषाएं समापत हो चुकी हैं। 1961 तक लगभग 1700 भाषाएं बोली जाती थी, जो 1,652 लोगों की मातृभाषा की जनगणना पर आधारित है। अगले 50 वर्षों में अन्य 150 भाषाएँ लुप्त हो सकती हैं।

जब कोई भाषा ख़त्म जाती है तो क्या होता है?

- जब एक भाषा में गिरावट आती है, तो वह ज्ञान प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। भाषा के समाप्त हो जाने से संस्कृति में हर चीज का नुकसान के साथ साथ एकजुटता का नुकसान होता है।
- जब कोई भाषा मर जाती है, तो उसके वक्ता माइग्रेट करने का निर्णय लेते हैं। सबसे पहले, वे दूसरी भाषा की ओर चले जाते हैं और फिर वे शारीरिक रूप से दूसरे क्षेत्र में पलायन करना शुरू कर देते हैं।
- दूसरी बात यह है कि उनके पारंपरिक आजीविका पैटर्न में गिरावट आती है। उनके पास कुछ विशेष कौशल हो सकते हैं, जो समाप्त हो जाता है।
- तीसरा, दुनिया को देखने का एक अनूठा तरीका ख़त्म हो जाता है। उल्लेखनीय है कि हर भाषा एक अद्वितीय विश्वदृष्टि है।

मातृभाषा आधारित बहु-भाषी शिक्षा (MTBMLE)

- भाषाई विशेषज्ञों का दावा है कि यह जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- मातृभाषा को नजरअंदाज करना- आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआती बचपन में हस्तक्षेप बचपन की सीखने की प्रक्रिया को संभावित रूप से बाधित कर सकता है।

आगे की राह

- भाषाई विशेषज्ञों का सुझाव है कि आदिवासी भाषाओं को अभिनव, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन किया जाना चाहिए।
- आदिवासी बहुल जिलों में संचार और शिक्षा के माध्यम के रूप में आदिवासी भाषाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह संचार अंतराल और स्कूल छोड़ने की दर को काफी कम कर सकता है।
- स्कूलों के पाठ्यक्रम में आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।
- जनजातीय भाषाएँ उस दुनिया को समझने के लिए मौलिक हैं, जिसमें हम रहते हैं, हम हमारी उत्पत्ति, जड़ें जहाँ से हम सभी आए हैं आदि को समझने में सक्षम बनाएगा।

- हमें भाषा के बोलने वालों के लिए आजीविका समर्थन बनाने की आवश्यकता है। यदि उनकी आजीविका उनकी भाषा के भीतर उपलब्ध है, तो कोई भी अपनी भाषा से किसी अन्य भाषा में स्विच नहीं करना चाहेगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- गैर-अनुसूचित भाषाओं की चुनौतियां
- युएलु उद्घोषणा

समलैंगिक विवाह

संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय समान सेक्स करने वाले जोड़ों द्वारा तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो यह घोषणा करने की मांग कर रहे थे कि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) और विदेशी विवाह अधिनियम (एफएमए) को सभी जोड़ों को अपनी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना आवेदन कर सके।

HC में याचिका के संबंध में सरकार द्वारा केंद्र / रुख का विरोध

- **भारतीय परिवार की अवधारणा के अनुकूल नहीं:** समान लिंग के व्यक्तियों को साथ साथ रहना और यौन संबंध बनाना एक पति, एक पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है।
- **संहिताबद्ध नहीं:** समान लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह "न तो मान्यता प्राप्त है और न ही किसी भी अवांछित व्यक्तिगत कानून या किसी संहिताबद्ध वैधानिक कानून में स्वीकृत है"।
- **व्यक्तिगत कानूनों के साथ मुद्दा:** मौजूदा विवाह कानूनों के साथ कोई भी हस्तक्षेप देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन के कारण पूरा होगा। यह ईसाई या मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्तियों के विवाह को नियंत्रित करने वाले कानूनों के साथ आगे की विसंगतियों को जन्म दे सकता है।
- समान-लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह के पंजीकरण से मौजूदा व्यक्तिगत के साथ-साथ संहिताबद्ध कानून प्रावधानों का उल्लंघन भी होता है - जैसे कि 'निषिद्ध संबंध की डिग्री'; शादी की शर्तें '; व्यक्तियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के तहत 'औपचारिक और अनुष्ठान संबंधी आवश्यकताएं'।
- **समान विवाह के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं:** नवतेज सिंह जौहर मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय "समान लिंग के दो व्यक्तियों द्वारा विवाह करने को अधिकार में मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए निजता के अधिकार का विस्तार नहीं करता है"।
- **विधायी चुनौतियाँ:** पति को एक जैविक पुरुष के रूप में और' पत्नी 'को एक जैविक महिला मानने के अलावा कोई भी अन्य व्याख्या सभी वैधानिक प्रावधानों को समाप्त कर देगी। समान ही लिंग के लोगो के मध्य विवाह में, विभिन्न विधानों की विधायी योजना के संदर्भ में एक को 'पति' के रूप में और दूसरे को 'पत्नी' की संज्ञा देना संभव नहीं है।
- **विधानमंडल का डोमेन:** "सामाजिक नैतिकता" के विचार एक कानून की वैधता पर विचार करने में प्रासंगिक हैं और यह भारतीय नैतिकता के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति को लागू करने के लिए विधानमंडल को आगे आना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नवतेज सिंह जौहर का मामला
- के एस पुट्टस्वामी निर्णय
- NALSAR केस

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

नई रोशनी: अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - सोसायटी और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- "नई रोशनी", अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है।
- मंत्रालय: अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों जैसे बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मविश्वास पैदा करना।
- इसमें प्रशिक्षु महिलाओं का सशक्तीकरण शामिल है ताकि वे समाज के स्वतंत्र और आश्वस्त सदस्य बन सकें।
- योजना छह दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदान करती है और उसके बाद एक वर्ष के लिए हैंडहोल्डिंग करती है।
- प्रशिक्षण में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल, सामाजिक, व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक है।
- इस योजना को नई रोशनी योजना के तहत नामांकित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

क्या आप जानते हो?

- सीखो और कमाओ योजना में कुल लाभार्थियों में से 33% महिलाएं हैं।
- इसी तरह नई मंज़िल योजना में कुल लाभार्थियों में से 30% महिलाएँ हैं।
- ये योजनाएँ अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में मदद करती हैं

"कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदीकरण और यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) पर कौशल प्रशिक्षण" का शुभारंभ किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - I - समाज / महिलाएं

समाचार में-

- "कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) पर कौशल प्रशिक्षण" हाल ही में शुरू किया गया।
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** प्रबंधन और उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद (MEPSC)
- यह छह महीने की परियोजना है।
- यह 1800 प्रशिक्षुओं और 240 प्रशिक्षण पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों के 15 जिलों में लागू किया जाएगा।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: प्रिया रमणी का अधिग्रहण

इस मुद्दे की संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

- अक्टूबर 2018 में, पत्रकार प्रिया रमानी ने 1993 में भाजपा नेता और मंत्री एम. जे. अकबर द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की, जिन दिनों वह एशियन एज के संपादक थे।

- इसके बाद, लगभग 20 अन्य महिलाओं ने भी अकबर के हाथों यौन उत्पीड़न को साझा किया और उसके द्वारा किए गए दावे का समर्थन किया।
- प्रिया रमानी के आरोपों के बाद, एमजे अकबर ने दिल्ली कोर्ट में उनके खिलाफ सभी आरोपों से इनकार करते हुए आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की। दबाव में, एमजे अकबर ने 2018 में इस्तीफा दे दिया।
- फरवरी 2021 में, अदालत ने रमानी द्वारा प्रस्तुत बचाव को स्वीकार कर लिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि के आरोप से बरी कर दिया।
- न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त ने सार्वजनिक हित में सत्य की बात की थी 'जो कि धारा 499, आईपीसी के तहत आपराधिक मानहानि का एक अपवाद है।

मुद्दे

- **अविश्वास और नौकरी छूटने का डर:** यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं पर अकसर अविश्वास नहीं किया जाता है। एक अपराधी के रूप में अपने मालिक को अपराधी कहने का मतलब है नौकरी और वेतन का तत्काल नुकसान।
- **संस्थागत विफलता:** यौन उत्पीड़न अकेले व्यक्तियों के बजाय संस्थानों की समस्या है। संस्थागत तंत्र महिलाओं की सुरक्षा या न्याय प्रदान करने में व्यवस्थित रूप से विफल रहे हैं।
- **पितृसत्ता का उपकरण:** दुनिया भर में, नियोक्ता महिला श्रमिकों को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में यौन उत्पीड़न को तैनात करते हैं।
- **गरीब कार्यान्वयन:** कारखाने के श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों, सब्जी विक्रेताओं, स्वच्छता और अपशिष्ट श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, यौन श्रमिकों, श्रम कानूनों या यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून केवल कागज पर मौजूद हैं।
- **असफलता का कारण:** बोलने वाली महिलाएं एकमत थीं कि व्यक्तिगत शिकायतें एक विकल्प नहीं थीं: उन्हें सामूहिक रूप से लड़ने के लिए यूनियनों की आवश्यकता थी। केंद्र सरकार द्वारा पारित श्रम संहिताएं श्रमिकों को संघ बनाने से रोकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- **बोलने के अधिकार में समय की कमी नहीं है:** फैसले ने समाज से "यह समझने का आग्रह किया कि कभी-कभी पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात के कारण वर्षों तक नहीं बोल सकता है" यहाँ तक की दशकों बाद भी।
- **निजी मामला और साक्ष्य जारी करना:** चूंकि यौन उत्पीड़न आम तौर पर निजी तौर पर होता है, इसलिए महिलाओं की गवाही को असत्य या मानहानि के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अपने आरोपों को अन्य गवाहों को देने में असमर्थ हैं।
- **सोशल मीडिया:** उत्तरजीवी को आत्म-रक्षा के रूप में मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी प्रशंसा साझा करने में न्यायोचित ठहराया जाता है।
- **मौलिक अधिकारों के विरुद्ध:** यौन दुर्व्यवहार गरिमा (अनुच्छेद 21) और समानता (14 और 15 के अनुच्छेद) के लिए संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करता है, और यह कि (एक पुरुष का) प्रतिष्ठा का अधिकार (महिला के) सम्मान की कीमत पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है ।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013।
- आंध्र प्रदेश का दिशा अधिनियम: यहां क्लिक करें
- आपको नहीं लगता कि यौन हिंसा के कार्य बचे लोगों के लिए गहरे आघात हैं, और यह कि उन्हें रिपोर्ट करने के लिए सिस्टम में बहुत साहस और विश्वास है?

स्वास्थ समस्या

2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पोलियो की बूँद राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर थीं, जिसे हर वर्ष 31 जनवरी 2021 को मनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से पोलियो रविवर के रूप में जाना जाता है।
- 5 साल से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को देश की पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे।
- पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की रणनीति की परिकल्पना दिसंबर 1993 में की गई थी और इसे 2 अक्टूबर 1994 से लागू किया गया था जब इस कार्यक्रम के तहत पोलियो के खिलाफ पहले बच्चे का टीकाकरण किया गया था।
- भारत में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में दर्ज किया गया था।
- भारत एक दशक से पोलियो से मुक्त है।

क्या आप जानते हो?

- 27 मार्च 2014 को भारत सहित WHO द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो-मुक्त प्रमाणीकरण भारत और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी।

संबंधित आलेख:

- पोलियो रोग: यहां क्लिक करें
- अन्य बीमारियों के लिए पोलियो की सफलता की जाँच: यहाँ क्लिक करें

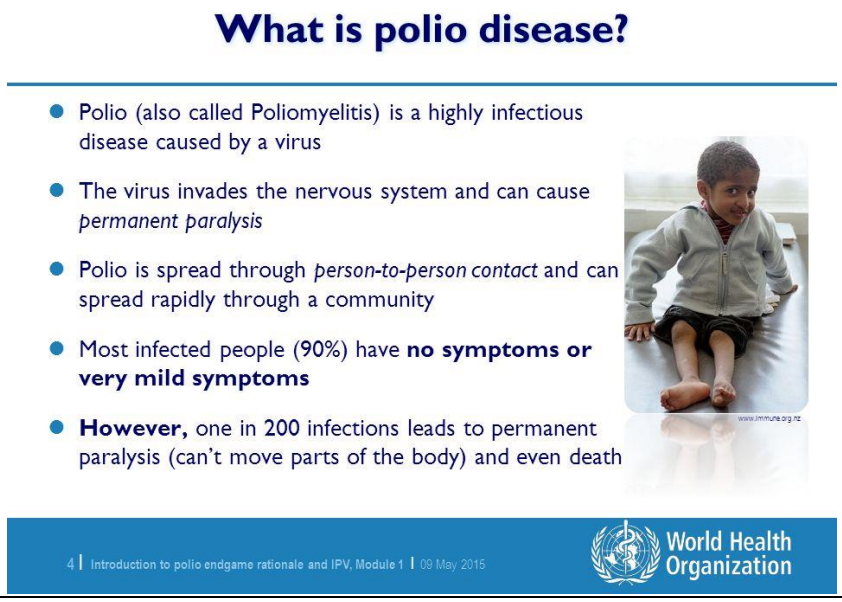

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की प्रमुख बातें स्वास्थ्य परिणामों पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के मजबूत सकारात्मक प्रभाव को प्रकट करती है।

सर्वेक्षण द्वारा अवलोकन

- स्वास्थ्य बीमा या वित्तपोषण योजना के तहत कवर किए गए किसी भी सामान्य सदस्य वाले परिवारों का अनुपात पीएमजय को अपनाने वाले राज्यों में NFHS 4 से NFHS 5 तक 54% की वृद्धि हुई।
- यह उन राज्यों में 10% कम हो गया जिन्होंने पीएमजेएवाई को नहीं अपनाया।
- अनुपात स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने में PMJAY की सफलता को दर्शाता है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी क्रमशः PMJAY और गैर-PMJAY राज्यों में 12% की तुलना में 20% थी।
- दो सर्वेक्षणों के बीच सभी राज्यों में परिवार नियोजन सुनिश्चित करने वाले लोगों का अनुपात बढ़ा।
- वृद्धि उन राज्यों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिन्होंने पीएम-जेएवाई को अपनाया है जो इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- PMJAY राज्यों में कुल बिना परिवार नियोजन की जरूरत वाली महिलाओं के अनुपात में 31% की कमी आई है।
- गैर-पीएमजेएवाई राज्यों में गिरावट केवल 10% थी।

संबंधित आलेख:

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: यहां क्लिक करें

औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं पर शोध

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB), आयुष मंत्रालय, केंद्रीय औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय योजना के तहत सरकारी और साथ ही निजी विश्वविद्यालयों को औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) में किए गए शोध में 24 नई दवाओं का विकास किया गया है।
- इसके अलावा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने CSIR-CIMAP, CSIR-NBRI और CSIR-CDRI में अपने समर्थित शोधों के माध्यम से औषधि फार्मूला विकसित किए हैं।
- प्रौद्योगिकी को इसके व्यावसायीकरण के लिए उद्योग में स्थानांतरित किया गया है।
- आईसीएआर- डीएमएपीआर अनुसंधान और संयंत्र आनुवंशिक संसाधनों / गुणवत्ता रोपण सामग्री पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- ऐसी संस्थाएँ जो नई दवाएँ विकसित करने में लगी हुई हैं, ऐसे गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का लाभ उठा सकती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना, (IC योजना) के तहत आयुष मंत्रालय, दुनिया भर में आयुर्वेद सहित चिकित्सा के आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है।
- इसके अलावा, CCRAS, ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद / आयुर्वेदिक दवाओं के प्रचार के लिए विभिन्न समझौतों / MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड (NMPB)

- यह भारत सरकार द्वारा व्यापार, निर्यात, संरक्षण और खेती के विकास के लिए औषधीय पौधों और समर्थन नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- बोर्ड आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के तहत काम कर रहा है।

संबंधित आलेख:

- औषधीय पौधों के लिए NMPB कंसोर्टिया: यहां क्लिक करें

इंडिया पोस्ट और टाटा मेमोरियल सेंटर ने विश्व कैंसर दिवस पर एक विशेष कवर जारी किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- इंडिया पोस्ट, मुंबई क्षेत्र, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के सहयोग से, विश्व कैंसर दिवस (4 फरवरी) पर एक विशेष कवर जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

विश्व कैंसर दिवस

- **उद्देश्य:** जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से और कैंसर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारों पर दबाव डालकर हर साल लाखों रोके जा सकने वाली मौतों को बचाना।
- **द्वारा आयोजित:** यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (यूआईसीसी), एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ जो वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को कैंसर से लड़ने में तेजी लाने में मदद करने के लिए मौजूद है।
- NGO की स्थापना 1933 में हुई थी और यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- **विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत:** पेरिस चार्टर ने 2000 में पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में अपनाया।
- **थीम:** 2019 में, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ने (आई एम और आई विल) थीम के साथ एक नया 3 साल का अभियान शुरू किया।
- अभियान व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए एक सशक्त कॉल-टू-एक्शन आग्रह है और भविष्य को प्रभावित करने के लिए अब तक की गई व्यक्तिगत कार्रवाई की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

एफएसएसएआई ट्रांस-फैटी एसिड (टीएफए) की समस्या के समाधान के लिए अपने नियमों में संशोधन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य उत्पादों में ट्रांस-फैटी एसिड (टीएफए) को कैप करने के अपने नियमों में संशोधन किया है, (तेल और वसा के मानदंडों में सुधार के कुछ ही हफ्तों बाद)

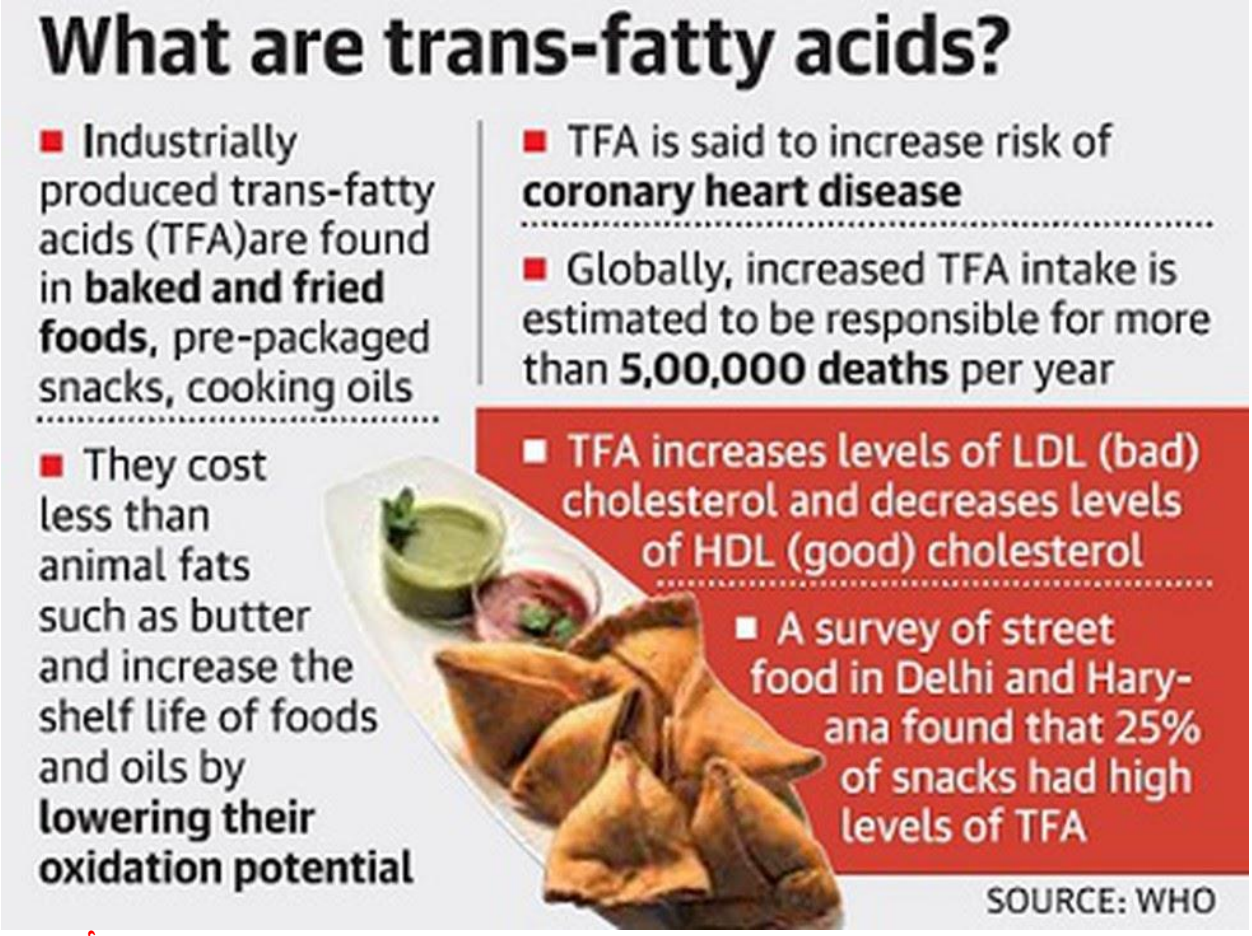

महत्वपूर्ण तथ्य

- खाद्य उत्पाद जिसमें खाद्य तेलों और वसा का उपयोग एक घटक के रूप में किया जाता है, उसमें 1 जनवरी 2022 से और इस उत्पाद में मौजूद कुल तेलों / वसा के द्रव्यमान से 2% से अधिक औद्योगिक ट्रांस-फैटी एसिड नहीं होंगे।
- 2% कैप को ट्रांस-फैटी एसिड का उन्मूलन माना जाता है, जिसे भारत 2022 तक हासिल करेगा।
- दिसंबर 2020 में, FSSAI ने तेल और वसा में TFAs को 2021 तक 3% और 2022 तक 2% को 5% के वर्तमान स्तर से कम किया कम जायेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ट्रांस-फैटी एसिड एक औद्योगिक प्रक्रिया में बनाया जाता है जो उन्हें अधिक ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजन को तरल वनस्पति तेलों में मिलाया जाता है, खाद्य पदार्थों के जीवन को बढ़ाता है, और एक मिलावट के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि वे सस्ते हैं।
- वे पके हुए, तला हुआ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और मिलावटी घी में मौजूद होते हैं, जो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाते हैं।
- वे वसा का सबसे हानिकारक रूप हैं क्योंकि वे धमनियों को रोकते हैं और उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे और अन्य हृदय रोगों का कारण बनते हैं।
- WHO ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस-फैटी एसिड के उन्मूलन का आह्वान किया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- केंद्र सरकार आयुर्वेदिक प्रणाली सहित आयुष प्रणाली के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मिशन इंटर-एलिया आयुर्वेदिक प्रणाली सहित आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है-
  1. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थान।
  2. अनन्य राज्य सरकार आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन।
  3. 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना।
  4. राज्य सरकार के स्नातक और स्नातकोत्तर शैक्षिक संस्थानों का उन्नयन।
  5. जिन राज्यों में यह सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, वहां नए राज्य सरकार आयुष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना।
  6. आयुष प्रणालियों में गुणवत्तापूर्ण दवाओं के विनिर्माण के लिए राज्य सरकार / राज्य सरकार के सहकारी समितियों / सार्वजनिक उपक्रमों का सुदृढ़ीकरण।
  7. राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण
  8. आयुष चिकित्सा और अन्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण और कटाई के बाद के प्रबंधन सहित औषधीय पौधे की खेती के लिए समर्थन।

विश्व यूनानी दिवस

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- 11 फरवरी, 2021 को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया।
- **उद्देश्य:** अपने निवारक और उपचारात्मक दर्शन के के कारण से यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल वितरण के बारे में जागरूकता फैलाना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हर साल विश्व यूनानी दिवस हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
- **यूनानी प्रणाली के सिद्धांत:** यह शरीर में चार तथ्यों की उपस्थिति को दर्शाता है: रक्त, बलगम (कफ), सफारी (पीला पित्त) और सौडा (काला पित्त)।
- चार तथ्यों की गुणवत्ता और मात्रा शरीर में स्वास्थ्य और रोग की स्थिति को प्रभावित करती है।
- **उत्पत्ति:** ग्रीस।
- भारत में, यह 11 वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों द्वारा लाया गया था।

मलेरिया वाहक के विस्तृत जीनोम मानचित्र का अनावरण किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य और जीएस - III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- वैज्ञानिकों ने मलेरिया मच्छर वाहक के विस्तृत जीन का अनावरण किया है।
- रोग संचरण की आनुवंशिक नियंत्रण रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हजारों नए जीन सामने आए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मलेरिया संचरण के खिलाफ रक्षा के उन्नत रूपों के लिए इंजीनियर, वैज्ञानिकों को वेक्टर मच्छरों के जीनोम के जटिल ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- CRISPR तकनीक एक जीन-संपादन उपकरण है जो शोधकर्ताओं को डीएनए अनुक्रमों को आसानी से बदलने और जीन फ़ंक्शन को संशोधित करने की अनुमति देता है।
- उन्होंने एशियाई मलेरिया वाहक मच्छर एनोफ़ेलीज़ स्टेफेन्सी के लिए एक नया जीनोम का उत्पादन किया।
- नए उन्नत एनोफ़ेलीज़ स्टेफ़ेनसी जीनोम के साथ, टीम ने 3,000 से अधिक जीनों का पता लगाया।
- ये जीन रक्त-भक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और माइक्रोबियल परजीवियों के खिलाफ रक्त के भोजन, प्रजनन और प्रतिरक्षा के चयापचय में भूमिका निभाते हैं।

क्या आप जानते हो?

- भारत में मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक है।

संबंधित आलेख:

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 जारी: यहां क्लिक करें
- प्लास्मोडियम ओवले: असामान्य प्रकार का मलेरिया: यहां क्लिक करें

टीबी नियंत्रण के लिए कोविड-19 से सबक

संदर्भ: डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि भारत में 10 मिलियन से अधिक सक्रिय टीबी के मामले हैं। देश में टीबी के कारण हर साल 4,00,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है (COVID-19 महामारी के कारण एक वर्ष की अवधि में 1,54,000 मौतें हुईं)।

तपेदिक निम्नलिखित कारणों से एक सामाजिक बीमारी है

- अधिक भीड़ और कुपोषण के कारण, यह गरीबों और हाशिए पर स्थित लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- इस बीमारी से जुड़े और मिथक के चलते ये सूचीबद्ध नहीं होते और न ही इनका कोई परीक्षण ही हो पाता है।
- लंबे समय तक दवा का उपयोग करने से दवा-प्रतिरोध होता है, जो इसके उन्मूलन में में बाधा उत्पन्न करता है।
- मधुमेह के साथ पहले से मौजूद बीमारी या एचआईवी के साथ सह-संक्रमण से जटिलताएं बढ़ जाती हैं।
- अंत में, रोग की पुरानी प्रकृति और कई अंगों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
- COVID-19 लड़ाई के दौरान मिली सीख से टीबी को नियंत्रित करने में बहुत कुछ कर सकते हैं अर्थात् समुदाय संचालित प्रयास 2025 तक सरकार को टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य में मदद कर सकते हैं
- चूंकि टीबी संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से फैलता है, शारीरिक दूरी बीमारी के संचरण को कम कर सकती है।
- टीबी के मरीजों को संक्रमण फैलने से बचाने के लिए मास्क पहनना चाहिए, और रोगी के नियमित संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को आत्म-सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए।
- शुरुआती निदान और उपचार सफलता की कुंजी हैं। पारंपरिक बलगम परीक्षण की तुलना में नए नैदानिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जो तेजी से और अल्ट्रासेकसीज़ परिणाम देता है।
- अंत में, तत्काल केस अधिसूचना बेहतर केस ट्रैकिंग और संपर्क निगरानी में मदद करती है।
- COVID-19 के खिलाफ लड़ाई से श्वसन संक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ी है, जो टीबी से जुड़े मिथक को दूर करने में मदद कर सकता है।

- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और नए मीडिया अभियानों के कारण कोरोनोवायरस को रोकने के भारत के प्रयास सफल रहे जिन्हें टीबी के लिए दोहराया जा सकता है

निष्कर्ष

एक सफल समुदाय संचालित रणनीति, जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान या COVID-19 नियंत्रण के दौरान देखा गया है, यदि मौजूदा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के साथ भी ऐसा ही किया जाये, (जो नि: शुल्क निदान और उपचार प्रदान करता है) तो टीबी उन्मूलन में तेजी आ सकती है।

गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग (NAFLD)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - स्वास्थ्य

समाचार में-

- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गैर-अल्कोहल फैटी रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है।

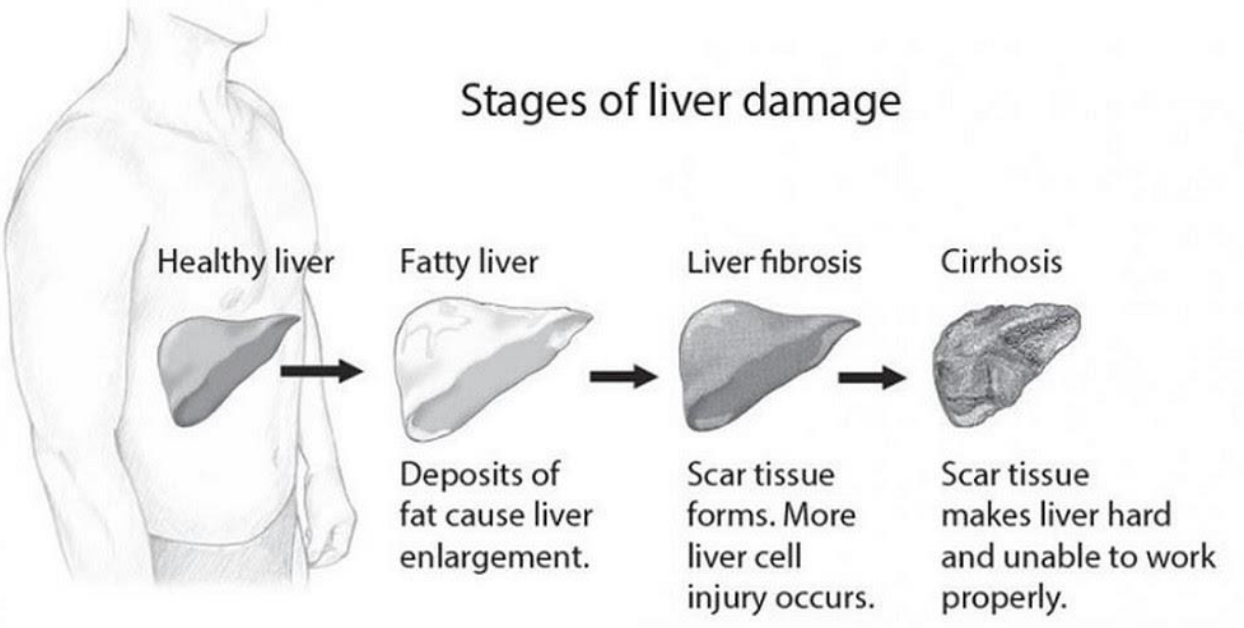

महत्वपूर्ण तथ्य

- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ NAFLD के एकीकरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश शुरू किए गए हैं।
- NAFLD यकृत की एक शब्द है जो ऐसे लोगों को प्रभावित करता है जो शराब नहीं पीते हैं।
- NAFLD की मुख्य विशेषता यकृत कोशिकाओं में बहुत अधिक वसा संग्रहित करना है।
- यह दुनिया भर में तेजी से आम होता जा रहा है, खासकर पश्चिमी देशों में।
- NAFLD वाले कुछ व्यक्ति गैर-अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH) विकसित कर सकते हैं।
- NASH फैटी लीवर की बीमारी का एक आक्रामक रूप है, जो लिवर की सूजन द्वारा चिह्नित है जो उन्नत स्कारिंग (सिरोसिस) और यकृत की विफलता का कारण बन सकता है।

संबंधित आलेख:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020
- स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति

सरकारी योजनाएँ

ONORC योजना का कार्यान्वयन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना को लागू कर रहा है। (एनएफएसए)।
- अब तक, यह सुविधा 32 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की गई है तथा यह लगभग 86% आबादी को कवर करने में सक्षम है।

महत्वपूर्ण तथ्य

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना

ओएनओआरसी के तहत, लाभार्थी किसी भी ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस) सक्षम फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) से ले सकते हैं, ईपीओएस डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा / मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके। पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उठा सकते है।

- ONORC के तहत लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
- हालांकि, ONORC संचालन के तहत एकरूपता के लिए, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को राशन कार्ड के लिए एक मानक द्वि-भाषी प्रारूप अपनाने की सलाह दी गई है, जब भी वे भविष्य में NFSA के तहत नए राशन कार्ड जारी / प्रिंट करने का निर्णय लेते हैं।
- एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत संचालित है।
- **राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी:** एनएफएसए के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, नामित डिपो से खाद्यान्न का उठाव, राशन कार्डधारियों को एफपीएस के माध्यम से उनके हक के अनुसार वितरण आदि।
- एनएफएसए की धारा-38 के तहत सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को एनएफएसए के तहत सभी पात्र विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

एनएफएसए की मुख्य विशेषताएं

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों द्वारा शासित है।
- पीडीएस के तहत कवरेज पूर्ववर्ती 'गरीबी अनुमान' से अलग है।
- यह अधिनियम देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2 / 3rd कवरेज प्रदान करता है, जिसका आधार जनगणना 2011 जनसंख्या अनुमान है।
- 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी लाभार्थियों की दो श्रेणियों - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता घरों (PHH) के तहत अत्यधिक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है।
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार कवरेज पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब एनआईटीआई अयोग) द्वारा 2011-12 के एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- यह अधिनियम प्रति माह AAY घरेलू में 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हक देता है, जबकि 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति PHH व्यक्ति प्रति माह।
- एनएफएसए के तहत लाभार्थियों / परिवारों की पहचान संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, जिसे अपने स्वयं के मानदंड की आवश्यकता होती है।
- जून, 2019 तक केंद्रीय अनाज के मूल्य, क्रमशः 2 रुपये और मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए रियायती मूल्य जारी किए गए।
- एनएफएसए के तहत किसी भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को खाद्यान्न आवंटन में कोई कमी नहीं। आवंटन अंतराल यदि कोई हो, तो टाइड-ओवर आवंटन के साथ कवर किया जाता है

- लाभार्थी घर की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार के मुखिया के रूप में माना जाता है।
- महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता के लिए पीडीएस परिचालनों से संबंधित अभिलेखों के प्रकटीकरण के प्रावधान
- इंट्रा-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च और खाद्यान्नों और एफपीएस डीलर्स के मार्जिन को संभालने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता

संबंधित आलेख:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में विकलांगों का समावेश: यहां क्लिक करें

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्री एस.एन. सुब्रह्मण्यन (सीईओ और प्रबंध निदेशक, एल एंड टी लिमिटेड) को तीन साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर-लाभकारी, स्व-वित्तपोषण सर्वोच्च निकाय है।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) पर एक स्वैच्छिक आंदोलन उत्पन्न करना, विकसित करना और बनाए रखना।
- यह एक स्वायत्त निकाय है।
- **1965 में श्रम और रोजगार मंत्रालय:** द्वारा स्थापित।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और बाद में, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुआ।

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) को 16000 करोड़ रुपये आवंटित

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - कृषि और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों तक फसल बीमा का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

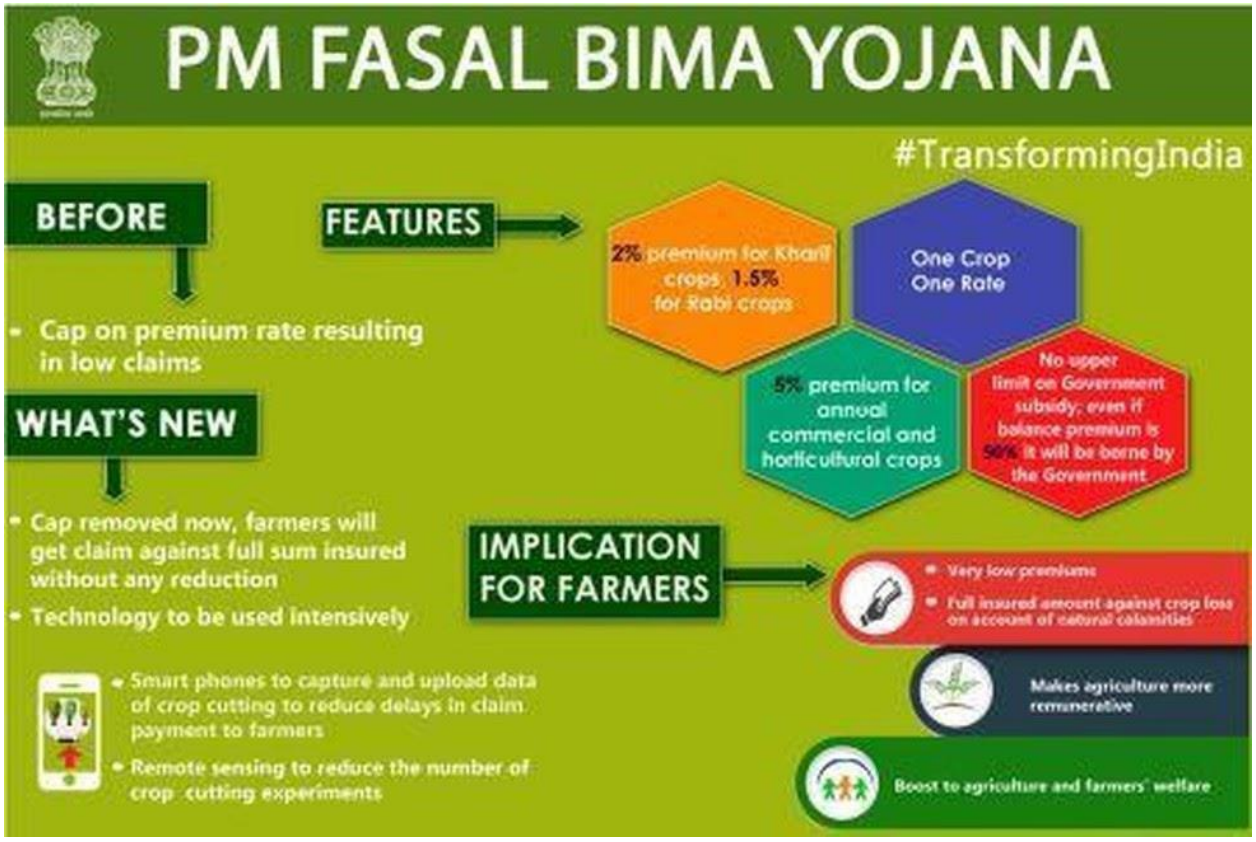

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले लगभग 305 करोड़ रुपये का बजटीय वृद्धि है।
- योजना पूर्व बुवाई चक्र से लेकर कटाई के बाद की फसल के लिए कवरेज का विस्तार करती है जिसमें रोकी गई बुवाई और मध्य मौसम प्रतिकूलताओं से होने वाले नुकसान के लिए कवरेज भी शामिल है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) 2016 में शुरू की गई थी।
- यह किसानों के लिए उनकी पैदावार के लिए एक बीमा सेवा योजना है।
- इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।
- यह पूर्व की दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) की जगह वन नेशन-वन स्कीम थीम के अनुरूप तैयार की गई थी।
- यह योजना सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों को कवर करती है, जिसके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध है और जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की अपेक्षित संख्या का संचालन किया जाता है।
- इसके द्वारा कार्यान्वित किया गया: सामान्य बीमा कंपनियाँ।
- **प्रशासित**: कृषि मंत्रालय
- अधिसूचित फसलों और अन्य के लिए स्वैच्छिक फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है।

संबंधित आलेख:

- प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सफलतापूर्वक 5 साल के संचालन को पूरा करती है: यहां क्लिक करें

प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - शिक्षा; कल्याणकारी योजनाएँ

समाचार में-

- लोकसभा को SC और OBC के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन के बारे में बताया गया।
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

योजना में शुरू किए गए महत्वपूर्ण बदलाव

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
  - फंडिंग पैटर्न - केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का निश्चित शेयरिंग पैटर्न (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 90:10) या नॉटिकल एलोकेशन जो भी कम हो।
  - वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2 लाख से 2.5 लाख रुपये से बढ़ गई।
  - रखरखाव भत्ते की दरें भी बढ़ाई गईं।
- एससी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
  - यह 2020-21 से 2025-26 तक जारी रहेगा
  - फंडिंग पैटर्न - केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का साझा अनुपात (NE राज्यों के मामले में 90:10)
- ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
  - प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 1 लाख रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष।
  - पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गई।

बाल भिक्षावृत्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - सामाजिक मुद्दे और जीएस- II - कल्याणकारी योजनाएं

समाचार में-

- लोकसभा ने हाल ही में बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित कदमों के बारे में जानकारी दी।
- **मंत्रालय:** महिला और बाल विकास मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) देश में बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है।
- अधिनियम, 2015 की धारा 2 के अनुसार, एक बच्चा जो श्रम कानूनों के उल्लंघन में काम करता पाया जाता है या भीख मांगता पाया जाता है, उसे "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में बच्चे" के रूप में शामिल किया जाता है।
- धारा 76 के अनुसार, जो कोई भी भीख मांगने के लिए किसी भी बच्चे को नियुक्त करता है, उसे पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा।
- समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत बाल संरक्षण सेवाएँ (सीपीएस) बाल भिखारियों और निराश्रित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों का समर्थन करती हैं।
- संस्थागत देखभाल बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के माध्यम से पुनर्वास उपाय के रूप में प्रदान की जाती है।
- यह योजना भारत में कहीं से भी संकट की स्थिति में बच्चों के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा (टोल फ्री नंबर, 1098) का समर्थन करती है।

- 10 शहरों में भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है।
- इसमें भीख मांगने में लगे बच्चों / भीख मांगने वाले व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा शामिल है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (MGNF) शुरू की गई

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - कौशल विकास

समाचार में-

- हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (MGNF) को शुरू किया गया था।
- **मंत्रालय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- MGNF के तहत अध्येताओं को जिला कौशल समितियों (DSCs) के साथ संलग्न होने के साथ-साथ समग्र कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में अकादमिक विशेषज्ञता और तकनीकी योग्यता प्राप्त होगी।
- यह उन्हें जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के गठन के तंत्र के माध्यम से जिला स्तर पर कौशल विकास योजना का प्रबंधन करने में मदद करेगा।
- पहला पायलट MGNF जिसमें 69 जिलों में काम करने वाले 69 फेलो सफल थे।
- मंत्रालय अब भारत के सभी शेष जिलों में MGNF का विस्तार कर रहा है।
- मंत्रालय ने केवल IIM के साथ शैक्षणिक साझेदारी की मांग की है।

पायलट पे जल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पायलट पे जल सर्वेक्षण- शहरी, जेजेएम-यू को लॉन्च किया गया था।

- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में मानचित्रण का पता लगाने के लिए शहरों में आयोजित किया जाएगा।
- इसे सबसे पहले 10 शहरों- आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चुरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में लॉन्च किया जाएगा।
- जेजेएम-यू को एसडीजी - 6 के अनुसार सभी 4,378 वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

संबंधित आलेख:

- जल जीवन मिशन: यहां क्लिक करें
- ग्राम पंचायतों और पाणी समितियों के लिए मार्गदर्षिका: यहाँ क्लिक करें

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- युवा मामले और खेल राज्य मंत्री ने लोकसभा को राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्य के बारे में जानकारी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्याक्रम (RYSK)

- योजना राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (RYSK) वर्तमान में संचालित क्षेत्र योजना है।
- वर्ष 2020-21 के लिए योजना RYSK का बजट आवंटन 486.48 करोड़ रूपये है।
- यह एक मिश्रित योजना है।

RYSK के तहत 7 उप-योजनाएं हैं

1. नेहरू युवा केंद्र संगठन।
2. राष्ट्रीय युवा वाहिनी।
3. युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. युवा छात्रावास।
6. स्काउटिंग और मार्गदर्शक संगठनों को सहायता।
7. राष्ट्रीय युवा नेताओं का कार्यक्रम।

टेक्नोग्राही के लिए नामांकन मॉड्यूल लॉन्च किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- टेक्नोग्राही के लिए एक नामांकन मॉड्यूल शुरू किया गया है।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)।

महत्वपूर्ण तथ्य

- टेक्नोग्राही IIT, NIT, इंजीनियरिंग, योजना और वास्तुकला महाविद्यालयों, संकाय सदस्यों, शिक्षाविदों और हितधारकों से छात्र हैं।
- MoHUA क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) को बढ़ावा दे रहा है।
- एलएचपी मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं।
- प्रत्येक स्थान पर लगभग 1,000 घर संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ बनाए जा रहे हैं।
- इच्छुक उम्मीदवार सीखने, परामर्श, विचारों की उत्पत्ति और समाधान, प्रयोग, नवाचार और तकनीकी जागरूकता के लिए एलएचपी साइटों में इन लाइव प्रयोगशालाओं का दौरा करने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
- उन्हें LHP के पूरा होने तक सूचना प्रसार के लिए साइटों से नियमित अपडेट भी मिलेगा।

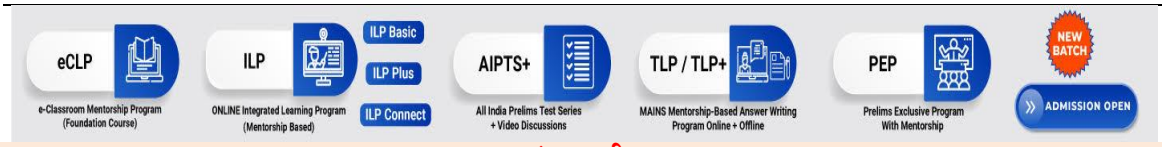

अंतरराष्ट्रीय

हांगकांग के निवासियों के लिए यूके स्पेशल वीज़ा योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- ब्रिटेन एक विशेष वीजा योजना बनाने जा रहा है, जो लाखों हांगकांग निवासियों को प्रवास करने और अंततः ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन करने का मौका देगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हांगकांग में उन लोगों को वीजा जारी किया जाएगा जो ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज) पासपोर्ट और अपने तत्काल आश्रितों को रखते हैं और ब्रिटेन की नागरिकता के लिए एक फास्ट ट्रैक की पेशकश करेंगे।
- वीज़ा धारक ब्रिटेन में 5 वर्ष तक रह और काम कर सकते हैं। जिसके बाद वे सेटलमेंट के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारह महीने बाद, वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वीज़ा धारक ब्रिटेन में 5 वर्ष तक रह और काम कर सकते हैं। वे ब्रिटेन की नागरिकता के लिये 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकते हैं।
- 2004 में नए यूरोपीय संघ के नागरिकों के प्रवेश के बाद से इस कदम को ब्रिटेन के विदेशी श्रमिकों का सबसे सरल स्वागत माना जाता है।
- यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के महीनों बाद आया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र-विरोधी विरोध प्रदर्शन है, जिसने 2019 के बाद से वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था।

संबंधित आलेख:

- हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून: यहां क्लिक करें

न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ 'न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty) परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके रूसी समकक्ष ने कथित तौर पर चर्चा की और बाद में, रूसी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कानूनी रूप दिया।
- यह रणनीतिक आक्रामक हथियारों की मात्रा में कमी करने और उन्हें सीमित करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी के बीच एक संधि है।
- यह 5 फरवरी, 2011 को लागू हुआ।
- वर्ष 1991 की स्टार्ट संधि (शीत युद्ध के अंत में) ने दोनों पक्षों (अमेरिका और रूस) को 1,600 सामरिक वितरण वाहनों और 6,000 युद्धक हथियारों तक सीमित कर दिया।
- यह दोनों पक्षों द्वारा 700 रणनीतिक लांचरों और 1,550 परिचालन युद्धक हथियारों को सीमित कर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को कम करने की द्विदलीय प्रक्रिया को जारी रखती है।

संबंधित आलेख:

- रूस ने नई स्टार्ट संधि को विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है: यहां क्लिक करें

व्यापार और निवेश पर प्रथम भारत-यूरोपीय संघ के उच्च-स्तरीय संवाद

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- हाल ही में उच्च स्तरीय संवाद (HLD), केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री और यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और व्यापार आयुक्त द्वारा सह-अध्यक्षता की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उल्लेखनीय है कि इस संवाद की नींव जुलाई, 2020 में आयोजित 15वें भारत-यूरोपीय संघ के नेता के शिखर सम्मेलन में रखी गई थी। जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के लिए एक मंत्रिस्तरीय मार्गदर्शन समिति बनाना था।
- वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 युग के बाद वैश्विक सहयोग और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सहमति व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ पुन: जुड़ने की संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुप्रचारित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ फिर से जुड़ने की योजना की घोषणा की है जो पूर्व राष्ट्रपति लगभग तीन साल पहले वापस ले लिया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है।
- **स्थान:** जिनेवा
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 2006 में हुई थी।
- इसने मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व आयोग (UNCHR) का स्थान लिया, जिसकी गरीब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों को सदस्य बनाने की अनुमति देने के लिए कड़ी आलोचना की गई थी।
- **कार्य:** (1) यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करता है; (2) यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों, एलजीबीटी अधिकारों और नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयगत मानवाधिकार मुद्दों को भी हल करता है।
- यूएनएचआरसी मानवाधिकार के उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय के साथ मिलकर काम करता है।
- **सदस्यता:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 47 सदस्य देश।
- परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है।
- परिषद के सदस्य तीन वर्षों तक सदस्य रहते हैं और लगातार दो कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं।
- भारत 1 जनवरी, 2019 से तीन साल के लिए यूएनएचआरसी के लिए चुना गया है।
- भारत पहले 2011-2014 और 2014-2017 के लिए यूएनएचआरसी के लिए चुना गया था।

नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- एक ऐसे विकास में जो यूएसए और जर्मनी के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, जो संघ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है, ने कहा है विवादास्पद परियोजना पर काम फिर से शुरू कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2015 में, गज़प्रॉम और 5 अन्य यूरोपीय ऊर्जा फर्मों ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसकी कीमत लगभग 11 बिलियन डॉलर थी।
- 1,200 किलोमीटर की पाइपलाइन रूस के उस्ट-लूगा से जर्मनी में ग्रीफ्सवाल्ड तक चलेगी।
- यह प्रति वर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ले जाएगा।
- निर्माणाधीन पाइपलाइन पहले से ही पूर्ण नॉर्ड स्ट्रीम 1 प्रणाली के साथ चलेगी, और दोनों मिलकर प्रति वर्ष जर्मनी को 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करेंगे।

पाइपलाइन विवादास्पद क्यों है?

- नॉर्ड स्ट्रीम 2 ने अमेरिका की आलोचना की है, जहाँ यह माना जाता है कि इस परियोजना से प्राकृतिक गैस के लिए रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ेगी, जिससे उसके राष्ट्रपति को बल मिलेगा।
- वर्तमान में, यूरोपीय संघ के देश अपनी गैस की 40% जरूरतों के लिए पहले से ही रूस पर निर्भर हैं।

लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच ललंदर (शतात) बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है।

- **लाभ:** (1) काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करना; (2) आस-पास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना; (3) मौजूदा सिंचाई और जल निकासी नेटवर्क का पुनर्वास करना; (4) क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता; (5) क्षेत्र को बिजली प्रदान करना।

क्या आप जानते हो?

- यह अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है, यह भारत द्वारा अफगानिस्तान मैत्री बांध (सलमा बांध), जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने जून 2016 में किया था।

फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अधिकार पर आईसीसी का फैसला

प्रसंग: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने कहा कि अदालत का फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में किए गए युद्ध अपराधों पर अधिकार है, एक ऐसा निर्णय जिसका फिलीस्तीनियों ने स्वागत किया और इस्राइल की आलोचना की।

आईसीसी के बारे में

- द रोम संविधि ', 2002 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित आईसीसी विश्व का पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है।
- इसकी स्थापना विभिन्न अपराधों के खिलाफ अभियोजन के लिए अंतिम उपाय के रूप में की गई थी इसका क्षेत्राधिकार नरसंघार मान्यवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध तथा अतिक्रमण का अधिकार शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से, ICC का उद्देश्य अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ना और इन अपराधों को फिर से होने से रोकने में मदद करना है।
- आईसीसी को पूरक करने का इरादा है, राष्ट्रीय आपराधिक प्रणालियों को बदलने के लिए नहीं; यह केवल उन मामलों पर मुकदमा करता है जब राज्य अनिच्छुक नहीं होते हैं या वास्तव में ऐसा करने में असमर्थ होते हैं।
- आईसीसी एक संयुक्त राष्ट्र संगठन नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सहयोग समझौता है।
- जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आईसीसी को यह अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली स्थिति का उल्लेख कर सकती है। यह दारफुर (सूडान) और लीबिया में स्थितियों में किया गया है।
- भारत अमेरिका और चीन के साथ रोम संविधि का पक्षकार नहीं है।

वर्तमान निर्णय क्या है?

- यह निर्णय वास्तव में 2015 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत की औपचारिक सदस्यता हासिल करने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण का एक परिणाम था। इजरायल आईसीसी का सदस्य नहीं है।
- इस नियम के अनुसार, फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संभावित युद्ध अपराधों की जांच के लिए आईसीसी का अधिकार क्षेत्र होगा।
- फिलिस्तीन के मामलें में न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों तक है, जो 1967 से पूर्वी गाजा सहित पूर्वी जेरुसलम तक हैं।
- न्यायाधीशों ने हालांकि कहा कि अधिकार क्षेत्र "फिलिस्तीनी राज्य का निर्धारण करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है, जो अनिश्चित या राष्ट्रीय सीमा है।"

शासन का जवाब

- **इज़राइल:** इसने यह कहते हुए इसकी निंदा की कि आईसीसी "नकली युद्ध अपराधों" के लिए इज़राइल की जांच कर रहा था, इसे "शुद्ध विरोधी-विरोधीवाद" कहा।
- **US:** इसने ICC के फैसले पर भी आपत्ति जताई

- फिलिस्तीन: फिलिस्तीन ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह एक "ऐतिहासिक दिन" है क्योंकि इस्राइल को पहले कानून से ऊपर माना गया था। "

सत्तारूढ़ का महत्व

- यह न्याय और जवाबदेही की तलाश में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी यरुशलम और गाजा सहित वेस्ट बैंक पर 53 वर्षों के कब्जे को उजागर करता हैं।
- सत्तारूढ़ हमास सहित इज़राइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों की आपराधिक जांच कर सकता है।

भारत का रुख क्या है?

- इज़राइल भारत को आईसीसी के फैसले के खिलाफ एक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन दिल्ली अपने स्वयं के भू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक राज्यों का विरोध नहीं करना चाहता।
- भारत ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से इजरायल को अवगत कराया है कि चूंकि भारत रोम संविधि का सदस्य नहीं है, इसलिए वह अदालत के किसी भी फैसले या फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगा।

व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत-मॉरीशस CECPA भारत द्वारा किसी भी अफ्रीकी देश के साथ हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता होगा।
- यह एक सीमित समझौता है।
- यह व्यापारके साथ-साथ अन्य क्षेत्र जैसे व्यापार के मूल नियम, सेवाओं में व्यापार, तकनीकी बाधाओं से व्यापार (टीबीटी), स्वच्छता और पादप संबंधी (एसपीएस) उपायों, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों के आंदोलन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और सहयोग को कवर करेगा।
- सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो वर्षों के भीतर सीमित संख्या में अत्यधिक संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (एटीएसएम) पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

भारत और मॉरीशस के बीच CECPA

संदर्भ: मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को उदार बनाना है।

समझौते के बारे में

- **एक मुक्त व्यापार समझौते की तरह:** CECPA, एफटीए के समान, भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को कवर करेगा, जिसमें खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा, आधार धातु, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक और रसायन, आदि शामिल हैं।
- **व्यापार और सेवाएँ शामिल हैं:** ऐसे समझौतों में, दो व्यापारिक साझेदार सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने के अलावा मेजबान देश के उत्पादों करों को कम करता है या समाप्त करता है ।
- **सभी पहलुओं को शामिल करता है:** यह माल के व्यापार अन्य क्षेत्रों में मूल के नियमों, सेवाओं में व्यापार, सेनेटरी और फ़ाइटोसैनिट्री (एसपीएस) जैसे उपायों के लिए तकनीकी बाधाएं, विवाद निपटान, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और सहयोग को कवर करेगा।
- मॉरीशस 615 उत्पादों के लिए भारत में तरजीही बाजार तक पहुंच से लाभान्वित होगा, जिसमें जमे हुए मछली, विशेष चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, रस, खनिज पानी, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण और परिधान शामिल हैं।
- यह उदाहरण एक अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता होगा।

भारत और मॉरीशस के बीच आर्थिक संबंध

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जहाँ 2018-19 में $ 1.2 बिलियन था वो 2019-20 में बढ़कर 690 मिलियन डॉलर हो गया।
- जबकि 2019-20 में भारत का निर्यात $ 662 मिलियन था, आयात केवल 27.89 मिलियन डॉलर था।
- मॉरीशस पेट्रोलियम उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, विद्युत मशीनरी, परिधान और कपड़े के सामान का आयात करता है, जबकि भारत के आयात में लोहा और इस्पात, मोती, कीमती / अर्ध-कीमती पत्थर आदि शामिल हैं।

- मॉरीशस में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था, 2019-20 के लिए लगभग 8.24 बिलियन डॉलर (लगभग 57,785 करोड़ रुपये) का लेखांकन किया गया।

ऑस्ट्रेलिया बनाम फेसबुक: समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता

संदर्भ: ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून (न्यूज मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य सौदेबाजी संहिता बिल 2020) के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए एक वैश्विक कूटनीतिक आक्रामक नीति की शुरूआत की है।

- यह बिल एक सौदेबाजी कोड को अनिवार्य करता है जिसका उद्देश्य Google और फेसबुक को उनकी सामग्री का उपयोग करने के लिए मीडिया कंपनियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य करना है।
- ऑस्ट्रेलियाई पीएम इस प्रकार के नियमों पर चर्चा करने के लिए भारतीय और कनाडाई पीएम से वार्ता किये।

ऑस्ट्रेलिया का विधान - स्वैच्छिक तंत्र समाधान नहीं था

- 2017 में, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग (ACCC) ने प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों और मीडिया व्यवसायों के बीच बातचीत करने तथा इनके बीच उत्पन्न समस्याओं का करने के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक कोड की सिफारिश की।
- इन सिफारिशों के आधार पर, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2019 में विभिन्न हितधारकों और ACCC को इस स्वैच्छिक कोड को विकसित करने के लिए कहा।
- हालांकि, ACCC ने अप्रैल 2020 में बताया कि व्यवसायों के स्वैच्छिक रूप से एक समझौते पर पहुंचने की संभावना नहीं थी। यह एक अनिवार्य कोड का मसौदा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
- Google और FB को मीडिया कंपनियों के साथ भुगतान वार्ता में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य कोड का प्रावधान - अगर कोई समझौता नहीं हुआ है, तो एक मध्यस्थ अनिवार्य है - या भारी जुर्माना का सामना करना, करना पड़ेगा।
- आर्बिटर को मुख्य रूप से छोटे प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो प्लेटफार्मों के साथ एक बातचीत का सामना कर सकते हैं।
- यूरोपीय अधिकारियों ने विशेष रूप से समझौतों में जबरन डिवाइस डाले बिना भुगतान को कॉपीराइट से जोड़ा है।
- दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया का कोड, लगभग पूरी तरह से समाचार आउटलेट्स की सौदेबाजी की शक्ति पर केंद्रित है, और साथ ही इसमें कुछ जबरदस्त विशेषताएं भी हैं।

टेक जायंट्स और रेगुलेटर्स के बीच मुख्य मुद्दा क्या है?

- हालांकि समाचारों के लिंक फेसबुक या Google के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन-स्पिनर नहीं हो सकते हैं, दोनों ही समाचारों की उपस्थिति को अपने उत्पादों के साथ दर्शकों के जुड़ाव के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखते हैं।
- Google और फेसबुक इतिहास की सबसे बड़ी और लाभदायक दो कंपनियों में से एक हैं और प्रत्येक में किसी भी समाचार प्रकाशक की तुलना में अधिक सौदेबाजी की शक्ति है। समाचार मीडिया सौदेबाजी कोड इस असंतुलन को दूर करने के लिए निर्धारित है।
- ऑस्ट्रेलिया में लड़ाई वास्तव में, इस बात पर केंद्रित है कि ये कंपनियां अपनी भुगतान प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण रख पाएंगी - परिचालन संबंधी पहलू जैसे कि समाचार फ़ीड स्रोतों के लिए भुगतान की मात्रा तय करना और उनके एल्गोरिथ्म में परिवर्तन प्रकट करना।

टेक दिग्गज द्वारा प्रतिक्रिया

- **चेतावनी:** जनवरी 2021 में जब बिल पेश किया जा रहा था, Google ने ऑस्ट्रेलिया से अपने खोज इंजन को हटाने की धमकी दी, और फेसबुक ने चेतावनी दी कि यह ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ताओं को समाचार लिंक पोस्ट करने या साझा करने से रोक सकता है।

- **Google और FB के तर्क:** वे कहते हैं कि मीडिया उद्योग पहले से ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से लाभान्वित हो रहा था, और यह कि प्रस्तावित नियम इंटरनेट कंपनियों को "वित्तीय और परिचालन जोखिम के स्तरों" को उजागर करेंगे।
- **Google की मिलीभगत की स्थिति:** Google ने एक समाचार निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे पीछे कर रहा है।
- **एफबी द्वारा प्रतिक्रिया:** हालांकि, फेसबुक जिसके ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन उपयोगकर्ता हैं - जवाबी कार्रवाई करते हुए, इसके मंच पर सभी समाचार लिंक को बंद कर रहा है।
- **एफबी की कार्रवाइयों के परिणाम:** इस प्रक्रिया में, एफबी ने कुछ आपातकालीन सेवाओं को भी बंद कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ़ मौसम विज्ञान, राज्य के स्वास्थ्य विभागों, आग और बचाव सेवाओं, दान और आपातकालीन और संकट सेवाओं से कथित तौर पर हटाए गए पोस्टों को समाप्त कर दिया।

भारत में बहस

- 2020 के लिए एक फिक्की-ईवाई रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों और एग्रीगेटर्स के 300 मिलियन उपयोगकर्ता हैं - 2019 के अंत में भारत में लगभग 46% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 77% स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं थे।
- 282 मिलियन अद्वितीय आगंतुकों के साथ, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन समाचार खपत वाला देश है।
- भारत में, डिजिटल विज्ञापन 2019 में सालाना 24% बढ़कर 27,900 करोड़ रुपये हो गया और 2022 तक बढ़कर 51,340 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है।
- समाचार मीडिया आउटलेट्स के स्वास्थ्य पर मध्यस्थ प्लेटफार्मों के प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा अभी तक किसी भी सार्थक तरीके से शुरू नहीं हुई है।

निष्कर्ष

- ऑस्ट्रेलिया का कानून भौगोलिक क्षेत्रों में सोशल मीडिया को विनियमित करने में एक मिसाल कायम करता है, और दुनिया भर में इसे बारीकी से देखा जा रहा है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना:

- बिग टेक का प्रभुत्व: यहां क्लिक करें
- Google खोज एकाधिकार: यहां क्लिक करें

IAS baba

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) - 2021

ECONOMICS DAILY CLASS AND TESTS

(Offline And Online)

Rs. 2,800/- (+ 18% GST)

REGISTER NOW

भारत और विश्व

भारत और श्रीलंका: भारत कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट

संदर्भ: हाल ही में, ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद कोलंबो पोर्ट पर रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण 'ईस्ट कंटेनर टर्मिनल' (ई.सी.टी.) विकसित करने के लिये भारत और जापान के साथ वर्ष 2019 में हुए समझौते को श्रीलंका सरकार ने रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कहा है कि ईस्ट टर्मिनल का संचालन 'श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण' स्वयं करेगी। **भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी है?**
श्रीलंकाई पीएम के इस कथन पर कि ईसीटी का विकास और संचालन अपने दम पर किया जाएगा, एक ऐसी खबर जिसे भारतीय पक्ष को शर्मिंदा करते हुए देखा गया, भारत की पहली प्रतिक्रिया थी कि मौजूदा राष्ट्र इस त्रिपक्षीय समझौते पर एकपक्षीय तरीके से निर्णय नहीं ले रहा है।

भारत के लिए श्रीलंका का प्रतिपूरक प्रस्ताव क्या है?

- 2019 के समझौते पर श्रीलंका के फैसले के बाद, देश की कैबिनेट ने अब जापान और भारत के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कोलंबो बंदरगाह के पश्चिम टर्मिनल को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- **वेस्ट टर्मिनल प्रस्ताव के पक्ष में श्रीलंका द्वारा दिए गए तर्क:**
  - वाणिज्यिक रूप से, पश्चिम टर्मिनल प्रस्ताव भारत के लिए बेहतर है क्योंकि यह ECT में 49% के मुकाबले वेस्ट टर्मिनल के डेवलपर्स के लिए 85% हिस्सेदारी देता है।
  - राजनीतिक रूप से भी, पश्चिम टर्मिनल लगभग समान है यदि सुरक्षा पहलू और श्रीलंका में पोर्ट टर्मिनल की आवश्यकता को माना जाता है
  - ईस्ट टर्मिनल की तुलना में वेस्ट टर्मिनल आकार या गहराई में छोटा नहीं है
  - ईसीटी का विकास आंशिक रूप से पूरा हो गया है जबकि वेस्ट टर्मिनल के विकास को प्रारंभ से शुरू करना है

ECT पर श्रीलंका ने अपना शब्द क्या बदला?

- **पहले की सरकार के तहत समझौता:** 2019 में पूर्व मैत्रीपाला सिरिसेना-रानिल विक्रमसिंघे प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, भारत और जापान ने एक साथ ईसीटी में 49% हिस्सेदारी रखी थी।
- **कोलंबो बंदरगाह ट्रेड यूनियनों का दबाव:** राष्ट्रपति दबाव में थे क्योंकि ट्रेड यूनियन पोर्ट के निजीकरण का विरोध कर रहे थे और 2019 के समझौते को रद्द करने की मांग कर रहे थे। सरकार के साथ वार्ता के दौरान, ट्रेड यूनियनों ने अपने स्वयं के राष्ट्रपति के घोषणापत्र को उद्धृत किया जो इस 2019 समझौते के विपरीत था।
- **समाज के अन्य वर्गों के विरोध प्रदर्शनों के लिए समर्थन:** जबकि राजनयिक सर्कल के बीच रिपोर्ट और आरोप थे कि चीनी ने भारत के हित के खिलाफ पोर्ट यूनियनों के विरोध को उकसाने में भूमिका निभाई थी, कुछ 223 श्रीलंकाई यूनियन ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न क्षेत्रों से और सिविल सोसायटी समूहों, पोर्ट ट्रेड यूनियनों के समर्थन की घोषणा को ईसीटी समझौते को रद्द करने की मांग की।

यदि भारत पश्चिम टर्मिनल प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो क्या ऐसे ही विरोध और संकट होंगे?

- ईसीटी समझौते को रद्द करने से पहले, श्रीलंका सरकार ने भी इस संबंध में यूनियनों की लिखित सहमति प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 23 में से 22 यूनियनों ने हस्ताक्षर किए और सरकार को अपनी योजनाओं को विकसित करने में सहयोग देने के लिए एक पत्र दिया।
- यूनियनों के सहमति पत्र में एक विशिष्ट बिंदु है, जिसमें कहा गया है: "हम एक अच्छे निवेश निर्णय का समर्थन करेंगे जो कि भविष्य में सरकार पश्चिमी टर्मिनल के संबंध में लेगी।"
- यह व्यावसायिक रूप से भारतीय कंपनी अडानी के लिए एक बेहतर सौदा है। और यूनियनों ने भी एक कैबिनेट पेपर में पूर्व और पश्चिम दोनों टर्मिनल फैसलों का उल्लेख करने पर सहमति व्यक्त की थी।

- वियाथमैगा (एक बेहतर भविष्य के लिए पेशेवर), शिक्षाविदों, पेशेवरों और उद्यमियों के एक नेटवर्क ने यूनियनों और सरकार के बीच अंतिम दौर की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने डब्ल्यूटीसी के नवीनतम प्रस्ताव का नेतृत्व किया था।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- चीन की पर्ल रणनीति का स्ट्रिंग
- हंबनटोटा बंदरगाह परियोजना - चीन को दी गई

म्यांमार में सैन्य तख्तापलट

संदर्भ: देश की नवनिर्वाचित संसद की एक निर्धारित बैठक से पहले म्यांमार की सेना (जिसे तमातदाव के नाम से जाना जाता है) ने 1 फरवरी की सुबह तख्तापलट में सत्ता हथिया ली।

आंग सान सू की, जिन्होंने 2020 के चुनावों में एक शानदार जीत के लिए नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेतृत्व किया था। को अब हिरासत में रखा गया है, सेना ने म्यांमार में एक साल की आपातकालीन स्थिति घोषित की।

आंग सान सू की के बारे में

- सुश्री सू की, म्यांमार के स्वतंत्रता नायक, जनरल आंग सान की बेटी हैं। 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होने से ठीक पहले, जब वह केवल दो साल की थी, तब उनकी हत्या कर दी गई थी।
- विदेश से लौटने के बाद, 1988 में सू की ने सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह को प्रमुखता दी और शांतिपूर्ण लोकतंत्र की वकालत की। उनकी एनएलडी पार्टी ने 1990 का चुनाव जीता, जिसे सेना ने रद्द कर दिया था। उसके बाद उसे 2010 तक लगभग दो दशकों तक हिरासत में रखा गया।
- तत्कालीन सैन्य शासित म्यांमार (जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है) में लोकतंत्र लाने के उसके व्यक्तिगत संघर्ष ने दमन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया।

- 2015 में उनकी शानदार जीत के बावजूद, म्यांमार के संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति बनने से मना किया क्योंकि उनके पास ऐसे बच्चे हैं जो विदेशी नागरिक हैं। लेकिन सुश्री सू की, अब 75, को व्यापक रूप से वास्तविक नेता के रूप में देखा जाने लगा।
- उसका आधिकारिक शीर्षक राज्य काउंसलर था।

2021 तख्तापलट के कारण

- **एनएलडी चुनावी जीत:** म्यांमार की आंग सान सू की और उनकी सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने 2020 के राष्ट्रीय चुनावों में लगातार दूसरी बार भारी जीत हासिल की, जिसमें पार्टी ने द्विसदनीय संसद में चुनाव लड़ी और 496 सीटों में से 396 सीटें हासिल कीं।
- **लोकतंत्र के लिए मतदान करने वाले लोग:** 2020 की जीत ने NLD को 2015 में मिली जीत की तुलना में नौ और सीटें दीं, जब उसने दशकों के सैन्य शासन के बाद म्यांमार के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में सत्ता हासिल की थी।
- **चुनाव परिणामों पर सेना द्वारा आरोप:** सेना ने आरोप लगाया है कि नवंबर 2020 में हुए आम चुनाव "अनियमितताओं" से भरे हुए थे और इसलिए, परिणाम वैध नहीं हैं। मिलिट्री ने चुनाव में डाले गए लगभग 9 मिलियन वोटों की सत्यता पर सवाल उठाया।
- **सेना की मांग खारिज:** सेना ने मांग की थी कि म्यांमार के संयुक्त चुनाव आयोग (UEC) जो कि चुनावों की देखरेख करते हैं, या सरकार, या निवर्तमान सांसद 1 फरवरी को नई संसद बुलाने से पहले एक विशेष सत्र में साबित करें कि चुनाव मुफ्त और निष्पक्ष है, कि मांग खारिज कर दी गई थी।
- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किए गए:** यूईसी ने कहा है कि उसे किसी भी मतदान कदाचार या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। इसने कहा है कि प्रत्येक मत को "चुनावी उम्मीदवारों, चुनाव कर्मचारियों, मीडिया, पर्यवेक्षकों और अन्य सामाजिक समाज संगठन द्वारा पारदर्शी रूप से गिना जाता है"।

लोकतांत्रिक परिवर्तन रुका

- **2008 का संविधान:** यह वह सेना थी जिसने 2008 के संविधान का मसौदा तैयार किया था, और इसे उस वर्ष अप्रैल में एक संदिग्ध जनमत संग्रह में डाल दिया था। संविधान सेना का "लोकतंत्र का रोडमैप" था, जिसे उसने पश्चिम से बढ़ते दबाव के तहत अपनाने के लिए मजबूर किया था।
- **सेना की भूमिका सुरक्षित थी:** लेकिन सेना ने संविधान की अपनी भूमिका और राष्ट्रीय मामलों में वर्चस्व की रक्षा करना सुनिश्चित किया। इसके प्रावधानों के तहत, संसद के दोनों सदनों में सेना के पास 25% सीटें हैं, जिसके लिए वह सैन्य अधिकारियों की सेवा करता है। इसके अलावा, एक राजनीतिक दल जो सैन्य चुनावों के लिए एक प्रतिनिधी है।
- **संवैधानिक सुधार:** म्यांमार का लोकतांत्रिक परिवर्तन कार्य प्रगति पर था। महामारी के दौरान आयोजित 2020 के चुनाव के परिणामों को एनएलडी द्वारा संवैधानिक सुधार की अपनी योजना के लिए एक जनादेश के रूप में देखा जा रहा था, जिसके माध्यम से राजनीति और शासन में सेना की भूमिका को कम करना था। लेकिन यह कभी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि संशोधनों के लिए संवैधानिक प्रतिबंध लगाएं गए थे।
- **मिलिट्री सत्ता को बनाए रखना चाहती थी:** 2020 के चुनाव में "अनियमितताओं" के अपने आरोपों के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि सेना ने सू की की अनिर्दिष्ट, यहां तक कि पांच साल की निरंतरता के बावजूद बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस किया। इसके अलावा, सेना की भूमिका की रक्षा करने वाले संविधान के बावजूद, जनरलों को लग रहा था कि सूची राष्ट्रीय मामलों में नागरिक वर्चस्व को बहाल करने के लिए अपने नए जनादेश का इस्तेमाल करेगी। यह डर आखिरकार तख्तापलट की ओर ले गया है।
- **तख्तापलट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आलोचना:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके जैसे कई देशों के राजनयिक मिशनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि "हम सैन्य और देश के अन्य सभी दलों

से लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करने का आग्रह करते हैं, और हम विरोध करते हैं चुनावों के परिणामों को बदलने या म्यांमार के लोकतांत्रिक परिवर्तन को बाधित करने का कोई भी प्रयास।

पहले कार्यकाल में सरकार और सेना के बीच संबंध कैसा था?

- **सौहार्दपूर्ण संबंध:** सू की पहले कार्यकाल सैन्यदृष्टि से आसान था। एक बिंदु पर, उसने "मीठे चाचा" की याद दिलाते हुए जनरलों को संदर्भित किया।
- **रोहिंग्या क्रैकडाउन में सेना के साथ खड़ी थी:** सू की ने रोहिंग्या के खिलाफ अपनी क्रूर कार्रवाई में उसने सेना का समर्थन किया, जिसने लगभग एक लाख बांग्लादेश भागने के लिए मजबूर किया। सू की ने बाद में रोहिंग्या के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए म्यांमार के खिलाफ एक मामले में सेना का बचाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी पेश हुई।
- **पहले कार्यकाल के दौरान फोकस अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहा था:** 2015 से पिछले साल तक, सू की अपने अन्य प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं दो दर्जन से अधिक अल्पसंख्यक मिलिशिया के साथ शांति निर्माण पर जोर दे रही थी जो म्यांमार राज्य के साथ युद्ध में थे, ताकि सभी अल्पसंख्यक एक साथ आ सकें।
- **1940 के दशक में उसके पिता द्वारा इसी तरह के प्रयास के बाद, एहसास:** कि सेना की शक्ति को कम करने की आवश्यकता है: अल्पसंख्यक मिलिशिया के बीच के प्रयासों को "21 वीं सदी के पंगलोंग सम्मेलन" कहा गया था। लेकिन 2015 में एक युद्धविराम समझौता केवल आंशिक रूप से सफल रहा था, और बैठकों की एक श्रृंखला ने कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिया, यह विश्वास दिलाते हुए कि शांति वापस आ जाएगी जब सेना को पीछे धकेल दिया जाएगा।

भारत और म्यांमार वर्षों में और तख्तापलट का प्रभाव

- **प्रो-डेमोक्रेसी आंदोलन के लिए प्रारंभिक समर्थन:** 1990 के दशक में सू की की रिहाई के अभियान में शामिल होने के बाद, नई दिल्ली ने जंटा के साथ पूर्ण समझौता शुरू करने के लिए अपनी स्थिति को फिर से व्यवस्थित किया, हालांकि यह म्यांमार के लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन और विशेष रूप से एनएलडी को परेशान करता है।
- **उत्तर-पूर्व को सुरक्षित करने के लिए सेना के साथ जुड़ाव:** उनके साथ भारत का जुड़ाव के बदले में, म्यांमार की सेना ने उल्फा और भारत के पूर्वोत्तर के अन्य आतंकवादी समूहों को म्यांमार में सुरक्षित ठिकानों पर क्रैक किया। वरिष्ठ जनरलों ने नियमित रूप से भारत का दौरा किया, बोधगया में दिल्ली से या वापस जाने के रास्ते पर रोक दिया।
- **सू की चीन के करीब जा रही हैं:** 2015 के बाद से, रोहिंग्या पर सेना की कार्रवाई पर भारत के समर्थन के रुख ने दोस्ती को जारी रखा है, हालांकि सू ची खुद एनडीए सरकार के लिए विशेष रूप रुचि नहीं लेती है। हाल के वर्षों में, जैसा कि वह पश्चिम से दूर था, सू की ने बीजिंग की ओर तेजी से रुख किया था, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके लिए लाल कालीन बिछाया था।
- **द्विपक्षीय संबंध पर सैन्य तख्तापलट का प्रभाव:** भारत द्वारा किए गए सैन्य समर्थन से पीछे हटने की संभावना नहीं है, हालांकि इसने म्यांमार में अचानक हुए घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र में प्रभाव के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा म्यांमार तक फैली हुई है, जो भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर से दक्षिण पूर्व एशिया तक महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- विडंबना यह है कि यह चीन हो सकता है कि म्यांमार की सेना पर सू की को रिहा करने और पीछे हटने के लिए सबसे अधिक दबाव खत्म कर सकता है।
- हालाँकि म्यांमार के जनरलों को अपने देश में चीन के बाहरी प्रभाव से नाराजगी है, फिर भी वे बीजिंग के लिए खड़े होंगे।
- अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी है लेकिन इसे अब आगे के सबसे अच्छे तरीके के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वे आम लोगों को चोट पहुंचाने की तुलना में अधिक करते हैं, जैसा कि वे नेताओं के साथ करते हैं जो वे उद्देश्य रखते हैं। व्यवस्था को अब ऐसी स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

एक 'स्वस्थ' भारत-अफ्रीका साझेदारी की ओर

संदर्भ: कोविद -19 महामारी का भारत पर प्रभाव विशेष रूप से गंभीर है। विश्व प्रणालियों के अंतर्संबंध को देखते हुए, यह जांचना महत्वपूर्ण है कि रिकवरी की प्रक्रिया के आसपास साझेदारी कैसे बनाई जा सकती है, खासकर अफ्रीका के देशों के साथ।

अफ्रीका में महामारी

- **युवा जनसांख्यिकी के कारण कम मामले:** जबकि अफ्रीका वायरस से प्रभावित होने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक था, और 35,000 से अधिक लोगों की मृत्यु के साथ इसकी युवा जनसांख्यिकी की वजह से इसने एशिया और यहां तक कि यूरोप में फैलने की संभावना के मामले में कम संख्या।
- **बहु-हितधारक प्रतिक्रिया नियंत्रित प्रसार:** अफ्रीकी नेताओं, अफ्रीकी संघ और रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अफ्रीका केंद्रों के बीच सहयोग के कारण परीक्षण क्षमता में वृद्धि हुई है। राज्य के प्रयासों के अलावा, अफ्रीकी देशों के नागरिक संगठनों और युवा कार्यकर्ताओं ने संसाधनों को जुटाने, जागरूकता फैलाने और समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अफ्रीका पर COVID-19 महामारी का आर्थिक प्रभाव

- **कम व्यापार:** यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन और अन्य बाजारों से घटती मांग के कारण अफ्रीका अंतर-अफ्रीकी व्यापार संख्या से कम प्रभावित हुआ है, जिससे आपूर्ति-और-मांग को झटका लगा है।
- **गरीबी के मोर्चे पर हुई प्रगति को नष्ट कर सकता है:** उप सहारा अफ्रीका की प्रति व्यक्ति जीडीपी इस वर्ष -5.4 प्रतिशत कम हो सकती है, जो 49 मिलियन अफ्रीकियों के गरीबी में धकेलने की संभावना के साथ प्रभावी ढंग से एक दशक पीछे कर सकती है।
- **बेरोजगारी:** यह अनुमान है कि 30 मिलियन नौकरियां संभवतः महामारी के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान के कारण गायब हो जाएंगी
- **रिकवरी के लिए लंबा समय:** नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को क्रमशः 2023 और 2024 तक पूर्व-कोविद -19 के स्तर पर वास्तविक जीडीपी विकास वापसी की उम्मीद नहीं है।
- **निर्बल कल्याणकारी राज्य:** महामारी ने इस क्षेत्र में सामाजिक कल्याण योजनाओं और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति को भी जन्म दिया है।

इस निर्णायक मोड़ पर भारत अफ्रीका की मदद कैसे कर सकता है?

1. गति पर बनाएँ

- पहले से ही, भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य सहयोग बहुआयामी एवं व्यापक है, और इसमें राष्ट्रीय, राज्य और उपनगरीय कार्यकर्ता शामिल हैं जो अफ्रीकी संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
- इसमें कम लागत वाली जेनरिक का निर्यात करना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण, सहायता प्रदान करना, तकनीकी सहायता और चिकित्सा पर्यटकों की मेजबानी करना शामिल है।
- हाल के दिनों में भारत-अफ्रीका संबंधों ने गति पकड़ी है: नियमित उच्च-स्तरीय यात्राओं के साथ, राजनयिक पदचिह्न बढ़ाना, क्षेत्रों में विविधीकरण और एक जीवंत प्रवासी - जो कि इस अभूतपूर्व संकट के दौरान निर्माण कर सकता है।

2. क्षेत्र में कम लागत वाले कोविद -19 टीकों की आपूर्ति में भागीदार

- दुनिया की "फार्मेसी" के रूप में, जबकि भारत पहले ही 25 से अधिक अफ्रीकी देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और अन्य दवाओं सहित दवाओं की खेप को भेज चुका है, यह इस क्षेत्र में कम लागत वाले कोविद -19 टीकों की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।
- जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने कहा है कि वह WHO समर्थित COVAX पहल को आपूर्ति भेजना शुरू कर देगा, दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसने SII के साथ एक समझौता किया है अगले दो महीने और उसे वैक्सीन के 1.5 मिलियन खुराक मिलेंगे।

3. अफ्रीका की स्वास्थ्य प्रणालियों का व्यापक सुदृढ़ीकरण

- भारतीय दवा कंपनियां अफ्रीकी दवा निर्माण क्षमता को बढ़ाने में भी भूमिका निभा सकती हैं
- अफ्रीका के लिए फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लान, 2007 में विकसित एक बिजनेस आइडिया है और 1 जनवरी 2021 को लागू होने वाला अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AFCTA) अफ्रीका में फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है।
- भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पहले से ही अफ्रीका में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हेल्थकेयर इकोसिस्टम बनाने, निवेश बढ़ाने, और क्रॉस-कंट्री पार्टनरशिप बनाने के उद्देश्य से हेल्थ फेडरेशन ऑफ इंडिया (NATHEALTH) और अफ्रीका हेल्थ फेडरेशन (AHF) के बीच हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ हैं स्वास्थ्य में एक मजबूत साझेदारी की सरासर व्यावसायिक क्षमता को पहचानता है।

4. ई-पहल को बढ़ावा देना

- भारत सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका भी निभा सकती है और अफ्रीकी देशों के समकक्षों के साथ वीडियो या टेलीकांफ्रेंस की मेजबानी के लिए चिकित्सा पेशेवरों के साथ कार्य समूह बना सकती है।
- ई-आरोग्य भारती (टेली-मेडिसिन) परियोजना, अक्टूबर 2019 में ई-वीबीएबी का हिस्सा है, इस दिशा में एक कदम है।
- ई-वीबीएबी परियोजना जिसमें ई-विद्याभारती (टेली-शिक्षा) भी शामिल है, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह पैन-अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना का निर्माण करता है और प्रमुख भारतीय शिक्षा संस्थानों और देश में चिकित्सा विशेषज्ञों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

5. बहुपक्षीय प्रयास

- भारतीय कर्ता डब्ल्यूएचओ या यूएन जैसे हितधारकों द्वारा अफ्रीकी रिकवरी के लिए और अधिक बहुपक्षीय प्रयासों को शुरू करने और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि कोविद -19 संकट का भारत गंभीर प्रभाव पड़ा है और देश के पास निपटने के लिए बहुत बड़े घरेलू दायित्व हैं, हमारी साझा वास्तविकता और भारत के प्रति अफ्रीका की एक जुटता के लिए में अफ्रीका के साथ इस महत्वपूर्ण मोड़ पर साझेदारी करना भारत की समृद्ध समृद्धि के लिए बहुत बड़ा मूल्य होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत की पड़ोस नीति

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहली भारत-बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- हाल ही में भारत और किंगडम ऑफ बहरीन के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और बहरीन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया है।
- उन्होंने अपनी संबंधित सरकारों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों द्वारा निर्धारित किए गए प्रयासों, प्रगति और भविष्य के लक्ष्यों को प्रस्तुत किया।
- वे अनुभव, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण में गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमति व्यक्त की और इस क्षेत्र में विशेष रूप से सौर, पवन और स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों और दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

वैक्सीन कूटनीति

एक ओर जहां अग्रणी और उन्नत देशों ने अनुमोदित टीकों की जमाखोरी में स्वार्थी है, यह वैश्विक दक्षिण देश, भारत और चीन हैं, जिन्होंने अधिकांश देशों को आशा की किरण प्रदान की है।

वैक्सीन राष्ट्रवाद

- टीकों का विकास उत्तर और दक्षिण के बीच वैश्विक सहयोग की एक उत्कृष्ट कहानी है।
- दुर्भाग्य से, महामारी के दौरान लोकतांत्रिक दुनिया की बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों ने वैश्विक सहयोग पर सकारात्मक कदम को चुनौती दी है।
- जब कोई देश अपने नागरिकों या निवासियों के लिए टीके की खुराक सुरक्षित करता है और अन्य देशों में उपलब्ध कराने से पहले अपने घरेलू बाजारों को प्राथमिकता देता है, तो इसे 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' के रूप में जाना जाता है।
- देश पूर्व खरीद समझौतों के लिए जा रहे हैं क्योंकि कंपनियों द्वारा इस तरह के टीकों के निर्माण की लंबी अवधि के लिए है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2022 की पहली तिमाही तक दुनिया भर में आपूर्ति 1 बिलियन खुराक तक नहीं पहुंच सकती है

क्या वैक्सीन राष्ट्रवाद नया है?

- ऐसी ही स्थिति 2009 में H1N1 फ्लू महामारी के दौरान हुई थी।
- ऑस्ट्रेलिया, एक वैक्सीन के साथ आने वाला पहला देश, निर्यात को अवरुद्ध कर दिया, जबकि कुछ सबसे अमीर देशों ने अपनी दवा कंपनियों के साथ पूर्व-खरीद समझौतों में प्रवेश किया।
- अकेले अमेरिका ने 600,000 खुराक खरीदने का अधिकार प्राप्त किया।
- यह केवल तब था जब H1N1 महामारी ने फिर से प्रसार करना शुरू कर दिया था जब विकसित देशों ने गरीब अर्थव्यवस्थाओं को वैक्सीन की खुराक दान करने की पेशकश की थी।
- हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि H1N1 एक मामूली बीमारी थी और इसका प्रभाव कोविद -19 की तुलना में बहुत कम था।

अग्रिम खरीद अनुबंध

- संभावित टीकों के लिए कुछ उन्नत देशों द्वारा किए गए अग्रिम खरीद अनुबंध उनकी आबादी को कई बार टीकाकरण करेंगे।
- उम्मीद है कि एक प्रारंभिक टीकाकरण सामान्य स्थिति को वापस लाएगा और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यकता ने कई उन्नत देशों को टीकाकरण की लड़ाई में शामिल होने के लिए ईंधन दिया।
- उन्नत देशों ने COVID-19 टीकों का उपयोग करने के लिए गरीब देशों की आवश्यकता पर अपना मुंह फेर लिया है।

ऐसे कार्यों का प्रभाव

- **असमान पहुंच:** इस तरह के अग्रिम समझौते दुनिया के अधिकांश देशों में प्रारंभिक टीकों को अप्रभावी और अप्राप्य बना देंगे, जो अमीर देशों में रहने वाले लोगों से अलग हैं।
- **आर्थिक सुधार की धीमी प्रगति:** यदि टीका प्राप्त करने में बड़ी संख्या में मामले सामने आते हैं, तो बीमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को बाधित करती रहेगी और इस तरह से महामारी प्रेरित सदमे से उबरने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी।
- **असमानता को गहरा करता है:** ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच की खाई और अधिक गहरी होती जा रही है, क्योंकि वैश्विक संसाधनों का उत्पादकता में कमी और टीके की निरंतरता के कारण ग्लोबल साउथ में मानव संसाधनों की उत्पादकता में और गिरावट आ रही है।

भारत और वैक्सीन कूटनीति

- भारत ने गरीब देशों की जरूरतों के लिए सहानुभूति प्रदर्शित की है।
- भारत ने एक स्थिति ली है कि निर्यात के लिए अनुमोदित खुराक की एक महत्वपूर्ण प्रतिशत की अनुमति होगी।
- जबकि पड़ोसी देशों के लिए इसका निर्यात अनुदान मोड के तहत होगा, कम से कम विकसित देशों को टीकों की प्रारंभिक शिपमेंट मुफ्त होगी।
- भारत स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को कवर करने के लिए टीकाकरण के अपने पहले चरण में है, भारत से निर्यात अन्य देशों को उनके टीकाकरण कार्यक्रम के चरण एक को आरंभ करने में भी मदद कर रहा है।
- भारत का दृष्टिकोण केवल COVID-19 को नियंत्रण में लाने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों के होने की आवश्यकता को पुष्ट करता है।
- इसने भारत का नाम दुनिया की फार्मेसी के रूप में समेकित किया है।
- इसने भारत के सॉफ्ट पावर को और बढ़ाया है और इन विकासशील और कम विकसित देशों के बीच सद्भावना उत्पन्न की है।
- इससे आस-पड़ोस के बीच की धारणा को दूर करने में मदद मिलती है कि भारत विषमलैंगिक है और "बिग ब्रदर" है। इसके बजाय यह दर्शाता है कि भारत एक "जिम्मेदार शक्ति" है

चीन और वैक्सीन कूटनीति

- कोरोनोवायरस के कारण बड़े पैमाने पर घर पर मुहर लगी, चीन अपने टीकों को विदेशों में बेच सकता है।
- "टीके" को वैश्विक सार्वजनिक रूप से अच्छा बनाया जाएगा, "शी ने मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा का वादा किया था।
- "वैक्सीन डिप्लोमेसी" चीन के कुशासन पर कुछ गुस्से को आत्मसात करने का एक उपकरण बन गया है, जो उस समय वैश्विक स्तर पर अपनी मदद कर रहा है जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोगों के दबाव में था।
- घर पर चीन की दक्षता का विदेशों में आसान जीत में अनुवाद नहीं हुआ है। चीनी टीकों में प्रभावकारिता दर कम होती है।
- ब्राजील और तुर्की के अधिकारियों ने देरी के बारे में शिकायत की है। फिर भी, कई देशों ने उनके लिए हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अमेरिकियों या यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए महीनों का इंतजार नहीं कर सकते थे

COVAX

- COVAX परियोजना, COVID-19 टीकों के समुचित खरीद और उचित वितरण के लिए एक वैश्विक जोखिम-साझाकरण तंत्र है, यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो उच्च और मध्यम आय वाले देशों से वित्त पोषण पर आधारित है।
- COVAX वैश्विक सहयोग और वैश्विक विकास परिणामों को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक बदलाव का एक अनूठा मामला है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था (I-ACE) हैकथॉन, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी (CSIRO) किक ने भारत-ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था (I-ACE) हैकथॉन, 2021 शुरू किया।
- **लक्ष्य:** अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान के माध्यम से आम राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत से प्रतिभाशाली अभिनव छात्रों और स्टार्ट-अप को सक्षम करेंगे।

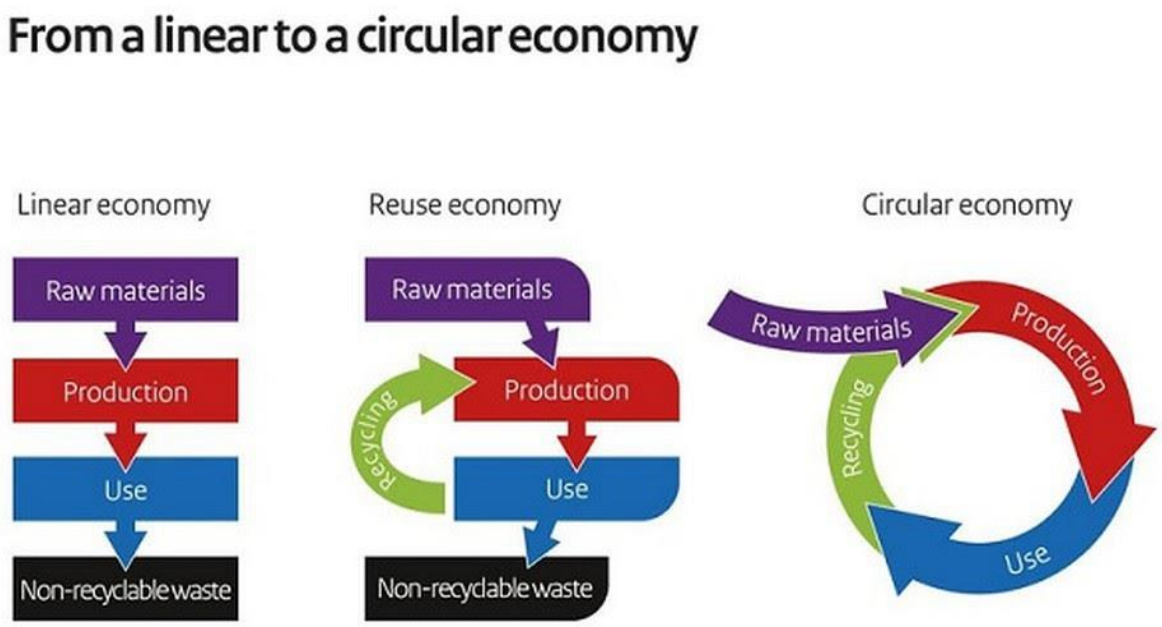

हैकाथॉन के लिए मुख्य विषय

- पैकेजिंग कचरे को कम करने वाली पैकेजिंग में नवाचार
- कचरे से बचने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार
- प्लास्टिक कचरे में कमी के अवसर पैदा करना
- महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं और ई-कचरे का पुनर्चक्रण

क्या आप जानते हो?

- एक 'परिपत्र अर्थव्यवस्था' मॉडल अपशिष्ट प्रबंधन को रोजगार देता है और पुन: उपयोग, रीसाइक्लिंग और जिम्मेदार निर्माण पर केंद्रित होता है।
- यह नए उद्योगों और नौकरियों के विकास, उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ाने का समर्थन कर सकता है।

भारत और मालदीव के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में-

- भारत और मालदीव ने व्यापक स्तर के डोमेन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- इनमें मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सतत शहरी विकास, सड़क अवसंरचना और आवास शामिल थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रसार समझौता प्रसार भारती और मालदीव के आधिकारिक राज्य मीडिया के बीच सहयोग के लिए है।
- यह सार्वजनिक प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने का इरादा रखता है।
- COVID वैक्सीन की एक लाख से अधिक अतिरिक्त खुराक भी मालदीव को सौंपी गई।
- भारत ने मालदीव के साथ रक्षा क्षेत्र में 50 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो समुद्री डोमेन में क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।
- मालदीव के साथ UTF हार्बर प्रोजेक्ट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- परियोजना समझौता मालदीव के तटरक्षक क्षमता को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों की सुविधा प्रदान करेगा।
- भारत ने मालदीव में नए खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट की एक नई लाइन को 40 मिलियन तक बढ़ाया।

संबंधित आलेख:

- मालदीव के साथ 'रणनीतिक आराम'
- भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा

अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: रोजगार

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रोजगार

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि 2019 और 2020 श्रम सुधारों के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- देश ने लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सम्मिलित, युक्तिसंगत और चार श्रम कोडों में सरलीकृत किया गया है।

1. मजदूरी पर कोड, 2019,
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020,
3. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति कोड, 2020 और
4. सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020

- सीओवीआईडी -19 ने शहरी आकस्मिक श्रमिकों की भेद्यता को उजागर किया है, जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जनवरी-मार्च, 2020 के अनुसार शहरी कार्यबल (अखिल भारतीय) का 11.2% है।
- कार्यबल पर उद्योग-वार अनुमान बताते हैं कि 42.5% कार्यबल के साथ 'कृषि' अभी भी सबसे बड़ा नियोक्ता है।
- अगला महत्वपूर्ण उद्योग अन्य सेवाएँ है जहाँ 13.8% लगे हुए थे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020:21 आत्मानिभर भारत योजना (ABRY)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नवंबर 2020 में घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक घटक एबीबीई की योजना अवधि के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 22,810 करोड़ रुपये है, जो कि 31 वें मई 2023 महीने तक है।

योजना में भुगतान का प्रस्ताव है

- संपूर्ण कर्मचारियों और नियोक्ताओं का योगदान अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि में 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ के लिए मजदूरी का 24% और COVID-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों को फिर से रोजगार देना।
- संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत देने के लिए, सरकार द्वारा 28 मार्च 2020 को जारी एक अधिसूचना, जिसमें बकाया राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने की मजदूरी जो भी कम हो, की गैर-वापसी योग्य अग्रिम का प्रावधान है, जो ईपीएफओ के सदस्यों को अनुमति है।
- प्रधान मंत्री ग़रीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (BOCW) को वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसमें BOCW के उपकर के तहत एकत्र धन से प्रवासी श्रमिक शामिल थे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21: बैंकिंग क्षेत्र

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.21% से घटकर सितंबर 2020 के अंत में 7.49% हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, यह बात कर्ज लेने वालों को मुहैया कराई गई परिसंपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ जोड़कर देखी जा सकती है।
- इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में सुधार के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात में मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच 14.7% से बढ़कर 15.8% हो गया।
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड- IBC (अपनी स्थापना के बाद से) के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वसूली दर 45% से अधिक हो गई है
- महामारी के कारण, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) को किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए निलंबित कर दिया गया था।
- निरंतर निकासी के साथ निलंबन ने संचित मामलों में एक छोटी गिरावट की अनुमति दी है।
- वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय प्रवाह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों द्वारा ऋण की वृद्धि के कारण बाधित रहा।
- 1 जनवरी 2021 तक बैंकों की ऋण वृद्धि 6.7% तक धीमी हो गई।

भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8 वें संस्करण का उद्घाटन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर के 8 वें संस्करण का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है।
- यह रेशम और रेशम मिश्रण उत्पादों के लिए सोर्सिंग मेला है।
- **द्वारा आयोजित:** भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद
- **मंत्रालय:** कपड़ा मंत्रालय
- **प्रायोजित:** वाणिज्य विभाग

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की सभी चार प्रमुख किस्मों यानि शहतूत, एरी, तसर, और मुगा का उत्पादन करता है।
- **शहतूत रेशम:** मुख्य रूप से कर्नाटक में
- **गैर-शहतूत रेशम:** महाराष्ट्र, डब्ल्यूबी, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में शीतोष्ण तुषार रेशम; उप-हिमालयी बेल्ट (मणिपुर, असम, मेघालय, आदि) में उष्णकटिबंधीय तुषार रेशम; असम में मुगा सिल्क और असम, ओडिशा, बिहार में एरी सिल्क

- भारत में लगभग 11 भौगोलिक संकेत (GI) हैं जैसे: पोचमपल्ली इकत, चंद्रपॉल सिल्क, मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, मुगा सिल्क, सलेम सिल्क, अरनी सिल्क, चंपा सिल्क, भागल सिल्क, बनारस ब्रोकेड और साड़ी, आदि।

संबंधित आलेख:

- रेशम के प्रकार और भारत के रेशम उद्योग की चुनौतियाँ: यहाँ क्लिक करें

बजट 2021-22: विनिवेश

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - निवेश; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2021-22 को पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी है जो सभी गैर-रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मौजूदा सीपीएसई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां इसके अंतर्गत शामिल होंगी।
- क्षेत्रों का दो बार वर्गीकरण किया जाएगा।
- **रणनीतिक क्षेत्र:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शेष न्यूनतम उपस्थिति और शेष सीपीएसई या बंद के साथ निजीकरण या विलय या सहायक कंपनियां बनाई जाएंगी।
- इसके अंतर्गत आने वाले 4 क्षेत्र
  1. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा
  2. परिवहन और दूरसंचार
  3. बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज
  4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं
- **गैर-सामरिक क्षेत्र:** इस क्षेत्र में, सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक उद्योग को रणनीतिक माना जाता है, यदि उसमें बड़े अभिनव कर्ता हों और यदि वह समान या संबंधित उद्योगों में अन्य फर्मों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।
- इससे पहले, रणनीतिक क्षेत्रों को औद्योगिक नीति के आधार पर परिभाषित किया गया था।
- सरकार ने औद्योगिक नीति के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को 'रणनीतिक' और 'गैर-रणनीतिक' के रूप में वर्गीकृत किया है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं।
- इसके अनुसार, सामरिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम हैं
  1. रक्षा उपकरणों का हथियार और गोला-बारूद
  2. रक्षा विमान और युद्धपोत
  3. परमाणु ऊर्जा पर
  4. कृषि, चिकित्सा और गैर-रणनीतिक उद्योग में विकिरण के अनुप्रयोग
  5. रेलवे
- रणनीतिक क्षेत्रों से अलग अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रम गैर-रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिनमें पावर डिस्कॉम शामिल हैं।

क्या आप जानते हो?

- विनिवेश एक संगठन या सरकार की संपत्ति या सहायक को बेचने या परिसमापन करने की क्रिया है।
- प्राथमिक उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं, श्रम और बुनियादी ढांचे से संबंधित निवेश (आरओआई) पर वापसी को अधिकतम करना है।

बजट 2021-22: न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III- अर्थशास्त्र और जीएस - II - शासन

समाचार में-

- केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट के छह स्तंभों में से एक में सुधार की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, अर्थात न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हो सकती है और इसे वर्ष 2021-2022 में 3,768 करोड़ आवंटित किया गया है।
- यह एक सुलह तंत्र स्थापित करने, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, अनुबंध संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए इसके उपयोग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
- इससे निजी निवेशकों और ठेकेदारों में विश्वास बढ़ेगा।
- नर्सिंग पेशे में पारदर्शिता, दक्षता और सुधार लाने के लिए, सरकार द्वारा राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पारित किया जाएगा।
- अधिकरण के कामकाज को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का भी प्रस्ताव है।
- केंद्र, पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति की हीरक जयंती वर्ष मनाने के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपये का अनुदान देगा।

बजट 2021: 10 सबसे बड़े कदम

संदर्भ: संघ सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष (2021-22) के लिए अपना बजट पेश किया जो न केवल विकास के लिए एक दिशा प्रदान करता है बल्कि सुधारों के लिए एक मजबूत इरादा भी रखता है।

बजट के शीर्ष 10 महत्वपूर्ण आकर्षण थे

1. व्यय बजट: केंद्र सरकार ने 2021-22 में राजकोषीय आवेग प्रदान करने के लिए स्थान पाया है। 2020-21 के संशोधित अनुमान (आरई) में 4.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की तुलना में, सरकार ने 2021-22 में इसे 34.46% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

- पूंजीगत व्यय को चुनना एक असंगत विकल्प की तरह प्रकट हो सकता है क्योंकि इसमें सीधे जरूरतमंदों को सौंपने के लिए धन शामिल नहीं है (और कोविद -19 व्यवधान के मद्देनजर बहुत से जरूरतमंद लोग हैं)।
- इसके बजाय, यह अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश है, जो सबसे अच्छा मौका है जब भारत को स्थायी आर्थिक विकास के रास्ते पर लौटना है।

2. एक सुधार संकेत: विनिवेश के लिए दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनी को चुना गया है। बीमा में एफडीआई 49% से अब 74% तक बढ़ाया गया है। एलआईसी के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश भी होगी।

3. लोकलुभावनवाद नहीं, बल्कि विकास पर ध्यान केंद्रित: आम आदमी के लिए एक कठिन वर्ष होने के बावजूद, सरकार ने कोई भी कर राहत देने से परहेज किया है। मानक कटौती में कोई वृद्धि नहीं, टैक्स स्लैब में कोई वृद्धि नहीं।

4. हेल्थ गेट्स इट्स ड्यू: एक साल में जब दुनिया कोविद -19 महामारी से तबाह हो गई थी, तब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य का ध्यान योग्यता से दिया। स्वास्थ्य आवंटन 2021 में 137% बढ़कर 2,23,846 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2020-21 में 94,452 करोड़ रुपये

था, जिसमें कोविद -19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर और धन मुहैया कराने का वादा किया है।

5. बैड बैंक: लगभग छह वर्षों के बाद, सरकार ने आखिरकार एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना करने का फैसला किया है जो बैंकों के बुरे ऋणों को अपने नियंत्रण में ले लेगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुधारों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

6. विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) पुनर्जन्म: यह विचार आईडीबीआई और आईसीआईसीआई सहित अधिकांश पहले के डीएफआई के साथ मृत था। लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए, 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ एक नया डीएफआई।

- हाल के समय में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में परेशानी यह रही है कि ऐसी परियोजनाओं में आमतौर पर दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, जैसा कि भारत ने किया था, जिसके कारण बैंकों का भारी एनपीए हो गया।
- एक के लिए, ऐसे बैंकों में जोखिम का सही आकलन करने की विशेषज्ञता नहीं थी। इसके अलावा, नियमित बैंकों को परिसंपत्ति-देयता बेमेल का सामना करना पड़ा - दूसरे शब्दों में, उन्होंने अल्पावधि के लिए जमा (अपनी देनदारियों) को स्वीकार किया, लेकिन बहुत अधिक अवधि के लिए विस्तारित ऋण (उनकी संपत्ति) भी दिया।
- प्रस्तावित डीएफआई में वैधानिक समर्थन होगा, लेकिन पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाएगा। तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये का उधार पोर्टफोलियो निर्धारित किया गया है।

7. एसेट मोनेटाइजेशन: यह एक निरंतर अभ्यास है, जहां सरकार ने आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। एनएचएआई, पीजीसीआईएल, रेलवे, हवाई अड्डों, गोदामों, खेल स्टेडियमों की संभावित संपत्तियों की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन।

8. चुनावी राज्यों में राजमार्ग परियोजनाएँ: चार पोल-बाउंड राज्यों को प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएँ मिली हैं- तमिलनाडु (3,500 किमी - 1.03 लाख करोड़ रुपये), केरल (1,100 किमी - 65,000 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (675 किमी - 25,000 करोड़ रुपये)) और असम (1,300 किमी - 34,000 करोड़ रु।)।

9. रणनीतिक विनिवेश - राजनीतिक / नौकरशाही की आवश्यकता को प्रेरणा: नीति आयोग ने रणनीतिक बिक्री के लिए गैर-प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को छोटी सूची देने के लिए कहा। 2020-21 में खराब प्रदर्शन के बाद, सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपये के विनिवेश की प्राप्ति का अनुमान लगाया है।

10. विकास बनाम विवेक - विकास की ओर झुकाव: 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत अनुमानित; इसके 2020-21 में 9.5% को छूने का अनुमान है। 2025-26 तक इसे जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में क्या? इसने बजट को कैसे प्रभावित किया है?

- आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है या तो आयात होने वाले सामानों पर शुल्क बढ़ाकर या घरेलु उत्पादों को सस्ते आयात स्रोत (आयात शुल्क कम करके) से मदद करना है
- एमएसएमई और अन्य उपयोगकर्ता उद्योगों को लोहे और स्टील की कीमतों में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए, सरकार ने गैर-मिश्रित धातु, मिश्रित धातु और स्टेनलेस स्टील्स के लंबे समय तक उत्पादों, फ्लैट, और लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क को घटाकर 7.5% करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा, सरकार ने कुछ स्टील उत्पादों पर एंटीडम्पिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी रद्द कर दी। यह कंपनियों को सस्ते आयात का स्रोत देता है जो उनकी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में काम करता है।
- इसी प्रकार, घरेलू कपड़ा उद्योग में एमएसएमई की मदद करने के लिए, सरकार ने नायलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर और यार्न आदि वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया जो कपड़ा क्षेत्र के लिए कच्चे माल का काम करता है।

- चमड़ा उद्योग में एमएसएमई के लिए, सरकार ने आयात पर छूट को वापस ले लिया - दूसरे शब्दों में, आयात को कठिन दिया गया - कुछ खास तरह के चमड़े का, क्योंकि वे घरेलू रूप से अच्छी मात्रा और गुणवत्ता में उत्पादित होते हैं, ज्यादातर एमएसएमई द्वारा।
- इसी तरह, सरकार ने अपने घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार सिंथेटिक रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया।
- किसानों को लाभान्वित करने के लिए, सरकार ने कपास पर नील से 10% और कच्चे रेशम और रेशम धागे पर 10% से 15% तक सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया
- कुल मिलाकर, इन कदमों से सरकार को उम्मीद है कि संकटग्रस्त एमएसएमई और संबंधित अनौपचारिक कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा।

क्या बजट अधिक रोजगार सृजन में मदद करेगा?

- उभरती बजट रणनीति का मुख्य कारण यह है कि सरकार पूंजीगत संसाधनों के निर्माण पर खर्च करना चाहेगी और निजी निवेश में "भीड़", जो बदले में, नई नौकरियों का स्रोत होगी।
- लेकिन यह तर्क कागजों तक सीमित है। वास्तविक दुनिया में, नौकरी सृजन में समय लगेगा। जिन लोगों ने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी या जो लोग अपना पहला जॉब नहीं प्राप्त कर सके, उनके लिए दृष्टिकोण अभी भी दानेदार है।
- इसलिए कि आर्थिक सुधार - विशेष रूप से उस आदेश के कारण जो बहुत सारी नौकरियां पैदा करता है और जल्दी से करता है अभी भी भारत को बाहर करता है।
- 2021-22 में, भारत तेजी से आर्थिक विकास दर्ज करेगा लेकिन तथ्य यह है कि यह केवल 2020-21 में हुए नुकसान की भरपाई ही करेगा।
- यह महत्वपूर्ण है कि भारत कोविद के संकट में जाने से (2019-20 में) लगभग 4% बढ़ रहा था। 7% या 8% की दर से बढ़ेगा (जो कि 2022-23 के बाद से है) या आगे बढ़ना कोई निष्कर्ष नहीं है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ऑफबॉडिंग बॉरोइंग
- राजकोषीय परिषद: भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है?

कपिला अभियान बौद्धिक संपदा के लिए शुरू किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - बौद्धिक संपदा

समाचार में-

- हाल ही में कपिला अभियान खबरों में था।

महत्वपूर्ण तथ्य

KAPILA

- सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता के लिए बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान (KAPILA) नाम से अभियान शुरू किया और 15 अक्टूबर 2020 से जागरूकता बड़ा रही है।

उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के बारे में जागरूकता पैदा करना,
2. HEI के संकाय और छात्रों द्वारा उत्पन्न आविष्कारों के आईपी संरक्षण को सक्षम करना,
3. आईपीआर पर क्रेडिट कोर्स का विकास,
4. HEIs के संकाय और छात्रों के लिए IPR पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और

5. संवेदीकरण और एक जीवंत आईपी फाइलिंग प्रणाली का विकास।

- अब तक, KAPILA के लिए कुल 46,556 उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए हैं।

संबंधित आलेख:

- भारत की आईपीआर नीति के उद्देश्य: यहां क्लिक करें

एमएफआई: डिजिटल और फिजिकल माइक्रो-लेंडिंग

संदर्भ: माइक्रो-लेंडिंग फिर से गलत कारणों से चर्चा में है - पहला असम से संबंधित है और दूसरा डिजिटल माइक्रो लेंडिंग से संबंधित है।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- माइक्रोफाइनेंस उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग और संबद्ध सेवाओं के संपर्क में कमी के लिए वित्तीय सेवाओं का एक आधार है।
- ऐसे ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं के लिए दो प्रमुख प्रणालियों में व्यक्तिगत उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के लिए 'समूह-आधारित मॉडल' के साथ 'संबंध-आधारित बैंकिंग' शामिल हैं, जहां कई उद्यमी समूह के रूप में ऋण और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए एक साथ आते हैं। ।
- माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (MFI) द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें सामान्य बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्क से कम हैं।
- आमतौर पर, छोटे ऋणों के विस्तार के अपने क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों में शामिल हैं।
- इस मॉडल में गरीबी उन्मूलन उपकरण के रूप में इसकी उत्पत्ति थी, जो आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए महिलाओं को किसी भी संपार्श्विक के बिना छोटी राशि के उधार के माध्यम से हाशिए के वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान पर केंद्रित था।
- सुरक्षा और उच्च परिचालन लागत में कमी गरीब लोगों को ऋण प्रदान करते समय बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। इन सीमाओं ने भारत में माइक्रोफाइनेंस के विकास के लिए वित्तीय समावेशन और समानता बनाने के उद्देश्य से गरीबों को ऋण प्रदान करने के विकल्प के रूप में नेतृत्व किया।
- एमएफआई बैंकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे न केवल माइक्रो क्रेडिट की पेशकश करते हैं बल्कि वे अन्य वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं जैसे बचत, बीमा, प्रेषण और गैर-वित्तीय सेवाएं, व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण और खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए समर्थन आदि।

माइक्रोफाइनेंस की मुख्य विशेषताएं

- उधारकर्ता निम्न आय वर्ग से होते है।
- ऋण छोटी राशि के होते हैं - सूक्ष्म ऋण
- लघु अवधि ऋण
- ऋण समतलीकरण के बिना दिए जाते हैं
- चुकौती की उच्च आवृत्ति
- ऋण आम तौर पर आय सृजन के उद्देश्य से लिए जाते हैं

भारत में माइक्रोफाइनेंस

- SEWA कोआपरेटिव बैंक की शुरुआत 1974 में अहमदाबाद, गुजरात में इला भट्ट द्वारा की गई थी, जो अब देश के पहले आधुनिक माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में से एक है।

- भारत में MFI एनजीओ (सोसाइटी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत), धारा 25 कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के रूप में मौजूद हैं।
- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने असंबद्ध लोगों, विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सेवाओं की पेशकश की और बाद में एक बहुत ही अलग मॉडल के साथ प्रयोग करने का फैसला किया, जिसे अब स्व-सहायता समूहों (SHG) के रूप में जाना जाता है।
- वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी समितियों और अन्य बड़े उधारदाताओं ने एमएफआई को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- बैंकों ने समूह उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए स्व-सहायता समूह (SHG) चैनल का भी लाभ उठाया है।

क्या आपको पता है?

- वित्त वर्ष 2015 के अंत तक एमएफआई ऋण पोर्टफोलियो 2.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 5.89 करोड़ पहुंच रहा है।
- कुछ एमएफआई, जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं और गैर-डिपॉजिट लेने वाली इकाइयां हैं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए आरबीआई के पंखों के तहत आती हैं। इन "लास्ट माइल फाइनेंसर्स" को एनबीएफसी एमएफआई के रूप में जाना जाता है।
- RBI के तहत उन्हें कवर करने का उद्देश्य इन NBFC MFI को स्वस्थ और जवाबदेह बनाना था।

असम में एमएफआई का मुद्दा क्या है?

- असम सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसने सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (MFI) को समाज के कमजोर वर्गों को उधार देने से रोक दिया है। यह एमएफआई के खिलाफ एक प्रतिक्रिया का जवाब था।
- चाय बागानों में काम करने वाले बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं ने एमएफआई से ऋण लिया था। आरबीआई ने उल्लेख किया कि चाय बागानों में आर्थिक मंदी और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विघटन के कारण भ्रम में वृद्धि हुई।
- एमएफआई ने उधारकर्ताओं रिकवरी वसूलने के लिए कलेक्टरों को भेजना शुरू कर दिया, जिससे बिल के संदर्भ में राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई।
- 2010 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के कानून को पारित कर दिया जैसे असम में एमएफआई के खिलाफ उद्योग में संकट पैदा हो गया।
- हालांकि ऋण देने का चलन असम में कम है और एमएफआई को संकट में डालने की संभावना नहीं है, वित्त अकेले के लिए नहीं है बल्कि इसमें परस्पर संबंध हैं।

डिजिटल माइक्रो-लेंडिंग में क्या समस्या है?

- डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म ने तेजी से वृद्धि की है और उच्च ब्याज दरों, छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य पुनर्प्राप्ति विधियों और उधारकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग की आलोचनाएं हैं।
- आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील की और विनियमित और अनियमित डिजिटल उधार दोनों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया ताकि एक उचित नियामक दृष्टिकोण रखा जा सके।
- फिनटेक की जल्द ही सूदखोर और ऋण शार्क होने के लिए आलोचना की जाएगी।

आगे की राह

- 1870 के दशक में, बॉम्बे प्रेसीडेंसी के पूना और अहमदनगर जिलों में एक समान प्रतिक्रिया हुई। 1860 के दशक के शुरुआती दौर में किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया। जैसे-जैसे ऋण बढ़ता गया, किसान इन ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ थे। साहूकारों ने ऋण के रूप में भूमि को जब्त कर लिया, विरोध प्रदर्शन और दंगों का रूप ले लिया।
- सरकार ने 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पारित करके जवाब दिया कि कृषक-ऋणी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और विशेष रूप से प्रतिज्ञा होने तक अपनी अचल संपत्ति को कुर्की और बिक्री से बचाया। हालाँकि, इस और अन्य संबंधित विधानों का वांछित प्रभाव नहीं था।
- इसलिए, दिन की सरकार को MFI के काम को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को पारित करने से पहले पिछली घटनाओं से सीखना चाहिए। इस क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के साथ जुड़कर पूरे मामले की ईमानदार से समीक्षा की जानी चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- एमएफआई के साथ चुनौतियां और सामाजिक प्रभाव की निगरानी की आवश्यकता: यहां क्लिक करें

RBI छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों तक सीधी पहुँच प्रदान करेगा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- आरबीआई ने सूचित किया है कि यह छोटे निवेशकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- खुदरा निवेशक सीधे आरबीआई के साथ अपने गिल्ट खाते खोल सकते हैं, और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं।
- इसे एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार के रूप में वर्णित किया जा रहा है।
- दो प्रमुख श्रेणियां हैं

1. ट्रेजरी बिल - शॉर्ट-टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो 91 दिनों, 182 दिनों या 364 दिनों के लिए होते हैं, और
2. दिनांकित प्रतिभूतियाँ - दीर्घकालिक साधन, जो 5 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के लिए होते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक "गिल्ट अकाउंट" का अर्थ है कि सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक खाता खोला और बनाए रखा जाए, एक इकाई या एक व्यक्ति जिसमें भारत के बाहर का निवासी हो, "RBI द्वारा अनुमत" कस्टोडियन "।
- सरकारी प्रतिभूति सरकार द्वारा पैसे उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, S.Secs टैक्स से मुक्त नहीं हैं।
- उन्हें आम तौर पर निवेश का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है क्योंकि वे सरकार द्वारा समर्थित हैं।
- डिफ़ॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य है।
- हालांकि, वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के अधीन हैं। इसलिए, वे पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका (CBSL) ने RBI से $ 400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा का निपटान किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका (CBSL) ने RBI से $ 400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा का निपटान किया।

- दोनों देशों ने शर्तों को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी।

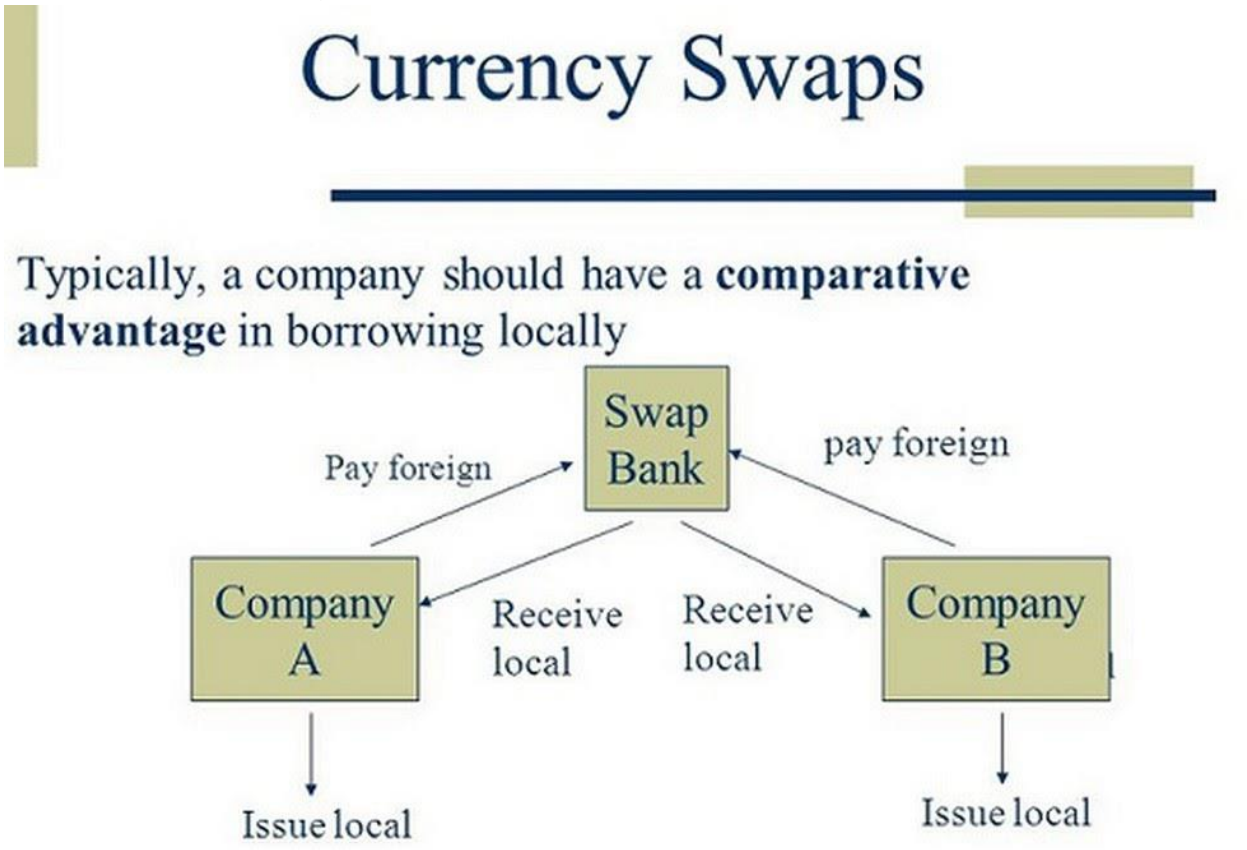

महत्वपूर्ण तथ्य

- महामारी के गंभीर आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए, CBSL ने 31 जुलाई, 2020 को तीन महीने की शुरुआती अवधि के लिए स्वैप की सुविधा प्राप्त की।
- इसके बाद, RBI ने CBSL के अनुरोध पर 1 फरवरी, 2021 तक तीन महीने का रोलओवर प्रदान किया।
- एक और विस्तार से आईएमएफ कार्यक्रम के लिए श्रीलंका को सफलतापूर्वक बातचीत के लिए कर्मचारी-स्तर के समझौते की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में श्रीलंका के पास नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मुद्रा विनिमय समझौतों में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शामिल होता है, जहां कोई देश अमेरिकी डॉलर की तरह तीसरे देश की मुद्रा की भागीदारी के बिना विनिमय की पूर्व निर्धारित दरों पर आयात और निर्यात के लिए भुगतान करते हैं।
- यह तीसरी मुद्रा के खिलाफ अस्थिरता के जोखिम को कम करता है और कई मुद्रा विनिमय में शामिल खामिओ को दूर करता है।

एक-व्यक्ति कंपनियां और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है

संदर्भ: अपने बजट भाषण में, केंद्रीय वित्त ने एक-व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) की स्थापना के मानदंडों को आसान बनाने के उपायों की घोषणा की।

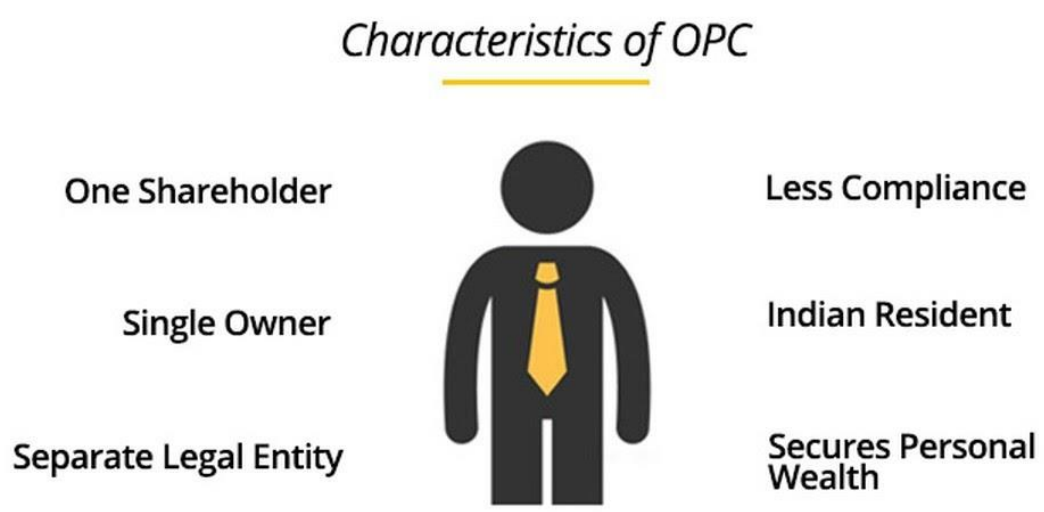

एक व्यक्ति कंपनी क्या है?

- जैसा कि नाम से पता चलता है, एक-व्यक्ति कंपनी एक कंपनी है जो केवल एक व्यक्ति द्वारा शेयरधारक के रूप में बनाई जा सकती है।
- इन कंपनियों को निजी कंपनियों के साथ विपरीत किया जा सकता है, जिन्हें शामिल करने के लिए न्यूनतम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है।
- हालांकि, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, ये निजी कंपनियों की तरह हैं।
- हालांकि, एक सामान्य कंपनी की तुलना में एकल-व्यक्ति कंपनी के लिए विनियामक प्रक्रिया बहुत अधिक सरल है
- ऐसा नहीं है कि एक अवधारणा के रूप में ओपीसी की शुरुआत से पहले व्यवसाय में आकांक्षाओं वाले व्यक्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी।
- एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति एकमात्र स्वामित्व मोड के माध्यम से व्यवसाय में आ सकता है, और यह एक रास्ता है जो अभी भी उपलब्ध है।

एकल-व्यक्ति और एकमात्र स्वामित्व कंपनी के बीच अंतर क्या है?

- एक एकल-व्यक्ति कंपनी और एकमात्र स्वामित्व कंपनी में काफी अंतर है कि उन्हें कानून की नजर में कैसे माना जाता है।
- एकल-व्यक्ति कंपनी के लिए, व्यक्ति और कंपनी को अलग-अलग कानूनी संस्थाएं माना जाता है।
- एकमात्र स्वामित्व है जहाँ मालिक और व्यवसाय को समान माना जाता है।
- यह एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि है जब यह व्यक्तिगत सदस्य या मालिक की देयता की बात आती है। किसी एक व्यक्ति की कंपनी में, एकमात्र मालिक का दायित्व उस व्यक्ति के निवेश तक सीमित होता है।
- एक एकल स्वामित्व सेट-अप में, हालांकि, मालिक की असीमित देयता है क्योंकि उन्हें अलग-अलग कानूनी संस्थाएं नहीं माना जाता है।

क्या यह एक नया विचार है?

- ऐसी अवधारणा कई देशों में पहले से मौजूद नहीं है।
- भारत में, अवधारणा को 2013 के कंपनी अधिनियम में पेश किया गया था।

- इसका परिचय जे.जे. के सुझावों पर आधारित था। कंपनी कानून पर ईरानी समिति की रिपोर्ट, जिसने 2005 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
- यह बताते हुए कि छोटे उद्यमों के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता थी, समिति ने कहा कि छोटी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, लेकिन उनके आकार के कारण, वे बड़े सार्वजनिक के रूप में अनुपालन आवश्यकताओं के समान स्तर पर बोझ नहीं डाल सकती थीं।
- रिपोर्ट ने, सूचना प्रौद्योगिकी के युग में लोगों के उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को एक आउटलेट के रूप में देने की बात करते हुए कहा, "यह उम्मीद करना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक उद्यमी जो अपने विचारों को विकसित करने और बाजार में भाग लेने में सक्षम है, व्यक्तियों के एक संघ के माध्यम से करना चाहिए।
- एक-व्यक्ति कंपनियों के लिए एक मामला बनाते हुए, समिति ने यह भी कहा, "इस तरह की इकाई को छूट के माध्यम से एक सरल शासन प्रदान किया जा सकता है, ताकि एकल उद्यमी को प्रक्रियात्मक मामलों पर अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को दूर करने के लिए मजबूर न किया जाए। "

समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई क्या थी?

- एक-व्यक्ति कंपनियों पर कानून, जिसके परिणामस्वरूप आकार लिया गया, ऐसी कंपनियों को कई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से छूट दी गई, और, कुछ मामलों में, छूट प्रदान की गई।
- उदाहरण के लिए, ऐसी कंपनी को वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता नहीं है, जो अन्य कंपनियों के लिए एक आवश्यकता है। एक-व्यक्ति कंपनी को अपने वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव और निदेशक दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि एक काफ़ी हैं।
- हालांकि, समिति ने आलोचना थी कि एक व्यक्ति कंपनी पर शासन करने वाले कुछ नियम प्रकृति में प्रतिबंधात्मक थे। इस वर्ष के केंद्रीय बजट ने इनमें से कुछ चिंताओं से निपटा है।

भारत में कितने ओपीसी हैं?

- 31 मार्च, 2015 तक ओपीसी की संख्या 2,238 (कुल 1 मिलियन कंपनियों में से) थी।
- कॉर्पोरेट सेक्टर पर मासिक सूचना बुलेटिन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2020 तक भारत में कुल 1.3 मिलियन सक्रिय कंपनियों में से 34,235 एक-व्यक्ति कंपनियां थीं।
- डेटा यह भी दर्शाता है कि आधे से अधिक ओपीसी व्यवसाय सेवाओं में हैं।

इस वर्ष के बजट में नए उपायों के साथ इन कंपनियों के लिए क्या बदलाव आया है?

- वित्त मंत्री ने बजट में जिन उपायों की घोषणा की है, उनमें से एक भुगतान पूंजी और टर्नओवर पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है।
- 2014 का नियम, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति-कंपनी उस स्थिति को समाप्त कर देगी, जब उसकी भुगतान की गई शेयर पूंजी औसतन 50 लाख से अधिक हो या पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए उसका औसत कारोबार 2 करोड़ से अधिक हो जैसी सीमा को हटा दिया गया है।
- प्रस्तावों में यह भी शामिल है, "182 दिनों से लेकर 120 दिनों तक एक भारतीय नागरिक को ओपीसी स्थापित करने के लिए रेजिडेंसी सीमा को कम करना और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में ओपीसी को शामिल करने की अनुमति देना।" इससे पहले, केवल एक भारतीय नागरिक और एक भारतीय निवासी एकल व्यक्ति कंपनी शुरू कर सकते थे।
- ये परिवर्तन उन कंपनियों के लिए पूंजी आधार और टर्नओवर सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ आते हैं जिन्हें छोटे 'के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वे थोड़ी देर के लिए आसान अनुपालन आवश्यकताओं का आनंद ले सकते हैं।

- पूंजी आधार की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है, और कारोबार की सीमा 2 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है।

निष्कर्ष

- छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रस्ताव को एक कदम के रूप में देखा जाता है।
- ये उन उद्यमिओ के लिए एक विकल्प है जो कोई बेवसाए शुरू करना चाहते हैं।

पंद्रहवां वित्त आयोग (15 वां एफसी)

संदर्भ: नवंबर 2017 में, यह 15 वां वित्त आयोग स्थापित किया गया था। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि को कवर करेंगी। इस आयोग की अध्यक्षता भारत के पूर्व संसद सदस्य और भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री एन.के.सिंह ने की थी।

आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था, एक 2020-21 के लिए और दूसरी 2021-22 से 2025-26 तक के पांच वर्षों की अवधि को कवर करने के लिए

विस्तार के लिए आधार

- सबसे पहले, जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर एक अनुमान लगाने की आवश्यकता थी।
- दूसरा, विकास में गिरावट और कम मुद्रास्फीति ने मामूली जीडीपी वृद्धि को मध्यम अवधि के जोखिम के अनुमानों को धीमा कर दिया है।
- अंत में, कर संग्रह और अधिक विशेष रूप से माल और सेवा कर के खराब राजस्व प्रदर्शन ने इस तथ्य के साथ संयुक्त रूप से कहा कि राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा समझौता 15FC की अनिश्चितताओं की अवधि केवल दो साल प्रभावी था
- यदि विस्तार के लिए नहीं है, तो वर्तमान परिदृश्य में मध्यम अवधि के अनुमानों को बनाने में गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ेगा।
- 2020-21 पर अंतरिम रिपोर्ट के लिए: यहां क्लिक करें

संसद में 2021-26 के लिए 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं

1. राज्यों के संघ के करों का लंबित विचलन

- इसने 41% पर ऊर्ध्वाधर विचलन को बनाए रखने की सिफारिश की है - 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी।
- यह 14 वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए विभाज्य पूल के 42% के समान स्तर पर है।
- इसने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य की बदलती स्थिति के कारण लगभग 1% का आवश्यक समायोजन किया है।
- XVFC के आकलन में, 5 साल की अवधि के लिए सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। उसमें से, डिविजनल पूल (सेस और सरचार्ज और कलेक्शन की लागत में कटौती के बाद) का अनुमान 103 लाख करोड़ है।
- राज्यों का 41 प्रतिशत विभाज्य पूल में हिस्सा 2021-26 अवधि के लिए 42.2 लाख करोड़ है।
- कुल अनुदान रु। 10.33 लाख करोड़ (बाद में विवरण) और रुपये का कर विचलन। 42.2 लाख करोड़, राज्यों को कुल हस्तांतरण 2021-26 की अवधि के दौरान विभाज्य पूल का लगभग 50.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- कुल XVFC स्थानान्तरण (विचलन + अनुदान) संघ की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों के लगभग 34 प्रतिशत का गठन करता है, जो संघ को अपनी संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय ढील प्रदान करता है।

2. क्षैतिज विचलन (राज्यों के बीच आवंटन):

- क्षैतिज विचलन के लिए, इसने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए 12.5% भारोत्तोलन, 45% आय, 15% आबादी और क्षेत्र, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10% और कर और राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% का सुझाव दिया है।
- क्षैतिज विचलन पर, जबकि XVFC ने सहमति व्यक्त की कि जनगणना 2011 की जनसंख्या के आंकड़े बेहतर ढंग से राज्यों की वर्तमान आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही इनाम के रूप में, जिन राज्यों ने जनसांख्यिकीय मोर्चे पर बेहतर काम किया है, उन्हें XVFC ने 12.5 प्रतिशत सौंपा है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की कसौटी पर वजन।
- XVFC ने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मानदंड को फिर से पेश किया है

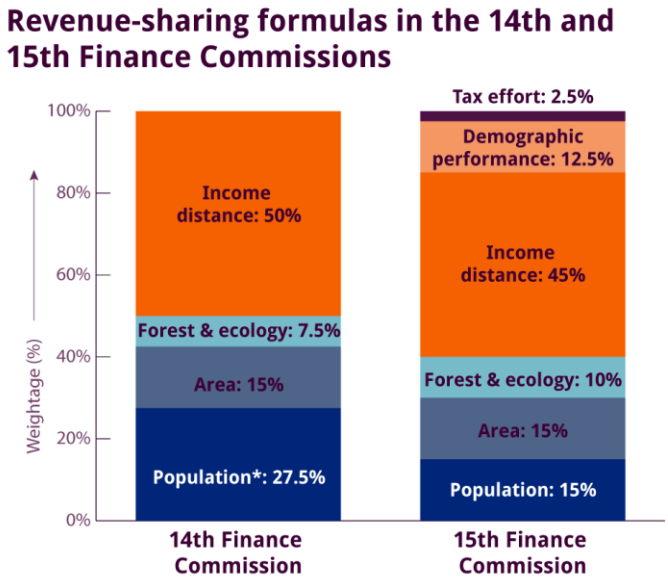

3. राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान

- राजस्व घाटा अनुदान राज्यों की राजकोषीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने राजस्व खातों पर पूरा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है, जो कि अपने स्वयं के कर और गैर-कर संसाधनों और कर विचलन पर विचार करने के बाद भी मिलते हैं।
- राजस्व घाटा राजस्व या वर्तमान व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कर और गैर-कर शामिल हैं।
- इसने में राजस्व में कमी के बाद लगभग वित्त वर्ष 2026 तक पांच साल की अवधि के लिए 2.94 लाख करोड़रुपये की सिफारिश की है।
- राजस्व घाटा अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 22 में 17 से घटकर, पुरस्कार अवधि का पहला वित्त वर्ष 2016 में।

4. राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान

ये अनुदान चार मुख्य विषयों के चारों ओर घूमते हैं।

- पहला सामाजिक क्षेत्र है, जहां इसने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है।
- दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहां इसने कृषि और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसमें देश की दो तिहाई आबादी, कुल कार्यबल का 70% और राष्ट्रीय आय का 46% हिस्सा शामिल है।
- तीसरा, शासन और प्रशासनिक सुधार जिसके तहत इसने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षात्मक जिलों और ब्लॉकों के लिए अनुदान की सिफारिश की है।
- चौथा, इसने बिजली क्षेत्र के लिए एक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकसित की है, जो अनुदान से जुड़ी नहीं है, लेकिन राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण, अतिरिक्त उधार खिड़की प्रदान करती है।

5. केंद्र के लिए राजकोषीय स्थान

- 15 वें वित्त आयोग का स्थानांतरण (विचलन + अनुदान) संघ के अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 34% है, जो अपने संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय स्थान छोड़ता है।
- संघ और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण पथ के लिए प्रदान की गई सीमा।
- बिजली क्षेत्र सुधारों में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त उधार कक्ष।
- XVFC ने माना है कि FRBM अधिनियम को एक बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता है और सिफारिश की है कि ऋण स्थिरता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लिए समय-सारणी की जांच एक उच्च-संचालित अंतर-सरकारी समूह द्वारा की जा सकती है।
- यह उच्चस्तरीय अंतर-सरकारी समूह को 15 वें वित्त आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख करने का काम सौंपा जा सकता है।
- राज्य सरकारें स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कोशिकाओं के गठन का पता लगा सकती हैं जो उनके उधार कार्यक्रम को कुशलता से चार्ट करेंगी।

6. स्थानीय सरकारों को अनुदान

- स्थानीय सरकारों को अनुदान का कुल आकार 2021-26 की अवधि के लिए 4.3 लाख करोड़।
- इन कुल अनुदानों में से 8,000 करोड़ रुपये नए शहरों के लिए उनके प्रदर्शन-आधारित अनुदान है और साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ है।
- 2.3 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 1 लाख करोड़ शहरी स्थानीय निकायों के लिए और स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़।
- शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, और प्रत्येक को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर अनुदान के प्रवाह के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग किया गया है।
- मूल अनुदान केवल उन शहरों / कस्बों के लिए प्रस्तावित हैं, जिनकी जनसंख्या दस लाख से कम है। मिलियन-प्लस शहरों के लिए, 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (MCF) के माध्यम से प्रदर्शन से जुड़े हैं।
- एमसीएफ राशि उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार और शहरी पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क को पूरा करने के लिए इन शहरों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है।

7. स्वास्थ्य

- XVFC ने सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाया जाना चाहिए।

- चिकित्सा डॉक्टरों की उपलब्धता में अंतर-राज्य असमानता को देखते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2 ए के तहत परिकल्पित है।
- पुरस्कार अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र को सहायता अनुदान कुल सहायता रु। 1 लाख करोड़, जो XVFC द्वारा अनुशंसित कुल अनुदान सहायता का 10.3 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान बिना शर्त होगा।
- XVFC ने रु। को कुल मिलाकर स्वास्थ्य अनुदान देने की सिफारिश की है। शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के लिए 70,051 करोड़, भवन उप-केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, ब्लॉक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां, प्राथमिक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता और ग्रामीण उप केंद्रों और पीएचसी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करना। ये अनुदान स्थानीय सरकारों को जारी किया जाएगा।

8. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

- भारत के सार्वजनिक खाते का गठन हो सकता है, एक समर्पित गैर-चूक योग्य निधि, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS)। 2021-26 की अवधि में प्रस्तावित एमएफडीआईएस का कुल सांकेतिक आकार रु। 2.3 लाख करोड़ रु।

9. आपदा जोखिम प्रबंधन

- आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शमन निधि की स्थापना की जानी चाहिए।
- शमन निधि का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाना चाहिए जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
- XVFC ने राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन के लिए 2021-26 की अवधि के लिए रु .6 लाख करोड़ के कुल कोष की सिफारिश की है, जिसमें से संघ का हिस्सा 1.2 लाख करोड़ और राज्यों का हिस्सा 37,552 करोड़।
- XVFC ने कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 11,950 करोड़, अर्थात् एनडीआरएफ के तहत दो (विस्तार और आधुनिकीकरण और फायर सेवाओं के विस्थापन और विस्थापन से प्रभावित लोगों का पुनर्वास) और चार एनडीएमएफ के तहत (कैटेलिटिक असिस्टेंस टू ट्विस्ट मोस्ट ड्रोन-प्रोन स्टेट्स, मैनेजिंग सिस्मिक एंड लैंडस्लाइड रिस्क) टेन हिल स्टेट्स में, सात सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करना और कटाव को रोकने के लिए शमन उपाय)।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- एफबीबी समीक्षा पर एन के सिंह समिति की रिपोर्ट

कर्नाटक में लिथियम रिज़र्व

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - भूगोल और जीएस- III - संसाधन

समाचार में-

- परमाणु खनिज निदेशालय ने कर्नाटक में लिथियम रिज़र्व के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

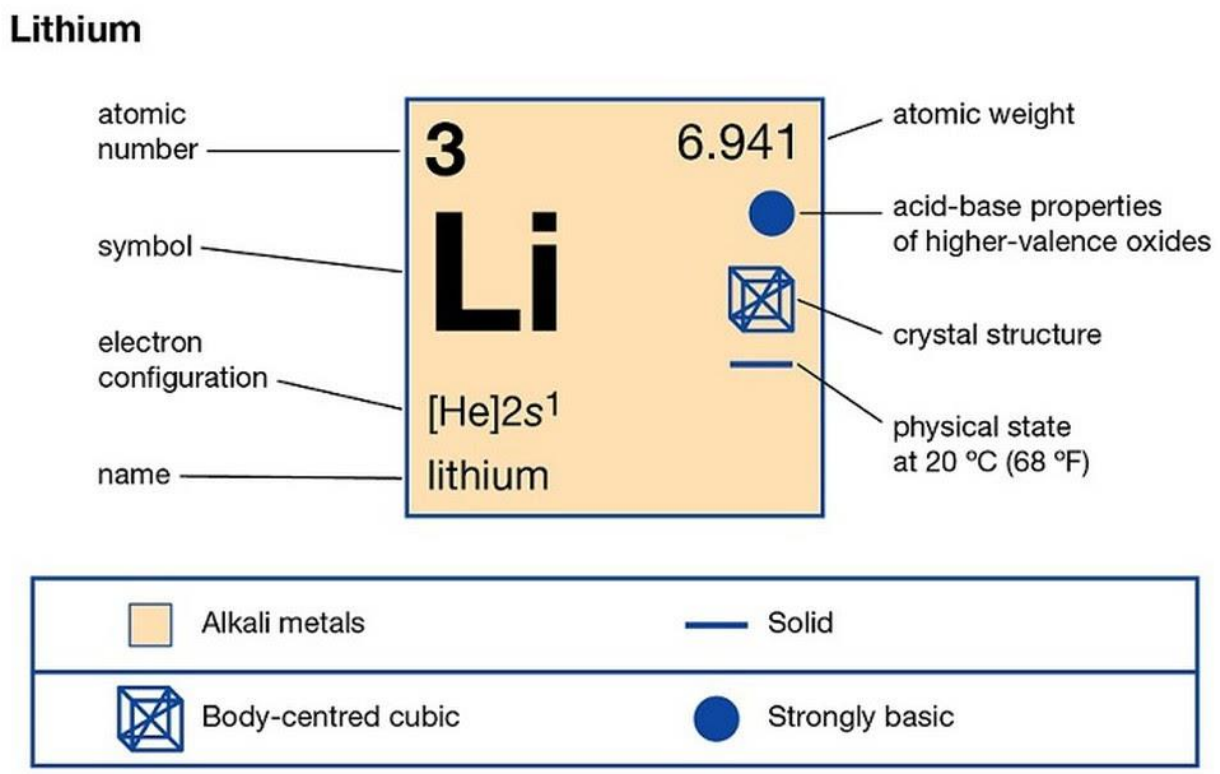

महत्वपूर्ण तथ्य

- अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय (एएमडी), परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की एक घटक इकाई दो एजेंसियां हैं जो खनिज अन्वेषण में शामिल हैं।
- नई प्रौद्योगिकियों के लिए लिथियम एक प्रमुख तत्व है।
- सिरेमिक, ग्लास, दूरसंचार और एयरोस्पेस उद्योगों में इसका उपयोग होता है।
- थर्मोन्यूक्लियर एप्लिकेशन लिथियम को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत एक "निर्धारित पदार्थ" बनाता है जो देश के विभिन्न भूवैज्ञानिक डोमेन में लिथियम की खोज के लिए एएमडी को अनुमति देता है।
- हाल ही में, लीला की खोज और Allapatna के संसाधन - Marlagalla सेक्टर, मंड्या जिले, कर्नाटक में समाचार आइटम विभिन्न मीडिया में प्रकाशित किए गए हैं।
- कुछ मीडिया में, लिथियम धातु के अनुमानों को मांड्या जिले में सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र के एक छोटे पैच में 14,100 टन के रूप में उच्च रूप में उद्धृत किया गया है।
- निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अन्वेषण प्रयासों ने अब तक ~ 1600 टन लिथियम को निम्न श्रेणी (विश्वास के निम्न स्तर) में स्थापित किया है।

बैंकों का निजीकरण

संदर्भ: 2021-22 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (IDBI बैंक के अलावा) और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की है।

विनिवेश के लिए एक स्पष्ट नीति रोडमैप तैयार करते हुए, सरकार ने चार रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें उनकी न्यूनतम उपस्थिति होगी।

1. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा;

2. परिवहन और दूरसंचार;
3. बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज;
4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।
अन्य क्षेत्रों के सभी सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा।

क्या आपको पता है?

- पीएसयू बैंक दोहरे नियंत्रण में हैं, आरबीआई बैंकिंग परिचालन की निगरानी कर रहा है और वित्त मंत्रालय स्वामित्व मुद्दों को संभाल रहा है।
- कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% से नीचे लाने का प्रस्ताव दिया था - नरसिम्हम समिति ने 33% और पी जे नायक समिति ने 50% से नीचे का सुझाव दिया।

कौन से दो PSB हैं जिन्हें निजीकृत किया जाएगा?

- वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक और एसबीआई के अलावा दस राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
- जबकि सरकार एसबीआई सहित शीर्ष तीन को छूने की संभावना नहीं है, छोटे और मध्यम स्तर के बैंकों का निजीकरण होने की संभावना है।
- सरकार ने यह खुलासा नहीं किया है कि इस वित्तीय वर्ष में किन दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
- अब जिन दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, उन्हें एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा जिसमें नीति आयोग सिफारिशें करेगा, जिन्हें विनिवेश और फिर वैकल्पिक तंत्र (या मंत्रियों के समूह) पर सचिवों के एक मुख्य समूह द्वारा विचार किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के कारण

- **पिछले सुधार उपायों के परिणाम नहीं मिले हैं:** केंद्र सरकार द्वारा वर्षों तक पूंजीगत निवेश और शासन व्यवस्था में सुधार किये जाने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। इनमें से कई सार्वजानिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियाँ निजी बैंकों की तुलना में काफी अधिक हैं और साथ ही उनकी लाभप्रदता, बाज़ार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है।
- **दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा:** दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से एक दीर्घकालिक परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों की परिकल्पना की गई है। यह कार्य या तो मज़बूत बैंकों को समेकित करके या फिर बैंकों का निजीकरण कर किया जाएगा।
- **बैंकों को मज़बूती प्रदान करना:** सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा साथ ही निजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है।
- **COVID के बाद के परिदृश्य में बैंकों का युक्तिकरण:** कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विनियामक छूट हटाए जाने के बाद उम्मीद थी कि बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। RBI की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5 प्रतिशत हो सकता है। इसका अर्थ होगा कि सरकार को फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के कमज़ोर बैंकों में इक्विटी को इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी।
- **वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन:** निजीकरण और एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव जो पूरी तरह से बैंकों के स्वामित्व में है, वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों के लिए बाजार के नेतृत्व वाले समाधान खोजने के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

- **बाज़ार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी:** बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में निजी बैंकों की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 21.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में 36 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 74.28 प्रतिशत से गिरकर 59.8 प्रतिशत पर पहुँच गई है।

बैंकों के बढ़ते निजीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

1. निजी बैंक बिना दोष के नहीं हैं

- पिछले कुछ वर्षों में, निजी बैंकों के प्रदर्शन पर कुछ सवाल उठे हैं, जयादा शासन के मुद्दों पर।
- आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर को कथित रूप से संदिग्ध ऋण देने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।
- यस बैंक के सीईओ राणा कपूर को आरबीआई द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया गया था और अब विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है।
- हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनका डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर में विलय हो गया।
- एक्सिस बैंक की पूर्व एमडी शिखा शर्मा को भी विस्तार से वंचित कर दिया गया।
- इसके अलावा, जब आरबीआई ने 2015 में बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा का आदेश दिया, तो यस बैंक सहित कई निजी क्षेत्र के बैंक एनपीए की रिपोर्टिंग कर रहे थे।

2. 1960 के दशक की गलतियों को दोहराते हुए निजी बैंकों के खतरे

- व्यापक रूप से यह धारणा है कि निजी क्षेत्र तब अपनी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त रूप से अवगत नहीं होती है और लाभ से अधिक चिंतित थी।
- इसने निजी बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए तैयार नहीं किया क्योंकि इससे लेनदेन की लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा।
- शाखाओं का विस्तार ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में था और ग्रामीण, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बिना रुके जारी रहा।

निष्कर्ष

सरकार की प्रारंभिक योजना के चार निजीकरण थे। पहले दो के साथ सफलता के आधार पर, सरकार के अगले वित्तीय वर्ष में अन्य दो या तीन बैंकों में विनिवेश के लिए जाने की संभावना।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बैंक के रूप में कॉर्पोरेट: यहाँ क्लिक करें

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक 2021 हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करना है।
- इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के प्रावधान हैं।
- यह सुलह की कार्यवाही आयोजित करने के कानून को परिभाषित करता है।
- यह निर्दिष्ट करता है कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो तो मध्यस्थता पुरस्कार पर स्टे लगाई जा सके।

- यह बदलाव 23 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी होगा।
- यह मध्यस्थों के लिए अनुसूची निकालता है।
- नियमों के तहत मध्यस्थता की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंड निर्दिष्ट किए जाएंगे।

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विनिर्माण; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद (टी एंड एन उत्पाद) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य भारत में टी एंड एन उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है।
- यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करता है।
- यह योजना निर्यात को भी प्रोत्साहित करेगी।
- MSME के लिए 7% से 4% और बेस ईयर से 5 साल ऊपर 6% से 4% तक इंसेंटिव वाले के लिए 100 करोड़।
- एमएसएमई और गैर एमएसएमई श्रेणियों के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक निवेश वाले आवेदकों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा।

संबंधित आलेख:

- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 10 और क्षेत्रों के लिए स्वीकृत: यहां क्लिक करें
- भारी मात्रा में ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजनाएं संशोधित

जेबी एक्का समिति का गठन किया जाए

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- असम के छोटे चाय श्रमिकों के समान वेतन के लिए प्रधान सचिव डॉ. जेबी एक्का के अधीन एकल समिति बनाई जाएगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- साथ ही, असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी 167 रुपये से बढ़ाकर 217 रुपये प्रति दिन करने की घोषणा की।
- चाय बागान प्रबंधन सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान करते हैं।
- असम का चाय जनजाति समुदाय भी शोषण , आर्थिक पिछड़ेपन , ख़राब स्वास्थ स्थितियों और कम साक्षरता दर से ग्रसित है।
- केंद्रीय बजट 2020-21 में, असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी।

संबंधित आलेख:

- वृक्षारोपण उत्पादों के निर्यात को बेहतर बनाने के लिए पिछड़े और आगे के विकास की आवश्यकता।
- असम में राजमार्ग परियोजनाएँ

RBI ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की।
- RBI के पास 3 लोकपाल हैं- बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (यानी NBFC) और डिजिटल लेनदेन।
- एक आम आदमी अपनी शिकायतों के लिए इन लोकपालों से संपर्क कर सकता है।
- इन योजनाओं को एक एकल योजना में विलय और एकीकृत किया जा रहा है जिसे जून 2021 से शुरू किया जाएगा।
- शिकायतों की प्राप्ति में लगभग 65% की वृद्धि हुई।
- उनमें से 92% को हल कर दिया गया है।

संबंधित आलेख

- एनबीएफसी के लिए कठिन नियामक ढांचा
- NBFCs, UCBs के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा मानदंड

उबर ड्राइवरों को श्रमिक माना जायगा न कि फ्रीलांस ठेकेदार : यूके सुप्रीम कोर्ट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - इंटरनेशन संबंध; & जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उबर ड्राइवरों को श्रमिक माना जाना चाहिए न कि फ्रीलांस ठेकेदार।
- यह आदेश उन्हें रोज़गार संबंधी सभी लाभों जैसे न्यूनतम वेतन, वार्षिक पत्ते, और बीमा के लिए योग्य बनाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस निर्णय के साथ, उबेर और अन्य सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफ़ॉर्म भी भारत में कानूनी और नियामक चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।
- इसके अलावा, भारतीय बजट 2021-22 में यह अनिवार्य है कि न्यूनतम मजदूरी पर कानून अब उबर जैसे प्लेटफार्मों से जुड़े सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगा।
- ऐसे कर्मचारियों को अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा कवर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नवंबर 2020 में, सरकार उबर और ओला जैसे ऐप के लिए विशिष्ट मानदंडों के साथ सामने आई थी।
- उनके तहत, ये ऐप ड्राइवर भागीदारों से प्रति सवारी अधिकतम 20% कमीशन वसूल सकता है, जबकि प्रति दिन काम के घंटे की कुल संख्या को कैपिंग भी करता है।
- अधिकतम किराया भी प्रदान किया जाता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म उच्च मांग पीक घंटों के दौरान भी ग्राहकों को चार्ज कर सकते हैं।
- उन्हें ड्राइवरों को बीमा उपलब्ध कराना होगा।

क्या आप जानते हो?

- एक गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थायी पद सामान्य और संगठन अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करते हैं।

संबंधित आलेख

- गिग इकोनॉमी और प्रपोजल -22: यहां क्लिक करें
- टमटम अर्थव्यवस्था: यहां क्लिक करें
- गिग वर्कर्स और इसके तिरछे शब्द: यहां क्लिक करें

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी।

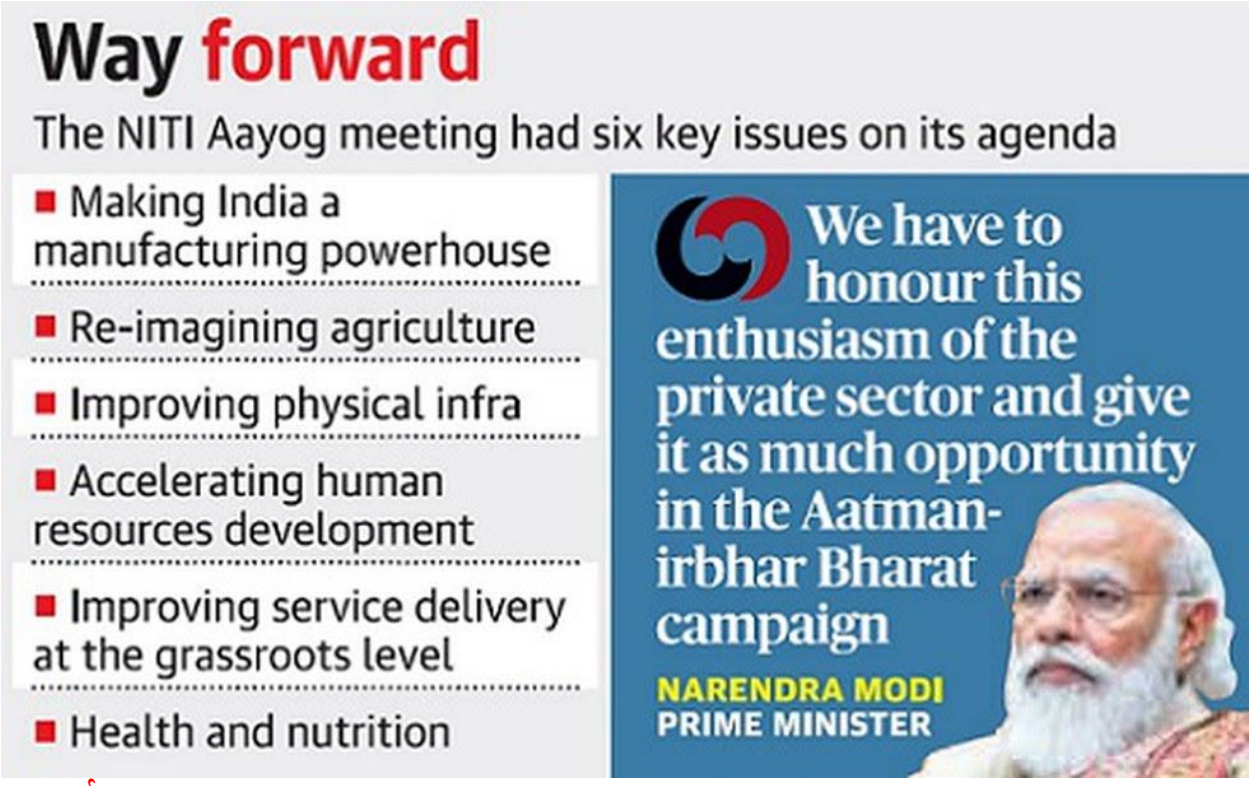

महत्वपूर्ण तथ्य

- गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं।
- छठी परिषद की बैठक के लिए एजेंडा में निम्नलिखित चीजे शामिल थे

1. मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस
2. कृषि में पुनः सुधार
3. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार
4. मानव संसाधन विकास में तेजी लाना
5. ग्रासरूट स्तर पर सेवा वितरण में सुधार
6. स्वास्थ्य और पोषण

कारीगर आधारित SFURTI क्लस्टर का उद्घाटन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये 18 राज्यों में विस्तृत 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति (SFURTI) क्लस्टर्स का उद्घाटन किया।
- MSME मंत्रालय पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करने और उनकी आय को बढ़ाने के लिये 'स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़' (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries- SFURTI) को लागू कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- MSME मंत्रालय ने क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में इस योजना को प्रारंभ किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) खादी के साथ-साथ ग्रामोद्योग उत्पादों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है।
- SFURTI क्लस्टर दो प्रकार के होते हैं
  1. नियमित क्लस्टर (500 कारीगर), जिनको 2.5 करोड़ रुपए तक की सरकारी सहायता दी जाती है।
  2. मेजर (Major) क्लस्टर (500 से अधिक कारीगर) जिनको 5 करोड़ रुपए तक की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।
- कारीगरों को SPVs में व्यवस्थित किया जाता है जो निम्न हैं
  1. सोसायटी (पंजीकरण) अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी
  2. एक उपयुक्त क़ानून के तहत सहकारी समिति
  3. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 के 18) की धारा 465 (1) के तहत एक निर्माता कंपनी
  4. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या (v) एक ट्रस्ट के तहत।

संबंधित आलेख:

- मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तनों में कारीगरों का समर्थन करने के लिए दिशानिर्देश

द इंडिया टॉय फेयर 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- भारतीय प्रधानमंत्री 27 फरवरी को इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना।
- यह खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों आदि सहित सभी हितधारकों को एकीकरण किया जायगा। सतत संबंध रहेगा जो उद्योग के समग्र विकास के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे।

क्या आप जानते हो?

- हाल ही में 'टॉयकाथॉन' अभिनव खिलौनों / खेल अवधारणाओं के लिए स्थापित किया गया था।
- टॉयकाथॉन-2021 में भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और लोकाचार पर आधारित उपन्यास टॉय एंड गेम्स की अवधारणा के लिए भारत के अभिनव सोच को बढ़ावा देने की कल्पना की गई है।

एकीकृत बांस उपचार संयंत्र का उद्घाटन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- असम के गुवाहाटी के पास बिरनीहाट में नॉर्थ ईस्ट बेंत और बांस विकास परिषद (NECBDC) में एकीकृत बांस उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

- **मंत्रालय:** उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय (DoNER)

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- संयंत्र वैक्यूम-दबाव-संसेचन तकनीक पर आधारित है।
- राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) और उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) द्वारा वित्त पोषित।
- यह केंद्र सरकार की एक पहल है जो भारत को बांस उद्योग में आत्मनिर्भर बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश NECBDC के सहयोग से तीन बांस क्लस्टर स्थापित करेगा।
- इन समूहों के तहत क्रमशः अगरबत्ती, टोकरी और लकड़ी का कोयला उत्पादित किया जाएगा।
- घर में उगने वाले बांस को 100 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया।
- COVID- महामारी के दौरान, अन्य देशों से आने वाली अगरबत्ती पर आयात शुल्क लगभग 35% तक बढ़ा दिया गया।
- यह बांस से बनी अगरबत्तियों के आयात को हतोत्साहित करेगा और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा।

संबंधित आलेख:

- बैम्बू शूट लॉन्च किए गए सबसे सस्ते इम्यूनिटी बूस्टर्स में से एक है।

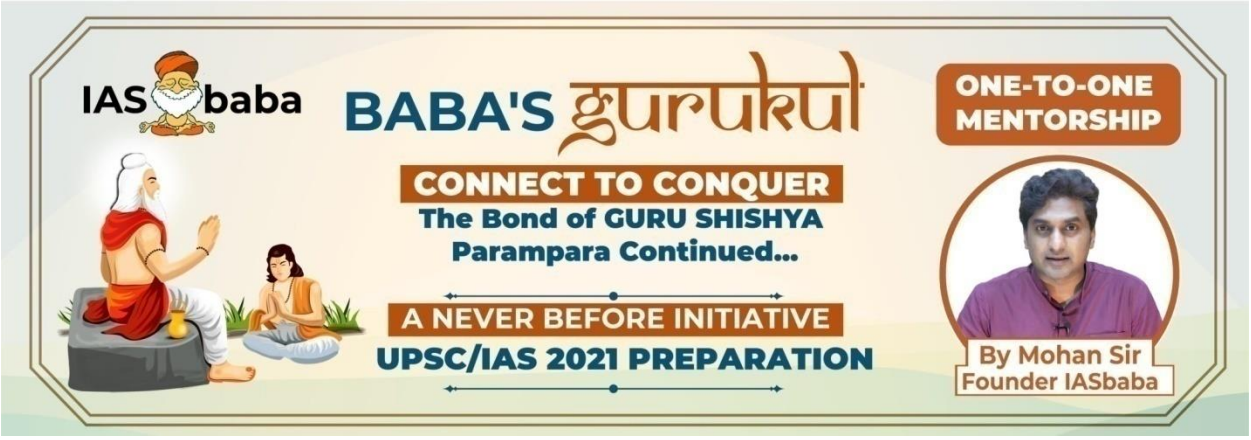

कृषि

कृतग्य: एग्री इंडिया हैकथॉन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एग्री इंडिया हैकथॉन के बारे में लोकसभा को सूचित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में KRITAGYA राष्ट्रीय स्तर हैकथॉन को आयोजन शुरू किया।
- कृषि-हैकथॉन आयोजन के लाभ हेतु छात्रों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने नवीन दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए संकायों, नवप्रवर्तकों को अनुमति देना चाहिये।
- आईसीएआर ने अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) के माध्यम से एक संस्थागत यंत्र स्थापित किया है ताकि कृषि क्षेत्र की समस्याओं का सामना किया जा सके।

प्रति बूंद अधिक फसल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) देश के सभी राज्यों में 2015-16 से 'प्रति बूंद अधिक फसल' केंद्र की प्रायोजित योजना को देश में लागू कर रही है।

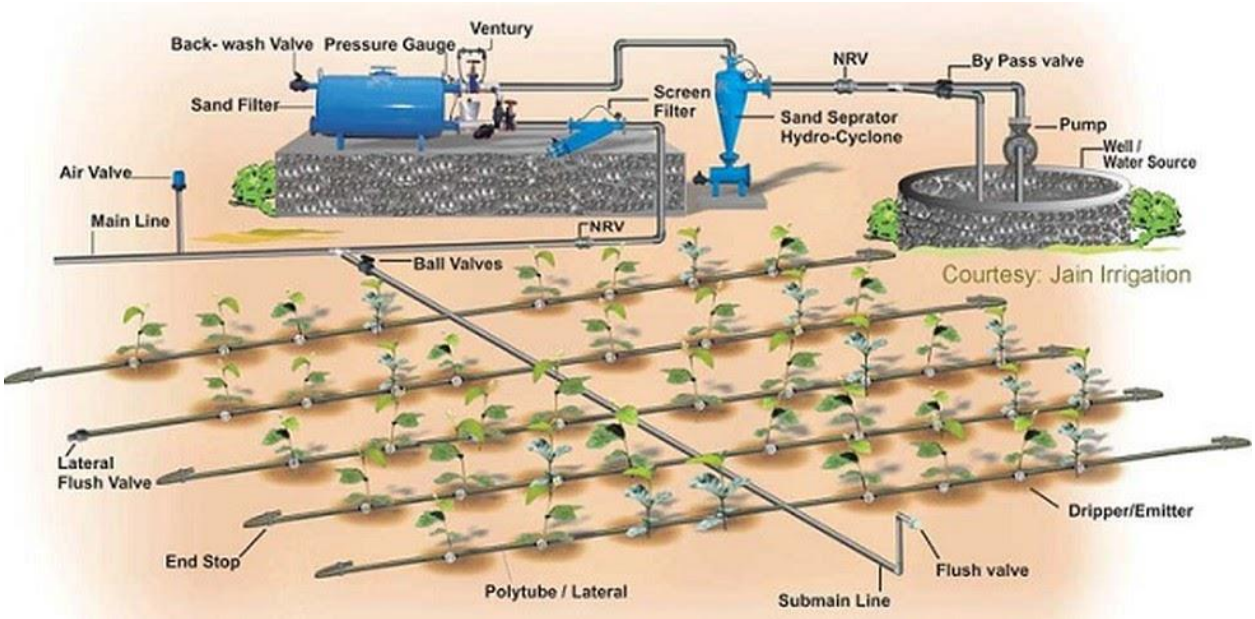

महत्वपूर्ण तथ्य

- ड्रिप सिंचाई प्रणाली निर्माताओं और किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि यह जल उपयोग दक्षता और उत्पादकता को बढ़ा कर स्पष्ट लाभ प्रदान करने में सक्षम है।
- सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा, यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण, सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण या जल संरक्षण / प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करेगा।

- प्रति बूंद अधिक फसल योजना को अटल भुजंग योजना (ABHY), नमामि गंगे जिलों, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, उत्तर प्रदेश महाभियान (पीएम-कुसुम), वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तथा PMKSY के वाटरशेड विकास घटकों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई सघन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
- 2018-19 के दौरान देश में माइक्रो इरीगेशन को प्रोत्साहन देने की उद्देश्य से नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपए का सृजन किया गया।
- राज्य सरकार को दिए गए ऋण पर सरकार MIF के तहत 3% ब्याज देती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY)

- PMKSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है
- 2015 में लॉन्च की गयी
- **आदर्श वाक्य**: हर खेत को पानी
- **उद्देश्य**: (1) सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्रों का विस्तार करना, खेतों में पानी इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना (2) सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का दोहन करके सुरक्षात्मक सिंचाई बनाना; (3) सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना तथा हर बूँद अधिक फसल आदि शामिल हैं।

संबंधित आलेख:

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जियो टैगिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन: यहां क्लिक करें

सोयाबीन के लिए कालाहांडी में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - कृषि

समाचार में-

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा को सोयाबीन के लिए कालाहांडी में एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने प्रावधान रखा गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ओडिशा का कालाहांडी जिला बहुत सीमित पैमाने पर सोयाबीन का उत्पादन करता है।
- 1987 में आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर (मध्य प्रदेश) फसल पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करने के लिए सोयाबीन पर एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान की स्थापना की।
- इसके अलावा, 1967 से आईसीएआर देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थान-विशेष उच्च उपज वाली किस्मों और उत्पादन तकनीकों को विकसित करने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के सहयोग से सोयाबीन पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) को लागू कर रहा है।
- सोयाबीन पर ICAR-AICRP का ओडिशा विश्वविद्यालय और भुवनेश्वर विश्वविद्यालय के तहत क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्टेशन, भवानीपटना (कालाहांडी) में एक स्वैच्छिक केंद्र है।
- यह स्टेशन ओडिशा के गर्म और नम उप-आर्द्र जलवायु के लिए सोयाबीन पर आवश्यकता-आधारित और स्थान-विशिष्ट अनुसंधान का कार्य कर रहा है, जिसमें कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सोयाबीन या सोयाबीन (ग्लाइसिन अधिकतम) पूर्वी एशिया में उगने वाली एक प्रजाति है, जो व्यापक रूप से अपने खाद्य फलियों के लिए उगाया जाता है।

- सोयाबीन के पारंपरिक अधूरे भोजन में सोया दूध शामिल है, जिससे टोफू और टोफू त्वचा बनाई जाती है।
- सोयाबीन में अधिक मात्रा में फाइटिक एसिड, खनिज आहार और विटामिन बी होती हैं।
- सोया वनस्पति तेल, जिसका उपयोग खाद्य और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जो यह फसल की प्रसंस्करण का एक अन्य उत्पाद है।
- फार्म के जानवरों के लिए सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, जो बदले में मानव उपभोग के लिए पशु, प्रोटीन का उत्पादन करते है।
- **खेती की स्थिति:** सोयाबीन की खेती के लिए गर्म मौसम की आवश्कता होती है इसकी अच्छी पैदावार 20 से 30^0C डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच अच्छी होती है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 40^0C से अधिक का तापमान इसकी वृद्धि रोक देता है।
- ये मिट्टी की एक विस्तृत श्रृंखला में विकसित होते हैं, अच्छी कार्बनिक सामग्री के साथ नम जलोढ़ मिट्टी में अधिक्तम वृद्धि होते है।
- अधिकांश फलियां जैसे सोयाबीन, जीवाणु ब्रैडीराइज़ोबियम जपोनिकम के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं।

संसद ने कृषि यंत्रीकरण के बारे में जानकारी दी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था; कृषि

समाचार में-

- भारत सरकार ने संसद को फार्म मशीनीकरण को बढ़ावा देने की पहल के बारे में सूचित किया।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- 2014-15 में भारत सरकार द्वारा एक विशेष समर्पित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) शुरू की गई है।
- **उद्देश्य:** कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए कृषि मशीनों को सुलभ और सस्ती बनाना तथा हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरण और फार्म मशीनरी बैंकों के लिए केन्द्र बनाना।
- व्यक्तिगत किसानों को विभिन्न अनुदानित कृषि उपकरण और मशीनों का वितरण भी इस योजना के तहत होने वाली गतिविधियों में से एक है।
- 2021-22 के लिए SMAM के लिए 1050 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था।
- **महत्व:** कृषि क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट की दक्षता में सुधार करने में योगदान देती है जिससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है।

मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - कृषि

समाचार में-

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा को मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के बारे में जानकारी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सरकार द्वारा मखाना, दरभंगा (बिहार) के लिए आईसीएआर-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एनआरसी) को मंजूरी दी। भारत में, मकई फसल के संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए 9 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) के दौरान एक नई योजना के रूप में हुई।
- हालांकि 10 वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान, मखाना के लिए एनआरसी को विलय कर दिया गया और बिना शासनादेश को पूर्वी क्षेत्र (आरसीईआर), पटना के आईसीएआर-रिसर्च कॉम्प्लेक्स के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया।
- विशेष रूप से (दरभंगा) मिथिला, मखाना के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में, मखाना की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में होती है।
- दुनिया भर में अकेले बिहार कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत मखाना का उत्पादक है।
- यह निम्फेशिया परिवार से है।
- यह एक बारहमासी पौधा है।
- यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में तालाबों, दलदलों और आर्द्रभूमि जैसे स्थिर पानी में कमल के समान उगता है।

उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस - III - पर्यावरण

समाचार में-

- पाँच दशकों में की गई जाँच ने संकेत दिया है कि अकेले नाइट्रोजन उर्वरकों के निरंतर उपयोग से मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होती जाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर राष्ट्रीय मिशन ने मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उर्वरक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया।
- परमपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) जैविक खेती को बढ़ावा देती है।
- उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCD-NER) जैविक खेती को बढ़ावा देता है।
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित किया जा रहा है।

संबंधित आलेख:

- जीरो घाटी के किवी: यहाँ क्लिक करें

समुद्री शैवाल मिशन वाणिज्यिक समुद्री शैवाल की खेती के लिए शुरू

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - कृषि; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) ने एक समुद्री शैवाल मिशन शुरू किया।
- **उद्देश्य**: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री शैवाल की वाणिज्यिक खेती और महत्वपूर्ण तथ्य के लिए इसका प्रसंस्करण करना।

मिशन निम्नलिखित गतिविधियाँ का कार्य करेगा

- भारतीय तटों पर निकटवर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री शैवाल की खेती के लिए एक हेक्टेयर से अधिक के मॉडल प्रदर्शन खेतों की स्थापना करना।
- बड़े पैमाने पर खेती के लिए बीज सामग्री की आपूर्ति के लिए समुद्री शैवाल नर्सरी की स्थापना करना।
- (I) सीडलिंग आपूर्ति सुविधा (ii) प्रसंस्करण के लिए समुद्री शैवाल की खेती
- पौधों की तीव्र वृद्धि (एसएपी) और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड जैसे अगर, अग्रोस, कैरेजेनन और एल्गिन से ताजा समुद्री शैवाल के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना।

मिशन के लाभ

- एक अनुमान के अनुसार, यदि भारत के EEZ क्षेत्र में 5% खेती की जाती है, तो यह (1) 50 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर करेगा; (2) नए समुद्री शैवाल उद्योग की स्थापना; (3) राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान; (4) समुद्र उत्पादकता में वृद्धि; (5) शैवाल वृद्धि को कम करने, (6) कार्बन अनुक्रम में वृद्धि; (7) 6.6 बिलियन लीटर का जैव-इथेनॉल प्रदान करना।

क्या आप जानते हो?

- लगभग 32 मिलियन टन के वैश्विक समुद्री शैवाल उत्पादन में से, 12 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास ताजे वजन का मूल्य है।
- चीन ~ 57%, इंडोनेशिया ~ 28% का उत्पादन करता है, जबकि भारत में ~ 0.01-0.02% की मात्र हिस्सेदारी है।

कृषि-बाजार की स्वतंत्रता: चीन और इज़राइल से सबक

संदर्भ: नए बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध हमें भारत की कृषि प्रणाली की तुलना अन्य देशों में मौजूद लोगों के साथ करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।

क्या आपको पता है?

- सभी तीन देशों - भारत, चीन और इजरायल ने 1940 के अंत में अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू की, लेकिन आज डॉलर के संदर्भ में चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग पांच गुना है, और इजरायल भारत से लगभग 20 गुना अधिक है।
- 2015 में पूर्ण गरीबी मुख्य गणना अनुपात $ 1.9 प्रति दिन (2011 क्रय शक्ति समता) की परिभाषा केवल चीन में 0.7 प्रतिशत थी, जबकि 2015 में भारत की 13.4 प्रतिशत थी।

भारतीय कृषि-नीतियों की समस्याएं

- भारतीय कृषि-खाद्य नीतियां "गरीबों की रक्षा" करने के दृष्टिकोण के साथ अधिक उपभोक्ता-केंद्रित रहीं। इस प्रक्रिया में, उन्होंने किसानों को कभी भी भारत या विदेश में मुक्त बाजारों से प्राप्त सर्वोत्तम मूल्यों का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी।
- निर्यात नियंत्रण, व्यापारियों पर स्टॉक सीमा, आंदोलन प्रतिबंध आदि सभी मूल्य वृद्धि के संकेत पर जारी रहे।
- इन सबका शुद्ध परिणाम किसानों की आय कम रही और ऐसा भूमिहीन कृषि-मजदूरों ने किया।
- आज, भारतीय कृषि खेती करने वालों की तुलना में अधिक कृषि-श्रमिकों (55 प्रतिशत) से दुखी, भारी सब्सिडी द्वारा समर्थित, जो गरीबी के निम्न-स्तर के संतुलन में हैं।

चीन का केस स्टडी

- **कृषि-उत्पादन:** चीन छोटे कृषि योग्य क्षेत्र से भारत की तुलना में तीन गुना अधिक कृषि उत्पादन करता है।
- **खंडित भूमि धारक का समान मामला:** चीन में 2016-18 में औसत होल्डिंग आकार सिर्फ 0.9 हेक्टेयर था, जो 2015-16 में भारत के 1.08 हेक्टेयर से छोटा था। इसलिए, भूमि का आकार कृषि-विकास के लिए एक बड़ी बाधा नहीं है।
- **सुधारों की शुरुआत:** चीन ने 1978 में अपने कृषि सुधारों को शुरू करते हुए अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इसने भूमि जोत के अपने कम्यून सिस्टम को ध्वस्त किया और कृषि-बाजारों को मुक्त कर दिया जिसने किसानों को उनकी उपज के लिए बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करने की अनुमति दी।
- **कृषि-विकास:** शुरुआती सुधारों के परिणामस्वरूप, 1978-84 में चीन में किसानों की आय लगभग 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, जो छह वर्षों में दोगुने से अधिक थी। भारत में, 1991 के सुधारों ने कृषि को दरकिनार करते हुए कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव थे जो विनिर्मित वस्तुओं पर शुल्क कम किये।
- **विनिर्माण वृद्धि के लिए फाउंडेशन:** शुरुआती कृषि-सुधार की सफलता ने जनता को प्राप्त होने वाले सुधारों के लिए राजनीतिक वैधता प्रदान की और औद्योगिक वस्तुओं की मांग की तथा चीन में विनिर्माण क्रांति के बीज बोए।
- **आर्थिक योगदान:** भारत में कृषि की कुल जीडीपी में केवल 17 प्रतिशत की तुलना में कृषि का योगदान 8 प्रतिशत है।
- **रोजगार:** चीन का लगभग 26 प्रतिशत कार्यबल कृषि में है जबकि भारत अभी भी 42 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न है।

इज़राइल का केस स्टडी

- **जल लेखांकन:** इसने कृषि में उच्च मूल्य वाली फसलों (खट्टे फल, खजूर, जैतून) की खेतीके लिए रेगिस्तान को उपजाऊ भूमि में बदलकर पानी की हर बूंद का उपयोग किया और समुद्र के पानी के डी-सैलिसिन द्वारा कृषि के लिए शहरी अपशिष्ट जल को रिसाइकिल किया।
- **भारत के भूजल में कमी:** यह पंजाब जैसे राज्य में बहुत खतरनाक है जहां लगभग 80 प्रतिशत ब्लॉक में अति दोहन, जिसका अर्थ है कि पानी की निकासी रिचार्ज से बहुत अधिक होना।
- जब तक भारत कृषि के लिए मुफ्त बिजली की नीति से दूर नहीं होता तब तक किसानों को पानी बचाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

आगे की राह

- भारतीय कृषि में अगले 15-20 वर्षों में अपने उत्पादन को दोगुना या तीन गुना करने की क्षमता है। कई देशों ने इसे किया है और हम भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे कृषि-खाद्य नीति की रूपरेखा नाटकीय रूप ले।
- सब्सिडी से लेकर निवेश- उन्मुख होने तक
- उपभोक्ता-उन्मुख होने से लेकर निर्माता-उन्मुख होने तक
- कारखानों और विदेशी बाजारों के साथ खेतों को जोड़कर आपूर्ति-उन्मुख होने से मांग-संचालित होने तक
- व्यवसाय होने से लेकर एक नवाचार-केंद्रित प्रणाली तक

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- किसान खेत कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं: यहां और यहां क्लिक करें
- पहले की सरकार की वार्ता विफल क्यों हुई: यहाँ क्लिक करें
- विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक समाधान क्या है: यहां क्लिक करें

कृषि ने रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - कृषि; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) को दूरस्थ रूप से पायलट विमान प्रणाली (RPAS) के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आरपीएएस का उपयोग अब प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कृषि क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए किया जाता है।
- छूट अनुमति जारी करने की तारीख से एक वर्ष से मान्य होगी।

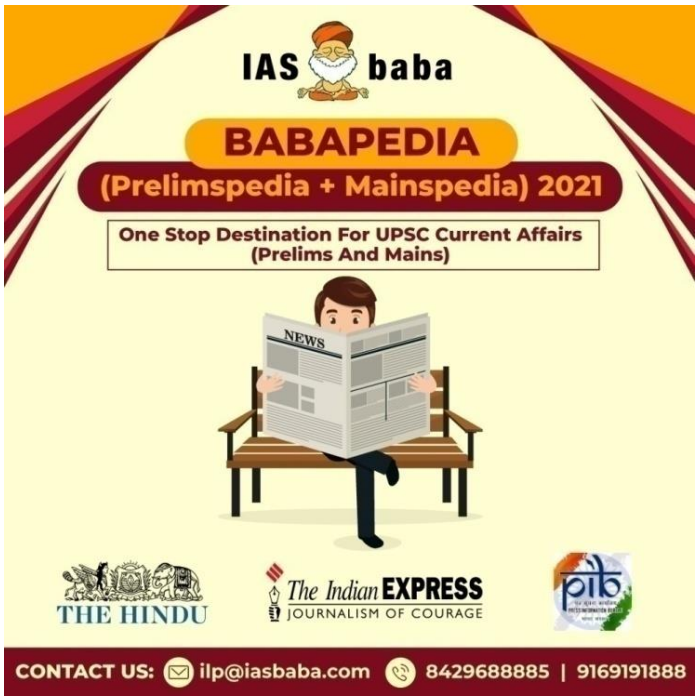

पर्यावरण/प्रदूषण

डेनमार्क की कृत्रिम ऊर्जा द्वीप परियोजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

समाचार में-

- डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में हरित ऊर्जा पर शिफ्ट होने के अपने प्रयास के तहत एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस परियोजना को डेनमार्क के इतिहास में DKK 210 बिलियन की अनुमानित लागत के साथ शुरू की जाने वाली सबसे बड़ी निर्माण परियोजना कहा जा रहा है।
- यह ऊर्जा द्वीप एक मंच पर आधारित है जो आसपास के अपतटीय पवन क्षेत्रों से बिजली उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- कृत्रिम द्वीप उत्तरी सागर में लगभग 80 किमी दूर स्थित होगा और इसका अधिकांश हिस्सा डेनमार्क सरकार के पास रहेगा।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य बड़े पैमाने पर अपतटीय पवन ऊर्जा प्रदान करना है।
- डेनमार्क और पड़ोसी देशों के बीच शक्ति को जोड़ने और वितरित करने का विचार है।
- यूरोपीय संघ द्वारा एक दशक के भीतर ज्यादातर नवीकरणीय वस्तुओं पर भरोसा करने और वर्ष 2050 तक अपनी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 25 गुना तक बढ़ाने के लिए अपनी बिजली प्रणाली को बदलने की योजना की घोषणा के बाद यह कदम आया है।

विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

समाचार में-

- 10 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **थीम:** हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना: सभी के लिए सुरक्षित वातावरण।
- यह द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (**TERI**) के फ्लैगशिप इवेंट का 20 वां संस्करण है।
- यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सरकारों, व्यापार नेताओं, शिक्षाविदों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और नागरिक समाज को एक साथ लाएगा।
- **शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार:** भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

मेडागास्कर में दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप खोजा गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - जैव विविधता

समाचार में-

- जर्मनी और मेडागास्कर के वैज्ञानिकों द्वारा मेडागास्कर में खोजा गया एक गिरगिट दुनिया का सबसे छोटा वयस्क सरीसृप है।
- इस खोज की रिपोर्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- टीम को 2012 में एक अभियान के दौरान इस प्रजाति की एक मादा तथा एक मिला, जिसका नाम ब्रुकेशिया नाना है।
- नर की लंबाई 13.5 मिमी (थूथन टू वेंट) और पूंछ शामिल होने पर 21.6 मिमी की कुल लंबाई होती है।
- इससे पहले, गिरगिट प्रजाति ब्रुकेशिया माइक्रा को सबसे छोटा माना जाता था।

क्या आप जानते हो?

- सबसे लंबा 'रेटिकुलेटेड पायथन' (Reticulated Python) जो कि लगभग 6.25 मीटर लंबा होता है, लगभग 289 ब्रुकेशिया नाना की लंबाई के बराबर होता है।
- मेडागास्कर छोटे छिपकलियों और सांपों की सबसे छोटी प्रजाति का घर है।
- ऐसी छोटी प्रजातियों का एक संभावित कारण तथाकथित "द्वीप प्रभाव" है जिसके कारण छोटे द्वीपों पर प्रजातियां छोटी हो जाती हैं।

वाहन मालिकों पर ग्रीन टैक्स

संदर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को रोकने और देश में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिये पुराने वाहनों पर 'हरित कर' (Green Tax) लगाने की घोषणा की।

इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

- **पुराने वाहनों पर अतिरिक्त सड़क कर:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आठ वर्ष से पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय एक हरित कर (रोड टैक्स की 10% से 25% दर तक) लगाएगा। निजी वाहनों से 15 वर्ष बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय हरित कर वसूला जाना प्रस्तावित है।
- **छूट:** मज़बूत हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे कि सीएनजी, इथेनॉल और एलपीजी द्वारा संचालित और खेती में उपयोग किये जाने वाले वाहनों, जैसे- ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और टीलर आदि को छूट दी जाएगी।
- **बड़े पैमाने पर परिवहन में वृद्धि:** सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे- सिटी बसों पर कम हरित कर लगाया जाएगा।
- **प्रदूषित शहरों में वाहन:** अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर उच्च हरित कर (रोड टैक्स का 50%) लगाया जाएगा।
- **पुराने सरकारी वाहन:** सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं विपंजीकृत करके बंद कर देना है।
- **अलग राशि:** राज्यों को प्रदूषण को मापने और इससे निपटने में मदद करने के लिए ग्रीन टैक्स फंड को एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए
- यह नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है
- निजी वाहनों से 15 वर्ष बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय हरित कर वसूला जाना प्रस्तावित है।

क्या पुराने वाहनों को खंगालने से बड़ा फायदा होता है?

- **लाभ ऑटोमोबाइल क्षेत्र:** पुराने वाहनों की हटाने की मांग को लेकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र और उससे संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे क्षेत्र जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और रीसाइक्लिंग के लिए वसूली होगी।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** कठोर उत्सर्जन और ईंधन दक्षता मानकों के अनुरूप नए वाहन अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं, और इनमें आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं हैं।
- **अन्य देशों द्वारा प्राथमिकता:** कई देशों में वैश्विक रूप से त्वरित वाहन प्रतिस्थापन योजनाओं का उपयोग किया गया है। 2008 की मंदी के बाद यूरोप में हाई-प्रोफाइल के अलावा, $ 3 बिलियन "कैश फॉर क्लंकर्स" या सीएआरएस (या कार भत्ता रिबेट सिस्टम) कार्यक्रम सबसे उल्लेखनीय था।
- **उच्च दक्षता वाले मानदंडों ने ईंधन के उपयोग को कम कर दिया:** वाहन प्रतिस्थापन से होने वाले लाभों का परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है। वाणिज्यिक वाहन बेड़े का 5% बनाते हैं लेकिन कुल वाहनों के प्रदूषण का अनुमानित 65-70% योगदान करते हैं। **BEE** का अनुमान है कि उच्चतर मानदंड भारत में 2025 तक 22.97 मिलियन टन के ईंधन उपयोग में कमी हो सकती है।

क्या परिमार्जन के लिए प्रस्तावित नीति व्यावहारिक है?

- क्या परिमार्जन के लिए प्रस्तावित नीति व्यावहारिक है?
- 2015 में इस आलेखन स्टेज दौरान, परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने यह विचार प्रस्तुत किया की पुराने वाहनों को बेचने वाले मालिकों को एक प्रमाण पत्र देने होगा तथा नए यात्री वाहनों के लिए 30,000 से 50,000 तक की छूट के लिए भुनाया जा सकता है।

- एक वाणिज्यिक वाहन के लिए, करों सहित लाभ अनुमानित 1.5 लाख होगा। हालांकि, इस विचार में प्रगति नहीं हुई और उच्च लागत पर आरक्षण व्यक्त करने वालों में नीति आयोग था।
- अयोग का कहना था की उच्च पूंजी लागत के कारण कुछ वर्ग पुराने वाहनों को वापस लेने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।
- पहले के ड्राफ्ट प्रस्तावों में उन लोगों के लिए कर छूट की परिकल्पना की गई जिन्होंने नए के लिए पुराने मोटरों का आदान-प्रदान किया था।
- हालाँकि, वर्तमान में आयोग का मुख्य उद्देश्य था की पुराने वाहनों के मालिकों को ग्रीन टैक्स पेनल्टी का भुगतान करने के बजाय उन्हें बेचने से रोकना था।
- वाहनों के निरंतर संचालन से स्वच्छ वायु उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और ऑटोमोबाइल उद्योग को कोई खुशी नहीं होगीक्या परिमार्जन के लिए प्रस्तावित नीति व्यावहारिक है?
- 2015 में इस आलेखन स्टेज दौरान, परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने यह विचार प्रस्तुत किया की पुराने वाहनों को बेचने वाले मालिकों को एक प्रमाण पत्र देने होगा तथा नए यात्री वाहनों के लिए 30,000 से 50,000 रुपए तक की छूट के लिए भुनाया जा सकता है।
- एक वाणिज्यिक वाहन के लिए, करों सहित लाभ अनुमानित 1.5 लाख होगा। हालांकि, इस विचार में प्रगति नहीं हुई और उच्च लागत पर आरक्षण व्यक्त करने वालों में नीति आयोग था।
- अयोग का कहना था की उच्च पूंजी लागत के कारण कुछ भाग पुराने वाहनों को वापस लेने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।
- पहले के ड्राफ्ट प्रस्तावों में उन लोगों के लिए कर छूट की परिकल्पना की गई जिन्होंने नए के लिए पुराने मोटरों का आदान-प्रदान किया था।
- हालाँकि, वर्तमान में आयोग का मुख्य उद्देश्य था की पुराने वाहनों के मालिकों को ग्रीन टैक्स पेनल्टी का भुगतान करने के बजाय उन्हें बेचने से रोकना था।
- वाहनों के निरंतर संचालन से स्वच्छ वायु उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और ऑटोमोबाइल उद्योग को कोई खुशी नहीं होगी

पॉलिसी को बेहतर करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

- साफ-सफाई के लिए, वाणिज्यिक परिवहन वाहन अधिक चिंता का विषय हैं: ईंधन दक्षता, उत्सर्जन और सुरक्षा पर।
- केंद्र अपने वित्तीय वाहनों जैसे छोटे ऑपरेटरों को ऋण और अनुदान के साथ हरे रंग के नए सौदे की पेशकश करता है, जबकि वे अपने ख़राब वाहनों को हटाने के लिए, वार्षिक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हरित टैक्स को कम करते हैं।
- बस कंपनियों के लिए एक दूसरी प्रोत्साहित बेड़े को हरित और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है।
- ऑटोरिक्शा जैसे छोटे ऑपरेटरों को कम ब्याज वाले ऋण की पेशकश की जाती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- कार्बन उपकर

भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण; भूमिकारूप व्यवस्था; कृषि

समाचार में-

- सीएनजी रूप में परिवर्तित भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर औपचारिक रूप से 12 फरवरी, 2021 को लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय**: मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा

महत्वपूर्ण तथ्य

- रूपांतरण किसानों को अपनी आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे
- यह भी बताया गया है कि डीजल से चलने वाले इंजन की तुलना में रेट्रोफिटेड ट्रैक्टर अधिक शक्ति उत्पादन करता है।
- डीजल की तुलना में कुल उत्सर्जन में 70% की कमी आएगी।
- यह किसानों को ईंधन लागत पर 50% तक बचाने में मदद करेगा।

लेदरबैक समुद्री कछुआ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - जैव विविधता; वातावरण

समाचार में-

- कुछ संरक्षणवादी विशालकाय लेदरबैक कछुओं को लेकर चिंतित हैं।
- नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और बंदरगाह विकास के प्रस्ताव रखे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- नीति आयोग की पर्यटन उद्देय में ग्रेट निकोबार द्वीप पर गैलाथिया खाड़ी में एक मेगा-शिपमेंट बंदरगाह का प्रस्ताव शामिल है।
- इसके अलावा, छोटे अंडमान योजना इस द्वीप पर पर्यटन के क्रमबद्ध विकास का प्रस्ताव करती है, जिसके कारण 200 वर्ग किमी से अधिक वर्षावनों का आरक्षण, लगभग 140 वर्ग किमी का ओन्गे ट्राइबल रिजर्व भी हो सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

लेदरबैक समुद्री कछुआ

- यह समुद्री कछुओं की सात प्रजातियों में से सबसे बड़ी है।
- **अन्य प्रजातियां हैं:** ओलिव रिडले कछुआ, हरा कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ, लॉगरहेड कछुआ, लेदरबैक कछुआ
- लॉगरहेड को छोड़कर, शेष चार प्रजातियां भारतीय तट के साथ निवास बनाते हैं।
- यह आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाता है।
- यह आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाता है।
- यह हिंद महासागर के इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास बनाते हैं।
- यह दरमोच्लएस और परिवार दारचेलीडे जीनस में एकमात्र जीवित प्रजाति है।
- इसे आसानी से एक बोनी शेल की कमी से अन्य आधुनिक समुद्री कछुओं से अलग किया जा सकता है।
- वे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

क्या आप जानते हो?

- पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी की है जिसमें A & N द्वीपों को प्रमुखता दी गई है।
- इस योजना के अनुसार, भारत ने अपने सभी महत्वपूर्ण समुद्री कछुए के आवासों की पहचान महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में की है।
- इन क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) - 1 में शामिल किया गया है।
- लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार गैलाथिया पर दक्षिण खाड़ी और पश्चिमी खाड़ी, भारत में महत्वपूर्ण समुद्री कछुआ निवास स्थान के रूप में उल्लिखित हैं।

संबंधित आलेख

- ओलिव रिडलिस का मास नेस्टिंग: यहां क्लिक करें

डब्ल्यूसीसीबी ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार-2020 जीता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

समाचार में-

- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2010 मिला।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- WCCB को तीन साल में दो बार पुरस्कार मिला।
- इसे इस वर्ष इनोवेशन श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया ।

महत्वपूर्ण बिंदु

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

- यह वाइल्डलाइफ (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- **मंत्रालय**: पर्यावरण और वन मंत्रालय
- **जनादेश**: देश में संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करने के लिए
- **मुख्यालय**: नई दिल्ली
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर
- डब्ल्यूसीसीबी ने पूरे भारत में वन्यजीव अपराधों के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।
- ऑपरेशन सेव कूर्मा, थंडरबर्ड, वाइल्डनेट, लेसकॉन, बीरबिल, थंडरस्टॉर्म, लेसकॉन- II आदि जैसे ऑपरेशनों को करने के लिए इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप टाइगर / लेपर्ड स्किन / हड्डियों, राइनो हॉर्न, एलिफेंट आइवरी आदि की भारी बरामदगी हुई है।

हैदराबाद दुनिया के ट्री सिटी के रूप में उभरा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

समाचार में-

- हैदराबाद ने भारत के शहरों के बीच एक हरे रंग की प्रतियोगिता जीती है, और दुनिया के 'ट्री सिटीज़' में से एक बनकर उभरा है। 'आर्बर डे फाउंडेशन' और संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organisation-FAO) द्वारा हैदराबाद शहर (तेलंगाना की राजधानी) को '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा सम्मानित किया गया।

- हैदराबाद ने अपने हरितम कार्यक्रम और शहरी वन पार्कों की योजना के तहत शहरी वानिकी को बनाए रखा।
- शहर का मूल्यांकन पांच मैट्रिक्स पर किया गया : उत्तरदायित्व स्थापित करें , नियम निर्धारित करें, आप क्या जानते हैं , संसाधन आवंटित करें और उपलब्धियां मनाएं।

ग्रीनपीस का वायु प्रदूषण के कारण अर्थव्यवस्था में लागत का विश्लेषण

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण; अर्थव्यवस्था

समाचार में-

- हाल ही में ग्रीनपीस दक्षिण पूर्व एशिया ने वायु प्रदूषण के कारण अर्थव्यवस्था के लिए लागत का विश्लेषण किया।
- रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण ने 2020 में दिल्ली में लगभग 54,000 जीवन समाप्त किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- छह भारतीय शहरों - दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ - वैश्विक विश्लेषण की सुविधा में।
- वैश्विक स्तर पर, लगभग 1,60,000 मौतों का श्रेय पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 वायु प्रदूषण को दिया गया है।
- ये मौतें पांच सबसे अधिक आबादी वाले शहरों - दिल्ली, मैक्सिको सिटी, साओ पाउलो, शंघाई और टोक्यो में हुई।
- अध्ययन के लिए 'लागत अनुमानक' उपकरण का उपयोग किया गया।
- यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो विश्व के प्रमुख शहरों में सूक्ष्म पीएम 2.5 वायु प्रदूषण से वास्तविक समय के स्वास्थ्य प्रभाव और आर्थिक लागत का अनुमान लगाता है।

'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण

समाचार में-

- हाल ही में "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया गया।
- **मंत्रालय**: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- **उद्देश्य:** भारत में ई-मोबिलिटी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों के बारे में जागरूकता लाना ।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह अभियान आयात निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।
- यह एक स्वच्छ और हरियाली भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

क्या आप जानते हो?

- इलेक्ट्रिक ईंधन जीवाश्म ईंधन के लिए एक प्रमुख विकल्प है।
- इन ईंधनों का आयात बिल 8 लाख करोड़ रूपये है।
- इलेक्ट्रिक ईंधन की कम लागत, कम उत्सर्जन है।
- यह मुख्यतया स्वदेशी है।

कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए : कार्बन वॉच ऐप

संदर्भ: चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसने किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन कार्बन वॉच लॉन्च किया।

कार्बन पदचिह्न क्या है?

- कार्बन पदचिह्न एक विशेष मानवीय गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीनहाउस गैसों-विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है।
- CO_2 उत्सर्जन के भार उत्पादित मात्रा टन के रूप में व्यक्त की जाती है।
- यह व्यापक उपाय हो सकता है या किसी व्यक्ति, एक परिवार, एक घटना, एक संगठन या यहां तक कि एक पूरे देश के कार्यों पर लागू किया जा सकता है।

- कार्बन पदचिह्न में प्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल है, जैसे कार चलाना
- कार्बन पदचिह्न पारिस्थितिक पदचिह्न से अलग है। जबकि कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन को मापता है, पारिस्थितिक पदचिह्न जैव-उत्पादक अंतरिक्ष के उपयोग को मापने पर केंद्रित है।

ऐप के बारे में

- मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकने वाला एप्लिकेशन व्यक्ति के कार्यों पर केंद्रित है तथा चार मानकों के आधार पर कार्बन पदचिह्न की गणना की जाती है: जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन (वाहन आंदोलन)
- यह एप्लिकेशन उत्सर्जन की राष्ट्रीय, विश्व औसत और उत्सर्जन पीढ़ी के व्यक्तिगत स्तर जैसी जानकारी भी प्रदान करता है।
- इस एप्लिकेशन का मकसद लोगों को क्लाइमेट-स्मार्ट सिटिज़न्स बनाना है, जबकि उन्हें अपने कार्बन फुटप्रिंट तक पहुंचने में सक्षम बनाने के साथ-साथ कम करने के लिए कदम भी उठाता है।
- मोबाइल एप्लिकेशन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार कार्बन पदचिह्न को कम करने के तरीकों का सुझाव।
- यह लोगों को उनकी जीवनशैली के उत्सर्जन, प्रभाव और उसी को कम करने के लिए संभावित प्रतिकार के बारे में भी संवेदनशील बनाता है।

उच्च कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव

- वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीनहाउस गैस प्रभाव का कारण होती है
- जलवायु परिवर्तन
- ध्रुवीय बर्फ का पिघलना
- संसाधनों की कमी: जैवमंडल में परिवर्तित कार्बन सांद्रता के कारण
- मौसम की बढ़ती (गंभीर) घटनाएं
- खाद्य आपूर्ति में बदलाव

कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीके

- **पानी:** बेहतर कृषि पद्धतियों (जैसे ड्रिप इरिगेशन) को अपनाना जैसे डाइटरी बास्केट को त्याग देना, अनाज की फसलों को पानी से बचाने के लिए जैसे बाजरा, उद्योगों में पानी की रिसाइक्लिंग, घरों में पानी की मात्रा
- **ऊर्जा:** नवीकरणीय ऊर्जा (कार्बन सघन कोयले से बदलाव), स्मार्ट मीटरिंग, विशेष रूप से डिस्कॉम्स में ऊर्जा सुधार उपकरणों का उपयोग करके सुधार
- **अपशिष्ट:** 4**R** को अपनाने से रिफ्यूज करना, कम करना, पुन: उपयोग, रीसायकल करना।
- **परिवहन:** सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, कार पूलिंग का उपयोग करना
- **कार्बन ट्रेडिंग जैसे बाजार तंत्र:** व्यक्ति और कंपनियां कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की भरपाई करना, जिसमें से पैसा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने जैसी परियोजनाओं में जाना आधी आदि है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों का कार्यान्वयन और इसके लिए भारतीय पहल तेजी से आगे बढ़ना।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- कार्बन टैक्स के लाभ

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति और जीएस - III - पर्यावरण

समाचार में-

- हाल ही में स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों (एसआईपी) के चरण IV के तहत 12 प्रतिष्ठित साइटों की घोषणा की गई।
- **मंत्रालय:** पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA), पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ जल शक्ति मंत्रालय।

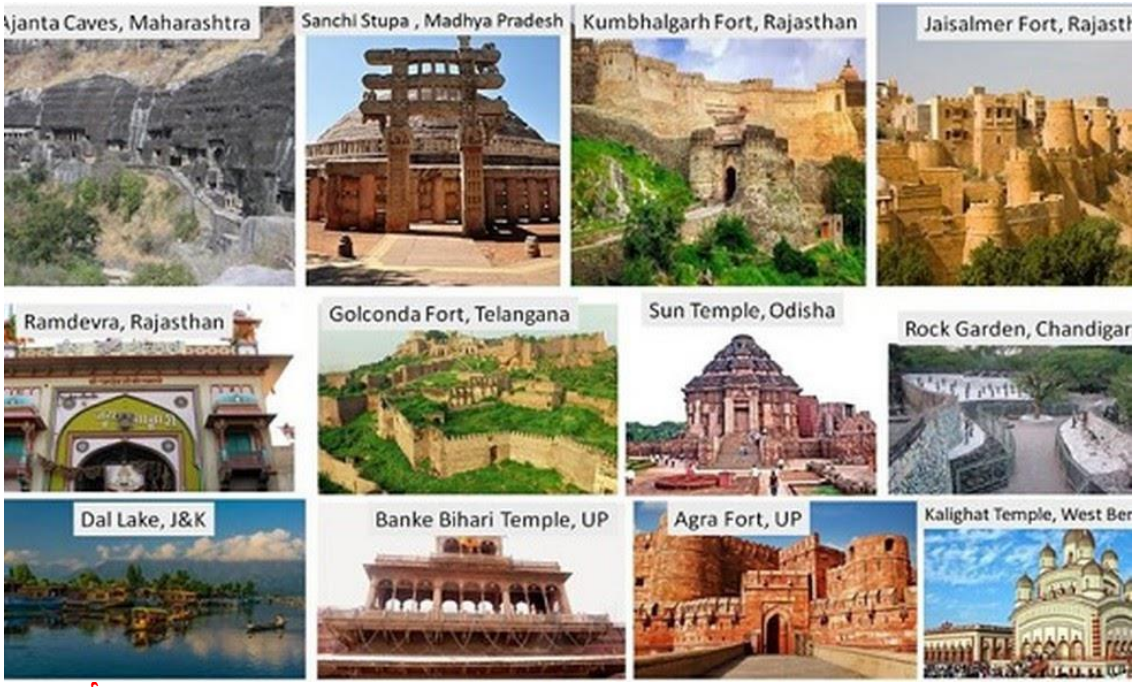

महत्वपूर्ण तथ्य

स्वच्छ चिह्न स्थान (SIP) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) की एक पहल है

उद्देश्य: प्रतिष्ठित विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को भारत में 'स्वच्छ पर्यटन स्थल' के रूप में बदलना। तथा इन स्थानों पर स्वच्छता / स्वच्छता के एक उच्च स्तर को प्राप्त करना।

ये स्थान हैं:

1. अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र
2. सांची स्तूप, मध्य प्रदेश
3. कुम्भलगढ़ किला, राजस्थान
4. जैसलमेर का किला, राजस्थान
5. रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान
6. गोलकोंडा किला, हैदराबाद, तेलंगाना
7. सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा
8. रॉक गार्डन, चंडीगढ़
9. डल झील, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
10. बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश
11. आगरा का किला, आगरा, उत्तर प्रदेश
12. कालीघाट मंदिर, पश्चिम बंगाल

समाचारों में एम्स / नेशनल पार्क्स

मंदारिन बतख

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - जैव विविधता

समाचार में-

- मंदारिन बतख को हाल ही में असम के मगुरी-मोटापुंग बील (आर्द्रभूमि) में देखा गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसे दुनिया में सबसे सुंदर बतख माना जाता है।
- यह पूर्वी एशिया का एक छोटा-सा दिखने वाला पक्षी है।
- यह बत्तख चीन, जापान, कोरिया और रूस के कुछ हिस्सों में भी पायी जाती है.
- अब ये पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में अधिक जनसख्या में मिलती है।
- ये बतख कभी-कभी ही भारत में आते हैं क्योंकि भारत उनके प्रवास मार्ग में नहीं आता है।
- आईयूसीएन स्थिति: कम संकटग्रस्त

मगुरी बील

- मगुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि, द्वारा घोषित एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो ऊपरी असम में डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के करीब स्थित है।
- यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है।

ब्लैक-ब्राउनेड बब्बलर 170 साल बाद फिर से खोजा गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - जैव विविधता

समाचार में-

- 170 वर्षों के बाद इंडोनेशिया के बोर्नियो वर्षा वनों में ब्लैक-ब्राउन बैबलर को फिर से खोजा गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पहले इसे विलुप्त मान लिया गया था।
- इस पक्षी को अकसर 'इंडोनेशियन पक्षी विज्ञान' में सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है।

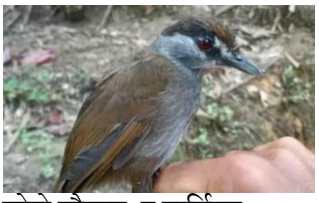

फोटो सौजन्य: द गार्जियन

संबंधित आलेख

- ल्यूसर इकोसिस्टम

- मृत कोरल रीफ का महत्व

Caracal (स्याहगोश) संकटग्रस्त लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - जैव विविधता

समाचार में-

- कैराकल, एक मध्यम आकार के जंगली बिल्ली को हाल ही में संकटग्रस्त लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया।
- **एजेंसियां:** वन्यजीव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय बोर्ड
- यह राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पायी गयी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में यह जानवर विलुप्त होने के कगार पर है।
- भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम में अब 22 वन्यजीव प्रजातियां शामिल हैं।
- भारत के अलावा, कैराकल अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया में पाया जाता है।
- जबकि यह अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मिलते है, एशिया में इसकी संख्या घट रही है।
- कैराकल जंगली बिल्ली (कैराकल कैराकल) भारत में पाई जाने वाली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह पतली एवं मध्यम आकार की बिल्ली है जिसके लंबे एवं शक्तिशाली पैर और काले गुच्छेदार कान होते हैं।

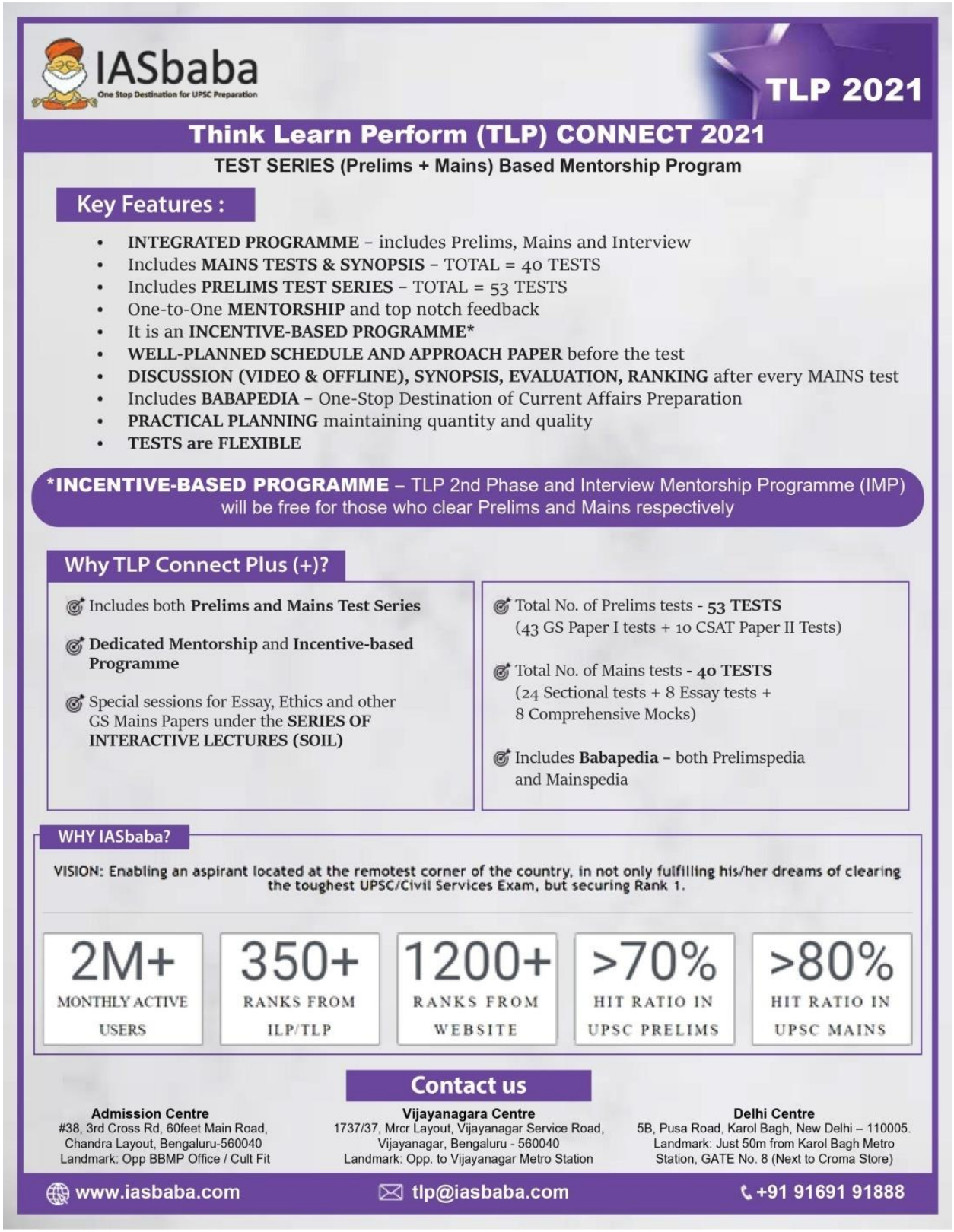
IASbaba
One Stop Destination for UPSC Preparation
TLP 2021
Think Learn Perform (TLP) CONNECT 2021
TEST SERIES (Prelims + Mains) Based Mentorship Program
Key Features :
INTEGRATED PROGRAMME – includes Prelims, Mains and Interview
Includes MAINS TESTS & SYNOPSIS – TOTAL = 40 TESTS
Includes PRELIMS TEST SERIES – TOTAL = 53 TESTS
One-to-One MENTORSHIP and top notch feedback
It is an INCENTIVE-BASED PROGRAMME*
WELL-PLANNED SCHEDULE AND APPROACH PAPER before the test
DISCUSSION (VIDEO & OFFLINE), SYNOPSIS, EVALUATION, RANKING after every MAINS test
Includes BABAPEDIA – One-Stop Destination of Current Affairs Preparation
PRACTICAL PLANNING maintaining quantity and quality
TESTS are FLEXIBLE
*INCENTIVE-BASED PROGRAMME – TLP 2nd Phase and Interview Mentorship Programme (IMP) will be free for those who clear Prelims and Mains respectively
Why TLP Connect Plus (+)?
Includes both Prelims and Mains Test Series
Dedicated Mentorship and Incentive-based Programme
Special sessions for Essay, Ethics and other GS Mains Papers under the SERIES OF INTERACTIVE LECTURES (SOIL)
Total No. of Prelims tests - 53 TESTS (43 GS Paper I tests + 10 CSAT Paper II Tests)
Total No. of Mains tests - 40 TESTS (24 Sectional tests + 8 Essay tests + 8 Comprehensive Mocks)
Includes Babapedia – both Prelimspedia and Mainspedia
WHY IASbaba?
VISION: Enabling an aspirant located at the remotest corner of the country, in not only fulfilling his/her dreams of clearing the toughest UPSC/Civil Services Exam, but securing Rank 1.
2M+ MONTHLY ACTIVE USERS
350+ RANKS FROM ILP/TLP
1200+ RANKS FROM WEBSITE
>70% HIT RATIO IN UPSC PRELIMS
>80% HIT RATIO IN UPSC MAINS
Contact us
Admission Centre
#38, 3rd Cross Rd, 60feet Main Road, Chandra Layout, Bengaluru-560040
Landmark: Opp BBMP Office / Cult Fit
Vijayanagara Centre
1737/37, Mrcr Layout, Vijayanagar Service Road, Vijayanagar, Bengaluru - 560040
Landmark: Opp. to Vijayanagar Metro Station
Delhi Centre
5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)
www.iasbaba.com
tlp@iasbaba.com
+91 91691 91888

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

मेट्रो-नियो बड़े पैमाने पर परिवहन की नवीन प्रणाली

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- केंद्रीय बजट में मेट्रो-नियो के लिए एक बड़ा बजटीय आवंटन करके, बड़े पैमाने पर परिवहन की अभिनव प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसे जल्द ही पूरे देश में दोहराया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- महाराष्ट्र के नासिक में देश में पहली बार अपनाया जा रहा है, मेट्रो-नियो एक आरामदायक, तीव्र, ऊर्जा-कुशल और कम शोर परिवहन माध्यम है।
- केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों से अपने टियर -2 और टियर -3 शहरों में मेट्रोनेटो तकनीक का उपयोग करने पर विचार करने का आग्रह किया है।
- मेट्रोनेटो सेवा में इलेक्ट्रिक बस कोच होते हैं - जिनकी लंबाई 18 से 25 मीटर तक होती है। एक बार में 200 से 300 यात्रियों की वहन क्षमता है।
- बसों में रबर के टायर होंगे और रेलवे या ट्राम के समान 600-750 वी डीसी आपूर्ति के साथ एक ओवरहेड बिजली के तार से बिजली खींची जाएगी।
- बसें वातानुकूलित होंगी, जिनमें स्वचालित दरवाजा बंद करने की प्रणाली, स्तरीय बोर्डिंग, आरामदायक सीटें, यात्री घोषणा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ एक सूचना प्रणाली होगी।
- स्टेशन अन्य मेट्रो रेल स्टेशनों के समान होंगे।

दक्षिण अफ्रीकी कोविड वेरिएंट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- डब्ल्यूएचओ ने यूके, ब्राजील और अब दक्षिण अफ्रीका में होने वाले कोरोनावायरस के तीन नए रूपों की पहचान हुई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- तीन में से, 20H / 501Y.V2 या B.1.351 के रूप में पहचनाने वाला नवीनतम दक्षिण अफ्रीकी संस्करण मूल वायरस की तुलना में अधिक संक्रामक प्रतीत हुआ।
- यह संभावित रूप से अधिक भिन्न है, जो पिछले साल 22 दिसंबर को देखा गया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 40 देशों में फैल गया है।
- दक्षिण अफ्रीकी संस्करण में N501Y नामक उत्परिवर्तन हुआ है जो इसे अधिक संक्रामक या फैलने में आसान बनाता है।
- पिछले वेरिएंट की तुलना में यह वेरिएंट "एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन के लिए कम संवेदनशील है"।
- यह दक्षिण अफ्रीकी संस्करण अपनी असामान्य रूप से बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन के कारण चिंता का एक प्रमुख कारण बन गया है, विशेषकर स्पाइक प्रोटीन में, जो वायरस मानव शरीर के भीतर कोशिकाओं में प्रवेश पाने के लिए उपयोग करता है।

संबंधित आलेख:

- यूके में कई उत्परिवर्तन द्वारा परिभाषित कोरोनोवायरस वैरिएबल: यहां क्लिक करें
- B.1.1.7 वंश: SARS-CoV-2 का नया संस्करण

भारत में शहरीकरण के बढ़ते मुद्दे

संदर्भ: ऐसा माना जाता है कि शहरीकरण को आधुनिकता और समृद्धि लाने के लिए जाना जाता है। पश्चिमी उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह खेत और शहरों में एक बड़े पैमाने पर आंदोलन उत्पादकता में बड़ी छलांग आई है। उम्मीद है कि भारत में भी इसी तरह के अनुभव को दोहराया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप शहरों से बड़ी उम्मीद रहेगी है
केंद्रीय बजट 2021-22 ने शहरीकरण के गुणक प्रभावों को मान्यता दी और इसके लिए प्रावधान किए हैं।

बजट 2021 में शहरीकरण के लिए प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार:** कुल 702 किमी की पारंपरिक मेट्रो लाइनें परिचालन में थीं और 1,016 किमी मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनों का निर्माण 27 शहरों में चला। सरकार ने कोच्चि, चेन्नई और बेंगलुरु मेट्रो परियोजनाओं के लिए 1,957 करोड़, 24 63,246 करोड़ और 14,788 करोड़ की केंद्रीय राशि की घोषणा की।
- **सिटी बस सेवा का विस्तार:** सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के संवर्द्धन में सहायता के लिए 18,000 करोड़ की लागत से एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत 20,000 से अधिक बसों को वित्त, अधिग्रहण, संचालन और रखरखाव के लिए निजी पीपीपी मॉडल की तैनाती की सुविधा होगी
- **टीयर -2 क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी:** पारंपरिक मेट्रो प्रणाली की तुलना में कम लागत पर जोड़ने के लिए टियर -2 शहरों और टीयर -1 शहरों के परंपरिक भागों में दो नई मेट्रो प्रौद्योगिकियों, मेट्रोलाइट और मेट्रोनेटो का उपयोग किया।

शहरी बिस्तार का मुद्दा

- **खराब बस अवसंरचना:** जनसंख्या के हिसाब से भारत में बसों का अनुपात प्रति 1,000 लोगों पर 1.2 है, जबकि थाईलैंड में 8.6 और दक्षिण अफ्रीका में 6.5 है, हालाँकि कर्नाटक जैसे कुछ राज्य राष्ट्रीय औसत से बहुत आगे हैं।
- **महामारी ने लोगों को व्यक्तिगत परिवहन में स्थानांतरित कर दिया:** COVID -19 के कारण लोगों को निजी कार और दोपहिया वाहनों की सुरक्षा के लिए ड्राइविंग को बहुत व्यापक प्रभाव डाला है।
- **बस परिवहन में निजी क्षेत्र की भागीदारी:** लाइसेंस प्राप्त निजी शहरी बस सेवाएं कई राज्यों में एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बनी हुई हैं, जहां राज्य के एकाधिकार वाले पैराट्रांसिट के साथ सह-अस्तित्व में हैं, और यह उन्हें समझाने का एक बड़ा प्रयास कर रही है कि एक बस पुनर्जागरण एक अच्छी पोस्ट-महामारी रिकवरी रणनीति है।
- **अम्ब्रेला प्राधिकरणों द्वारा कमजोर विनियम:** राज्य सरकारें, जो शहर के प्रशासन के बजाय शहरी विकास पर प्रभावी नियंत्रण रखती हैं, परिवहन को विनियमित करने के लिए अम्ब्रेला प्राधिकरणों के संचालन में विफल रही हैं।

- **वाहनों की अधिकता के कारण प्रदूषण:** डब्ल्यूएचओ के अध्ययन के अनुसार, दुनिया के शीर्ष -15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तरके कारण यह आर्थिक नुकसान में भी तब्दील हो जाता है। विश्व बैंक के वर्तमान अनुमानों के अनुसार, नुकसान देश का सकल घरेलू उत्पाद 7.7% है।
- **यातायात भीड़:** कुछ महानगरों में वाहन औसतन 17kph की गति से चलते हैं। सड़कों पर जमा सिलोस में मौजूद नहीं है, और इसके प्रतिकूल प्रभाव उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। बीसीजी-उबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष चार मेट्रो शहरों में भीड़भाड़ के कारण होने वाले नुकसान का संयुक्त अनुमान 22 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है।
- **व्यावसायिक क्षेत्रों में सड़कों का बहुउद्देश्यीय उपयोग:** शहरों में सड़कें बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सामान हैं, जिनका उपयोग मोटर चालित और गैर-मोटर चालित वाहनों के विभिन्न वर्गों द्वारा यात्रा, पार्क, रोड-सेल्स आदि के लिए किया जाता है। जिससे मोटर चालित वाहन धीमा हो।
- **एक नए राज्य में अभी भी नयी उत्पाद:** सामान्य आने जाने वाला कार्ड जो नागरिकों को बस, ट्रेन और फीडर नेटवर्क का उपयोग करने में मदद करेंगे, वे महामारी से पहले भी पायलट प्रोजेक्ट मोड में मुख्य रूप से उपयोग में थे।
- **महँगा जन परिवहन:** वैध आलोचना कि वर्तमान प्रतिमान "बहिष्करण शहरीकरण" में से एक है, जो मेट्रो और बस सेवाओं को बहुमत के लिए महंगा बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आवास की लागत के कारण उपनगरों में रहने के लिए मजबूर हैं, और कभी-कभी एक दो किलोमीटर का उपयोग करने के लिए वाहन अधिक आकर्षक की लागत से बनाते हैं।
- **शहरी क्षेत्रों की खराब मान्यता:** जनगणना 2011 ने दर्शाया कि जनगणना के उद्देश्य से शहरी जनगणना शहरों की संख्या में में स्थानीय निकायों के नाम नहीं हैं, और एक दशक में काफी वृद्धि हुई है। उनके पास अब भी जनसख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन, बुनियादी ढांचे और क्षमता तक पहुंच नहीं है।

आगे की राह

- **संवर्धित निवेश:** मानक नीति सिफारिशें जैसे भीड़ मूल्य निर्धारण या अन्य प्रकार के यात्रा प्रतिबंध गतिशीलता में सुधार करने के लिए बहुत कम कर सकते हैं। इसके बजाय, शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए संभावित रूप से महंगा बुनियादी ढांचा निवेश एकमात्र तरीका हो सकता है।
- **व्यापक दृष्टिकोण:** केंद्र सरकार को अपनी परिवहन दृष्टि के साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए , जैसे कि सस्ती इनर-हाउसिंग आवास, किराये की परियोजनाएं, नागरिक सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, स्थिरता, हरियाली और अस्थिरता आदि ।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- स्मार्ट सिटीज मिशन
- हाइपरलूप तकनीक: यहां क्लिक करें

बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सुधार के रूप में, राज्य ने सितंबर, 2020 से किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया।
- इस प्रकार, राज्य ने बिजली क्षेत्र में तीन निर्धारित सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू किया।
- आंध्र प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश ने बिजली क्षेत्र में सुधार किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाले राज्यों को जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई।
- यह सेक्टर में 3 सुधारों के समूह से जुड़ा है:

1. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राज्य में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में कमी के लिए जीएसडीपी का 1.0.05%
2. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राज्य में जीएसडीपी का औसत 0.05% आपूर्ति की औसत लागत और राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR गैप) के बीच अंतर को कम करने की अनुमति ।
3. सामान्य रूप से, राज्य के सभी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए 0.15% जीएसडीपी मुफ्त / रियायती बिजली के बदले में राज्य के सभी किसानों को दिया। इसके लिए, राज्य सरकार को नकद हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करनी होगी और योजना को कम से कम एक जिले में 31 दिसंबर, 2020 तक लागू करना होगा।

रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अब से रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के विकास पर भी ध्यान दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मंत्रालय इस क्षेत्र में निर्माण, अनुसंधान और नीति की भी देखभाल करेगा।
- प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत, वित्तीय और नियामक ढांचे का गठन भी योजना के दायरे में आएगा।
- इस योजना से इस क्षेत्र में आने के लिए विनियामक शासन की स्थापना, अनुसंधान और नई तकनीक की सुविधा के द्वारा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम, 1961 में एक संशोधन अधिसूचित किया।

इस कदम के महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं

- दूरस्थ स्थानों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी
- मुख्य सड़कों पर भीड़ को कम करना
- विश्व स्तरीय रोपवे बुनियादी ढांचे को विकसित करने की संभावना
- एक संगठित और समर्पित रस्सी-मार्ग और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान उद्योग की स्थापना
- नई तकनीक, जैसे सीपीटी - केबल प्रोपेल्ड ट्रांजिट सेक्टर में आ रही है
- अनियमित रोपवे के लिए सुरक्षा मानदंड स्थापित करना

फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने आगामी परियोजनाओं में तटरेखा के साथ-साथ विश्व स्तर के फ्लोटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए एक विजन के साथ फ्लोटिंग संरचनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दिशानिर्देशों में मरीना, माइनर हारबर्स, फिशिंग हारबर्स आदि तटीय क्षेत्रों, स्थानीय, जलमार्गों, नदियों और जलाशयों में फ्लोटिंग जेटी या प्लेटफार्मों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी पहलुओं को निर्धारित किया गया।
- इन दिशानिर्देशों का उपयोग विभिन्न जलजनित प्रणालियों में अस्थायी प्लेटफार्मों के लिए उपयुक्त रूप से किया जाता है।
- अपने अंतर्निहित लाभ के कारण फ्लोटिंग संरचना एक आकर्षक समाधान है।
- फ्लोटिंग जेटी के लाभ में उनकी लागत-प्रभावशीलता, तेजी से कार्यान्वयन, आसानी से विस्तार योग्य और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हैं।

क्या आप जानते हो?

- पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने गोवा में यात्री फ्लोटिंग जेटी की स्थापना हुयी, साबरमती नदी पर पानी-एयरोड्रोम और सीप्लेन सेवाओं के लिए सरदार सरोवर बांध सहित कुछ परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है जो संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं।

संबंधित लेख

- सागरमाला विमान सेवा (एसएसपीएस): यहां क्लिक करें
- भारत का पहला सीप्लेन प्रोजेक्ट: यहां क्लिक करें

अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए न्यायिक निर्णयों की जांच के लिए अध्ययन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था; भूमिकारूप व्यवस्था

समाचार में-

- नीति आयोग ने एक अध्ययन का गठन किया जो पर्यावरणीय आधारों पर बड़े बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं को बाधित करने और रोकने वाले न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणामों की जांच करेगी।
- यह अध्ययन जयपुर-मुख्यालय सीयूटीएस (कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी) सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक रेगुलेशन द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय की उपस्थिति रहती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रिपोर्ट यह बताती है कि प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले निर्णय नौकरियों और राजस्व के नुकसान के मामले में पर्याप्त रूप से आर्थिक गिरावट पर विचार नहीं करते।
- ऐसा करने से न्यायपालिका द्वारा अपने निर्णयों में आर्थिक रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं के बीच सार्वजनिक बातचीत में योगदान होना।
- संक्षिप्त प्रोजेक्ट का कहना है कि यह पाँच प्रमुख परियोजनाओं की जाँच करने की उम्मीद रखती है जो सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायिक निर्णयों से प्रभावित हुई हैं।
- यह उन लोगों के साक्षात्कार के द्वारा करने की योजना बना रहा है जो परियोजनाओं के बंद होने से प्रभावित हुए हैं, पर्यावरण प्रचारक, विशेषज्ञ और बंद व्यावसायिक प्रभाव का आकलन कर रहे हैं।
- विश्लेषण की जाने वाली परियोजनाओं में गोवा के मोपा में एक हवाई अड्डे का निर्माण, गोवा में लौह अयस्क खनन पर रोक, तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करना शामिल है ।
- तथा अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बालू खनन और निर्माण गतिविधियों से जुड़े एनजीटी के फैसले हैं।

डोभी - दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अनुभाग का उद्घाटन हुआ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - ऊर्जा; भूमिकारूप व्यवस्था

समाचार में-

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने एलपीजी आयात टर्मिनल, 348 किमी डोभी - दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अनुभाग को राष्ट्र को समर्पित किया।
- यह भाग प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी कैटेलिटिक-इसोडेवेक्सिंग इकाई के लिए नींव भी रखा गया।
- ये परियोजनाएं हल्दिया को निर्यात-आयात के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में भी मदद करेंगी।
- इस पाइपलाइन से पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के 10 जिले लाभान्वित होंगे।
- यह दूसरी कैटेलिटिक डेवैक्सिंग यूनिट लुब्रिकेटिंग आधारित तेलों के संबंध में आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगी।

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020

संदर्भ: संसद ने ऐतिहासिक मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2020 पारित किया है

विधेयक भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और योजना के संचालन के लिए इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना चाहता है। यह मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेना चाहता है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं

- **अधिनियम का आवेदन:** विधेयक 12 प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगा - दीनदयाल (तत्कालीन कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मर्मुगाओ, न्यू मंगलौर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पहले एन्नोर), वीओ चिदंबरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित)) का है। इन दोनों ने मिलकर 2019-20 में 705 मिलियन टन (MT) कार्गो को संभाला था।
- **प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड:** विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का बोर्ड बनाने का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे।

- **बोर्ड की संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष शामिल होंगे, दोनों को केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड में राज्य सरकार, रेलवे, रक्षा मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग के एक-एक सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पोर्ट प्राधिकरण के कर्मचारियों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले 2-4 स्वतंत्र सदस्य और दो सदस्य बोर्ड का हिस्सा होंगे।
- **पोर्ट बोर्ड की शक्तियां:** विधेयक बोर्ड को अपनी संपत्ति, संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है जैसा कि प्रमुख बंदरगाह के विकास के लिए उपयुक्त है। अपनी पूंजी और कार्य व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बोर्ड बैंकों, वित्तीय संस्थानों और विदेशों से ऋण उठा सकता है।
- **बोर्ड को स्वायत्तता:** उन्हें अनुबंध, योजना और विकास, राष्ट्रीय हित में टैरिफ को तय करने, निष्क्रियता और डिफ़ॉल्ट से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा और आपात स्थिति को छोड़कर, में प्रवेश करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान एमपीटी अधिनियम, 1963 में 22 उदाहरणों में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।
- **पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए धक्का:** विधेयक पीपीपी परियोजनाओं को परिभाषित करता है क्योंकि बोर्ड द्वारा रियायत अनुबंध के माध्यम से परियोजनाएं ली जाती हैं। इस तरह की परियोजनाओं के लिए, बोर्ड शुरुआती बोली उद्देश्यों के लिए शुल्क तय कर सकता है, लेकिन नियुक्त रियायतें बाजार की स्थितियों के आधार पर वास्तविक टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** विधेयक यह प्रावधान करता है कि बोर्ड सामाजिक निधियों को प्रदान करने के लिए अपने धन का उपयोग कर सकता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
- **सहायक सरकार:** विधेयक केंद्र सरकार द्वारा एक सहायक बोर्ड के गठन की शक्ति प्रदान करता है। यह बोर्ड 1963 अधिनियम के तहत गठित मौजूदा टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स (TAMP) का स्थान लेगा। यह बोर्ड बंदरगाहों और पीपीपी रियायतों के बीच विवादों को देखता है और तनावग्रस्त पीपीपी परियोजनाओं की भी समीक्षा करता है

विधेयक का महत्व

- **वैश्विक संस्थागत संरचना के समान:** यह इन बंदरगाहों की संस्थागत संरचना का आधुनिकीकरण करता है। विधेयक केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को जमींदार बंदरगाह मॉडल के सफल वैश्विक अभ्यास के अनुरूप बनाता है
- **विकेंद्रीकरण:** विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने के विकेन्द्रीकरण और प्रमुख बंदरगाहों के शासन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है।
- **पारदर्शिता:** यह हितधारकों और बेहतर परियोजना निष्पादन क्षमता को लाभान्वित करते हुए तेज और पारदर्शी निर्णय प्रदान करता है।
- **कॉम्पैक्ट बोर्ड:** पोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड की एक सरलीकृत रचना में 11 से 13 सदस्य होंगे जो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं (पहले 17 से 19 सदस्य)। पेशेवर स्वतंत्र सदस्यों के साथ एक कॉम्पैक्ट बोर्ड निर्णय लेने और रणनीतिक योजना को मजबूत करेगा।
- **पोर्ट सेक्टर को बढ़ावा:** यह निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्तता के कारण अधिक दक्षता के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों को सशक्त करेगा, जो बदले में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को बढ़ावा देता है और व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाता है। यह प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों के माध्यम से देश में तटीय रेखा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है।
- **निजीकरण नहीं:** नए अधिनियम का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण करना नहीं है, बल्कि निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी निर्णय लेने की शक्तियों को बढ़ावा देना है। इसे पोर्ट्स के कॉरपोरेटाइजेशन में पहले चरण के रूप में देखा जाता है और फिर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगम

सागरिका: पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में-

- हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने केरल के कोच्चि में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सागरिका, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया।
- यह भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन से समुद्री इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के इच्छुक लोगों को मदद मिलेगी।
- साउथ कोल बर्थ रसद लागत में कमी लाएगा और कार्गो क्षमता में सुधार करेगा।
- प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना (पीडीपीपी) भारत की यात्रा को आत्मानबीर होने की दिशा में मजबूत बनाने में मदद करेगी क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- रो-रो वेसल्स के साथ, सड़क पर लगभग 30 किमी की दूरी जलमार्ग के माध्यम से कम भीड़ और अधिक सुविधा, वाणिज्य और क्षमता-निर्माण के माध्यम से 3.5 किमी हो जाएगी।

सभी प्रकार के इस्पात को राजमार्ग निर्माण में अनुमति दी गई

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- हाल ही में आदेश जारी किए गए थे कि सभी स्टील - चाहे वह अयस्क, बिल्ट, छर्रों या स्क्रैप के पिघलने से उत्पन्न हों इसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए किया जाएगा।
- **मंत्रालय:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- स्टील को विशिष्ट ग्रेड के आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- उपयोग किए जाने वाले स्टील का अनुमोदन से पहले NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाएगा।
- स्टील की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए निर्णय लिया गया, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की लागत को प्रभावित कर सकता है।
- इस कदम से, इस्पात के लिए आपूर्तिकर्ता आधार बढ़ेगा, जिससे बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धा और बेहतर कीमत की खोज होगी।

तेल और गैस परियोजनाएं तमिलनाडु में

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- भारतीय प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी 2021 को तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की नींव रखी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रामनाथपुरम - थूटुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जाएगा।

- यह पाइपलाइन एन्नोर- तिरुवल्लूर- बेंगलुरू- पुदुचेरी- नागापट्टिनम- मदुरै- तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का एक भाग है।
- **लाभ:** यह ओएनजीसी गैस क्षेत्रों से गैस का उपयोग करने में मदद करेगा, उद्योगों और अन्य वाणिज्यिक ग्राहकों को फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस वितरित करेगा।
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली में गैसोलीन डिसल्फराइज़ेशन यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा।
- यह कम सल्फर (8 पीपीएम से कम) पर्यावरण के अनुकूल गैसोलीन का उत्पादन करेगा, उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान करने में मदद करेगा।

महाबाहु-ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- भारतीय प्रधानमंत्री 18 फरवरी 2021 को असम में 'महाबाहु-ब्रह्मपुत्र' का शुभारंभ करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- महाबाहु-ब्रह्मपुत्र के प्रक्षेपण को निम्नलिखित द्वारा चिह्नित किया जाएगा
- नेमाटी-माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी-दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी-हाटसिमारी के बीच रो-पैक्स पोत संचालन
- जोगीगोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) टर्मिनल का शिलान्यास
- ब्रह्मपुत्र नदी पर विभिन्न पर्यटक घाट
- ईज ऑफ डूइंग-बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान का शुभारंभ
- **उद्देश्य:** भारत के पूर्वी भागों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना

केरल में ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

320 केवी पुगलुर (तमिलनाडु) - त्रिशूर (केरल) बिजली पारेषण परियोजना

- यह भारत का पहला हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) प्रोजेक्ट है
- यह पश्चिमी क्षेत्र से 2000 मेगावाट बिजली के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। केरल के लोगों के लिए लोड में वृद्धि को पूरा करने में मदद करेगा।।
- यह पारंपरिक एचवीडीसी प्रणाली की तुलना में 35-40% कम भूमि के निशान को भी सुनिश्चित करेगा।

50 मेगावाट कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना

- इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया।

तिरुअनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र

- यह तिरुवनंतपुरम नगर निगम के लिए स्मार्ट समाधान की मेजबानी करने के लिए स्थापित किया जा रहा है,
- यह समन्वित कार्रवाई, और पुलिस, नागरिक आपूर्ति, राजस्व, स्वास्थ्य और अग्निशमन जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच निर्णय लेने की सुविधा के लिए आपातकालीन स्थितियों के दौरान कार्रवाई के एक सामान्य बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

तिरुवनंतपुरम में स्मार्ट रोड्स प्रोजेक्ट

- परियोजना में सभी ओवरहेड उपयोगिताओं को नीचे, सड़क और जंक्शन सुधार लाने के लिए 37 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को विश्व स्तरीय स्मार्ट सड़कों में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है।
- इसमें सुरक्षित रास्ते, तूफान के पानी की नालियां, बिजली के लिए भूमिगत नलिकाएं और संचार लाइनें जैसी विशेषताएं होंगी।

अरुविकारा में जल उपचार संयंत्र

- यह AMRUT मिशन के तहत बनाया जा रहा है।
- यह तिरुवनंतपुरम को पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ावा देगा

महत्वपूर्ण बिंदु

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)

- इसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** बुनियादी ढांचे की स्थापना करना जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।

राष्ट्रीय सौर मिशन

- **उद्देश्य:** सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की कई नीतियों में से एक है।
- इस कार्यक्रम का उद्घाटन 2022 तक 20 GW के लक्ष्य के साथ 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में किया गया।
- इसे बाद में 2015 में 100 GW तक बढ़ाकर 2030 तक हासिल किया गया।
- भारत ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2014 में 2,650 मेगावाट से लगभग 5 गुना बढ़ाकर 2017 में लगभग 12,000 मेगावाट कर दिया।
- 20 GW का मूल लक्ष्य 2018 में पहुंच गया जो 2022 की समयसीमा से चार साल आगेहै।

संबंधित आलेख:

- शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ अमृत योजना: यहाँ क्लिक करें
- 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन: यहां क्लिक करें
- भारत का सौर ऊर्जा पुश: यहां क्लिक करें

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - राजनीति और शासन और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) खबरों में था, जब प्रकाश कुमार सिंह ने इसके सदस्य के रूप में शपथ ली थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)

- भारत सरकार द्वारा स्थापित
- यह विद्युत अधिनियम, 2003 के लिए केंद्रीय आयोग है जिसने ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया।

- **रचना:** अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य जिनमें अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण शामिल हैं जो आयोग के पदेन सदस्य हैं।
- **कार्य:** (1) केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित कंपनियों के उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करने के लिए; (2) बिजली के अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करने के लिए; (3) बिजली के ऐसे प्रसारण के लिए टैरिफ का निर्धारण करना।
- सीईआरसी केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति बनाने की सलाह भी देता है।

फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था; निर्माण क्षेत्र

समाचार में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2028-29 के लिए फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस योजना से दवा क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
- यह फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना का हिस्सा होगा।
- **उद्देश्य:** (1) निवेश बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना; (2) उच्च मूल्य वाले सामानों को शामिल करने के लिए उत्पाद विविधीकरण।
- **लक्षित समूह:** भारत में पंजीकृत निर्माता, योजना के व्यापक प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के लिए अपने वैश्विक विनिर्माण राजस्व (GMR) के आधार पर समूहीकृत किए जाएंगे।
- प्रोत्साहन की मात्रा: 15,000 करोड़।
- माल की श्रेणी

1. श्रेणी 1: बायोफर्मासिटिकल; जटिल जेनेरिक दवाएं; पेटेंट समाप्ति के पास पेटेंट दवाओं; सेल-आधारित या जीन थेरेपी ड्रग्स तथा अनुमोदित के रूप में अन्य दवाओं।

2. श्रेणी 2: सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, प्रमुख शुरुआती सामग्री, दवा मध्यवर्ती।

3. श्रेणी 3: श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत आने वाली दवाओं को शामिल नहीं किया गया है।

संबंधित आलेख:

- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का विस्तार
- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई

अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से परिवहन के लिए एलपीजी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में-

- अब, अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से रसोई गैस का परिवहन किया जा सकता है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने MOL (एशिया ओशिनिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग -1 और 2 के माध्यम से रसोई गैस के परिवहन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **मंत्रालय:** बंदरगाह मंत्रालय, जहाजरानी और जलमार्ग

महत्वपूर्ण तथ्य

- MOL समूह मेक-इन-इंडिया पहल के तहत निर्माण और संचालन के लिए निवेश करेगा।

- यह परियोजना कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में मदद करेगी, जिससे कुल रसद लागत कम होगी।
- यह उज्ज्वला योजना में भी मदद करेगी।
- **परियोजना का महत्व:** वर्तमान में, एलपीजी का 60% सड़क के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ट्रांसपोर्टर्स, रोड ब्लॉकेज की हड़ताल से कभी-कभी ट्रांसपोर्टेशन में भी देरी होती है। इसके अलावा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल या सड़क के माध्यम से जाना कठिन है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

एथिलीन ग्लाइकॉल: एक रसायन जो एंटीफ्रीज़र में पाया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- हाल ही में एंटीफ्रीज़र में पाए जाने वाले रसायन एथिलीन ग्लाइकॉल पीने के बाद ग्यारह अमेरिकी सैनिक बीमार पड़ गए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एथिलीन ग्लाइकॉल एक औद्योगिक यौगिक है जो उपभोक्ता उत्पादों में पाया जाता है जिसमें मोटर वाहन एंटीफ्रीज़र, हाइड्रोलिक ब्रेक तरल पदार्थ, कुछ स्टैंप पैड स्याही, बॉलपॉइंट पेन, सॉल्वैंट्स, पेंट, प्लास्टिक, फिल्म और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं, तथा इसका उपयोग एक फार्मास्युटिकल वाहन के रूप में भी किया जाता है।
- यह एक सिंथेटिक तरल है, जो गंधहीन होता है।
- इसका उपयोग कारों, हवाई जहाज और नौकाओं के लिए एंटीफ्रीज़र और डी-आइसिंग घोल बनाने के लिए किया जाता है।
- एक बार अंतर्ग्रहण के बाद, एथिलीन ग्लाइकॉल रासायनिक रूप से विषाक्त यौगिकों में टूट जाता है।
- ये उप-उत्पाद तब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS), हृदय और फिर गुर्दे को प्रभावित करते हैं।
- ईथीलीन ग्लाइकॉल का प्रसार इनडोर वायु, पानी, भोजन, बाहरी हवा और कृषि उत्पादों के माध्यम से किया जाता है।

बजट 2021-22: विज्ञान और तकनीक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2021-22 ने देश में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए, वित्त मंत्री ने पाँच वर्षों में फैले 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा।
- 1,500 करोड़ रुपये एक ऐसी योजना के लिए प्रस्तावित किए गए हैं जो भुगतान के डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NTLM) नामक एक नई पहल का प्रस्ताव किया गया है जो इंटरनेट पर शासन और नीति से संबंधित ज्ञान के संग्रह को डिजिटाइज़ करेगा और प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), अंतरिक्ष विभाग के तहत एक PSU, PSLV-CS51 लॉन्च करेगा, जिसमें कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से अमोनिया उपग्रह भी ले जाएगा।
- दिसंबर 2021 में शुरू होने वाले गगनयान मिशन के लिए, रूस में जेनेरिक स्पेस फ़्लाइट पहलुओं पर चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- महासागरों के क्षेत्र को बेहतर ढंग से जानने के लिए, वित्त मंत्री ने पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट परिव्यय के साथ दीप महासागर मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

स्टारडस्ट 1.0: बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- 31 जनवरी को, स्टारडस्ट 1.0 को पूर्व सैन्य अड्डे, यूएस के मेन में लोरिंग कॉमर्स सेंटर से लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह जैव ईंधन से संचालित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बन गया, जो पर्यावरण के लिए गैर-विषाक्त है, जो पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट ईंधन के विपरीत है।
- स्टारडस्ट 1.0 एक लॉन्च वाहन है जो छात्र और बजट पेलोड के लिए उपयुक्त है।
- रॉकेट 20 फीट लंबा है तथा इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है।
- रॉकेट अधिकतम पेलोड द्रव्यमान को 8 किलोग्राम तक ले जा सकता है।
- ये रॉकेट एक तरह से अंतरिक्ष में क्यूबेट्स नामक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेंगे जो पारंपरिक रॉकेट ईंधन का उपयोग करने की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता है और पर्यावरण के लिए कम विषाक्त है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बायोफ्यूल्स बायोमास से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे सीधे तरल ईंधन में परिवर्तित किया जाता है और इसे परिवहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आज उपयोग में आने वाले दो सबसे अन्य प्रकार के जैव ईंधन इथेनॉल और बायोडीजल हैं।
- ये दोनों जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की पहली पीढ़ी के हैं।
- इथेनॉल नवीकरणीय और विभिन्न प्रकार के पौधों से बना है।
- बायोडीजल का उत्पादन, नयी शराब का मिश्रण, वनस्पति तेलों, जानवरों की वसा, पुनर्नवीनीकरण खाना पकाने का तेल के साथ मिलाकर किया जाता है।

क्या आप जानते हो?

- अन्य कंपनियां अंतरिक्ष तक आसानी से पहुंच बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
- उनमें से एक अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है जिसे ब्लू ओरिजिन कहा जाता है।
- पिछले साल अक्टूबर में, कंपनी ने न्यू शेफर्ड नामक रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया।
- रॉकेट प्रणाली पर्यटकों को अंततः अंतरिक्ष में ले जाने के लिए होती है और पृथ्वी से 100 किमी ऊपर अंतरिक्ष में जाती है और पेलोड के लिए आवास प्रदान करती है।
- इस तरह के प्रयास वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती संख्या का एक हिस्सा हैं, जो आम लोगों के लिए अंतरिक्ष में आसान और सस्ती पहुंच प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं और अकादमिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी विकास और एक-दूसरों के बीच उद्यमशीलता उपक्रमों के प्रयोजनों के लिए अंतरिक्ष की लागत को प्रभावी बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं।

संबंधित आलेख:

- जैव ईंधन कृषि आय को दोगुना कैसे कर सकता है: यहां क्लिक करें

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - स्टार्ट-अप, इनोवेशन

समाचार में-

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) को 2021-22 से शुरू होने वाले अगले चार वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 1 अप्रैल 2021 से इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप को बीज वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रूपये के कोष को अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा।
- इस योजना के बारे में 3600 स्टार्टअप को समर्थन की उम्मीद है।

स्क्वायर किलोमीटर ऐरे टेलीस्कोप

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन के लिए एक वैश्विक सहयोग ने एक अंतर सरकारी परिषद के गठन के साथ औपचारिक मंज़ूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO) परियोजना दो महाद्वीपों तक फैली हुई है और इसमें 20 देश शामिल है।
- SKAO एक एकल दूरबीन नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रणनीतिक रूप से डिजाइन और स्थापित एंटेना की एक सारणी होगी।
- इस दशक के अंत इसको पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है।
- **लक्ष्य:** ब्रह्मांड और उसके विकास, ब्रह्मांडीय चुंबकत्व की उत्पत्ति और विकास, काली ऊर्जा और आकाशगंगाओं के विकास का अध्ययन।
- इसे दो चरणों में बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके बारे में अनुमान लगाया गया है कि अगले दस वर्षों में 1.8 बिलियन यूरो की आवश्यकता होगी।

क्या आप जानते हो?

- **मुख्यालय:** यूनाइटेड किंगडम
- दक्षिण अफ्रीका में टेलीस्कोप में 197 व्यंजन होंगे और यह कारू क्षेत्र में स्थित होगा।
- ऑस्ट्रेलिया में टेलीस्कोप में 1,31,072 एंटेना होंगे, और यह मर्चिसन रेडियो-खगोल विज्ञान वेधशाला के परिसर में स्थापित किया जाएगा।
- एसकेएओ के माध्यम से भारत परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) भी भाग ले रहा है।

सोशल मीडिया विनियमन: ट्विटर को केंद्र की सूचना

संदर्भ: माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ने 250 से अधिक खातों को बहाल करने के बाद ट्विटर को नोटिस जारी किया है जो सरकार की 'कानूनी मांग' पर पहले निलंबित कर दिए गए थे।

जारी किए गए नोटिस की पृष्ठभूमि

- **किसान विरोध और सोशल मीडिया अभियान:** यह मुद्दा चल रहे किसानों के विरोध पर कुछ हैंडल किए गए ट्वीट से संबंधित है, यह एक हैशटैग है जिसमें बताया गया है कि किसान नरसंहार की योजना बनाई जा रही थी।

- **मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया:** इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन हैंडल (257 यूआरएल और एक हैशटैग) को इस आधार पर अवरुद्ध करने का आदेश दिया कि वे विरोध के बारे में खतरनाक गलत सूचना फैला रहे थे।
- **ट्विटर का जवाब:** ट्विटर ने शुरू में आदेश का अनुपालन किया, लेकिन फिर इन ट्वीट्स और हैंडल को बहाल किया, जिसमें मीडिया हाउस शामिल थे।
- **सरकार के आदेश का आधार:** सरकार का प्रारंभिक आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 A के तहत जारी किया गया था।

आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69 A क्या है?

यह सरकार को एक मध्यस्थ को निर्देशित करने का अधिकार देता है कि वह जनता के हित में किसी भी जानकारी को अवरुद्ध कर सके।

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- भारत की रक्षा
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक आदेश या
- उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकना

यह वही धारा है जिसके तहत हाल के महीनों में सैकड़ों चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया था

क्या सरकारी अनुरोधों के अनुपालन के लिए प्लेटफार्मों की आवश्यकता है?

- प्रौद्योगिकी सेवाओं कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को अब साइबर अपराध से लड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और विभिन्न अन्य अपराध जो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करते हैं।
- ये हैकिंग, डिजिटल प्रतिरूपण और डेटा की चोरी शामिल हैं।
- इंटरनेट और इसके ऑफशूट जैसे मेल, मैसेजिंग सेवाओं और सोशल मीडिया नेटवर्कों से संभावित हानिकारक सामग्री जैसे घृणास्पद भाषण, अफवाहें, भड़काऊ संदेश और बाल पोर्नोग्राफी को प्रसारित करने की क्षमता के कारण कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने लगातार इन माध्यम का उपयोग करने के बुरे प्रभाव पर अंकुश लगाने की मांग की है।
- इसलिए, अधिकांश राष्ट्रों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य बिचौलियों द्वारा सहयोग को अनिवार्य कानून बनाए हैं।

भारत में कानून क्या है?

- भारत में, समय-समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- इसमें सभी 'मध्यस्थ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
- 'बिचौलियों' शब्द में दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा और वेब होस्टिंग के प्रदाता हैं, इसके अलावा खोज इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी स्थल, ऑनलाइन बाज़ार और साइबर कैफे भी शामिल हैं।
- इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को "प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या प्रसारित करता है"। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
- अधिनियम की धारा 69, केंद्र और राज्य सरकारों पर किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी सूचना को अवरोधन, निगरानी या डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

सरकार वेबसाइटों और नेटवर्क को कैसे अवरुद्ध करती है?

- धारा 69A, इसी तरह के कारणों और आधारों पर, जो सूचना को बाधित या मॉनिटर कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर केंद्र को सरकार की किसी भी एजेंसी या किसी मध्यस्थ से किसी भी जानकारी के सार्वजनिक, एक्सेस, प्राप्त या संग्रहीत या होस्ट करने के लिए ब्लॉक करने में सक्षम बनाता है।
- ब्लॉकिंग एक्सेस के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिए गए कारणों पर आधारित होना चाहिए।
- प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को उद्देश्य के लिए तैयार किए गए नियमों में शामिल किया गया है।

भारतीय कानून के तहत बिचौलियों के क्या दायित्व हैं?

- मध्यस्थों को निर्दिष्ट अवधि के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित तरीके और प्रारूप में निर्दिष्ट जानकारी को संरक्षित और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रावधान का विरोध करने पर जुर्माना के अलावा तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
- जब निगरानी, अवरोधन या डिक्रिप्शन के लिए एक दिशा दी जाती है, तो मध्यस्थ, कंप्यूटर संसाधन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को शामिल संसाधन तक पहुंच या सुरक्षा प्रदान करने के रूप में तकनीकी सहायता का विस्तार करना, संबंधित सूचना को इंटरसेप्ट या मॉनिटर या डिक्रिप्ट करना और अनुरोध का अनुपालन करना चाहिए।
- ऐसी सहायता का विस्तार करने पर जुर्माना के अलावा सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
- सरकार के लिखित अनुरोध पर जनता तक पहुंच को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश का पालन करने में विफलता के अलावा, सात साल तक की जेल अवधि भी हो सकती है।
- यह अधिनियम सरकार को यातायात पर डेटा एकत्र करने और निगरानी करने का अधिकार भी देता है। जब एक अधिकृत एजेंसी इस संबंध में तकनीकी सहायता मांगती है, तो मध्यस्थ को अनुरोध का अनुपालन करना चाहिए। गैर-अनुपालन से जुर्माने के अलावा तीन साल तक की जेल हो सकती है।

क्या मध्यस्थ का दायित्व पूर्ण है?

- अधिनियम की धारा 79 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या संचार लिंक उपलब्ध कराने या उसके द्वारा होस्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- यह खंड बिचौलियों जैसे इंटरनेट और डेटा सेवा प्रदाताओं और उन होस्टिंग वेबसाइटों को सामग्री के लिए उत्तरदायी बनाता है जिनसे उपयोगकर्ता पोस्ट या जेनरेट कर सकते हैं।
- हालांकि, दायित्व से छूट लागू नहीं होती है अगर इसमें सबूत है कि मध्यस्थ अधिनियम में शामिल या गैरकानूनी अधिनियम के कमीशन को प्रेरित करता है।
- इसके अलावा, प्रावधान बिचौलियों पर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या किसी गैरकानूनी कार्य के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होने पर जैसे ही यह उनके संज्ञान में लाया जाता है।
- श्रेया सिंघल बनाम यूओआई (2015) में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को पढ़ लिया कि इसका अर्थ यह है कि बिचौलियों को केवल वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर कि अदालत का आदेश पारित किया गया है, जिससे [उन्हें] शीघ्रता से हटाने या कुछ सामग्री तक पहुंच को अक्षम करने के लिए कहा गया।
- यह इसलिए था क्योंकि अदालत ने महसूस किया कि Google या फेसबुक जैसे मध्यस्थों को लाखों अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं, और उनके लिए यह निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है कि इनमें से कौन वैध था।

श्रेया सिंघल केस के बाद सरकार की कार्रवाई क्या रही है?

- बिचौलियों की भूमिका को 2011 में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अलग-अलग नियमों में लिखा गया था। 2018 में, केंद्र ने बिचौलियों की जिम्मेदारियों पर मौजूदा नियमों के नए अपडेट के साथ आने का पक्ष लिया, लेकिन मसौदा विवादित हो गया।
- ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रस्तावित परिवर्तनों में से एक यह मध्यस्थों को आक्रामक सामग्री के प्रवर्तक की पहचान करने में मदद करनी चाहिए।
- इससे गलतफहमी पैदा हुई कि इससे निजता के उल्लंघन और ऑनलाइन निगरानी में मदद मिल सकती है।
- इसके अलावा, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करने वाली तकनीकी कंपनियों ने तर्क दिया कि वे सही की पहचान करने के लिए बैक डोर को नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि यह उनके ग्राहकों के लिए वादा का उल्लंघन होगा।
- अन्य प्रस्तावित परिवर्तनों, जिन पर कार्रवाई नहीं की गई ये नियम शामिल हैं कि बिचौलियों को गैरकानूनी जानकारी को सार्वजनिक रूप से हटाने या अक्षम करने के लिए स्वचालित उपकरणतैनात करने चाहिए और कानून प्रवर्तन की आवश्यकताओं से निपटने के लिए 24x7 यंत्र होना चाहिए।

मुद्दे का महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **सोशल मीडिया पर उपद्रव हिंसा को जन्म दे सकता है:** एक बहुत ही संवेदनशील सेटिंग में, कम से कम एक बिंदु पर बड़े पैमाने पर हिंसा की क्षमता चल रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले किसी भी प्रकार का उकसाना अस्वीकार्य है। इसलिए, लोक व्यवस्था और शांति के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट बिचौलियों का विनियमन आवश्यक है।
- **ट्विटर की कार्रवाई फिसलन ढलान है:** विश्व भर में, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी होने के बिना मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। लेकिन ट्विटर के कानून के अनुसार आदेशों की अवहेलना करने का मतलब है कि स्लिपरी टेरोटेरी (फिसलन भरा इलाका) है।
- **एससी द्वारा धारा 69 को बरकरार रखा गया:** हालांकि प्रक्रिया के आसपास की गोपनीयता के लिए धारा 69 A के उपयोग की अकसर आलोचना की गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में बरकरार रखा था।
- **हैशटैग का अनुच्छेद 19 (1) (A) के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता है:** जबकि ऐसे कई आधार हैं जिन पर सरकार के फार्म विरोध प्रदर्शनों की आलोचना की जा सकती है, यह कहा जा सकता है कि यह जिस हैशटैग को अवरुद्ध किया गया था वह न केवल अप्रिय बल्कि गंभीर रूप से समस्याग्रस्त था, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपरिहार्य था।

निष्कर्ष

इस फेस-ऑफ में आगे जो कुछ होगा वह सिर्फ दो पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व की सरकारों के साथ-साथ विश्व के प्लेटफॉर्म के लिए भी हितकारी होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बिग टेक का प्रभुत्व: यहां क्लिक करें

समाचार में कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- केंद्र ने 250 से अधिक खातों को बहाल करने के बाद ट्विटर को नोटिस जारी किया है जो सरकार की कानूनी मांग पर पहले निलंबित कर दिए गए थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में, समय-समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- इसमें सभी ' मध्यवर्ती संस्थाएँ ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
- **मध्यवर्ती संस्थाएँ शामिल हैं:** दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा और वेब होस्टिंग, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन बाज़ार और साइबर कैफे के प्रदाता।
- इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त, संग्रहीत या प्रसारित करता है।

केंद्र की शक्तियां एक-दूसरे से जुड़ती हैं:

- अधिनियम की धारा 69, केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
- जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, वे हैं: भारत की संप्रभुता या अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, किसी संज्ञेय आयोग के उत्पीड़न को या किसी अपराध की जांच के लिए।
- धारा 69 A केंद्र को सरकार की किसी भी एजेंसी, किसी मध्यस्थ से कंप्यूटर संसाधन पर उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी तक जनता की पहुँच को रोकने में सक्षम बनाता है।
- प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को उद्देश्य के लिए तैयार किए गए नियमों में शामिल किया गया है।

JATP - उत्कृष्टता केंद्र (JATP - CoE)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- डीआरडीओ ने मौजूदा संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे और उद्देश्य का विस्तार करने के लिए आईआईएससी के परिसर में JATP- सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (JATP - CoE) के निर्माण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- JATP-CoE डायरेक्ट बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च को सक्षम करेगा और मल्टी-डिसिप्लिनरी तथा मल्टी-इंस्टीट्यूशनल सहयोग के माध्यम से प्रीमियर रिसर्च संस्थानों के साथ जुड़ने में सक्षम होगा।
- केंद्र में केंद्रित अनुसंधान प्रयासों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति होगी।
- एमओयू के अनुसार, डीआरडीओ JATP को उन्नत और अद्वितीय अनुसंधान सुविधाओं से लैस करने में सहायता करेगा जो संकाय और विद्वानों को उन्नत शोध करने में सक्षम बनाएगा।
- डीआरडीओ भविष्य के अनुप्रयोगों में प्रौद्योगिकी परिणामों का उपयोग करने के लिए उन्नत अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा।

क्या आप जानते हो?

- JATP भारत के राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 1983 में बनाया गया था जहाँ डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने IISc के संकाय के साथ विभिन्न मिसाइल तकनीकों पर काम करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग किया।

आवर्त सारणी में 99 वें तत्व के गुण बताए गए

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- बर्कले लैब के वैज्ञानिकों के एक दल ने एलबर्ट आइंस्टीन के नाम पर "आइंस्टीनियम" नामक आवर्त सारणी में 99 वें तत्व के कुछ गुणों की जानकरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पहली बार, शोधकर्ता इस तत्व के कुछ गुणों को चिह्नित करने में सक्षम हुए हैं।
- इसकी खोज 1952 में पहले हाइड्रोजन बम (प्रशांत महासागर में **आइवी माइक** नामक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के विस्फोट) के मलबे में हुई थी।
- तत्व का सबसे सामान्य समस्थानिक, आइंस्टीनियम 253 में 20 दिनों का आधा जीवन होता है।
- इसकी उच्च रेडियोधर्मिता और सभी आइंस्टीनियम समस्थानिकों के अल्पकालिक जीवन के कारण, भले ही तत्व पृथ्वी पर अपने गठन के दौरान मौजूद था, लेकिन यह निश्चित रूप से क्षय हो गया है।
- यही कारण है कि यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है और इसे बहुत सटीक और गहन प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।

यूएई का होप मिशन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक; अंतरिक्ष

समाचार में-

- यूएई के होप प्रोब के सात महीने बाद जापान में यूएई का पहला मिशन मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, जिसे जापान में तनेगाशिमा से लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसके साथ, मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला यूएई, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और भारत के बाद पांचवां देश बन गया है।
- मानव रहित अंतरिक्ष यान को 'अल-अमल' कहा जाता है - आशा के लिए अरबी शब्द।
- ऐतिहासिक घटना को संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात के एकीकरण की 50 वीं वर्षगांठ में एक साथ होना।
- एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरा और एक स्पेक्ट्रोमीटर सहित तीन उपकरणों को ले जाने से, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की जलवायु की गतिशीलता पर डेटा एकत्र करने के लिए एक कक्षीय मिशन पर है और यह वैज्ञानिकों को समझने में मदद करता है कि मंगल का वातावरण अंतरिक्ष में क्षय क्यों हो रहा है।
- आशा है कि संयुक्त अरब अमीरात का चौथा अंतरिक्ष मिशन और पहला इंटरप्लेनेटरी है।
- पिछले तीनों सभी पृथ्वी- पर्यवेक्षण उपग्रह थे।
- इसका समग्र मिशन जीवन एक मंगल वर्ष है, जो पृथ्वी पर लगभग 687 दिन है।

क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन

संदर्भ: सरकार ने भारत में इन मुद्राओं की वैधता पर मौजूदा अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर एक कानून लाने का प्रस्ताव किया है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोक्यूरेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जो नकली या दोहरे खर्च को लगभग असंभव बना देता है।
- ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित कई क्रिप्टोकरंसीज विकेंद्रीकृत नेटवर्क हैं - कंप्यूटर के एक असमान नेटवर्क द्वारा लागू एक वितरित खाता-बही।

क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन

- सरकार ने समय-समय पर सुझाव दिया है कि यह क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी वैध मुद्रा नहीं मानता।
- सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी की अस्वीकृति इस तथ्य के कारण है कि ऐसी मुद्राएं अत्यधिक अस्थिर हैं, जो अवैध इंटरनेट लेनदेन के लिए उपयोग की जाती हैं और राज्य के दायरे से पूरी तरह बाहर है।
- 2018 में, RBI ने बैंकों को एक परिपत्र भेजा जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया कि वे क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने वालों के लिए सेवाएं प्रदान न करें।
- सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई के परिपत्र को चुनौती देने वालों ने तर्क दिया था कि ये वस्तुओं थीं न कि करंसी। इसलिए, आरबीआई के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था।
- परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग रखा गया था, जो इसे "असम्बद्ध" बताता था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी आदि जैसे नियामक निकायों को क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा नहीं है, क्योंकि वे न तो मुद्राएं हैं और न संपत्ति या पहचान योग्य उपयोगकर्ता द्वारा जारी की गई वस्तुएं हैं।

चुनौतियों

- हालाँकि, यह कानूनी अस्पष्टता, भारत में क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ते उपयोगकर्ता आधार को रोकने में सक्षम नहीं है।
- उनका आकर्षण अब बढ़ सकता है, यह देखते हुए उनमें से सबसे प्रसिद्ध, मूल्यवान, बिटकॉइन ने कीमत में नई उचाईयों तक पंहुचा है और टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क जैसे प्रभावशाली अनुयायियों से को प्राप्त कर रहा है।
- क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, जो उछला है, कथित तौर पर सरकार के साथ लॉबी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मुद्राओं को एकमुश्त प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

आगे की राह

- स्मार्ट विनियमन बेहतर है, क्योंकि किसी चीज पर प्रतिबंध, वितरित वितरित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।
- चीन में भी, जहां क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है, क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग कम है, लेकिन गैर-मौजूद नहीं है।
- सरकार को प्रतिबंध के विचार का विरोध करना चाहिए और स्मार्ट विनियमन के लिए धक्का देना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ब्लॉकचेन और वोटिंग: यहां क्लिक करें

कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और प्रौद्योगिकी

संदर्भ: पुलिस बलों को जनता के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। वे नागरिकों के दैनिक जीवन को बाधित किये बगैर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होते हैं। पुलिस बलों को अक्सर नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और उनके दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। भारत में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात प्रति 100,000 आबादी पर लगभग 150 से कम है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार, यह अनुपात प्रति 100,000 आबादी पर 222 पुलिस बल होना चाहिये।
निम्नलिखित तरीके से LLA अपनी दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं:

1. सिटीजन-फेसिंग सेवाओं को डिजिटाइज़ करना: पुलिस को डिजिटल पहुंच प्रदान करके, नागरिक अपने घर से इस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए: पंजाब पुलिस के पास एक सिटीजन-फेसिंग पोर्टल है जिसका नाम सांझ है, जो FIRS को डाउनलोड करने, चुराए गए वाहनों, खोए हुए मोबाइल की खोज और अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है।
2. विभागीय निगरानी: प्रौद्योगिकी का उपयोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र के डैशबोर्ड विचारों को प्रदान करने, रुझानों, पैटर्न, आउटलेर की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी किया जा सकता है। **3. नागरिक जागरूकता:** डिजिटल पोर्टल्स, सोशल मीडिया का उपयोग LEA द्वारा नागरिकों तक सीधे पहुंचने के लिए किया जा सकता है जैसे- ट्रैफिक जाम के बारे में जानकारी प्रदान करना, साइबर क्राइम से बचाव, अफवाहों को दूर करना, नकली समाचारों का विरोध करना।
4. क्राइम डिटेक्शन: फोन के बढ़ते उपयोग के कारण, मैन्युअल रूप से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सीडीआर) का विश्लेषण करना मुश्किल होता है। सीडीआर विश्लेषण उपकरणों का उपयोग कॉल पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिन्हें अकसर भू-स्थान, नंबर कहा जाता है। जो लापता व्यक्तियों, मोबाइल, आंदोलन को पता लगाने में मदद करना, आपराधिक सहयोगियों के बीच संबंध स्थापित करता है।
5. लीवरेजिंग एआई और बिग डेटा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग उंगलियों के निशान, चेहरे की छवियों का मिलान , सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने और वाहन की नंबर प्लेट को पहचानने के लिए किया जाता है। बिग डेटा का उपयोग कई स्रोतों जैसे कि सोशल मीडिया टूल्स, वित्तीय संस्थानों, यात्रा रिकॉर्ड, होटल में ठहरने, सीडीआर और आपराधिक रिकॉर्ड से डेटा को एकीकृत करने के लिए किया जाता है। यह अपराधी के 360-डिग्री दृश्य बनाने और आपराधिक सहयोगियों के बीच संबंध बनाने में मदद करता है।
6. अपराध की रोकथाम: अपराधों की रोकथाम में बिग डेटा एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसका उपयोग अपराध पैटर्न और हॉट स्पॉट की पहचान करने के लिये किया जा सकता है। इसी तरह अपराध के प्रकार, समय और स्थान के बीच संबंध स्थापित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जा सकता है।
7. दंगा नियंत्रण: सोशल मीडिया चैटर के भावुकता पूर्ण विश्लेषण का उपयोग संभावित दंगों (स्थान और समय सहित) की पहचान करने, साथ ही सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए बनाई गई अफवाहों के स्रोत को ट्रैक करना आदि शामिल है। और अन्य उपयोग जैसे अफवाहों को दूर करने, जनता को प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है।
8. मानव संसाधन प्रबंधन: इसी प्रकार मुख्य प्रदर्शन संकेतकों जैसे कि चार्जशीट दायर करने और शिकायतों को संबोधित करने हेतु लिया गया समय, हल किये गए अपराधों के प्रकार तथा नागरिक प्रतिक्रिया स्कोर का उपयोग बेहतर और तार्किक ढंग से अधिकारियों के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिये किया जा सकता है।
9. आपराधिक न्याय प्रणाली का एकीकरण: 'पुलिस, अदालत, अभियोजन, जेल और फोरेंसिक' आपराधिक न्याय प्रणाली के पाँच स्तंभ हैं। इन संस्थानों के बीच फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अनगिनत मानव-वर्ष (कार्यदिवस के संदर्भ में) नष्ट हो जाते हैं। इन स्तंभों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बीच रियल टाइम इंटीग्रेशन से डुप्लिकेट डेटा प्रविष्टि और त्रुटियों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। यह हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में वृद्धि करेगा और साथ ही न्याय प्रदान करने में लगने वाले समय को काफी कम कर देगा।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी एकीकरण से हमारे LEAs की दक्षता में काफी वृद्धि होगी और साथ ही, न्याय प्रदान करने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी। यह सभी प्रमुख हितधारकों के लिए एक जीत हो सकती है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पुलिस सुधार: यहाँ क्लिक करें
- कस्टोडियल डेथ्स: यहां क्लिक करें

सुपरमैसिव ब्लैक होल, बीएल लैकर्टे से सबसे मजबूत फ्लेयर्स में से एक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अंतरिक्ष; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- भारतीय खगोलविदों ने एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से सबसे मजबूत फ्लेयर्स की जानकारी मिली है जिसे बीएल लैकेर्टे कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- फीडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल में जटिल उत्सर्जन तंत्र होते हैं।
- ये प्रकाश की गति से लगभग गति करने वाले आवेशित कणों के जेट का उत्सर्जन करते हैं।
- वे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान कणों से एक होते हैं।
- बीएल लैकेर्टे ब्लेजर 10 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
- इसे छोटे टेलिस्कोप की मदद से देखा जा सकता है।
- पूरी पृथ्वी ब्लेज़र टेलीस्कोप (WEBT) ने फ्लेयर्स की भविष्यवाणी की थी।
- **महत्व:** (1) यह ब्लैक होल के द्रव्यमान और इस उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाने में मदद करता है; (2) यह ब्रह्मांड के विकास के विभिन्न चरणों में रहस्यों की जांच करने और घटनाओं का पता लगाने के लिए नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

सोशल मीडिया विनियमन: ट्विटर पर केंद्र की नोटिस - भाग 2

मुद्दे के भाग 1 के लिए यहां क्लिक करें (कानूनी परिप्रेक्ष्य से मुद्दे और विश्लेषण की पृष्ठभूमि)

निम्नलिखित तर्कों के कारण ट्विटर ने आईटी अधिनियम की धारा 69 A के तहत भारत सरकार के वैधानिक आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया हैह

- **वैध इनवाइस** : ट्विटर ने कहा है कि सरकार की अवरुद्ध सूची में पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के खाते थे जिनके खाते प्रमाणित प्रतीत होते हैं; उनकी पोस्ट वैध अभिव्यक्ति है
- **असंगत आदेश:** ट्विटर ने कहा है कि यह यथोचित रूप से मानता है कि उन्हें अवरुद्ध रखना भारतीय कानून और मंच के चार्टर उद्देश्यों के विपरीत एक अनुपातहीन कार्य होगा।

ट्विटर क्रियाओं की आलोचना

- **भारतीय कानूनों का अपमान करना:** ट्विटर अधिनियम के तहत सरकार के वैधानिक आदेशों द्वारा बाध्य एक मध्यस्थ है, और इसको न मानना भारतीय कानून के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है।
- **ट्विटर जज नहीं है:** ट्विटर, एक निजी कंपनी के रूप में, आनुपातिक या वैध क्या है, इस बारे में सरकार के फैसले पर अपील नहीं दे सकता लेकिन इस आदेश को अदालत में चुनौती और आंशिक रूप से पालन करने का विकल्प नहीं चुन सकते।
- **अपने कार्यों में असंगतता:** डोनाल्ड ट्रम्प के अकाउंट पर ट्विटर की रोक, भले ही वह यू.एस. के वर्तमान अध्यक्ष थे भले ही वह अमेरिका में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति थे और यहां ब्लॉक करने से इंकार करने से पता चलता है कि अमेरिका भारत के साथ है।
- **बिग टेक की प्रभावहीनता:** ट्विटर की अवहेलना, बिग टेक की बढ़ती शक्ति और अशुद्धता को इंगित करती है, जिसके लिए एक स्पष्ट और असमान शून्य सहिष्णुता प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

आलोचनाओं का प्रतिवाद

- **सरकार की शक्तियां निरपेक्ष नहीं हैं:** ट्विटर ने उचित रूप से एक सूचित बनाई है कि अवरोधक आदेश, भले ही आईटी अधिनियम की धारा 69A (1) के तहत वैध रूप से जारी किए गए हों, आंशिक रूप से वैध नहीं हैं आंशिक रूप से मान्य नहीं हैं और एक चुनौती है आदेशों को लागू करने के लिए सरकार को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

- **मौलिक अधिकार:** यह निर्विवाद है कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस बात पर महत्वपूर्ण नियंत्रण है कि लोगों के स्वतंत्र और सूचित भाषण का अधिकार कैसे पूरा होता है। यांत्रिक रूप से उनकी वैधता, आवश्यकता या आनुपातिकता के संबंध में सरकारी आदेशों का पालन करना दर्शकों के मौलिक अधिकारों को विचारशीलता से प्रभावित करता है
- **लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐच्छिकता पर जाँच:** दो शक्तिशाली संस्थाओं के बीच तनाव - सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म - जिन सवालों पर भाषण को बढ़ावा देना है और जिनके भाषण को घुमावदार बनाना स्वस्थ और रचनात्मक है। यह उस ऐच्छिकता शक्ति पर एक जाँच के रूप में कार्य करता है जो यदि दोनों एक ही पक्ष की दिनचर्या के रूप में प्रबल होते है
- **ट्रम्प मामले के साथ उचित तुलना नहीं:** अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के भ्रामक ट्वीट्स के संबंध में, ट्विटर ने शुरू में अपनी सामग्री को चिह्नित करने के लिए कम घुसपैठ वाले उपाय का सहारा लिया, इसके बाद अपने खाते को निलंबित करने से पहले अपनी पहुंच को सीमित कर दिया। ये सभी कार्रवाइयाँ सरकार के आदेशों के तहत नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए प्रेरित थीं।

निष्कर्ष

- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यू.एस. कानून के तहत बेहतर प्रतिरक्षा और पहले संशोधन संरक्षण का आनंद लेते हैं जो उन्हें सरकारी कार्रवाई के खिलाफ अपने उपयोगकर्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा में मदद करते हैं। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए समान सुरक्षा उपायों को विस्तारित करने का प्रयास, जो सिद्धांत में भी एक सार्वभौमिक मानवाधिकार शासन के तहत समान सुरक्षा की गारंटी का स्वागत करता है।
- सरकार और बिग टेक दोनों की शक्ति को सीमित करने, तर्कसंगत और जिम्मेदारी से कार्य करने तथा अपने दायित्व को लागू करने के लिए संरचनात्मक और संस्थागत समाधान खोजने होंगे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बिग टेक का प्रभुत्व: यहां क्लिक करें

सैंड्स: एक त्वरित संदेश मंच

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- हाल ही में व्हाट्सएप की तर्ज पर सैंड्स नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
- यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सैंड का उपयोग सभी प्रकार के संचार, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किया जा सकता है।
- इसका इंटरफ़ेस वर्तमान में उपलब्ध अन्य ऐप्स के समान है।

क्या आप जानते हो?

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है।
- एनआईसी सरकारी आईटी सेवाओं के वितरण और डिजिटल इंडिया की कुछ पहलों के वितरण में मदद करने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

भू-स्थानिक क्षेत्र का उदारीकरण

संदर्भ: हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) द्वारा भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र (Geo-Spatial Sector) हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जो मौजूदा प्रोटोकॉल को निष्क्रिय कर इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धा हेतु अधिक उदार बनाते हैं।

भू-स्थानिक डेटा क्या है?

- भू-स्थानिक आँकड़ों में पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं, घटनाओं आदि के विषय से संबंधित आँकड़े शामिल होते हैं।
- ये आँकड़े स्थिर और अस्थिर दोनों वस्तुओं का हो सकते हैं, जैसे- सड़क का स्थान, भूकंप की घटना, गतिशील वाहन, पैदल यात्री की चाल, संक्रामक रोग का प्रसार आदि।
- भू-स्थानिक डेटा के उपयोग के परिणामस्वरूप पिछले दशक में खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स, मौसम जैसे विभिन्न एप्स की वजह से दैनिक जीवन में वृद्धि देखी गई है।
- देश में बुनियादी ढाँचे, विकास, व्यवसाय आदि के लिये आँकड़ों की भारी कमी है, जिससे नियोजन में बाधा उत्पन्न होती है।
- इन आँकड़ों का उपयोग स्टार्टअप और व्यवसाय विशेष रूप से ई-कॉमर्स तथा भू-स्थानिक आधारित एप अब अपनी समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं, जिसे इन क्षेत्रों में रोज़गार में वृद्धि होगी।

भू-स्थानिक डेटा पर वर्तमान नीति क्या है?

- संग्रह, भंडारण, उपयोग, बिक्री, भू-स्थानिक डेटा के प्रसार और आंतरिक और साथ ही बाहरी सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित मौजूदा शासन के तहत मानचित्रण पर सख्त प्रतिबंध हैं।
- निजी कंपनियों को सरकार के विभिन्न विभागों (गृह, रक्षा, आदि) से अनुमति की एक प्रणाली को संचालन करने की आवश्यकता है जो भू-स्थानिक डेटा एकत्र करने, बनाने या प्रसारित करने में सक्षम हो।

क्यों सरकार ने भू-स्थानिक डेटा को समाप्त कर दिया है?

- लाइसेंस प्राप्त करने या अनुमति देने की इस प्रणाली ने निजी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों दोनों के लिए परियोजनाओं में देरी की है।
- अविनियमन सुरक्षा चिंताओं के लिए भी अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर जांच भी करता है।
- भारतीय कंपनियां अब सरकारी एजेंसी द्वारा निगरानी किए बिना सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आत्म-सत्यापन कर सकती हैं।
- देश में डेटा की भी भारी कमी है जो आधारभूत संरचना, विकास और व्यवसायों के लिए नियोजन में बाधा डालती है जो डेटा-आधारित हैं।
- पूरे देश की मैपिंग, वह भी उच्च सटीकता के साथ, भारत सरकार अकेले दशकों तक कर सकती है। इसलिए, इस क्षेत्र को खोलने और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने से मानचित्रण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- वैश्विक प्लेटफार्मों पर बड़ी मात्रा में भू-स्थानिक डेटा भी उपलब्ध हैं, जो अन्य देशों में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने वाले डेटा के विनियमन को अस्थिर बनाता है।

ढील

- भू-स्थानिक डेटा जो प्रतिबंधित हुआ करता था अब भारतीय कंपनियों के लिए भारत में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा।
- वे अब प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे और न ही उन्हें भारत के क्षेत्र के भीतर डिजिटल जियोस्पेशियल डेटा और मैप्स को इकट्ठा करने, तैयार करने, स्टोर करने, प्रकाशित करने, अपडेट करने से पहले पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

अवगुण के लाभ

- **क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएँ:** प्रणाली को सरल बनाकर, वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को सरकारी क्षेत्र में अधिक खिलाड़ियों को सुनिश्चित करेगी।
- **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण:** यह सुनिश्चित करेगा कि योजनाओं को तैयार करने और इसके कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सरकार के पास अधिक सटीक डेटा उपलब्ध है। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे नदियों के संपर्क, औद्योगिक गलियारों का निर्माण और स्मार्ट पावर सिस्टम की तैनाती।

- **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना:** मैपिंग उद्योग का सरलीकरण और मौजूदा डेटासेट का लोकतंत्रीकरण, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और भारतीय कंपनियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर वैश्विक मैपिंग पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम करेगा।
- **आत्मनिर्भर भारत:** भारतीय कंपनियां स्वदेशी ऐप विकसित कर सकेंगी, उदाहरण के लिए गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण द्वारा हुआ।
- **रोजगार सृजन:** यह कदम देश के निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए जायदा अवसर प्रदान, नवाचारों को बढ़ाना और स्केलेबल समाधानों का निर्माण करेगा जो बदले में रोजगार पैदा करेगा।
- **अर्थव्यवस्था में निवेश और वृद्धि:** सरकार को कंपनियों द्वारा भू-स्थानिक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की भी उम्मीद है, और विदेशी कंपनियों और देशों को डेटा के निर्यात में वृद्धि भी है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

नासा का दृढ़ता और चीन का तियानवेन -1 मंगल मिशन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अंतरिक्ष; विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- नासा की दृढ़ता और चीन की तियानवेन -1 क्रमशः 18 फरवरी और मई 2021 में मंगल पर उतरने के लिए तैयार हैं।

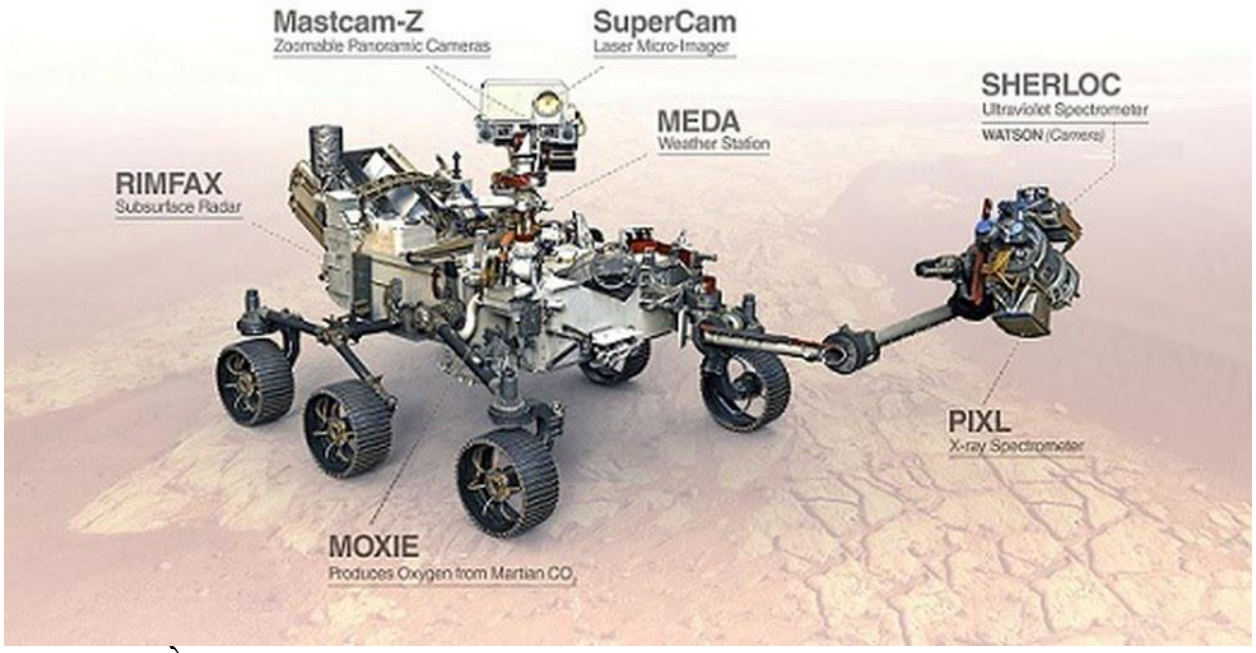

नासा का दृढ़ता रोवर

- यह सबसे परिष्कृत मिशन है।
- यह Jezero Crater में उतरने के लिए तैयार है, जो पहले से ही पानी से भरा हुआ था।
- यह नासा की चौथी पीढ़ी का मंगल रोवर है।
- **लक्ष्य:** Jezero Crater में सूखने वाली झील के बिस्तर में बायोसिग्नेचर देखने के लिए।

तियानवेन -1

- तियानवेन -1 चीन से मंगल पर पहला मिशन है।

- यह एक परिक्रमा, एक लैंडर और एक रोवर ले जाता है।
- इस साल मई में भूमि पर उतरने से पहले कुछ महीनों के लिए यह मंगल की परिक्रमा करेगा।

ग्रीन हाइड्रोजन

संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों आर एंड डी में 100 मिलियन डॉलर तक के निवेश की घोषणा करने के चार महीने से भी कम समय बाद, भारत ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (एनएचएम) की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट में औपचारिक रूप से एनएचएम के लिए प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) एक महीने के भीतर मसौदा नियमों को प्रकाशित करेगा।

भारत में पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है

- अक्टूबर में, छह महीने के पायलट प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन स्पाइक्ड कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (H-CNG) पर चलने वाली बसों का संचालन करने वाला दिल्ली पहला भारतीय शहर बन गया। सीएनजी में एचओसी- 18 प्रतिशत हाइड्रोजन सीधे प्राकृतिक गैस से उत्पादित करने के लिए IOCL द्वारा पेटेंट की गई नई तकनीक पर बसें चलेंगी।
- पावर प्रमुख एनटीपीसी लिमिटेड लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल-आधारित इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कारों को चलाने के लिए एक पायलट का संचालन और आंध्र प्रदेश में एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

हाइड्रोजन ईंधन

- हाइड्रोजन प्रकृति में उपयोग हेतु मात्रा में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है।
- इसे प्राकृतिक गैस से बनाया जा सकता है या पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह द्वारा बनाया जा सकता है।
- जब हाइड्रोजन जलाया जाता है, तो यह केवल जल वाष्प का उत्सर्जन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का उत्पादन नहीं होता है।
- यह आंतरिक दहन इंजन की तुलना में अधिक कुशल है।
- हालांकि हाइड्रोजन एक अणु है, लेकिन इसे निकालने की प्रक्रिया सघन ऊर्जा है। इसके अलावा, हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहन का निर्माण महंगा है।
- जिन स्रोतों और प्रक्रियाओं से हाइड्रोजन प्राप्त होता है, उन्हें रंग टैब द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।
- जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है; यह उत्पादित हुए हाइड्रोजन के ढेर को ग्रहण करता है।
- कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन को नीले हाइड्रोजन कहा जाता है।
- पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अंतिम प्रक्रिया में, अक्षय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मामला

ग्रीन हाइड्रोजन के विशिष्ट फायदे हैं।

- पर्यावरण के अनुकूल: ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को अगली बड़ी चीज के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके उपयोग से शून्य उत्सर्जन होगा
- **देकार्बोनीज़ विभिन्न क्षेत्रों के लिए संभावित:** यह एक साफ जलने वाला अणु है, जो लोहे और इस्पात, रसायन और परिवहन सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनेट कर सकता है।
- **रिन्यूएबल एनर्जी का कुशल उपयोग:** रिन्यूएबल एनर्जी जिसे ग्रिड द्वारा संग्रहित या उपयोग नहीं किया जा सकता है, हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इसे चैनल किया जा सकता है।

- **दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता में कमी:** ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक गतिशीलता को साफ करने की कुंजी भी रखता है जो दुर्लभ खनिजों पर निर्भर नहीं करता है। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण के रूप में खनिजों और दुर्लभ-पृथ्वी तत्व-आधारित बैटरी पर निर्भरता की दीर्घकालिक दृष्टि को प्राप्त करने में मदद करता है।
- **पेरिस लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है:** भारत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हरित हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वपूर्ण है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** हरित ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने में मदद करती है

कई क्षेत्रों के लिए लागू: विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन वाहन लंबी-लंबी ट्रकिंग और अन्य हार्ड से विद्युतीकरण क्षेत्रों जैसे कि शिपिंग और लंबी-लंबी हवाई यात्रा में प्रभावी हो सकते हैं। इन अनुप्रयोगों में भारी बैटरी का उपयोग करना विशेष रूप से देशों के लिए प्रतिकूल होगा। जैसे कि भारत, जहां बिजली ग्रिड मुख्य रूप से कोयला आधारित है।

- **क्षमता:** हाइड्रोजन आधारित वाहन बैटरी आधारित ईवी के लिए चार्ज करने में 30-45 मिनट की तुलना में सिर्फ पांच मिनट का ईंधन भरने का समय लगता है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट वॉल्यूम और वजन के बारे में पांच गुना बेहतर ऊर्जा भंडारण मिलता है।

हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में चुनौतियां

- **ईंधन की अवसंरचना:** हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों को अपनाने के लिए एक बड़ा अवरोधक ईंधन स्टेशन के बुनियादी ढांचे की कमी है - ईंधन सेल कारें पारंपरिक कारों के समान तरीके से ईंधन भरती हैं, लेकिन एक ही स्टेशन (दुनिया में केवल 500) का उपयोग नहीं कर सकती हैं और वह भी यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया आदि।
- **सुरक्षा को एक चिंता के रूप में देखा जाता है:** हाइड्रोजन को एक क्रायोजेनिक टैंक में दबाया और संग्रहीत किया जाता है, वहाँ से इसे एक निम्न-दबाव सेल में खिलाया जाता है और विद्युत-रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है।
- प्रौद्योगिकी को स्केल करना और महत्वपूर्ण द्रव्यमान प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। सड़क पर अधिक वाहन और अधिक सहायक बुनियादी ढाँचा लागत कम कर सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल: यहां क्लिक करें

यूके COVID-19 के लिए पहला मानव चुनौती परीक्षण

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II हेल्थ एंड जीएस - III - बायोटेक्नोलॉजी

समाचार में-

- यूके अब से एक महीने के भीतर पहला COVID-19 मानव चुनौती परीक्षण (HCT) आयोजित करने जा रहा है।
- **द्वारा संचालित:** यूके सरकार के टीकेफोर्स टास्कफोर्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन, रॉयल फ्री लंदन एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट और नैदानिक कंपनी एचवीआईवीओ।

महत्वपूर्ण तथ्य

- परीक्षण पहली बार अक्टूबर 2020 में घोषित किया गया।
- इस अध्ययन में, 18-30 वर्ष की आयु के बीच के 90 से अधिक स्वस्थ स्वयंसेवकों को नियंत्रित सेटिंग्स में वायरस की थोड़ी मात्रा के साथ जानबूझकर लगाया जाएगा
- **उद्देश्य:** उपचार और टीकों का परीक्षण करना।
- इस तरह, प्रतिभागियों को वायरस द्वारा "चुनौती दी" जाती है।
- यह मानक वैक्सीन परीक्षणों के समान नहीं है।

- **महत्व:** एचसीटी रोग और मनुष्यों पर इसके प्रभावों के बारे में अधिक सटीक जानकारी देने में सक्षम और संक्रमित मनुष्यों पर टीकों की प्रभावकारिता के बारे में भी परिणाम देते हैं।

नई लेड (Pb) मुक्त सामग्री की खोज की

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक; भारतीयों की उपलब्धियां

समाचार में-

- वैज्ञानिकों ने एक नई लेड (Pb) मुक्त सामग्री पाया है।
- इसकी पहचान वैज्ञानिकों ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR), बेंगलुरु में की गई।
- इसे कैडमियम (Cd) डॉप्ड सिल्वर एंटिमोनी टेल्यूराइड (AgSbTe2) कहा जाता है।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- यह हमारे छोटे घरेलू उपकरणों और ऑटोमोबाइल को बिजली देने के लिए कुशलतापूर्वक अपशिष्ट गर्मी में परिवर्तित कर सकता है।
- अब तक विकसित सबसे कुशल थर्मोइलेक्ट्रिक सामग्री बड़े घटक तत्वों के रूप में लेड (पीबी) का उपयोग करते हैं, बड़े पैमाने पर बाजार अनुप्रयोगों के लिए उनके उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
- यह काम स्वर्ण-जयंती फैलोशिप द्वारा समर्थित है।

क्या आप जानते हो?

- भारत सरकार द्वारा भारत की 50 वीं स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना शुरू की गई थी।
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सक्षम करने के लिए एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ चयनित युवा वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करता है।

देवस्थल टेलीस्कोप

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में-

- देवस्थल पर स्थापित ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने गामा-रे बर्स्ट्स और सुपरनोवा जैसी महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय विस्फोटक घटनाओं के अवलोकन के लिए वैश्विक महत्व का अनुमान लगाया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- देवस्थल उत्तराखंड में एक पर्वत शिखर है।
- यह एक विश्व स्तरीय 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है।

- यह एशिया का सबसे बड़ा पूरी तरह से चलाने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप है।
- **स्थापित:** आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज (ARIES), 2016 में बेल्जियम सरकार के समर्थन के साथ, DST का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
- यह भविष्य के ऑप्टिकल सुविधाओं जैसे कि थर्टी मीटर टेलीस्कोप के लिए भी उपयोगी होगा।

संबंधित आलेख:

- एसएन 2010kd: एक सुपर-चमकदार सुपरनोवा

भारत शहरी डाटा एक्सचेंज (IUDX) का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- शासन और जीएस - III - सूचना प्रौद्योगिकी

समाचार में-

- हाल ही में भारत शहरी डेटा एक्सचेंज (IUDX) लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामले

महत्वपूर्ण तथ्य

- IUDX को स्मार्ट सिटीज मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के बीच साझेदारी में विकसित किया गया है।
- IUDX डेटा प्रदाताओं और डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य:** शहरों, शहरी शासन और शहरी सेवा वितरण से संबंधित डेटासेट साझा करना, अनुरोध करना और एक्सेस करना।
- यह एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है।
- यह विभिन्न डेटा प्लेटफार्मों के बीच डेटा के सुरक्षित और प्रमाणित विनिमय को सुनिश्चित करेगा।

संबंधित आलेख:

- टेक्नोग्राही के लिए नामांकन मॉड्यूल लॉन्च किया गया।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II शासन और जीएस - III - सूचना प्रौद्योगिकी

समाचार में-

- हाल ही में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) शुरू किया गया।
- **मंत्रालय:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

महत्वपूर्ण तथ्य

- NUDM शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा।
- यह शहरों और कस्बों को पूरा समर्थन प्रदान करने के लिए लोगों, प्रक्रिया और मंच के तीन स्तंभों पर काम करेगा।
- यह शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत करेगा।
- यह 2024 तक भारत के सभी शहरों और कस्बों में क्रियाशील होगा।

न्यू सोशल मीडिया कोड

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट (प्रज्जवल मामले) के निर्देशों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में संसद में उठाई गई चिंताओं का हवाला देते हुए, सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सोशल मीडिया, डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सामग्री प्रदाताओं को विनियमित करना है।

सरकार तीन साल से इन दिशानिर्देशों पर काम कर रही थी लेकिन हालिया ट्विटर विवाद से गहरा झटका लगा

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

1. **ऑनलाइन सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गरिमा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं:**

- बिचौलियों से संबंधित सामग्री की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बिचौलियों को हटा दिया जाएगा या उन्हें अक्षम कर दिया जाएगा।
- इस तरह की शिकायत व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।।

2. शिकायत निवारण तंत्र

- सोशल मीडिया पर मध्यस्थों को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे में शिकायतें दर्ज करके 5 दिनों के भीतर इसका समाधान करे
- शिकायत निवारण अधिकारी को भारत में निवासी होना चाहिए।

3. सोशल मीडिया मध्यस्थों के दो वर्ग

- महत्वपूर्ण अनुपालन की आवश्यकता के लिए छोटे प्लेटफार्मों को जारी किए बिना नए सोशल मीडिया मध्यस्थों के नवाचारों और विकास को प्रोत्साहित करना, यह नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों और महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया के बीच अंतर करते हैं।
- यह अंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं की संख्या पर आधारित है (जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा)
- नियमों को कुछ अतिरिक्त देय का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों की आवश्यकता होती है।

4. महत्वपूर्ण कारण परिश्रम के बाद महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमेडरी का अनुसरण करना

- महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को अब भारत में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, जो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24 × 7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त करने की भी आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई के विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा लगातार हटाए गए सामग्रियों के विवरण को प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी।
- महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ का भारत में अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या दोनों पर प्रकाशित शारीरिक संपर्क पता होगा।
- मामले में, मध्यस्थ, सुरक्षित बंदरगाह प्रावधानों (आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79) का पालन नहीं करने के कारण उन पर लागू नहीं होगा।

5. ट्रेसबिलिटी

- चरितार्थ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महत्यपूर्ण सामग्री के पहले प्रवर्तक के रूप में प्रकट करना आवश्यक होता, जैसा कि अदालत के आदेश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत पारित आदेश के लिए आवश्यक होता है।
- यह आदेश केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या सार्वजनिक व्यवस्था, या उत्पीड़न से संबंधित अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या दंड के प्रयोजनों के लिए पारित

किया जाएगा। बलात्कार, यौन स्पष्ट सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री के संबंध में एक अपराध जो पांच साल से कम अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय है।

- प्रथम प्रवर्तक को किसी भी संदेश या किसी अन्य जानकारी की सामग्री का खुलासा करने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी।

6. गैरकानूनी जानकारी को हटाना

- नियम सामग्री की 10 श्रेणियां निर्धारित करते हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को होस्ट नहीं करना चाहिए। इनमें वह सामग्री शामिल है जो
    - भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या सार्वजनिक व्यवस्था, या
    - किसी भी संज्ञेय अपराध के आयोग को उकसाने का कारण बनता है, किसी अपराध की जांच को रोकता है या किसी विदेशी राज्य का अपमान कर रहा है
    - बदनाम, अश्लील, पाओडोफिलिक, दूसरे की गोपनीयता का आक्रामक, जिसमें शारीरिक गोपनीयता भी शामिल है
    - लिंग के आधार पर अपमान करना या परेशान करना;
    - अपमानजनक, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक;
    - मनी लॉन्ड्रिंग या जुआ से संबंधित या प्रोत्साहित करना, या
    - अन्यथा भारत के कानूनों के विपरीत या असंगत
- नियम यह निर्धारित करता हैं कि अदालत या उपयुक्त सरकारी एजेंसी से निषिद्ध सामग्री की मेजबानी करने वाले मंच के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, उसे 36 घंटे के भीतर उक्त सामग्री को हटा देना चाहिए।

7. स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र

- जो उपयोगकर्ता अपने खातों को स्वेच्छा से सत्यापित करना चाहते हैं, उन्हें अपने खातों को सत्यापित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र प्रदान किया जाएगा और सत्यापन के प्रदर्शन और दृश्य चिह्न प्रदान किए जाएंगे।

8. उपयोगकर्ताओं को सुनने का अवसर देना

- ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ किसी भी जानकारी को अपने हिसाब से हटाते हैं या उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, तो उसी के लिए एक पूर्व सूचना उपयोगकर्ता को दी जाएगी।
- मध्यस्थ द्वारा की गई कार्रवाई के लिए उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

9. ओटीटी सेवाओं के लिए नियम

- **आईटी अधिनियम, 2000 के दायरे में लाया गया:** डिजिटल मीडिया, ओटीटी और इंटरनेट पर अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा, लेकिन समग्र वास्तुकला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत होगा, जो डिजिटल प्लेटफार्मों को नियंत्रित करता है।
- **ऑनलाइन समाचार, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता:** इस आचार संहिता में ओटीटी प्लेटफार्मों, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन किया है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- बड़ी तकनीक का प्रभुत्व
- ऑस्ट्रेलिया का समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता

ग्लोबल बायो-इंडिया 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - विज्ञान और तकनीक; जैव प्रौद्योगिकी

समाचार में-

- ग्लोबल बायो-इंडिया का दूसरा संस्करण 1-3 मार्च 2021 से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मजबूती और अवसरों का दिखाना
- इन-इंडिया के साथ साझेदारी में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) द्वारा सह-संगठित।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **थीम:** "ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ"
- **टैग लाइन:** "बायोसाइंसेस टू बायोसोनॉमी"
- 50+ देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- भारत का राज्य भागीदार के रूप में स्विट्जरलैंड भागीदार देश और कर्नाटक होगा।
- ग्लोबल बायो-इंडिया 2019 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

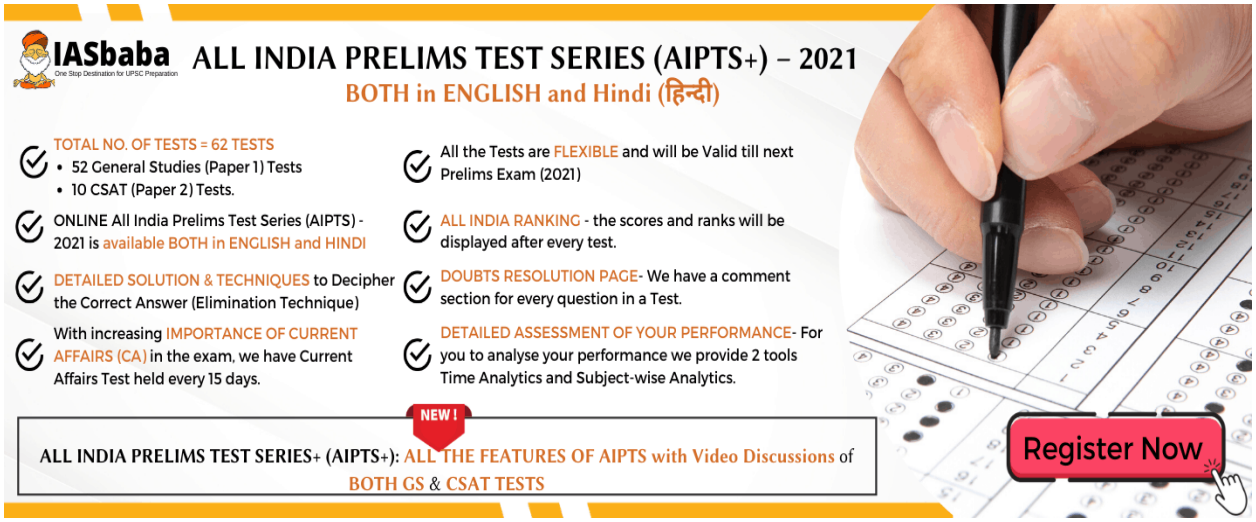

आपदा प्रबंधन

उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा

प्रसंग: उत्तराखंड के नंदादेवी पर्वत के एक ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने और आगामी बाढ़ में कई लोगों की जान चली गई।

वास्तव में क्या हुआ?

- उत्तराखंड के चमोली जिले में बाढ़ के बाद 200 से अधिक लोग लापता हो गए। अब तक 20 शव बरामद किए गए।
- हिमालय की ऊपरी ऊंचाई में ग्लेशियर के फटने के कारण बाढ़ आई।
- अलकनंदा नदी प्रणाली (चमोली जिले में ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी) में उत्पन्न हिमस्खलन और जलप्रलय ने एक पनबिजली स्टेशन (तपोवन बिजली परियोजना) और पांच पुलों (जो आस-पास के गांवों से जुड़े हुए हैं) को बहा ले गया गया।
- राज्य में मल्टी-एजेंसी से बचाव कार्य जारी है तथा राहतकर्मियों ने प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को बाहर निकाला गया।
- भूभाग और कम तापमान के कारण सुरंग में कीचड़ और मलबे से बचाव दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है।

किस वजह से आई बाढ़?

- अब तक जहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ की दूरदर्शिता का किसी के पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर बर्फ के ब्लॉक तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर को तोड़ दिया, जिससे भारी मात्रा में पानी निकल गया।
- यह चट्टानों और कीचड़ को नीचे लाने वाले हिमस्खलन का कारण बन सकता था। यह एक मजबूत संभावना थी क्योंकि भारी मात्रा में तलछट नीचे बह रही थी।
- एक अन्य संभावना यह थी कि हिमस्खलन या भूस्खलन ने कुछ समय के लिए नदी को नुकसान पहुंचाया हो, जिससे जल स्तर बढ़ने के बाद यह फट सकता था।
- विशेषज्ञों का कहना है कि हिमस्खलन ग्लेशियल झील को भी चपेट में ले सकता था जो फट सकती थी। (ग्लेशियल झील का प्रकोप बाढ़- GLOF के रूप में जाना जाता है।)

क्या आपको पता है?

- धौलीगंगा, उत्तराखंड के हिमालय में अलकनंदा, गंगा के बाएँ तट की एक सहायक नदी है।
- धौलीगंगा, रैनिगा नदी से रेनी में शामिल हो जाती है, जहां बिजली परियोजना बांध पर आपदा हुई थी।

स्रोत: बीबीसी

उत्तराखंड त्रासदी का आलोचनात्मक विश्लेषण

- **विकासात्मक चुनौतियां:** त्रासदी जलवायु-परिवर्तन प्रभावों से जटिल, पारिस्थितिक तंत्र, स्थलाकृति और विकास अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाने में विफल है। क्षेत्र में विकास की बढ़ती गति ने वनों की कटाई और अन्य पर्यावरणीय मुसीबतों से गिरने के बारे में आशंकाओं को बढ़ा दिया है।
- **इस तरह की त्रासदियों के कारण जलवायु परिवर्तन:** वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन द्वारा बेअसर प्रोलगेशियल झीलें भूमिका बन सकती हैं, जो विकास परियोजनाओं द्वारा खराब हो सकती हैं।
- **भूकंप प्रवण क्षेत्र:** विशेषज्ञों ने बताया है कि सैकड़ों विद्युत परियोजनाएं और सड़कों का क्षेत्रफल बढ़ना पारिस्थितिक रूप से टूटे-फूटे क्षेत्र के साथ तबाही मचा रहा है जो भूकंप से ग्रस्त है।
- **भयंकर स्मरण:** त्रासदी एक घातक अनुस्मारक के रूप में आती है कि इस टूटे-फूटे, भूगर्भीय गतिशील क्षेत्र को कभी भी नहीं लिया जा सकता है।

- **राज्य का पर्यावरणीय खोना:** एक बार सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चिपको आंदोलन ने पर्यावरणवाद की क्रूरता के कारण, राज्य के गहरे घाटियों ने भूकंप जोखिम के लिए थोड़ी चिंता के साथ कई पनबिजली परियोजनाओं और बांधों को आकर्षित किया है।
- **कोई नई घटना नहीं:** लाल झंडे को बार-बार उठाया गया है, विशेष रूप से 1991 में क्षेत्र में मध्यम भूकंप के बाद, जहाँ टिहरी बांध बनाया गया था और 2013 में आई बाढ़ ने केदारनाथ को तबाह कर दिया, जो कई तरह अस्थिर ग्लेशियल झीलों और जलवायु परिवर्तन, बांध-प्रेरित सूक्ष्मवाद, भूस्खलन और बाढ़ से खतरे की ओर इशारा करता है।
- **जलविद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र:** भारत में जलविद्युत के विकास में बड़े पैमाने पर हिमालय क्षेत्र में (पहाड़ियों में 28 नदी घाटियों में बांध बनाने की योजना) निवेश किया जाता है, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कटौती हो सके। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के खतरों में संभावित भूकंप प्रभाव, जैव विविधता का नुकसान और समुदायों के लिए अत्यधिक खतरा शामिल है।
- **बांधों के जीवन का विविधीकरण:** कुछ सबूत भी हैं कि बांधों का जीवन अकसर अतिशयोक्तिपूर्ण होता है, तथा गाद कम करता है, सकल रूप से कम आंका जाता है- उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध में, यह गणना की गई थी कि गाद 140% से अधिक थी।
- **भविष्य में खतरे:** ग्लेशियर झीलों की संख्या और क्षेत्र में आने वाले दशकों में अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि होती रहेगी, और नई झीलें अस्थिर पहाड़ो के करीब विकसित होंगी, जहां झील का प्रकोप अधिक आसानी से हो सकता है

निष्कर्ष / आगे की राह

- केंद्र और उत्तराखंड सरकार पर्यावरण के झटके के कारण राज्य की बढ़ती धोखाधड़ी के संदर्भ की अनदेखी नहीं कर सकते।
- हिमालय पर नीति के प्रभाव का कठोरता से अध्ययन करने और कम से कम प्रभाव वाले लोगों को जलविद्युत परियोजनाओं को सीमित करने की है, जबकि कम प्रभाव वाली रन-ऑफ-द-नदी बिजली परियोजनाओं पर अधिक भरोसा करते हैं जिन्हें विनाशकारी बड़े बांधों और जलाशयों की आवश्यकता नहीं है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना: यहां क्लिक करें

हिमनद झील का प्रकोप बाढ़ (GLOFs)

GLOFs के बारे में

- ग्लेशियर धीरे-धीरे बढ़ते हुए बर्फ के बड़े पिंड हैं।
- **झील का निर्माण:** जब एक ग्लेशियर पीछे खिसकता है, तो जमीन में एक भारी गड्ढे के रूप में हो जाता है , और पानी भर जाता है जिससे एक झील का निर्माण है। यह एक मोराइन (ग्लेशियर द्वारा बहा कर लाया हुआ मलबा) के रूप में जाना जाता है, जिसे मलबे और दबी बर्फ के अनिश्चित ढेर से लाया गया था।
- **झील का फटना:** जब इस तरह की झील (मोरेन) टूटती है, तो इसे हिमाच्छादित झील के रूप में जाना जाता है। GLOFs एक हिमस्खलन पीछे खिसकने से बने अस्थिर प्राकृतिक बांध से होते हैं। GLOFs के कारण वे उभरी झील से दबाव में गिर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है। पानी का प्रकोप भी कटाव, बर्फ या चट्टान के हिमस्खलन, बर्फ के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकता है।
- **हिंदू कुश हिमालय में, मोराइन-** क्षतिग्रस्त ग्लेशियल झीलें आम हैं कई GOLF घटनाओं को मोराइन बांधों की विफलता का पता लगाया गया है।
- **जलवायु परिवर्तन और GLOFs:** हि हिमनदों का प्रकोप ग्लोबल वार्मिंग से भी संबंधित है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पीछे खिसक जाते हैं, जो पानी से भरे, अस्थिर मोराइन क्षतिग्रस्त झीलों को पीछे छोड़ देते हैं।

- **भविष्य में लगातार होने की संभावना:** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के नवीनतम आकलन रिपोर्टों के अनुसार, ग्लेशियर पीछे खिसकने और पर्माफ्रॉस्ट थावे को पहाड़ की ढलान की स्थिरता को कम करने और ग्लेशियर झीलों की संख्या और क्षेत्र को बढ़ाने का अनुमान है। इस प्रकार GLOFs जैसी घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

GLOF को कम करना

- **ऐसी झीलों की पहचान और उनकी मैपिंग करना:** क्षेत्र की टिप्पणियों, अतीत की घटनाओं जानकारी , झील / बांध और आसपास की भू-तकनीकी विशेषताओं और अन्य भौतिक स्थितियों के आधार पर संभावित खतरनाक झीलों की पहचान की जा सकती है।
- **एक मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली,** कमजोर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण और उत्खनन के लिए एक व्यापक ढांचे को राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित करने की आवश्यकता है।
- **उत्तोलन प्रौद्योगिकी:** एनडीएमए ने मानसून के महीनों के दौरान नए झील निर्माणों सहित जल निकायों के परिवर्तनों का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए सिंथेटिक-एपर्चर रडार इमेजरी के उपयोग की सिफारिश की है। अंतरिक्ष से झील निकायों की दूरस्थ निगरानी की अनुमति देने तरीके और प्रोटोकॉल भी विकसित किए जा सकते हैं।
- **अचानक उल्लंघन को रोकने के लिए संरचनात्मक उपाय:** एनडीएमए पानी के आयतन को कम करने की सलाह देता है जैसे कि नियंत्रित ब्रीचिंग, पंपिंग या पानी को बाहर निकालना, मोराइन बैरियर के माध्यम से या बर्फ के बांध के नीचे सुरंग बनाना।
- **विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करना:** विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करना: जीएलओएफ बहुल क्षेत्रों में निर्माणों और विकास को प्रतिबंधित करना, बिना किसी लागत के जोखिम को कम करने के लिए कुशल साधन है। किसी भी आवास का निर्माण उच्च खतरे वाले क्षेत्र में निषिद्ध होना चाहिए।
- मौजूदा इमारतों को आसपास के एक सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्वास के लिए सभी संसाधनों को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए।
- **निगरानी तंत्र:** मध्यम खतरे वाले क्षेत्र में नई संरचनाएं विशिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ होनी चाहिए। डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और बस्तियों के निर्माण से पहले और बाद में निगरानी प्रणाली होनी चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भूस्खलन
- ध्रुवीय चक्रवात

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

समग्र कच्चे माल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और मिश्रा धातू निगम लिमिटेड (MIDHANI) ने बेंगलुरु में एयरो 2021 के दौरान मिश्रित कच्चे माल के विकास और उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह पहली बार है कि इस तरह के समझौता ज्ञापन पर समग्र कच्चे माल के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

- कंपोजिट कच्चे माल, मुख्य रूप से प्रीपेग्स के रूप में (कार्बन, ऐरेमिड, ग्लास प्रकार, आदि) का उपयोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA), एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH), लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH), और लाइट यूटिलिटी जैसे प्लेटफार्मों में किया जाता है। हेलीकाप्टर (LUH)।
- ये वर्तमान में आयातित हैं।
- यह मिश्रित सामग्री के क्षेत्र में प्रमुख कदम है।
- एचएएल न केवल फ्रंटलाइन विमान उत्पादन बल्कि कच्चे माल की भी देखभाल कर रहा है।
- विमान अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रीप्रेग के लिए कोई भी समान भारत अनुमोदित / योग्य आपूर्तिकर्ता नहीं है।
- यह विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) पर निर्भरता पैदा करता है।
- "आत्म भारत" पहल के साथ, ये प्रयास सहयोग के माध्यम से भारत में इस तरह के प्रीपरग्स के विकास और निर्माण में मदद करेंगे।
- एयरोस्पेस में कंपोजिट का उपयोग जारी रखने और बढ़ाने के लिए जा रहा है, विशेष रूप से लड़ाकू विमान / हेलीकॉप्टरों के लिए क्योंकि इसके धातु के कच्चे माल पर निहित लाभ हैं।

संबंधित आलेख:

- एयरो इंडिया - 2021 - यहां क्लिक करें

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- इंडियन ओशन रीजन (IOR) डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव की शुरुआत 4 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री के बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2021 के मौके पर मुख्य भाषण से हुई।

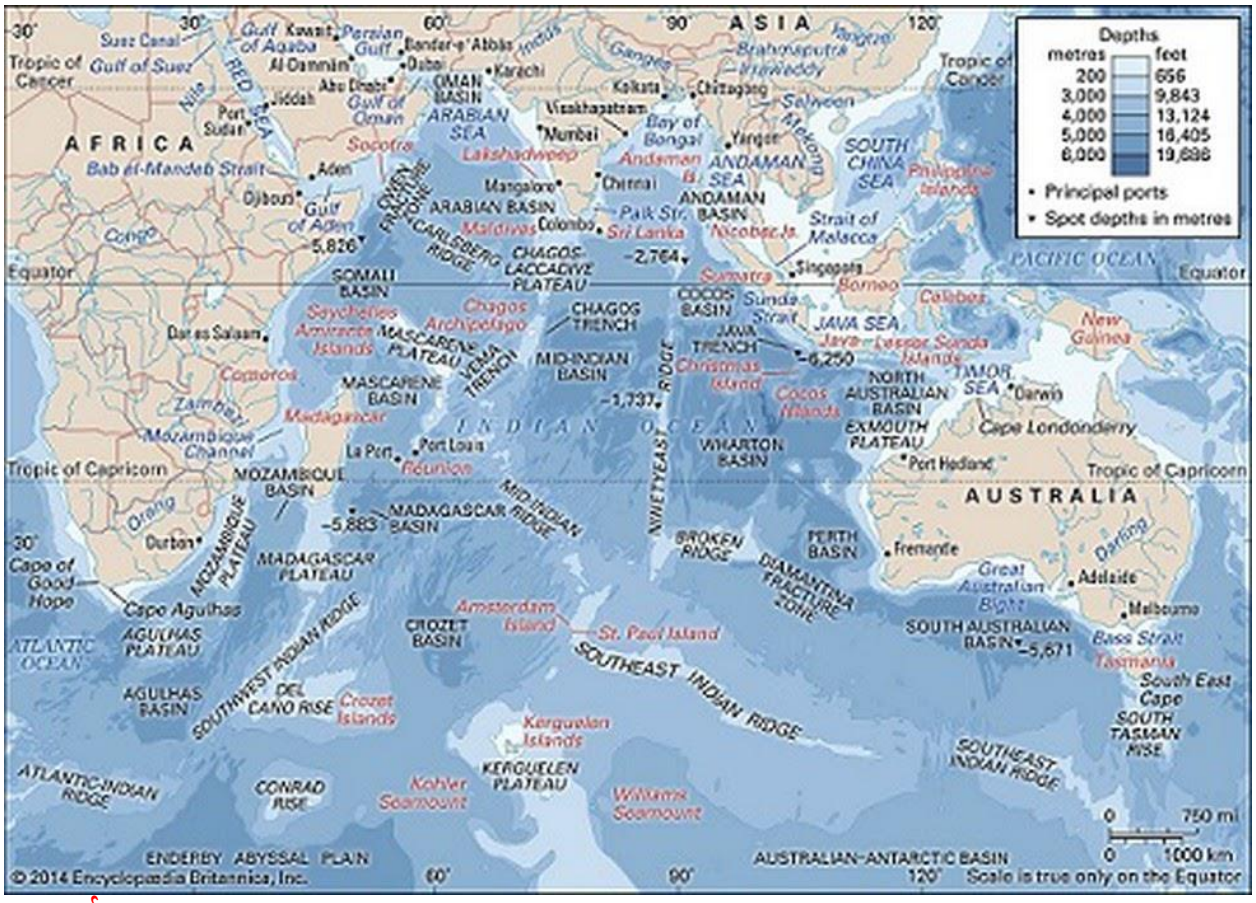

महत्वपूर्ण तथ्य

- 7500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा के साथ आईओआर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़े देश के रूप में, सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह-अस्तित्व के लिए सक्रिय भूमिका है।
- SAGAR - 2015 में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हिंद महासागर नीति का विषय है।
- वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को प्रधान मंत्री की गतिशील पांच विज़न एस - सम्मान (सम्मान), सामवेद (संवाद), सहियोग (सहयोग), शांति (शांति) और समृद्धि (समृद्धि) द्वारा उजागर किया गया था।

संबंधित आलेख:

- एयरो इंडिया - 2021 - यहां क्लिक करें

'मेड इन इंडिया' MK-III एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा; स्वदेशी तकनीक

समाचार में-

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तीन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) भारतीय नौसेना (Indian Navy) को सौंप गया।
- हेलीकॉप्टर तटीय सुरक्षा के लिए मदद करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के नौसैनिक संस्करण में एडवांस सेंसर साथ सुसज्जित किया गया है जो भारतीय नौसेना पर घुसपैठ जैसे मुंबई आतंकवादी हमलों का पता लगा सकता है।
- इन हेलीकॉप्टरों में नवीनतम पीढ़ी के एवियोनिक्स, स्वदेशी कम आवृत्ति वाले डनकिंग सोनार, एक फुल ग्लास कॉकपिट कॉकपिट के साथ HAL के इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम (IADS) लगे हैं।
- इसमें 270-डिग्री कवरेज के साथ एक नाक-माउंटेड निगरानी रडार भी है जो कई समुद्री लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है।
- इसका सिंथेटिक एपर्चर रडार और उलटा सिंथेटिक एपर्चर रडार समुद्र पर लक्ष्य का पता लगा सकता है।

लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (LUH) को प्रारंभिक परिचालन मंजूरी मिली

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (LUH) ने भारतीय सेना के लिए सेंटर फ़ॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन (CEMILAC) से इनिशियल ऑपरेशनल क्लीयरेंस (IOC) प्राप्त हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

- LUH तीन टन की नई पीढ़ी का एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है।
- **स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित:** रोटरी विंग रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ऑफ़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा तैयार किया।
- इसकी विशेषताएं भारत के लिए विविध परिचालन स्थितियों में परिचालन के लिए उपयुक्त हैं।
- एलयूएच सेवाओं द्वारा संचालित चीता / चेतक हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को बदल देगा।

- LUH हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले मिशनों को आसानी से पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति मार्जिन के साथ एक एकल टर्बोशाफ्ट ई द्वारा संचालित है।
- LUH स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम (ग्लास कॉकपिट), अत्याधुनिक HUMS (स्वास्थ्य और उपयोग निगरानी प्रणाली) से सुसज्जित है और इसे विभिन्न उपयोगिता और सशस्त्र भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कामोव-226T: यूटिलिटी हेलीकॉप्टर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- हाल ही में Ka -226 टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खबरों में रहा।
- भारत और रूस द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (टीओटी) के साथ संयुक्त रूप से निर्मित होने वाले Ka-226 टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की कुल स्वदेशी सामग्री 27% -33% के बीच है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सेना में चीता हेलीकॉप्टरों और चेतक हेलीकॉप्टरों का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उनमें से कुछ लगभग 50 साल पुराने भी हैं और उन्हें तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और 'रशियन हेलीकॉप्टर्स' (RH) ने एक साथ मिलकर 'भारत-रूस हेलीकॉप्टर लिमिटेड' (IRHL) नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जो कि भारत में कामोव-226T हेलीकॉप्टरों को असेंबल करेगा।

पृष्ठभूमि की जानकारी:

- 2015 में, भारत और रूस ने कम से कम 200 Ka-226T ट्विन-इंजन यूटिलिटी हेलिकॉप्टरों के लिए एक अंतर-सरकारी समझौता (IGA) किया था, जिसका अनुमान था कि 60 हेलिकॉप्टरों को सीधे आयात किए जाने के लिए $ 1 बिलियन से अधिक की लागत आएगी और शेष 140 का स्थानीय रूप से निर्माण किया जाएगा।
- अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से 36 महीने के भीतर पहला हेलीकॉप्टर वितरित किया जाएगा।
- रूसी प्रस्ताव के अनुसार, स्थानीयकरण योजना चार चरणों में फैलेगी, 35 हेलीकाप्टरों के लिए 3.3% स्वदेशीकरण के साथ, अगले 25 हेलीकाप्टरों के लिए 15% तक, चरण 3 में - 30 हेलीकाप्टरों के लिए 35% और अंत में 50 हेलीकाप्टरों के लिए चरण 4 में 62.4% स्वदेशीकरण।

मैलवेयर: नेटवायर खबरों में

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- एक्टिविस्ट रोना विल्सन ने बॉम्बे HC में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है।
- वह भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जेल में है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एक डिजिटल फोरेंसिक परामर्श कंपनी, आर्सेनल कंसल्टिंग, श्री विल्सन की रक्षा टीम द्वारा काम पर रखा गया था।
- इसकी रिपोर्ट बताती है कि 22 महीनों के लिए, श्री विल्सन का कंप्यूटर एक हमलावर द्वारा नियंत्रित किया गया था
- उनका लक्ष्य विल्सन के कंप्यूटर पर बढ़ते दस्तावेजों को वितरित करना था, जिसने उनके खिलाफ मामले का आधार बनाया।

महत्वपूर्ण बिंदु

नेटवायर

- यह एक प्रसिद्ध मालवेयर है।
- यह सबसे सक्रिय लोगों में से एक है।
- यह एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन (RAT) है जो एक हमलावर को संक्रमित प्रणाली का नियंत्रण देता है।
- ऐसे मैलवेयर कीस्ट्रोक्स लॉग कर सकते हैं और पासवर्ड से समझौता कर सकते हैं।
- मैलवेयर अनिवार्य रूप से दो काम करता है: (1) डेटा एक्सफ़िलिएशन (डेटा चोरी करना); (2) किसी व्यवस्था में घुसपैठ करना।

संबंधित आलेख:

- भारत-जापान साइबर सुरक्षा सहयोग: यहां क्लिक करें
- यूएस साइबर अटैक - सोलरविंड हैक: यहां क्लिक करें

अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (Mk-1A)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- भारत के प्रधानमंत्री ने चेन्नई में एक समारोह में स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक (MK-1A) भारतीय सेना को सौंप।

महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्धन

- सेना को टैंक की 118 इकाइयाँ मिलेंगी।
- ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं।

- अर्जुन टैंक अपने फिन स्टैबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्चार्जिंग फॉर सबोट (एफएसएपीडीएस) गोला बारूद और 120-एमएम कैलिबर वाली राइफल्ड गन के लिए खड़े हैं।
- इसमें स्थिर नियंत्रण के साथ एक कंप्यूटर-नियंत्रित एकीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली भी है जो सभी प्रकाश स्थितियों में काम करती है।
- द्वितीयक हथियारों में एंटी-कर्मियों और एंटी-एयरक्राफ्ट और ग्राउंड टारगेट के लिए मशीनगन शामिल हैं।
- एमके -1 ए संस्करण के पहले संस्करण में 14 प्रमुख उन्नयन हैं।
- हालांकि, नवीनतम संस्करण के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि 54.3% स्वदेशी सामग्री है जो पहले के मॉडल में 41% थी।

क्या तुम जानते हो?

- एमके -1 ए परियोजना को 1972 में DRDO द्वारा शुरू किया गया था।
- लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (CVRDE) इसकी प्रमुख प्रयोगशाला थी।
- 1996 में बड़े पैमाने पर उत्पादन, भारतीय आयुध निर्माणी की उत्पादन सुविधा में अवधी, तमिलनाडु में शुरू हुआ।

ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- हाल ही में ई-छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- **उद्देश्य:** पूरे भारत में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना।
- पोर्टल के माध्यम से, छावनी क्षेत्रों के निवासी पट्टों के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, आदि जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- eGov फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), महानिदेशक रक्षा संपदा (DGDE) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित।

हेलिना और ध्रुवस्त्र के लिए परीक्षण किया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- हेलिना और ध्रुवस्त्र के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण रेगिस्तान रेंज में लाइट हेलीकाप्टर (ALH) प्लेटफॉर्म से किए गए हैं।
- हेलिना, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर-लॉन्च किया गया संस्करण है।
- 'ध्रुवस्त्र' इसका वायु सेना संस्करण है।

महत्वपूर्ण तथ्य

हेलिना

- हेलिना एक तीसरी पीढ़ी का संस्करण है, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च (एलओबीएल) फायर और भूल श्रेणी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) प्रणाली।
- इसमें सभी मौसम दिन और रात परिचालन क्षमता है।
- यह पारंपरिक और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (ईआरए) के साथ युद्धक टैंक को हरा सकता है।

- यह प्रत्यक्ष हिट मोड के साथ-साथ शीर्ष हमले मोड दोनों को लक्षित कर सकता है।
- ध्रुवस्त्र में भी समान गुण होते हैं।
- हालांकि, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में-

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRMAM) के दो सफल प्रक्षेपण किए।
- इसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है।
- DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित।

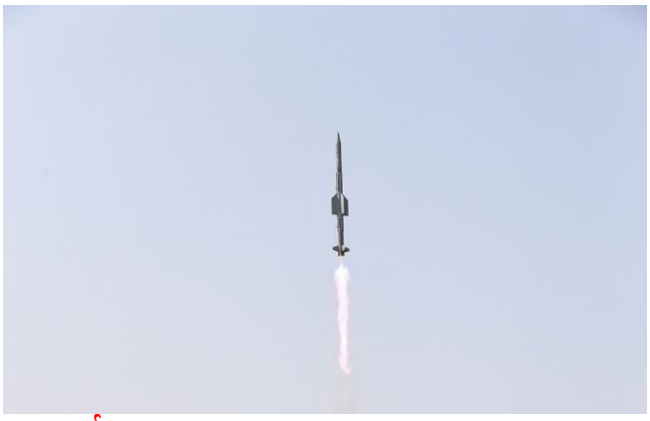

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह समुद्र-स्किमिंग लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर कर सकता है।
- ये प्रक्षेपण, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए किए गए थे।

'ग्रेटर टिपरलैंड'

संदर्भ: हाल ही में त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य ने 'ग्रेटर टिपरालैंड' की एक नई राजनीतिक मांग सामने रखी है। इस शाही वशंज का दावा है कि 'ग्रेटर टिपरालैंड' की उनकी मांग बांग्लादेश में खगराचारी, बंदरबन, चटगांव और अन्य निकटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के बाहर रहने वाले आदिवासियों, गैर-आदिवासियों के साथ-साथ त्रिपुरा में रहने वाले सभी आदिवासियों के हित में काम करेगी।

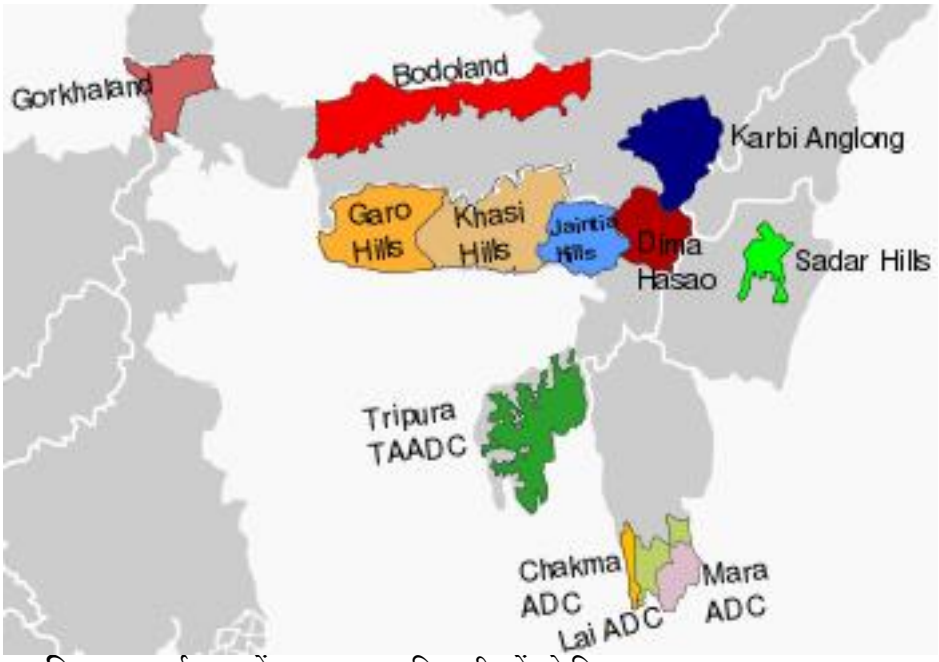

मानचित्र: उत्तर पूर्व भारत में स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों को दिखाना

ग्रेटर टिप्रलैंड की मांग क्या है?

- ग्रेटर टिप्रलैंड 'ग्रेटर नगालिम' की तर्ज पर एक राजनीतिक माँग है
- इसके अलावा प्रस्तावित 'ग्रेटर टिपरालैंड' में पड़ोसी देश बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों- बंदरबन, चटगाँव और खगराचारी आदि में रहने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।
- त्रिपुरा में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी) 7,132.56 वर्ग किमी में फैला हुआ है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% कवर करता है। हालांकि, राज्य की 37 लाख लोगों की आबादी में आदिवासियों की संख्या एक तिहाई शामिल है।
- त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद (TTAADC) के तहत 70 प्रतिशत भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढकी है और अधिकांश निवासी 'झूम' (स्लैश और बर्न) खेती करते हैं हैं। आदिवासी परिषद की 28 सीटों के अलावा, राज्य विधान सभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि आदिवासी मतदाता कम से कम 10 सीटों में एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं।

'टिपरलैंड' और 'ग्रेटर टिप्रलैंड' क्या हैं?

- टिपरलैंड 'स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) की मांग थी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में त्रिपुरा में सत्ता में है। यह स्वदेशी समूहों के लिए एक अलग राज्य के निर्माण के लिए एक राजनीतिक आह्वान था।
- ग्रेटर टीप्रालांड की मांग है कि टीटीएएडीसी के बाहर आज जो भी स्वदेशी क्षेत्र या गांव है उन्हें शामिल किया जाए
- प्रदीप किशोर, जो अब ग्रेटर टिपरलैंड की मांग की अगुवाई कर रहे हैं, ने दावा किया है कि त्रिपुरा में एनआरसी को संशोधित करने और पिछले दिनों सीएए के विरोध में अधूरी मांगों के कारण मांग उठी थी।

समस्या का गंभीर विश्लेषण:

- **वोट बैंक की राजनीति:** TTAADC के आसन्न चुनावों के मद्देनजर, यह प्रद्योत द्वारा उनकी पार्टी, टिपरा इंडिजीनस पीपल्स रीजनल अलायंस (TIPRA) के लिए आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास है।

- **परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य:** प्रद्योत की नई राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के साथ, TIPRA, त्रिपुरा के सबसे बड़े आदिवासी राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। शाही वंशज ने सभी प्रमुख आदिवासी राजनीतिक दलों के साथ एक मेगा विलय और गठबंधन की घोषणा की है। यह राज्य में शक्ति संतुलन को बदल सकता है (सीपीआईएम और सत्तारूढ़ भाजपा-आईपीएफटी सरकार का प्रभुत्व)
- **नए जमाने की जातीय राजनीति:** त्रिपुरा ने पिछले तीन दशकों से अलग-अलग गैरकानूनी विद्रोही संगठनों द्वारा अशांत हिंसक संघर्षों को देखा। सभी अलग-अलग सामुदायिक दिशा पर आत्मनिर्णय और संप्रभुता की मांग कर रहे थे। यह नई मांग जातीय पहचान के आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों से लोगों को एकजुट करने की है।
- **फेडरल स्पिरिट को चुनौती:** ग्रेटर टिपरलैंड अंतिम रूप से लोकतांत्रिक दिशा है, इस तरह की जातीयता सीमाओं पर आधारित होने से उत्तर पश्चिम में विषम संतुलन में बाधा आएगी। यह नागाओं की मांग बढ़ा सकता है और पूरे क्षेत्र को मुकाबलों में शामिल कर सकता है।
- **बांग्लादेश के साथ प्रभाव संबंध:** 2015 के 100 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा का निपटारा हो गया। हालाँकि, ऐसी माँगों में बांग्लादेश में पड़ने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं जो दोनों देशों के बीच सहकारी द्विपक्षीय संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।
- **उग्रवाद पैदा कर सकता है:** यह एक राजनीतिक संवेदनशील मुद्दा है जहां जातीयता, विकास और संघवाद शामिल हैं, केंद्र सरकार को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए इस घटनाक्रम को नजदीकी से देखना और हितधारकों के साथ मिलकर रहनाहै। यदि इसको ऐसा छोड़ दिया गया तो यह उग्रवाद में बदल सकती है।

पश्चिमी गोलार्ध

भले ही इस स्तर पर, परिषद चुनाव के लिए वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है, सरकार (संघ और राज्य दोनों) को इन विकासों पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ब्रू शरणार्थी समझौते और प्रद्युत किशोर की भूमिका: यहाँ क्लिक करें

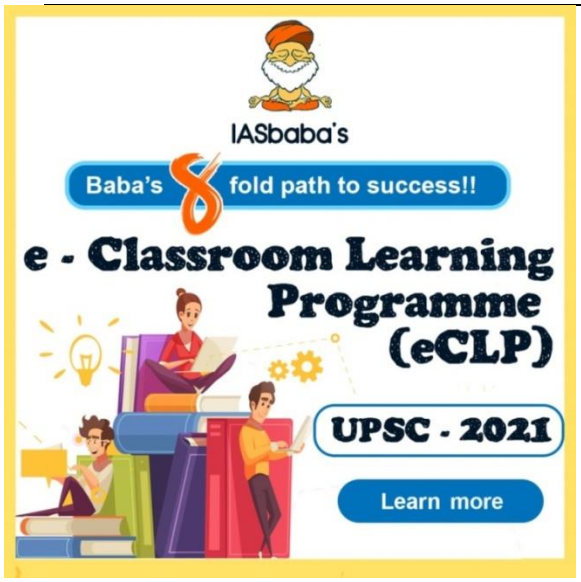

विविध

समाचार	विवरण में
1. एयरो-इंडिया 2021	• एयरो इंडिया 2021 का उद्घाटन समारोह, 03-05 फरवरी, 2021 के बीच बेंगलुरु के वायु सेना स्टेशन, येलहंका में आयोजित किया जा रहा है। • यह एशिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है। • एयरो इंडिया एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है जो भारत के बेंगलुरु में येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित की जाती है। • यह रक्षा प्रदर्शनी संगठन, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। • एयर शो का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था। • एयरो इंडिया 2021, एयरो इंडिया का 13 वां संस्करण है। • इस वर्ष एयरो इंडिया 2021 को अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समवर्ती आभासी प्रदर्शनी के साथ हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है।
2. भीमसेन जोशी	• संगीत के महान पंडित भीमसेन जोशी के जन्म का वर्षगांठ समारोह 4 फरवरी, 2021 से शुरू होगा। • पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी (1922–2011) हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में कर्नाटक के एक भारतीय गायक थे। • उन्हें गायन के साथ-साथ भक्ति संगीत (भजन और अभंग) में लोकप्रिय गायन के लिए जाना जाता है। • भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराना परंपरा से संबंधित हैं। • 1998 में, उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान होता है। • उन्होंने 2009 में भारत रत्न मिला ।
3. जोशीमठ	• हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे धौलीगंगा बांध और लोगों का जीवन खतरे में हो गया । • जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। • यह कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों, ट्रेकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है। • ज्योतिर्मठ उत्तारमण्य मठ या उत्तरी मठ, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार कार्डिनल संस्थानों में से एक है, तथा अन्य श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में हैं।
4. लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना	• नेपाल सरकार ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सबसे बड़ी भारतीय पनबिजली कंपनी SJVN को नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना आवंटित की है।

	• लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल के संखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। • नेपाल में SJVN द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं के परिणामस्वरूप संपूर्ण विकास होगा और भारत और नेपाल में पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
5. विज्ञान में महिलाओं और युवा लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	• **विज्ञान में महिलाओं** और **लड़कियों** की भागीदारी का **अंतर्राष्ट्रीय दिवस** के रूप में **मनाने** के लिए घोषित किया • **मंत्रालय:** महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से • उद्देश्य: (1) उन महिलाओं को मनाने के लिए जिन्होंने एसटीईएम के क्षेत्र में खुद के लिए एक जगह बनाई है; (2) उन युवा लड़कियों को प्रोत्साहित करना जो एसटीईएम में उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान करना चाहती हैं; (3) महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में भागीदारी के लिए पूर्ण और समान पहुंच को बढ़ावा देना • यह 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बाद मनाया गया है। • यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों का विशेष दिन है।
6. तपोवन बांध	• एनटीपीसी के तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट सुरंग में बचाव अभियान फिर से शुरू हुआ, जहां हिमस्खलन के बाद कई कर्मचारी फंसे हुए हैं • इसका निर्माण चमोली जिले के उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर किया जा रहा है। • इस संयंत्र से प्रति वर्ष 2.5 से अधिक बिजली प्राप्त होने की उम्मीद है।
7. ट्रॉपेक्स 21	• TROPEX-21 (थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज) कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। • यह अभ्यास भारतीय नौसेना के तीनों कमांडों, पोर्ट ब्लेयर में त्रि-सेवा कमान, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल शामिल हैं। • यह हर दो साल में आयोजित किया जाता है। • यह भारतीय नौसेना द्वारा किया गया सबसे बड़ा अभ्यास है।
8. आईएनएस प्रलय	• भारतीय नौसेना का जहाज प्रलय, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा। • यह NAVDEX 21 (नौसेना रक्षा प्रदर्शनी) और IDEX 21 (अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी) में भाग लेगा, जो 20 से 25 फरवरी 2021 तक किया जायेगा है। • INS प्रलय स्वदेशी रूप से निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। • जहाज का निर्माण स्वदेशी रूप से महत्वपूर्ण जानकारी: • भारतीय नौसेना का उद्घाटन संस्करण - UAE नेवी द्विपक्षीय अभ्यास GULF STAR 1 मार्च 2018 में आयोजित किया गया था।
9. लक्ष्मी विलास पैलेस	• लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा, गुजरात में स्थित है।

	• इसका निर्माण गायकवाड़ परिवार द्वारा हुआ, जो एक प्रमुख मराठा परिवार था। जिसने बड़ौदा राज्य पर शासन किया था। • इसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने 1890 में बनवाया था। • मेजर चार्ल्स मांट को महल के मुख्य वास्तुकार होने का श्रेय दिया गया। • इसे इंडो-सरैसेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया गया है।
10. नोज़ी ओकोन्जो-इवेला	• नोज़ी ओकोन्जो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया था। • वह इतिहास के पन्नों में यह भूमिका निभाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। • वह महानिदेशक के रूप में चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। • विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है।
11. महामृत्युंजय मंदिर	• महामृत्युंजय मंदिर नौगाँव, असम में स्थित है। • इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा 126 फीट ऊंचा शिवलिंग है। • महामृत्युंजय मंत्र को रुद्र मंत्र या त्र्यंबकम मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। • यह ऋग्वेद का एक श्लोक है। • सूक्त को त्र्यंबक, "द थ्री-आइड वन" से संबोधित किया जाता है, जो रुद्र का उपकथाकार है जिसे शैव धर्म में शिव के साथ पहचाना जाता है। • श्लोक यजुर्वेद में भी आता है।
12. बोरोदुआ तीर्थ	• यह महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली है। • उन्होंने असम से नई वैष्णव परंपरा शुरू की और वैष्णव परंपरा को जीवंत बनाया।

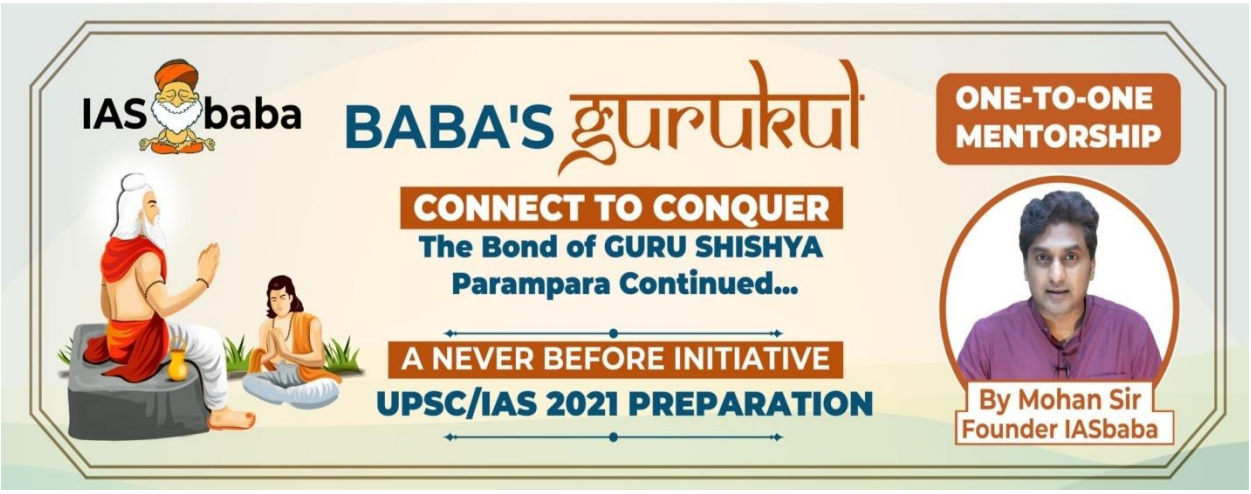

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मॉडल प्रश्न(उत्तर अंत में दिए गए हैं) :

Q.1 निम्नलिखित में से कौन सा देश / देशों पोलियो स्थानिक हैं?

1. नाइजीरिया
2. पाकिस्तान
3. अफगानिस्तान
4. भारत

सही कोड का चयन करें:

a) 1, 2 और 3 ही
b) 2 और 3 ही
c) केवल 1 और 4
d) केवल 1

Q.2 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी उन राज्यों में अधिक है जिन्होंने पीएम जन आरोग्य योजना को अपनाया था, जिन्होंने इसे नहीं अपनाया।
2. शिशु मृत्यु दर हर 100 जीवित जन्मों के लिए शिशु मृत्यु की संख्या है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3 आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में संपूर्ण कर्मचारियों और नियोक्ताओं का ईपीएफ में 24% वेतन का योगदान।
2. 1000 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ के योगदान का केवल 12% मजदूरी का हिस्सा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4 निम्न कथन पर विचार करें:

1. भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी चार प्रमुख किस्मों का उत्पादन करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5 एथिलीन ग्लाइकॉल एक औद्योगिक यौगिक है जो निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में पाया जाता है:

1. ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज़र
2. बॉलपॉइंट पेन
3. सॉल्वैंट्स
4. प्लास्टिक

सही कोड का चयन करें:

a) 1, 2, 3 और 4
b) 2 और 3 ही
c) केवल 1 और 4
d) केवल 1

Q.6 पट्टचत्र चित्रकला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य / राज्य में स्थित है?

1. पश्चिम बंगाल
2. ओडिशा
3. झारखंड
4. महाराष्ट्र

सही कोड का चयन करें:

a) 1, 2, 3 और 4
b) 2 और 3 ही
c) केवल 1 और 2
d) केवल 1

Q.7 रणनीतिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं:

1. रक्षा उपकरणों का हथियार और गोला-बारूद
2. रक्षा विमान और युद्धपोत
3. उच्च ऊर्जा
4. कृषि, चिकित्सा और गैर-रणनीतिक उद्योग में विकिरण के अनुप्रयोग
5. रेलवे
6. पावर डिस्क

सही कोड का चयन करें:

a) 1, 2, 3, 4 और 5
b) 2, 3 और 6 ही
c) केवल 1 और 2
d) 1, 3, 4 और 6 केवल

Q 8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें:

1. लाभार्थी परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार के मुखिया के रूप में माना जाता है।
2. यह अधिनियम प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में देता है, जबकि 5 किलोग्राम खाद्यान्न (प्राथमिकता घरों) PHH व्यक्ति प्रति माह।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9 चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई?

a) सत्याग्रह
b) असहयोग
c) दांडी मार्च
d) भारत छोड़ो आंदोलन

Q.10 कृतयोग हैकथॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?

a) नीति आयोग
b) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
c) इसरो
d) शिक्षा मंत्रालय

Q.11 एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाती है?

a) जापान
b) चीन
c) सिंगापुर
d) भारत

Q.12 निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका में नहीं है?

a) कर्क रेखा
b) भूमध्य रेखा
c) मकर रेखा के ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्र
d) अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा

Q.13 मेट्रोनो जो हाल ही में खबरों में, पहली बार भारत के किस राज्य में अपनाया जाएगा?

a) कोलकाता
b) दिल्ली
c) पंजाब
d) महाराष्ट्र

Q.14 कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू किया गया है?

a) शिक्षा
b) कृषि
c) आईपीआर
d) बाहरी स्थान

Q.15 न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में एक चार्टर अपनाया गया था और विश्व कैंसर दिवस की उत्पत्ति के निशान निम्नलिखित में से किस पर आयोजित किए गए थे?

a) पेरिस
b) एम्स्टर्डम
c) दक्षिण कोरिया
d) भारत

Q.16 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक स्वायत्त निकाय है।
2. यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 निम्नलिखित में से कौन-सी योजनाएँ राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (RYSK) के तहत हैं?
1. नेहरू युवा केंद्र संगठन
2. राष्ट्रीय युवा वाहिनी
3. युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
5. युवा छात्रावास
सही कोड का चयन करें:
a) 1, 4 और 5 ही
b) 1, 2 और 4 केवल
c) 1, 2, 3, 4 और 5
d) 4 और 5 ही

Q.18 'प्रति बूंद अधिक फसल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना का एक घटक है।
2. यह लघु सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है
उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19 स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO) परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. दक्षिण अफ्रीका और ग्रीनलैंड में रणनीतिक रूप से डिजाइन और स्थापित एंटेना की एक सारणी है।
2. इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है ?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20 उत्तर सागर की सीमाएँ निम्नलिखित में से किस देश में हैं?
1. डेनमार्क
2. नॉर्वे
3. जर्मनी
4. फ्रांस
सही कोड का चयन करें:
a) 1,2 और 3 ही
b) 2 और 3 ही
c) 1, 2, 3 और 4
d) केवल 4

Q.21 पहला सी-प्लेन प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यरत है?
a) साबरमती नदी और एकता की प्रतिमा
b) धारोई बांध और अंबाजी
c) शत्रुंजय बांध और तापी
d) गेटवे ऑफ इंडिया और अजंता गुफाएं

Q.22 सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ये टैक्स फ्री हैं।
2. ये निजी कंपनियों द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था?
a) एक आर्थिक और एक मौद्रिक संघ की स्थापना
b) एक सामान्य विदेशी और रक्षा नीति को लागू करना
c) घरेलू मामलों और न्याय के क्षेत्र में संबंध विकसित करना
d) उपरोक्त सभी

Q.24 ट्रांस फैटी एसिड निम्नलिखित में से किसमें होता है?
1. पका हुआ

2. तले हुए
3. प्रोसेस्ड फूड
4. खाना पकाने का तेल

सही कोड चुनें:

a) 1 और 2 ही
b) 4 ही
c) केवल 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.25 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र और राज्य सरकारों पर किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी की निगरानी करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है?

a) धारा 67
b) धारा 87
c) धारा 69
d) धारा 70

Q.26 प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम उपलब्ध है
2. 5% प्रीमियम केवल व्यावसायिक फसलों के लिए उपलब्ध है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27 'विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021' निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है?

a) भारत
b) रूस
c) जापान
d) सिंगापुर

Q.28 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

a) स्विट्जरलैंड
b) फ्रांस
c) जिनेवा
d) नीदरलैंड

Q.29 'नई रोशनी योजना' निम्न में से किस मंत्रालय के तहत है?

a) कृषि मंत्रालय
b) विमानन मंत्रालय
c) वित्त मंत्रालय
d) अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

Q.30 कृषि यांत्रिकीकरण (एसएमएएम) पर 'उप मिशन' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को लक्षित करता है।
2. इस योजना के तहत सब्सिडी वाले कृषि उपकरण और मशीनें भी वितरित की जाएंगी।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31 विश्व का सबसे छोटा वयस्क सरीसृप हाल ही में निम्न में से किस देश में खोजा गया था?

a) इज़राइल
b) मेडागास्कर
c) मोजाम्बिक
d) भूटान

Q.32 99 वें तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो हाल ही में समाचार में देखे गए थे:

1. इसका नाम इस्साक न्यूटन के नाम पर रखा गया है
2. यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.33 निम्नलिखित में से कौन सा लिथियम के उपयोग हैं?

1. चीनी मिट्टी की वस्तुएं
2. ग्लास
3. दूरसंचार
4. एयरोस्पेस उद्योग

सही कोड का चयन करें:

a) 1, 2 और 3 ही
b) केवल 2
c) केवल 1 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.34 Pre, SC और OBC छात्रों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं?

a) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
b) शिक्षा मंत्रालय
c) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय
d) महिला और बाल विकास मंत्रालय

Q.35 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 (OSH Code) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोड केवल संगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों को पूरा करता है।
2. यह हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 10 या अधिक अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 36 निम्न में से कौन सी योजना / योजनाएं जैविक खेती को बढ़ावा देती हैं?

a) मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर राष्ट्रीय मिशन
b) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
c) प्रधान मंत्री-फेसल बीमा योजना
d) दोनों (a) और (b)

Q.37 तपोवन बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया जा रहा है?

a) धौलीगंगा
b) ऋषिगंगा
c) गंगा
d) यमुना

Q.38 थोलपावकुथु, छाया कठपुतली का एक रूप है, जो प्रचलित हैं :

a) केरल
b) तमिलनाडु
c) आंध्र प्रदे श
d) तेलंगाना

Q.39 निम्नलिखित में से कौन गलत है?

a) लोगों के व्यापक पुनर्वास में भीख मांगने वाले बच्चों की शिक्षा शामिल है
b) समेकित बाल विकास सेवा योजना के बाल संरक्षण सेवा (CPS) के तहत बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के माध्यम से संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है।
c) जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2 के अनुसार, एक बच्चा जो भीख मांगता पाया जाता है, उसे "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता में एक बच्चा" के रूप में शामिल किया जाता है।
d) धारा 76 के अनुसार, जो कोई भी भीख मांगने के लिए किसी भी बच्चे को नियुक्त करेगा, उसे 10 साल तक कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा।

Q.40 संकल्प निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) विद्युत मंत्रालय
b) पर्यावरण मंत्रालय
c) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
d) शिक्षा मंत्रालय

Q.41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. फीडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल प्रकाश की गति से दो बार यात्रा करने वाले आवेशित कणों के जेट का उत्सर्जन करता है।
2. वे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तुओं में से एक हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 महात्मा गांधी नेशनल फैलोशिप (MGNF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MGNF को भारत के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा।
2. आईआईएम और आईआईटी से शैक्षणिक भागीदारी की मांग की जाएगी।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है।
2. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) भारत में आईटीआई के माध्यम से 137 ट्रेडों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

a) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
b) शिक्षा मंत्रालय
c) एमएसएमई मंत्रालय
d) कपड़ा मंत्रालय

Q.45 सागरिका, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जो भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, निम्न में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया था?

a) केरल
b) तमिलनाडु
c) महाराष्ट्र
d) गुजरात

Q.46 डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है:

a) मेघालय
b) मणिपुर
c) त्रिपुरा
d) असम

Q.47 सैंड्स, एक त्वरित संदेश मंच, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था?

a) नीति आयोग
b) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
c) विज्ञान और तकनीक मंत्रालय
d) रिलायंस इंडिकेटेड

Q.48 निम्नलिखित में से कौन भारतीय तट पर निवास नहीं बनाता है?

a) ओलिव रिडले कछुआ
b) हॉक्सबिल कछुआ
c) लॉगरहेड कछुआ
d) लेदरबैक कछुआ

Q.49 एक मामले में, यदि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसके लिए देय विमुद्रीकरण और भत्ते निम्नानुसार होंगे:

a) राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए दो राज्यों में से एक
b) वह पहला राज्य जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया
c) दोनों राज्यों ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार साझा
d) दूसरा राज्य जिसमें वह नियुक्त किया गया

Q.50 निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें:

1. मुंबई
2. गोवा
3. छत्तीसगढ़
4. तेलंगाना

उपरोक्त राज्यों को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करें:

a) 1-3-2-4
b) 1-2-3-4
c) 2-1-3-4
d) 2-1-4-3

Q.51 ई-छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था?

a) ऊर्जा मंत्रालय
b) पर्यावरण मंत्रालय
c) रक्षा मंत्रालय
d) शिक्षा मंत्रालय

Q.52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तियानवेन-1 जापान से मंगल पर पहला मिशन है।
2. नासा का मार्स रोवर परविरेंस खतरनाक सतह पर उतरेगा, जो शुरू में पानी से भरा हुआ था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 निम्न में से कौन सा कथन अमृत योजना के बारे में सही है / हैं?

1. अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन मिशन आपस में जुड़े हुए हैं।
2. अमृत स्मार्ट शहरों के विकास और विकास के लिए आधारशिला रखेगा।

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 अमृत योजना का उद्देश्य क्या है?

a) बुनियादी ढांचा प्रदान करना
b) किफायती आवास ऋण प्रदान करना
c) गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना
d) स्वच्छ और स्थायी वातावरण सुनिश्चित करना

Q.55 राष्ट्रीय सौर मिशन ने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की है।

a) 100 GW
b) 150 GW
c) 1000 GW
d) 10 GW

Q.56 व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (CECPA) हाल ही में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था?

a) नाइजीरिया
b) घाना
c) मॉरीशस
d) मोरक्को

Q.57 निम्न में से किस शहर को 'ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' से सम्मानित किया गया है?

a) हैदराबाद
b) सूरत
c) इंदौर
d) मुंबई

Q.58 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली वन्य जीवन अपराधों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है?

a) TROPEX
b) NAVDEX
c) AMPHEX
d) IDEX

Q.60 "गो इलेक्ट्रिक" अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था?

a) ऊर्जा मंत्रालय
b) पर्यावरण मंत्रालय

ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
d) कृषि मंत्रालय

Q.61 गुरु रविदास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वह भक्ति आंदोलन युग के थे।
2. गुरु रविदास के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है?
a) नीति आयोग
b) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
c) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
d) केंद्रीय जांच ब्यूरो

Q.63 गिग इकॉनमी क्या है?
a) कृषि अर्थव्यवस्था
b) सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था
c) सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था
d) श्रम बाजार में अल्पकालिक अनुबंध और फ्रीलांस काम की व्यापकता की विशेषता।

Q.64 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया?
a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
b) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
c) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
d) एमएसएमई मंत्रालय

Q.65 स्मार्टकोड प्लेटफार्म का उद्देश्य क्या है?
a) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सीधे शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाना।
ख) नागरिकों को वस्तुतः कोडिंग सीखने में सक्षम बनाना
c) आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम करना
d) शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मौजूदा कोड और कस्टम थीम का उपयोग करने में सक्षम बनाना।

Q.66 स्वर्ण जयंती फैलोशिप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
2. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सक्षम करने के लिए चुने गये वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करता है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.67 बैंकों और NBFC के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार करें:
1. बैंक, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिकृत वित्तीय माध्यम हैं। जबकि एनबीएफसी बिना बैंक लाइसेंस के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
2. एनबीएफसी कंपनी अधिनियम के तहत शामिल है, जबकि एक बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68 सिरोसिस मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग का रोग है?
a) जिगर
b) किडनी
c) दिल
d) त्वचा

Q.69 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय बांस मिशन को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू किया गया था।
2. वित्त मंत्रालय द्वारा पारंपरिक उद्योगों की पुनर्जनन की योजना (SFURTI) शुरू की गई।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.70 हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच नेतृत्व पहल के लिए डच भारतीय जल गठबंधन (DIWALI) साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। यह निम्नलिखित में से किस से संबंधित है?

a) छात्र विनिमय कार्यक्रम
b) पानी से संबंधित चुनौतियों का समाधान
c) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
d) अपशिष्ट प्रबंधन

Q.71 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा / से शामिल है?

1. एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी
2. इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद
3. ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक
4. फार्मास्यूटिकल्स दवाओं

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 4
c) केवल 2, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.72 विलुप्त माने जाने वाले निम्न में से कौन सा पक्षी, हाल ही में बोर्नियो, इंडोनेशिया के वर्षावनों में 170 साल बाद फिर से खोजा गया था?

a) रेड हेडेड वल्चर
b) जंगली उल्लू
c) जेरडन के कोर्टर
d) ब्लैक-ब्राउन बब्बलर

Q.73 भारत शहरी डेटा एक्सचेंज (IUDX) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शहरी स्थानीय निकायों के बीच शहरी प्रशासन से संबंधित आंकड़ों को सुचारू किया जाएगा।
2. यह एक बंद-स्रोत सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.74 हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के साथ निम्नलिखित में से कौन सा / से जुड़ा हुआ है?

a) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
b) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
c) एनआईटीआईयोग
d) दोनों (a) और (b)

Q.75 महामृत्युंजय मंदिर, हाल ही में, समाचार में, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

a) मध्य प्रदेश
b) उत्तर प्रदेश
c) असम
d) कर्नाटक

Q.76 नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा कराकर प्रजातियों को दी गई नई स्थिति कौन सी है?

a) गंभीर खतरे
b) विलुप्त
c) कमजोर
d) लुप्तप्राय

Q.77 उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के साथ अगले तीन वर्षों में प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए दिए जाएंगे।
2. घरों की महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन जारी किया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.78 निम्नलिखित में से जो हाल ही में स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों (एसआईपी) के चरण IV में जोड़े गए थे?

1. जैसलमेर का किला, राजस्थान
2. रामदेवरा (जैसलमेर) राजस्थान
3. गोलकोंडा किला (हैदराबाद) तेलंगाना
4. सूर्य मंदिर (कोणार्क) ओडिशा
5. अजमेर शरीफ (अजमेर) राजस्थान

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1,2, 3 और 5
b) केवल 1, 2, 4 और 5
c) केवल 1, 2,3, और 4
d) केवल 1 और 2

फरवरी 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1	B	21	A	41	B	61	C
2	D	22	D	42	A	62	B
3	D	23	D	43	C	63	D
4	B	24	D	44	A	64	C
5	A	25	C	45	A	65	D
6	C	26	A	46	D	66	B
7	A	27	A	47	B	67	C
8	B	28	C	48	C	68	A
9	B	29	D	49	C	69	D
10	B	30	C	50	B	70	B
11	D	31	B	51	C	71	D
12	D	32	B	52	B	72	D
13	D	33	D	53	C	73	A
14	C	34	A	54	A	74	D
15	A	35	B	55	A	75	C
16	A	36	B	56	C	76	A
17	C	37	A	57	A	77	C
18	C	38	A	58	C	78	C
19	B	39	D	59	A		
20	C	40	C	60	C		

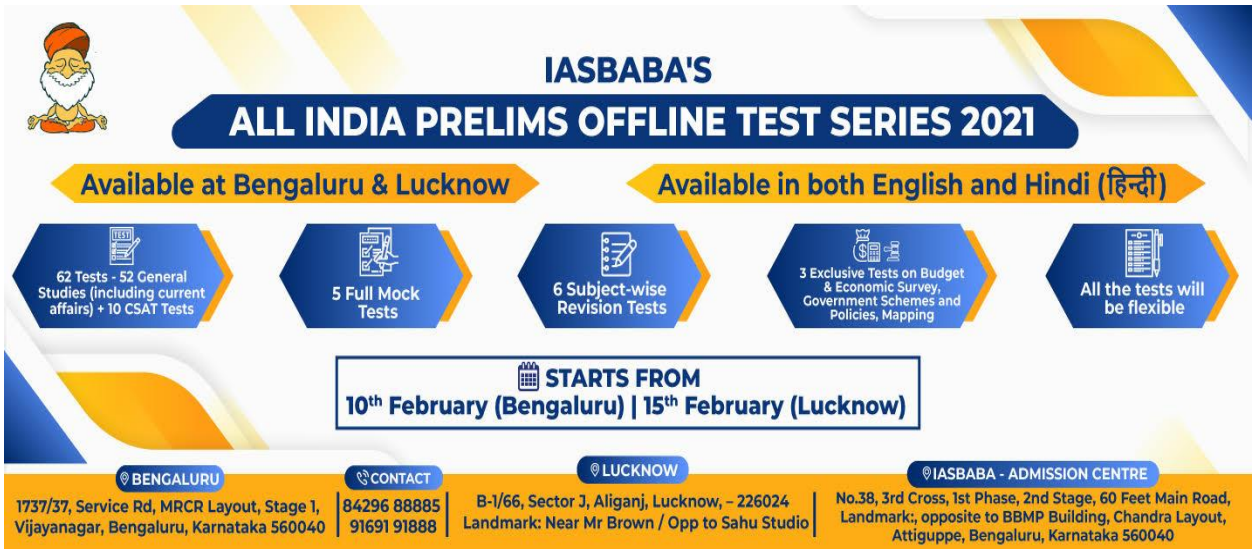

IASBABA'S
ALL INDIA PRELIMS OFFLINE TEST SERIES 2021
Available at Bengaluru & Lucknow
Available in both English and Hindi (हिन्दी)
62 Tests - 52 General Studies (including current affairs) + 10 CSAT Tests
5 Full Mock Tests
6 Subject-wise Revision Tests
3 Exclusive Tests on Budget & Economic Survey, Government Schemes and Policies, Mapping
All the tests will be flexible
STARTS FROM
10th February (Bengaluru) | 15th February (Lucknow)
BENGALURU
1737/37, Service Rd, MRCR Layout, Stage 1, Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka 560040
CONTACT
84296 88885
91691 91888
LUCKNOW
B-1/66, Sector J, Aliganj, Lucknow, – 226024
Landmark: Near Mr Brown / Opp to Sahu Studio
IASBABA - ADMISSION CENTRE
No.38, 3rd Cross, 1st Phase, 2nd Stage, 60 Feet Main Road, Landmark:, opposite to BBMP Building, Chandra Layout, Attiguppe, Bengaluru, Karnataka 560040

IASbaba
8 FOLD PATH
1 Hybrid Model
2 Integrated Programme (Prelims, Mains, Interview)
3 Focus on Fundamentals through Strategy Classes
4 Frequent Prelims & Mains Tests/Assignments
5 Value Add Notes
6 Connecting the Dots - Sessions by Experts & Toppers
7 Subject-wise Mentorship by Experts
8 Direct interaction with mentors and teachers (offline classes) and Live Doubt Clearing Session (Online classes)